संपादकीय

अमृतवर्षा संपादकीय

धनखड़ का धमाल...

यह दूसरी बार है जब निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मांग मानी है। शायद कुछ महीनों की देरी से लेकिन अंततः उन्होंने वही किया जिसकी मांग विपक्षी सांसद पिछले साल से कर रहे थे। पिछले साल दिसंबर में इंडिया गठबंधन के 60 सांसदों ने धनखड़ को हटाने की मांग की थी। उन्होंने एक प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि धनखड़ ने ह्यस्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और विपक्षी सदस्यों के प्रति अनुचित व्यवहार किया है। स्वाभाविक रूप से यह नोटिस राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका तर्क था कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया था और इसका उद्देश्य उपराष्ट्रपति की छवि खराब करना था। कुछ महीनों बाद, वही विपक्ष जो कभी उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, अब उनके समर्थन में खड़ा है। और धनखड़ जो पहले अपने पद पर अड़े हुए थे, अब वही कर गए जिसकी उम्मीद विपक्ष उनसे पिछले साल कर रहा था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया है। जिस गति से उन्होंने इस्तीफा दिया उसने सभी को चौंका दिया है। वही विपक्ष जो पहले उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, अब उन्हें किसान पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आया पलटा वह बेहद दिलचस्प हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ को राष्ट्र हित में अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। यह वही रमेश हैं जिन्होंने पहले आरोप लगाया था कि धनखड़ सरकार के प्रचारक की तरह व्यवहार करते हैं, न कि एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह। वे विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का नेतृत्व करने वालों में भी शामिल थे लेकिन अब रमेश उनकी निर्भीकता की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी धनखड़ के समर्थन में बयान दिया है। यह वही खड़गे हैं जो कई बार उन पर संसद में बोलने से रोकने का आरोप लगाते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे। यह दूसरी बार है जब निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मांग पर सहमति जताई है। हालांकि इसमें कुछ महीनों की देरी जरूर हुई लेकिन अंततः उन्होंने वह कदम उठाया जिसकी मांग विपक्षी सांसद लगातार कर रहे थे। दिसंबर 2023 में इंडिया गठबंधन के 60 सांसदों ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष का आरोप था कि धनखड़ ने खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और विपक्षी सांसदों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने यह नोटिस खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया है और उपराष्ट्रपति की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। उन्होंने तय समय से दो साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल वर्ष 2027 में समाप्त होना था। धनखड़ और विपक्ष के बीच जो आज समीकरण दिखाई दे रहे हैं, वह हाल ही में बने हैं। इस्तीफे से पहले तक उनका विपक्ष के साथ टकराव का रिश्ता रहा है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें मंच से नकल उतारकर निशाना बनाया था, साथ ही उनके महंगे सूट पर भी टिप्पणी की थी कि वह लाखों का सूट पहनते हैं। सपा सांसद जया बच्चन की धनखड़ से बहस तब हुई जब उन्होंने सदन में उनकी आवाज के अस्वीकार्य लहजे को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने करीब एक साल पहले सदन में गरजते हुए कहा था, मुझे माफी चाहिए। इसके अलावा उनका यह भी आरोप था कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तब उपराष्ट्रपति ने उनका माइक बंद करवा दिया। अब तस्वीर बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में विपक्ष का समर्थन करने के कारण धनखड़ को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकार ने लोकसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की शुरूआत की थी और 153 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह राज्यसभा में 63 सांसदों ने उपराष्ट्रपति को नोटिस भेजा। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा के सभी हस्ताक्षरकर्ता विपक्षी दलों से थे। तो सवाल उठता है कि राज्यसभा के भाजपा सांसद इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रहे जवाब स्पष्ट है उन्हें राज्यसभा में दिए गए नोटिस की जानकारी ही नहीं थी। यह घटनाक्रम न केवल सरकार की लोकसभा में चलाई जा रही कार्रवाई को बाधित करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार की नैतिक बढ़त को भी कमजोर करता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को आम सहमति के आधार पर हटाना चाहती थी। इसी के तहत लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 100 हस्ताक्षरों के मुकाबले 145 सांसदों ने समर्थन किया जिनमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे लेकिन जानकारों के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल्दबाजी में राज्यसभा को सूचित कर दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का नोटिस प्राप्त हो गया है, यह उस समय हुआ जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने निचले सदन को इस बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी थी।

संस्थापक संपादकः स्व. पारसनाथ तिवारी
स्वत्वाधिकारी एवं प्रकाशक रीता तिवारी,मुद्रक कुंज बिहारी के द्वारा आर डी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., प्लॉट नं- सी 16-17 पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013 से मुद्रित व B-14 जगत भवानी अपार्टमेंट, एसपी सिन्हा लेन, बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1 से प्रकाशित
संपादक-बन बिहारी
दूरभाष - 9905463571, 8757425017, धनबाद कार्यालयः मास्टर पाड़ा जे.सी. मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद दूरभाष - 2204991, दिल्ली कार्यालयः बी-49, जैन मंदिर गली, शकरपुर मेन मार्केट, दिल्ली-110092, फोन नं.- 011-22055208, आर.एन.आई नं. 44420/87
ईमेलः amritvar-shanews2015@gmail.com

'भगवा आतंकवाद' शब्द को गढ़ने वाले अब क्षमा मांगें

साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर को गंभीर स्थिति के कैंसर की स्थिति में भी कारावास में रखा गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। क्या इस पीड़ा के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या झूठे मुकदमों के लिए जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी?

प्रवीण गुगनानी

जब भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जबरन गढ़ दिया गया था तब मैंने मेरी कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा पुस्तक में लिखा था कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द या टर्म हो ही नहीं सकता, यह एक अशब्द है जिसे हमें बोलचाल, लेखन व विमर्श से निकला फेंकना होगा। इस शब्द को मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग, केंद्र में एकाधिक विभागों के मंत्री रहे पी. चिदंबरम, तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे और कांग्रेस ने केवल मोहरा बनकर गढ़ा था। इस शब्द के पीछे वस्तुतः तो वामपंथी छुपे हुए हैं जो प्रेत बनकर वेताल यानि कांग्रेस की पीठ पर अब भी सवार है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जब भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी के विरुद्ध दिग्विजय सिंह चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने समूचे चुनाव को भगवा आतंकवाद को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के मध्य समाचार पत्रों में मेरा एक आलेख भी प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था भगवा आतंकवाद शब्द की अंत्येष्टि का सटीक समय। इस चुनाव में जानता ने दिग्विजय सिंह को भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने का यथोचित दंड दे दिया था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी भी भोपाल के सुंदर तालाब के किनारे पर बैठकर हिंदुत्व को मछली समझकर जाल डालकर बैठे हुए दिखे थे। उन्होंने भोपाल के ताल में एक नया शाब्दिक विष उँडेला था - हिंदू तो सदा से हिंसक रहा है। अरे, दिग्विजय जी, येचुरी जी, सहित भगवा आतंकवाद शब्द के सभी कथित नेताओं सुनो; हिंदू सदा से सहिष्णु रहा है, इतना सहिष्णु कि कई अवसरों पर इसका भूगोल और इतिहास ही बदल गया और कई अवसरों पर इस हिंदू सहिष्णुता ने हिंदूत्व के कुछ अध्यायों का समापन ही करवा दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो, बाबर हजार मील दूर से भारत में आकर हमारे देश के आराध्य श्रीराम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को नेस्तनाबूद कर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर पाता। और, न ही दुर्दांत मुस्लिम शासक तैमुरलंग दिल्ली से हरिद्वार के समूचे मार्ग में हिंदू नरमुंड बिछा पाता, हिंदू हिंसक होता तो बख्तियार खिलजी भारतीय ज्ञान के प्रतीक, नालंदा को यूं आग के हवाले न कर पाता, न ही औरंगजेब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ पाता और न ही लाखों भारतीय मातृशक्ति को जौहर करने को मजबूर होना पड़ता। यदि हिंदू हिंसक होता तो गुरु गोविन्द सिंह के दोनों पुत्रों को जीवित दीवार में चुनकर मार डालने जैसी दुर्दांत घटना न हुई होती और न ही, मोहम्मद गजनवी श्रीकृष्ण जन्म स्थान को मथुरा में ध्वस्त कर कब्जा पाता। मालेगांव मामले में आए हुए निर्णय का मर्म यही है कि यदि हिंदू सहिष्णुता और उस पर हुए अत्याचारों का इतिहास और पढ़ना हो तो वे संत मतिदास को पढ़ लें, गुरु तेगबहादुर को पढ़ लें, जलियांवाला बाग पढ़ लें, भगतसिंह के बम फेंकने की मानवीय शैली पढ़ लें, भारत का धर्म आधारित विभाजन और उसके बाद यहां की भूमि पर मुस्लिमों की बसाहट व पाकिस्तान से हिन्दूओं का मारकाट भरा निर्वासन पढ़ लें, वे सोहरावरदी पढ़ लें, मोपला काण्ड पढ़ लें। और यदि पुराना इतिहास न पढ़ना हो भगवा आतंकवाद की माला जपने वाले नेताओं को हाल ही का रामसेतु विध्वंस भगवान राम को काल्पनिक कहने का शपथपत्र और ऐन दीवाली की रात्रि पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी का तालिबानी आदेश पढ़ लेना चाहिए। इन घटनाओं सहित लाखों अन्य इतिहास सिद्ध घटनाओं ने यह ब्रह्मसत्य स्थापित किया है कि हिंदू हिंसक नहीं सहिष्णु रहा है, क्षमाशील रहा है, सर्वसमावेश को, सर्वस्पर्श को आतुर व उत्सुक समाज रहा है! मालेगांव के संदर्भ में कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह भी कहा गया था कि आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिमों से अधिक हिंदू सम्मिलित रहते हैं। 2008 के बाद, विशेषकर 26/11 के मुंबई हमले से ठीक पहले, मालेगांव केस को आधार बनाकर कम्युनिस्ट रिमोटेड कांग्रेस्टिस्टों ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया था कि भारत में आतंकवाद को हिंदू संगठन बढ़ा रहें हैं। लेकिन यह एक वैचारिक आगजनी वाला झूठ था झ राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया नैरेटिव, जिसकी कीमत निर्दोष हिंदुत्व के मासूम संतों, सैनिकों व नागरिकों ने चुकाई है। लेफ्ट-लिबरल मीडिया, कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी और वामपंथी इतिहासकारों ने इस नैरेटिव को खुलकर समर्थन दिया। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद जैसे लोग, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे, उन्हें आतंकवादी की तरह पेश किया गया, मीडिया ट्रायल चला, और तथाकथित सेकुलर ताकतों ने उनकी छवि को नष्ट-भ्रष्ट करने के प्रयास किए। साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर को गंभीर स्थिति के कैंसर की स्थिति में भी कारावास में रखा गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। क्या इस पीड़ा के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या झूठे मुकदमों के लिए जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो वे चुप हैंझ कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई क्षमा नहीं। यह उनकी नैतिकता की हार है और इस देश के विवेक के लिए एक चेतावनी भी। आज की आवश्यकता है कि वे हिंदू समाज से उनके द्वारा गढ़े गए छद्म शब्दों के लिए क्षमा मांगे और उनका उत्तरदायित्व हमारा समाज तय करे। कांग्रेस नेतृत्व को अपने इस झूठे नरैटिव गढ़ने के दोष हेतु देश से क्षमा माँगनी चाहिए। मालेगांव 2008, बम विस्फोट केस में कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देना एक बहुत बड़ा न्यायिक पड़ाव है झ न केवल उन निदोर्षों के लिए, जिन्होंने वर्षों तक अपमान, पीड़ा और मानसिक प्रताड़ना को भोगा, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अब जब न्यायपालिका ने अपना निर्णय सुना दिया है, तब समय आ गया है कि इस केस के जरिए रची गई उस सुनियोजित राजनीतिक कथा का गहराई से विश्लेषण किया जाए झ जिसे हिंदू आतंकवाद कहा गया था। इस अभियान का मकसद स्पष्ट था — जिहादी आतंकवाद से ध्यान हटाना और राष्ट्रवादी शक्तियों को कठघरे में खड़ा करना। उस समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, विशेषकर मुंबई हमलों, संसद हमले, और कंधार कांड जैसे मामलों ने कांग्रेस सरकार की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया था। ऐसे में उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ा, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी चेहरों को आतंकवादी घोषित करके यह दिखाया जाए कि भारत में आतंकवाद केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। सोलह वर्षों तक झूठे मुकदमों का सामना करने के बाद जब आरोपी बरी हो गए, तब न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सब केवल भूल थी, या किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा?

एक क्लिक में दुनिया से जुड़ने की क्रांति

आज के दौर में जब हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है और हर सवाल का जवाब बस एक क्लिक की दूरी पर है, तब हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह चमत्कारिक व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई इंटरनेट तो एक विशाल महासागर है लेकिन उस महासागर तक पहुंचने का द्वार बना वर्ल्ड वाइड वेब यानी। बिल्कुल साधारण से प्रतीत होने वाले इन तीन अक्षरों ने मानव जीवन को इस कदर बदल दिया है कि अब पूरी दुनिया में इसका कोई विकल्प ही नहीं बचा। इंटरनेट की यह जादुई खिड़की 1 अगस्त को एक प्रतीक के रूप में याद की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में, ताकि हम उस विलक्षण मस्तिष्क को याद कर सकें, जिसने यह राह खोली। वर्ल्ड वाइड वेब यानी के जनक थे टिम बर्नर्स-ली। बचपन से ही तकनीक में गहन रुचि रखने वाले टिम बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। 1976 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हुए उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही स्वयं का एक कंप्यूटर सैट तैयार कर लिया था। टिम बर्नर्स-ली किसी सामान्य इंजीनियर की तरह केवल सीमित सोच तक नहीं रुके। वर्ष 1980 में जब वे एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे तभी उन्होंने कंप्यूटर में मौजूद दस्तावेजों और फाइलों को आपस में लिंक करने के लिए इनक्वायर नामक एक प्रयोगात्मक प्रोग्राम बनाया। यह उनकी एक छोटी-सी लेकिन दूरदर्शी सोच की नींव थी, जो बाद में पूरे विश्व को एक ही डिजिटल धागे में पिरोने वाली बन गई। बर्नर्स-ली की यह सोच सीमाओं में सिमटी हुई नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे वैश्विक सूचना तंत्र की कल्पना कर रहे थे जो समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सके और वह लोगों के लिए सूचनाओं का एक व्यापक, सहज और सुलभ मंच बन जाए। इसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा प्रस्तुत की और वर्ष 1991 में इस प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं थी बल्कि यह मानव सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़ था जिसने संचार, शिक्षा, व्यापार, शोध और मनोरंजन की परिभाषा ही बदल दी। यह वही दौर था, जब इंटरनेट केवल टेक्स्ट तक सीमित था लेकिन 1993 के बाद इसमें चित्र, ग्राफिक्स और ऑडियो-वीडियो की सुविधा भी जुड़ने लगी जिससे इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और एक वैश्विक जीवनशैली का हिस्सा बन गया। आज, वर्ल्ड वाइड वेब के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। ऑफिस हो या स्कूल, बैंकिंग हो या अस्पताल, फिल्में देखनी हों या संगीत सुनना हो, किसी नए देश की जानकारी लेनी हो या कहीं की यात्रा करनी हो, प्रत्येक रास्ता से होकर गुजरता है लेकिन इतना सब होते हुए भी यह कहना गलत नहीं होगा।

पाक परमाणु ठिकानों को पल भर में मिट्टी में मिला देगी भारत की हाइपरसोनिक बंकर बस्टर मिसाइल

नीरज कुमार दुबे

हाल ही में अमेरिका ने अपनी अत्याधुनिक बंकर बस्टर बम का उपयोग कर ईरान के भूमिगत परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। इसने विश्व को यह दिखाया था कि अत्यधिक संरक्षित और गहराई में स्थित ठिकाने भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करने की खबरें सामरिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हम आपको बता दें कि यह मिसाइल बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम होगी और गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट कर सकेगी। यह खबर सामने आने के बाद से पाकिस्तान की चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि उसके कई परमाणु प्रतिष्ठान भूमिगत बंकरों में स्थित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकती है। देखा जाये तो भारत की यह उपलब्धि दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की यह नई मिसाइल भारत की अग्नि-श बैलिस्टिक मिसाइल का संशोधित संस्करण हो सकती है। इसकी गति की बात करें तो यह हाइपरसोनिक है यानि ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक से दौड़ेगी। यह पारंपरिक बंकर बस्टर है और लगभग 7,500 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी भेदन क्षमता 200 फीट तक भूमिगत प्रवेश कर विस्फोट करने की बताई जा रही है। इसकी रेंज लगभग 2,500 किलोमीटर होगी। हम आपको बता दें कि भारत के पास अमेरिका या रूस की तरह महंगे स्टेल्थ बॉम्बर नहीं हैं। इसलिए मौजूदा लड़ाकू विमानों से बंकर बस्टर बम गिराना जोखिमपूर्ण होगा क्योंकि वे दुश्मन के राडार पर आ जाएंगे। परन्तु मिसाइल आधारित प्लेटफॉर्म भारत को सुरक्षित दूरी से गुप्त और सटीक हमले की क्षमता देगा। हम आपको यह भी बता दें कि भारत की यह मिसाइल क्षमता उसकी सामरिक बढ़त को काफी बढ़ा देगी। साथ ही इससे पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल रणनीति भी ध्वस्त हो जायेगी। इस मिसाइल के जरिये भारत सुरक्षित दूरी से दुश्मन के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल का विकास चीन पर भी एक रणनीतिक दबाव बनाएगा। जहां तक इस मिसाइल से पाकिस्तान की चिंता की बात है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की सामरिक मामलों की विशेषज्ञ राबिया अख्तर ने डॉन अखबार में लिखा है कि भारत का यह कदम पारंपरिक और परमाणु रणनीति के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि यदि भारत इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल उसके परमाणु ठिकानों पर करता है, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से परमाणु प्रथम-हमले जैसा लगेगा, भले ही वारहेड पारंपरिक ही क्यों न हो। राबिया अख्तर ने चेतावनी दी है कि किसी भी परमाणु-सशस्त्र देश के लिए यह मायने नहीं रखेगा कि वारहेड पारंपरिक है या परमाणु। यदि कोई हाई-स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर दागी जाती है, तो इसे परमाणु हमले की शुरूआत माना जाएगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपनी सामरिक या रणनीतिक परमाणु हथियारों का तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने हमेशा यह घोषित नीति अपनाई है कि वह परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा। लेकिन बंकर बस्टर मिसाइलें इस नीति के तहत नहीं आती हैं। क्योंकि एक ओर, ये पारंपरिक हथियार हैं और तकनीकी रूप से वह एनएफयू यानि न्यूक्लियर फर्स्ट यूज नीति का उल्लंघन नहीं करते। दूसरी ओर, ये सीधे दुश्मन के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया में परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत हाल ही में चलाये गये ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह तय कर दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत की यह नीति आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वाले देशों के बीच कोई अंतर नहीं करती है।

हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता

कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने इस झूठ को नकार दिया। शाह के इस ब्यान के बाद चर्चा छिड़ी है कि उन्होंने आखिर ऐसा दावा कैसे कर दिया कि हिन्दू कभी आतंकी नहीं हो सकता?

राकेश सैन

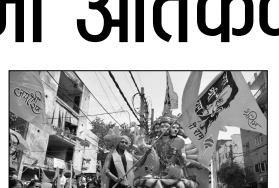

आपरेशन सिन्दूर पर संसद में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि ह्यमैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। गृहमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उसने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धान्त बनाया। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने इस झूठ को नकार दिया। शाह के इस ब्यान के बाद चर्चा छिड़ी है कि उन्होंने आखिर ऐसा दावा कैसे कर दिया कि हिन्दू कभी आतंकी नहीं हो सकता? पूछा जा रहा है कि उन्होंने भावावेश में आकर अतकथनी कर दी या हिन्दू अस्मिता के प्रेम में फंस कर ये दावा कर दिया? अमित शाह का उक्त कथन उन लोगों के तो गले बिल्कुल नहीं उतर रहा जो अभी तक इसी विमर्श को पल्लवित-पोषित करते आ रहे हैं कि ह्यआतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर कैसे हिन्दुओं को इस मामले में एकतरफा चरित्र प्रमाणपत्र दिया जा रहा है? निष्पक्ष हो कर अमित शाह के ब्यान को जांचा-परखा जाए तो सामने आता है कि इसमें न तो अतिरंजना है न मनोवेश या अतिश्योक्ति, बल्कि यह एतिहासिक सत्य, भारत-भूमि पर पनपा प्रमाणिक हिमालयी तथ्य है कि हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आओ सबसे पहले जानें कि आतंकवाद आता कहां से है, इसका वीर्य क्या है? असल में विश्व में ईश्वर को लेकर दो तरह की अवधारणाएं या मार्ग हैं, एक सनातन व दूसरा सेमेस्टिक या सामी। सभी मार्ग सम्मानित हैं, पर इनमें मौलिक अन्तर हैं। सेमेस्टिक मजहब में ईश्वर का एक निश्चित संदेशवाहक या पैगम्बर या दूत, एक ही धर्म ग्रन्थ रहता है-जैसे इस्लाम, ईसाई व यहूदी मजहब। उक्त सभी मजहब अपने-अपने पैगम्बर को ईश्वर का अंतिम दूत और अपने-अपने धर्म ग्रन्थों में वर्णित बातों को ही ईश्वर का अंतिम सन्देश मानते हैं। सामी मजहब वाले केवल ऐसा मानते ही नहीं बल्कि अपने पैगम्बर व ग्रन्थों की बातों को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हुए उन पर थोपने का प्रयास भी करते हैं। धीरे-धीरे इनके अनुयायियों में श्रेष्ठता की यही ग्रन्थी केवल मजहबी उन्माद तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि रहन-सहन, खान-पीन, भाषा-वाणी अर्थात जीवन के हर क्षेत्र को संक्रमित कर देती है। दूसरे को हीन समझ उस पर अपने विचार व आस्था लादने के लिए कोई क्रूसेड करता है तो कोई जिहाद। दुनिया में ईसाईयत व इस्लाम के नाम पर जो अत्याचार, हिंसा, खूनखराबा हुआ सभी इसी श्रेष्ठा की ग्रन्थी के संक्रमण के चलते हुआ। दूसरे की आस्था के प्रति असम्मान, हिकारत, तिरस्कार में ही आतंकवाद के बीज छिपे रहते हैं। मध्ययुग में ईसाईयत के नाम पर आतंकवाद फैला परन्तु पश्चिमी समाज में आई नवचेतना के चलते इसने रूप बदल कर सेवा व लालच का ले लिया परन्तु इस्लाम के प्रचार-प्रसार का अमानवीय ढंग निरंतर जारी रहा, जिसे आज इस्लामिक आतंकवाद कहा जाने लगा है। आज ईसाई मिशनरीड्डा सेवा व लालच के बल पर धर्मपरिवर्तन करते हैं और जिहादी बंदूक की नोक पर, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि अपने-अपने मजहबों की संख्या बढ़ाना चाहे साधन अलग-अलग हैं। इस्लामिक जिहाद की तरह अगर ईसाईयों की सेवा व प्रलोभन के प्रपंचों को भी आतंकवाद का नाम दे दिया जाए तो कोई विषयभटकाव नहीं होगा। सामी मजहबों के विपरीत दूसरी विचारधारा है सनातन, जिसे हिन्दू धर्म भी कहते हैं। श्री अरविन्द की दृष्टि में हिन्दू धर्म और सामी मजहब पुस्तक में महर्षि अरविन्द कहते हैं-जिस धार्मिक संस्कृति को हम आज हिन्दू धर्म के नाम से पुकारते हैं उसने अपना कोई नाम नहीं रखा, क्योंकि उसने स्वयं अपनी कोई साम्प्रदायिक सीमा नहीं बांधी। उसने सारे संसार को अपना अनुयायी बनाने का कोई दावा नहीं किया, किसी एकमात्र निर्दोष सिद्धांत की प्रस्थापना नहीं की, मुक्ति का कोई एक ही संकीर्ण पथ या द्वार निश्चित नहीं किया। वह कोई मत या पन्थ की अपेक्षा कहीं अधिक मानवआत्मा के ईश्वरोन्मुख प्रयास की एक सतत विकासशील परम्परा है। सनातन का विचार है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अर्थात सत्य एक है जिसे विद्वान उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। अर्थात तेरे-मेरे की भावना छोटे मन का प्रतीक है, उदारचित्त वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। सनातन धर्म मानता है तेरा धर्म तुझे मुबारक और मेरी आस्था मुझे। दोनों की मार्ग श्रेष्ठ हैं। मार्ग अलग-अलग हैं परन्तु सभी की मंजिल एक है, जैसे सभी नदियां अंततः एक समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसी तरह सभी पथ उसी एक मंजिल पर ही मिलते हैं। यही भावना है जो हिन्दू को आतंकवादी बनने से रोकती है। इतिहास साक्षी है कभी भारत ने तलवार के जोर पर न तो किसी के भू-भाग को कब्जाया और न ही दूसरे पर अपना धर्म या विचार थोपा। इसी सर्वसमावेशी व सर्वपन्थ समादर भाव वाली जीवन शैली के आधार पर ही अमित शाह ने राज्यसभा में डंके की चोट पर दावा किया कि हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। केवल आस्था ही क्यों, हिन्दू ने तो कभी नास्तिक या अनिश्वरवादियों को भी नहीं दुत्कारा। महर्षि चारवाक ईश्वरवाद के उलट और पूर्णतः भौतिकवादी थे। वेदों के बारे उनके विचार नकारात्मक थे।

यौन गतिविधियों का पूर्ण अपराधीकरण को चुनौती

न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए वैधानिक उम्र 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष करने की शीर्ष अदालत से सिफारिश की है। चर्चित 'निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने वाली न्यायमित्र इंदिरा जयसिंह ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 और आईपीसी की धारा 375 के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर एवं किशोरियों से जुड़ी यौन गतिविधियों का पूर्ण अपराधीकरण करने को चुनौती देते हुए अपनी लिखित प्रस्तुतियां दी हैं। दलील दी है कि वर्तमान कानून किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए प्रेम संबंधों को अपराध मानता है, और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अपनी स्थापना के पक्ष में उन्होंने जोरदार तर्क रखा है कि कानूनी ढांचा किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को गलत तरीके से दुर्व्यवहार के बराबर मानता है तथा उनकी स्वायत्तता, परिपक्वता और सहमति देने की क्षमता को अनदेखा करता है। सहमति की आयु 16 से बढ़ा कर 18 वर्ष करने को उचित ठहराने के लिए कोई तर्कसंगत कारण या अकाट्य आंकड़ा भी नहीं है। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिलाया है कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा आयु बढ़ाए जाने से पहले 70 वर्षों से अधिक समय तक आयु सीमा 16 वर्ष (शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति की) ही रही थी। यह भी ध्यान दिलाया है कि आयु बिना किसी बहस के बढ़ा दी गई और ऐसा करते समय वर्मा समिति की सिफारिश की भी अनदेखी की गई। बेशक, यह सामयिक मुद्दा है, और इसे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। आजकल किशोर समय से पहले ही यौवन प्राप्त कर लेते हैं, और अपनी पसंद के रोमांटिक और यौन संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। फिर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कषरे के साथ ही वैज्ञानिक एवं सामाजिक आंकड़ों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए जो बताते हैं कि किशोरों में यौन रुझान असामान्य नहीं हैं। आयु संबंधी मौजूदा व्यवस्था किशोरों की सामान्य चेष्टाओं और रुझानों का अपराधीकरण करती है। यह आंकड़ा भी हतप्रभ करने वाला है कि 2017-21 के बीच 16-18 आयु वर्ग के नाबालिगों पर पॉक्सो कानून के तहत अभियोजन में 180 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है।

बिहार को लेकर 'सुप्रीम' निर्णय

आरती कुमारी

बिहार विधानसभा का चुनाव के दृष्टिगत सभी के भीतर इस बात को लेकर कौतूहल है कि वहां सरकार का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार अगली बार फिर सत्ता में लौटेंगे या नहीं ?दूसरे, यहां मोदी का जादू चलता है या नहीं? तीसरे, लालू की लालटेन यहां जलेगी या फिर राहुल गांधी कुछ विशेष कर पाएंगे ? ये सारी बातें भी लोगों के लिए कौतूहल का कारण बन रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि ज्यों-ज्यों निकट आती जा रही है, त्यों-त्यों राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए तरह-तरह से हाथ पांव मार रहे हैं। सत्ता में आना प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है, परन्तु उसके लिए अनिवार्य कसौटी होती है-लोकप्रियता। लोकप्रियता का अर्थ है- जनता का साथ मिलना। लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान करना सबसे अनिवार्य होता है, परंतु भारत के राजनीतिक दल लोकतंत्र के इस अनिवार्य मूल्य की 'हत्या' करके भी सत्ता हथियाने का प्रयास करते रहे हैं । इसके लिए वे लोक और तन्त्र दोनों की दृष्टि में धूल झोंककर भी सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि अधिकांश राजनीतिक दल मतदाता सूची को मनमाने ढंग से संशोधित और परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। यदि बिहार चुनाव की बात करें तो यहां पर भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं । पता चला है कि 7 लाख ऐसे फर्जी मतदाता मतदाता सूचियों में सम्मिलित कर लिए गए हैं, जिनका एक से अधिक स्थानों पर पहले से ही वोट बन चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। जबकि 28 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से अन्यत्र पलायन कर चुके हैं । कुल मिलाकर लगभग 62 लाख फर्जी मतदाता अभी तक बिहार की विधानसभा के चुनावों की मतदाता सूची में फर्जी रूप में पकड़े जा चुके हैं। लोकतंत्र की हत्या करने के इस बड़े खेल को कौन कर रहा था? यदि यह प्रश्न किया जाए तो पता चलता है कि जो राजनीतिक दल आज भारत के चुनाव आयोग को इसलिए गाली दे रहे हैं कि उसने मतदाता सूची में दर्ज किए गए इन नामों को यथावत क्यों नहीं रहने दिया ? वही वे अपराधी हैं जो 'लोकतंत्र की हत्या' के इस खेल में सम्मिलित हैं। चुनाव आयोग ने डंडा लेकर ऐसे राजनीतिक दलों की पीठ को तोड़ना आरंभ किया तो उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ कर दिया कि भारत में चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। अपनी तानाशाही चला रहा है और पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आया है । देश के जनमानस को इस प्रकार के शोर शराबे को गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या में सम्मिलित राजनीतिक दल इस प्रकार का शोर क्यों मचा रहे हैं ? इस प्रकार के शोर शराबे में सम्मिलित राजनीतिक दल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर इन राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय को बिहार चुनाव आयोग के इस प्रकार के मनमाने आचरण पर रोक लगाने के लिए कहा है । परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के मसौदा (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) के प्रकाशन पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र अर्थात वोटर आईडी कार्ड (EPIC) को भी सम्मिलित करे। चुनावी प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कहीं नाम काटे जा रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कर लेने चाहिए थे, परंतु नहीं किये जा सके हैं, उन्हें मतदाता सूची में जोड़ भी लिया जाए। वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि यहां पर प्रधान से लेकर संसद तक के सबसे बड़े चुनाव तक में मतदाता सूचियों में बड़ी गड़बड़ी होती है। जिले स्तर पर होने वाले जिला पंचायत के चुनाव में तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह गुंडागर्दी पर आधारित होकर रह गया है। सारा देश जानता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में किस प्रकार जिला पंचायत सदस्यों को खरीदने का खुल्लम-खुल्ला काम होता है ? इसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी गुंडागर्दी होती है। यदि हम शहरी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के चुनावों को देखें तो वहां पर भी लोग विकास कार्यों पर कम ध्यान देते हैं, राजनीतिक उठापटक में अधिक लगे रहते हैं। अपनी सोसाइटी के अध्यक्ष पद को कैसे हथियाया जाए ? – इस पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। इस सबके उपरांत भी लोकतंत्र के हत्यारों को 'बदमाशी' करने से रोका नहीं जाता। हम इस लेख के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि अकेले बिहार की मतदाता सूचियों के ही निरीक्षण पुनरीक्षण का कार्य किया जाना पर्याप्त नहीं है, पूरे देश की यही बीमारी है। लोकतंत्र के नाम पर यहां पर गली मोहल्लों तक में चुनाव होते हैं , परंतु धांधली सभी में होती है। सभ्य और शालीन लोगों का चुनाव के प्रति ध्यान और आकर्षण भंग हो चुका है। वे इसे अपराधियों के लिए छोड़ चुके हैं। इसलिए भारतवर्ष में चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के साथ-साथ मजबूत और आत्म स्वावलंबी निकाय बनाया जाना भी आवश्यक है। इसके पास अपना सुरक्षा बल और अपने अधिकारी जिले स्तर तक होने चाहिए। अभी तक हो यह रहा है कि किसी भी चुनाव के समय जिलाधिकारी, एसडीएम , तहसीलदार और उनका समस्त विभाग और उसके कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करना आरंभ कर देते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अपनी सरकार का ही 'अंकुश' होता है। जिससे सरकार को प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए प्रत्येक चुनाव में धांधली होना स्वाभाविक होता है। इसी के चलते चुनाव आयोग पर हर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हैं। यदि सत्ता पक्ष पूर्ण पारदर्शिता अपनाना चाहता है तो उसे अपनी ओर से यह पहल करनी चाहिए कि वह चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के साथ-साथ उसका अपना सुरक्षा बल स्थाई रूप से उपलब्ध कराएगा ? सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्यारे कहां-कहां हैं और कैसे-कैसे ढंग से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिहार के संदर्भ में न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए बधाई।

बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के चुनाव में हो सकता है बड़ा उलटफेर

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

बिहार की राजनीति वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर तेजी से बढ़ रही है। नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं, एक ओर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी ओर हैं रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जो अब "जन सुराज" के साथ बिहार की राजनीति में निर्णायक मोड़ लाने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का चुनावी हस्तक्षेप न सिर्फ भाजपा और जदयू की रणनीति को चुनौती दे रहा है, बल्कि यह विपक्ष के लिए भी एक अप्रत्याशित सियासी समीकरण बनता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने राजनीति के गलियारों में अपनी पहचान बतौर एक चुनावी रणनीतिकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक और कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, प्रशांत किशोर ने लगभग हर प्रमुख दल के लिए कभी न कभी चुनावी गणित बैठाया है। लेकिन अब प्रशांत किशोर एक नई भूमिका में हैं, एक नेता के रूप में। प्रशांत किशोर ने बिहार की यात्रा कर, जन संवाद को मुख्य हथियार बनाया है। उनका दावा है कि उन्होंने राज्य के हर जिला, हर प्रखंड और गांव में जाकर जनता की समस्याएं सुना है। इस यात्रा के बाद उन्होंने "जन सुराज" को एक राजनीतिक संगठन का रूप दिया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि "जन सुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के, अपने दम पर सरकार बनाएगी।" प्रशांत किशोर ने बिहार के सामने जो समस्याएं चिन्हित किया हैं, वह नई नहीं हैं बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बदहाली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि उनके पास इन समस्याओं का ठोस और व्यावहारिक समाधान है। बिहार में केवल 23 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जो आबादी का सिर्फ 2% है। 98% लोगों के लिए निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और उद्योग ही एकमात्र विकल्प हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि "सरकारी नौकरी देकर पलायन नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए बिहार को शिक्षा और पूंजी का केंद्र बनाना होगा।" बिहार से मजदूर, छात्र, बुद्धिजीवी और पूंजी, सभी पलायन कर रहे हैं। जन सुराज का दावा है कि यदि सरकार ईमानदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पूंजी सुलभ करे, तो एक साल में पलायन की रफ्तार थम सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके साथ 10 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री काम कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार के लिए एक विशेष आर्थिक मॉडल तैयार किया है। प्रशांत किशोर अपने भाषणों और जनसभाओं में भाजपा, जदयू और तेजस्वी यादव, सभी को एक साथ लपेट लेते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करते हैं, जिससे उनका संवाद जनता में प्रभाव छोड़ता है। "मुख्यमंत्री ने गरीबों को दो लाख रुपये देने का वादा किया था, एक भी परिवार को अब तक पैसा नहीं मिला।" "नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ जातीय आंकड़े बदलने की राजनीति हुई है।" भाजपा पर सीधा वार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि "अब बीजेपी भी पीली टोपी पहन रही है क्योंकि उन्हें पता है जनता अब हमारे साथ है।" उन्होंने कहा है कि "पीएम मोदी ने 15 लाख की बात कही थी, नीतीश कुमार ने दो लाख की — दोनों झूठे वादे निकले।" सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए कहा है कि "सम्राट चौधरी मेरे भाई हैं, लेकिन भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। गलती की है तो सामने आएंगे।" "मंगल पांडे पर किस्तों में खुलासे होंगे।" प्रशांत किशोर ने भू-सर्वे और भ्रष्टाचार पर कहा है कि बिहार में 2013 से भू-सर्वे शुरू हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 20% जमीन की मापी हो सकी है। CO और DCLR की पोस्टिंग में 25-50 लाख की रिश्वत ली जा रही है। सर्वे का काम धन उगाही का उद्योग बन गया है। उन्होंने कहा है कि 2006 में वादा किया गया था कि महादलितों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी।आज तक सिर्फ 2.34 लाख परिवारों को जमीन दी गई है, जिनमें से 1.2 लाख को आज तक कब्जा नहीं मिला है। नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने का दावा किया। लेकिन केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव नहीं भेजा गया। तांती-तंतवा समुदाय को एससी का दर्जा देने की घोषणा तो हुई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जातियों का वर्गीकरण सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया गया। तेजस्वी यादव अपने बयानों से नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। वे बेरोजगारी, अपराध और शिक्षा की दुर्दशा को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन उनका खुद का पारिवारिक विवाद आरजेडी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। तेज प्रताप ने "टीम तेज प्रताप" बनाकर महुआ सीट से निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवार और पार्टी को अनफॉलो कर दिया है। वे पीले रंग को अपनी पहचान बता रहे हैं, जो प्रशांत किशोर की जन सुराज का भी रंग है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, महबूब अली कैसर, उदय नारायण चौधरी, इन चारों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। सभी वर्गों को संतुलन के साथ प्रतिनिधित्व दिया गया है, सवर्ण, दलित, मुसलमान और यादव। लेकिन प्रश्न यह है कि तेजस्वी-तेज प्रताप का आंतरिक टकराव क्या आरजेडी की साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? भाजपा ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक सवर्ण चेहरे को आगे किया है। लेकिन राज्य में पार्टी की पकड़ कमजोर माना जा रहा है। वहीं चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं लेकिन उन्हीं के साथ गठबंधन में बने हुए हैं। मंत्री बने रहने की चाहत उनके राजनीतिक विरोध को कमजोर बनाती है। बिहार में तीनध्रुवीय मुकाबला बनता दिख रहा है, एनडीए (भाजपा + जदयू + लोजपा रामविलास), महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल) और जन सुराज (प्रशांत किशोर का अकेला अभियान)। देखा जाए तो पढ़ा-लिखा युवा वर्ग प्रशांत किशोर की ओर झुक सकता है। वहीं मुस्लिम-दलित वोटबैंक आरजेडी के साथ रहने की संभावना है। नीतीश कुमार के कुशल प्रशासन के दावों पर अब जनता भरोसा कम कर रही है। बिहार की सियासत इस बार सिर्फ जाति, धर्म और गठबंधन पर नहीं चलेगी।

जनता रोजगार, शिक्षा, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे ठोस मुद्दों पर सोच रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान यदि जनता को यह भरोसा दिला पाए कि वे वाकई समाधान ला सकता है, तो 2025 के चुनाव में बड़ा उलटफेर संभव होगा। जबकि, प्रशांत किशोर को अभी संगठनात्मक ढांचा, उम्मीदवारों की तैयारी और जमीनी पकड़ को और मजबूत करना होगा। वहीं आरजेडी को आंतरिक कलह से उबरना होगा, और भाजपा-जदयू को अपनी साख दोबारा बनाना होगा। 2025 का बिहार चुनाव निर्णायक होगा, सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि क्या बिहार एक बार फिर विकास की मुख्यधारा में लौट सकता है। और इस बदलाव के केंद्र में हो सकता है एक नया नाम प्रशांत किशोर का हो।

मेष राशिः आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस के सिलसिले मे आप नये लोगो से मिलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सीनियर लोग आपके कार्यो की तारीफ करेंगे। आज आपके बच्चे आपको कोई गुड न्यूज दे सकते हैं, जिससे आप उनपर गर्व महसूस करेंगे। आज घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों के साथ समय बितायेंगे।

वृष राशिः आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होने के कारण आज घर पर पार्टी करेंगे। घरेलू कार्यों परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में आज आपका मन लगा रहेगा। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ कर सकते है। आपके जुनियर आपसे काम सीखना पसन्द करेंगे।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। पहले किये गए किसी सामाजिक कार्य के लिए आज आपको सम्मानित किया जायेगा। जॉब की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। परिवार वालों के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बन सकता है। आज आप कोई नया व्यापार शुरु करने का मन बनायेंगे। जिससे आपको भविष्य में अच्छा फायदा होगा।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके मन में नए–नए विचार आयेंगे। आज आप किसी नए व्यापार की योजना भी बनाएंगे। पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ बनाया हुआ ट्रीप का प्लान आज कैन्सिल हो सकता है। संगीत तथा कला में रुझान रखने वाले लोगों को आज किसी अच्छे प्लाफोर्म पर काम करने का ऑफर आएगा।

सिंह राशिः आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास कार्यक्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। आज दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। राजीनीति में सक्रीय लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लेखन कार्य कर रहे लोगों के किसी लेख की तारीफ होगी। आज आपके व्यापार में दो गुना वृद्धि होगी।

कन्या राशिः आज आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़ी हुए ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो समय रहते पूरा हो जाएगा। फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन शुभ है। जीवनसाथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी।

तुला राशिः आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के ऑर्किटेक के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कम्पनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। अगर कोई नयी गाड़ी खरीदना चाह रहें है तो आज ले लीजिए। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशिः आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। आज आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लायेंगे, इससे परिवार वाले प्रसन्न होंगे। आज इलेक्ट्रानिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज आप घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज के दिन कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगना कर देगा। कार्यक्षेत्र में बढोतरी के नये अवसर प्राप्त होंगे।

धनु राशिः आज का दिन बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। दाम्पत्य रिश्ता आज मधुरता से भरपूर रहेगा। आज आप किसी दोस्तों के साथ कोई बिज़नस शुरू करने का प्लान बना सकते हैं। लक्ष्मी के रुप में नए मेहमान के आने की खुशी में घर में पार्टी करेंगे। ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा।

मकर राशिः आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहें तो आज ट्रांसफर किसी ऐसे स्थान पर होगा, जहां से अप-एण्ड-डाउन करने में आपको आसानी होगी। जीवनसाथी से निजी समस्यायों को शेयर करने से मन का बोझ हल्का होगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी।

कुम्भ राशिः आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आज घरेलू चीजों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते है। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से काम जल्द खत्म होगा। शाम को जीवनसाथी के सहयोग से आप कोई घर का काम पूरा करने में सफल होंगे। आज किसी अनुभवी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी।

मीन राशिः आज का दिन आपके लिए उत्तम है। आज आपको व्यापार में अचानक धनलाभ का अवसर प्राप्त होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपके मन मे व्यापार को लेकर नए-नए विचार आएंगे। आज सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी, जिनसे आप बचपन की यादें शेयर करेंगे।

निठारी कांड - उन्नीस साल सिर पटकने पर भी नहीं मिला इंसाफ

मनोज कुमार अग्रवाल

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी में बच्चों की लाश मिलने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. मामला राजधानी दिल्ली से सटे हुए इलाके का था, तो नेशनल-इंटरनेशनल मीडिया पहुंचने लगी. बच्चों की लाश मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पास मिली तो पुलिस ने कोठी के मालिक सहित उसकी देखभाल करने वाले नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया. फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया. पुलिस द्वार पेश किए गए सबूतों के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी. लेकिन साल 2023 में हाईकोर्ट ने पंढेर को निठारी कांड से जुड़े सभी मामलों से बरी कर दिया. इसके बाद नौकर सुरेंद्र कोली भी धीरे-धीरे बरी होता चला गया. हालांकि अभी वो बस एक मामले में जेल में बंद है. आशंका है कि उसमें भी ये बरी हो सकता है, आपकों याद रहे कि नोएडा के निठारी गांव में जब एक के बाद एक बच्चों के कंकाल और अवशेष मिले थे, तो पूरा देश सन्न रह गया था. मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली इस सनसनीखेज नरसंहार के आरोपी थे. कोर्ट से उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी. लेकिन साल 2023 में हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को नया मोड दे दिया. मोनिंदर सिंह पंढेर को निठारी कांड से जुड़े सभी मामलों से बरी कर दिया गया. इसके बाद उसका नौकर सुरेंद्र कोली भी एक बाद एक मामलों में बरी होता गया. अब वो महज एक मामले में जेल में बंद है. जिसमें उसे जल्दी राहत मिल सकती है।अब फिर वही बड़ा सवाल है कि अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो फिर निठारी कांड का जिम्मेदार कौन है?देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां 16 मासूमों के असली कातिल को पकड़ने में नाकाम क्यों रहीं? या पकड़ ने के बावजूद अभियोजन में ऐसी विसंगतियां जानबूझकर छोड़ दी गयी जो अभियुक्तों के बचाव में सहायक बन गयी? जो भी हो न्याय की तलाश में उन्नीस साल तक अदालत की चौखट पर टकटकी लगा कर बैठे उन अभागे अभिभावकों को गहरा धक्का लगा है जिनके निर्दोष बच्चों को कत्ल कर उनके शरीर के अंग खूनी कोठी के पिछवाड़े नाले में फेंक दिए गए थे। आपकों बता दें कि निठारी में साल 2006 में जब बच्चों के शवों के टुकड़े नाले से बरामद हुए थे, तो पूरा देश सन्न रह गया था. सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर इस वीभत्स कांड के मुख्य आरोपी बनाए गए. लेकिन सालों चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. केस में कई बुनियादी खामियां रहीं – जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य की कमी, पुलिस कस्टडी में दिए इकबालिया बयानों का बिना पुष्टि कोर्ट में पेश किया जाना और अहम सबूतों की गुमशुदगी. इन सब बातों ने पूरे केस की नींव ही हिला दी. हाल ही में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष कोली और पंढेर के खिलाफ 'उचित संदेह से परे' अपराध साबित करने में विफल रहा. जांच में मिली चिप, जिस पर कोली के कबूलनामे का वीडियो था, वह पेश ही नहीं की गई. ना ही उस बयान पर कोली के दस्तखत थे. कोर्ट ने पाया कि जांच एजेंसी ने आपराधिक केस के बुनियादी नियमों की भी अनदेखी की.पुलिस की सबसे बड़ी चूक थी – फॉरेंसिक एविडेंस और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का न होना। डी-5 कोठी से ना खून के निशान मिले, ना शवों के अवशेष. सीमन के सैंपल तक कोली से मैच नहीं हुए. यहां तक कि कोली के 'आदमखोर' होने का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला. शवों को बाथरूम में रखने, काटने, गाड़ने और पकाने जैसी बातें सिर्फ पुलिस कस्टडी में दिए उसके बयानों तक ही सीमित रहीं जिनकी पुष्टि कहीं नहीं हुई. यह सवाल अब भी अब एक रहस्य बन गया है कि अगर कोली भी बरी हो जाएगा, तो वो कौन था जिसने 16 बच्चों को नृशंसता से मारा? कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस केस को एक गरीब नौकर पर जबरन मढ़ा गया. कोर्ट ने कहा कि अंगों की तस्करी के एंगल की कभी जांच ही नहीं हुई. डी-5 कोठी के मालिक की भूमिका तक की जांच नहीं की गई, जबकि वह पहले से ही किडनी स्कैम मामले में आरोपी था. क्या हत्याएं किसी और ने की और एजेंसियों ने असली कातिल को छोड़ दिया? कोर्ट ने यह भी कहा कि ना तो हत्या के लिए कोई हथियार मिला, ना कोई गवाह, ना कोई हत्या के पीछे का मकसद. यही कारण है कि पंढेर को बरी कर दिया गया और सुरेंद्र कोली को भी राहत मिल गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में पंढेर और कोली को बराबर का गुनाहगार बताया गया. पर बाद में पंढेर को धीरे-धीरे क्लीनचिट मिली गई और सारा आरोप कोली पर आ गया. कोली की कानूनी मदद नहीं की गई. मेडिकल जांच भी अधूरी रह गई और उसे लंबे समय तक पुलिस रिमांड में रखा गया। कोली के बयानों के अनुसार उसने शवों के टुकड़ों को पॉलीथिन में डालकर नाले में फेंका और कुछ को जमीन में दबाया था . लेकिन जमीन की खुदाई में कुछ नहीं मिला. न ही किसी शव की पहचान डीएनए से करवाई गई. जांच एजेंसी यह भी साबित नहीं कर पाई कि कोठी के अंदर हत्याएं हुईं. कोर्ट ने कहा – 'ना तो हत्या के लिए कोई हथियार मिला, ना कोई गवाह, ना कोई मकसद.' यही कारण है कि पंढेर को बरी कर दिया गया और अब कोली को भी राहत मिल गई है. कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कोली को अकेले दोषी ठहराने की जल्दबाजी क्यों की गई. शुरुआत में पंढेर और कोली को बराबर का गुनहगार बताया गया, पर बाद में पंढेर को धीरे-धीरे क्लीनचिट मिलती गई और सारा आरोप कोली पर आ गया. कोली की कानूनी मदद नहीं की गई, मेडिकल जांच भी अधूरी रही और उसे लंबे समय तक पुलिस रिमांड में रखा गया. क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा था? निठारी केस की जांच से जुड़ा एक और पहलू था – ऑर्गन ट्रैफिकिंग का. कोर्ट ने कहा कि इस पहलू की जांच कभी गंभीरता से नहीं की गई. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तक ने इस दिशा में जांच की मांग की थी. लेकिन सीबीआई ने डी-5 कोठी के मालिक से पूछताछ तक नहीं की. क्या ये केस सिर्फ 'बलात्कार और हत्या' की कहानी थी या इसके पीछे कोई बड़ा और संगठित गिरोह काम कर रहा था? गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में और पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा दी. लेकिन हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये सभी सजाएं खारिज कर दीं. आखिर एक ही केस में दो अदालतों की राय इतनी अलग कैसे हो सकती है? हाई कोर्ट के मुताबिक ये केस पुलिस और सीबीआई की लापरवाही का नमूना बन चुका है. जो चिप सबसे अहम सबूत थी, वही गायब कर दी गई. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर साल 2023 में रिहा हो गया था. लेकिन कोली की एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. रिंपा हलधर केस में उसे पहले फांसी और फिर उम्रकैद हुई थी. अगर उस केस में भी बरी हो गया तो वो भी बाहर आ सकता है. यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम में गड़बड़ियों की वजह से सबसे गंभीर मामले भी 'नतीजा विहीन' रह जाते हैं. अब यह सवाल देश की जांच एजेंसियों और न्यायपालिका पर कलंक लगा रहा है कि आखिर देश को हिला देने वाला निठारी कांड अब कानून की नजर में अनसुलझा कैसे बन गया . आरोपी अभियुक्त पंढेर बाहर है, कोली एक मामले में जेल में है, बाकी सभी केसों से बरी हो चुका है. लेकिन जिन 16 बच्चों के शव नाले से मिले थे, उनका गुनहगार कौन है?

जो आगे बढ़ने का जोखिम उठाते हैं, वही जान सकते हैं कि कोई कितनी दूर जा सकता है। -टीएस इलियट

बांग्लादेश की नीयत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में एक सवाल के जवाब में बेहद गंभीर व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का खुलासा किया, जो ढाका में सक्रिय एक कट्टरपंथी समूह 'सल्तनत-ए-बांग्ला' द्वारा तुर्किये के एक गैर-सरकारी संगठन के समर्थन से 'ग्रेटर बांग्लादेश' का नक्शा जारी किए जाने से संबंधित है, जिसमें भारत के भी कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथ हावी हो रहा है और अंतरिम सरकार के मुखिया के चिकन नेक और इसी तरह के दूसरे बयान सामने आते रहे हैं, उनसे बांग्लादेश की नीयत का पता चलता है। इस पृष्ठभूमि में देखें, तो ग्रेटर बांग्लादेश के विचार के पीछे एक दूरगामी भू-राजनीतिक मंशा और सांप्रदायिक उन्माद से भरी खतरनाक परियोजना के लक्षण देखे जा सकते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश का विचार दशकों पुराना है, जो कट्टरपंथी इस्लामी गुटों और बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों के बीच पनपता रहा है, लेकिन विदेशी समर्थन के साथ उसका इस रूप में सामने आना भारत की अखंडता को सीधी चुनौती है। इसे भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या से अलग करके नहीं देखा जा सकता, जिनकी आए दिन धरपकड़ हो रही है। उल्लेखनीय है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिये पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु तक पहुंच गए हैं। कुछ ही समय पहले गुजरात और दिल्ली में हुई कार्रवाई में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अभाव में यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, लेकिन विभिन्न रपटें बताती हैं कि इनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। स्थानीय स्तर पर देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन घुसपैठियों की मौजूदगी ने सामाजिक-आर्थिक संतुलन पर किस तरह असर डाला है। पश्चिम बंगाल में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव इसका एक प्रत्यक्ष नतीजा है। यही नहीं, राज्यों में अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करने की शिकायतों ने स्थानीय राजनीति को और जटिल

बना दिया है। अच्छी बात है कि सरकार घुसपैठियों से छुटकारे का हरसंभव प्रयास कर रही है। ग्रेटर बांग्लादेश का विचार मौजूदा जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियों की झलक देता है। इनसे निपटने के लिए कूटनीतिक सतर्कता और सामाजिक एकजुटता, दोनों स्तरों पर आगे बढ़ना होगा। यह केवल एक सीमाई मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और पहचान के खिलाफ वैचारिक चुनौती भी है, जिसे हम एकजुट होकर ही जीत सकते हैं।

अतीत की परछाइयों से बाहर निकलता भारत

दुनिया बदल रही है। ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार से दुनिया सकते में है। वैश्विक संबंधों की सुनामी में भारत ने अपने आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखते और हितों की रक्षा करते हुए अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित किया है। यह अतीत की गलतियों और बंधनों से मुक्ति का नव दृष्टिकोण है।

क्या भारत की आंतरिक-बाह्य नीतियां विदेश से प्रभावित हैं? लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में 'ऑपरेशन सिंदूर' को स्थगित किया। इस संदर्भ में राहुल का व्यवहार कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि वह अपने विदेश दौरों में अक्सर अमेरिका-यूरोप से भारत में 'लोकतंत्र बचाने' की गुहार लगाते हैं? राहुल की ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पाकिस्तान जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की भी मांग कर चुके हैं। जब राहुल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहें, तो मुझे आश्चर्य होता है। वैश्विक राजनीति कोई किशोरावस्था की तकरार नहीं, जिसमें व्यक्ति क्षणिक आवेश में अपमानजनक या कटु शब्दों का प्रयोग करता हो। इस तरह के गैर-जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा केवल राहुल गांधी से ही की जा सकती है, जिन्होंने वर्ष 2013 में सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के एक अध्यादेश को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी।

बलबीर पुंज
पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

वास्तव में, ट्रंप के टैरिफ प्रहार और लंबित व्यापार समझौते पर भारत ने जो निर्भीक रुख अपनाया है, वह राहुल के दावे को पूरी तरह झुठलाता है। जैसे अमेरिका अपने हितों के अनुसार मित्र और शत्रु चुनने हेतु स्वतंत्र है, उसी प्रकार भारत को भी अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। शीतयुद्ध काल से रूस (तब सोवियत संघ) भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। इस ऐतिहासिक संबंध को किस दिशा में और कितनी गहराई तक ले जाना है, यह केवल भारत तय करेगा, कोई अन्य देश नहीं। भारत के इस आत्मविश्वासपूर्ण और स्वायत्त दृष्टिकोण से शेष विश्व, विशेषकर अमेरिका और यूरोप स्तब्ध हैं। दशकों तक भारत की विदेश नीति बाह्य-वैचारिक प्रभाव से संचालित होती रही, जिसके कारण भारत को बार-बार उन देशों के सामने झुकना पड़ा, जो हमारे दूरगामी हितों के विपरीत खड़े थे। वर्षों तक भारत ने फलस्तीन और इस्लामी देशों का समर्थन किया, जबकि वे कश्मीर के मुद्दे पर मजहबी कारणों से पाकिस्तान का साथ देते रहे। जब

पाकिस्तान या चीन से भारत का टकराव हुआ, तब भारतीय नेतृत्व अमेरिका-यूरोप से मध्यस्थता की याचना करता दिखा, जिसमें कई बार स्थिति गिड़गिड़ाने तक पहुंच गई थी। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखकर पाकिस्तानी आक्रमण रोकने हेतु संपर्क साधा था। 5 दिसंबर, 1971 को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, 'इस संकट की घड़ी में भारत सरकार और भारत की जनता आपकी सहानुभूति की आकांक्षी है...आपसे आग्रह है कि आप पाकिस्तान को अकारण आक्रामकता एवं सैन्य दुस्साहस की नीति से तत्काल विरत होने के लिए प्रेरित करें...मैं महामहिम से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने निर्विवाद प्रभाव का उपयोग करें...।'

इंदिराजी का यह रुख उनके पिता पं. नेहरू की परंपरा से ही प्रेरित था। 1962 में भारत को न केवल चीन से अपमानजनक पराजय झेलनी पड़ी, बल्कि हम हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि से भी हाथ धो बैठे। यह सब नेहरूजी की मार्क्स-मैकॉले चिंतन से निकटता और चीन की साम्राज्यवादी मंशा की उपेक्षा का परिणाम था। पंचशील, सुरक्षा परिषद की सदस्यता चीन को सौंपना और 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' जैसे नारे भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। उस पर अमेरिका के समक्ष पं. नेहरू की बारंबार मिन्नतों ने भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान को और भी आहत किया।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी ब्रूस रीडेल ने अपनी पुस्तक *जेएफके फॉरगॉटन क्राइसिसः तिब्बत, द सीआईए एंड द सीनो-इंडियन वार* में भारत-चीन युद्ध के समय पं. नेहरू द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी को लिखे गुप्त पत्रों के अंश सार्वजनिक किए हैं। 11–19 नवंबर के बीच हुए पत्राचार में पं. नेहरू ने कहा था, 'यह संकट केवल भारत का नहीं, समूचे उपमहाद्वीप और एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अस्तित्व का प्रश्न है।' उन्होंने तत्काल हवाई मदद मांगते हुए लिखा– 'हमें कम से कम 12 स्क्वाड्रन सुपरसोनिक सर्व-मौसमी लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता है। देश में आधुनिक राडार व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है। जब तक हमारे सैनिकों को इस हेतु प्रशिक्षण नहीं मिल जाता, तब तक इन विमानों एवं राडार प्रतिष्ठानों का संचालन अमेरिका की वायुसेना के कर्मियों को करना होगा।' तब पं. नेहरू यह आश्वासन भी देते दिखे कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों का उपयोग पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं, केवल 'चीन के विरुद्ध प्रतिरोध हेतु' किया जाएगा। इन पत्रों की भाषा से स्पष्ट होता है कि पं. नेहरू ने अमेरिका के समक्ष भारत का स्वाभिमान गिरवी रख दिया था।

वर्ष 1965 के युद्ध में जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, तब भारतीय नेतृत्व ने जो कुछ जीता था, उसे अगले वर्ष ताशकंद जाकर सोवियत संघ (रूस) की मध्यस्थता से लौटा दिया। इसका रणनीतिक औचित्य आज तक स्पष्ट नहीं है। क्या इससे पाकिस्तान सुधरा? क्या उसने भारत के प्रति शत्रुभाव छोड़ दिया? ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी की रहस्यमयी मौत ने इस समझौते को और भी विवादास्पद बना दिया। ऐसे ही 1960 में पं. नेहरू ने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर पाकिस्तान के साथ अव्यावहारिक 'सिंधु जल समझौता' किया था।

इसी तरह अमेरिकी दबाव में वर्ष 1995 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने पोखरण परमाणु परीक्षण टाल दिया था। परंतु 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयीजी ने अमेरिकी-यूरोपीय प्रतिबंधों की धमकियों को दरकिनार करते हुए सफलतापूर्वक पोखरण परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत से लड़ाई रोकने को कहा था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि तब अटलजी ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना के कारगिल से निकलते ही युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा। अर्थात-जब तक पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर है, युद्ध जारी रहेगा।

विश्व बदल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार से दुनिया सकते में है। वैश्विक संबंधों की सुनामी में भारत ने अपने आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखते और हितों की रक्षा करते हुए अपनी भूमिका को पुनःपरिभाषित किया है। यह अतीत की गलतियों और बंधनों से मुक्ति का एक सुखद और प्रशंसनीय नव दृष्टिकोण है।

आर्थिकी

कहीं यह ट्रंप की चाल तो नहीं

ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ ने भारतीय व्यापार गलियारों में हलचल मचा दी है। संभव है कि अमेरिका ने बेहतर शर्तें सुनिश्चित करने के लिए यह दबाव बनाया हो।

ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा और रूस से तेल आयात पर द्वितीयक प्रतिबंध के खतरे से भारतीय वित्तीय बाजारों और व्यापार गलियारों में हलचल है। हो सकता है कि अमेरिका ने व्यापार समझौते में बेहतर शर्तें सुनिश्चित करने के लिए यह दबाव बनाया हो, लेकिन भारत पर इसका तत्काल प्रभाव तो पड़ेगा ही। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को 87 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, और लगभग 45 अरब डॉलर का आयात किया, जिससे भारत के पक्ष में 42 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष हुआ, जिस पर अब सीधा खतरा है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन, वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़े के सामान और जूते, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन और समुद्री खाद्य अमेरिका को निर्यात करता है। सामूहिक रूप से ये क्षेत्र अमेरिका को भारत के सालाना 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात करते हैं। 25 फीसदी टैरिफ न केवल उन्हें गैर-प्रतिस्पर्धी बना देगा, बल्कि निर्माताओं को घाटा सहने, बाजार से बाहर निकलने, या अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि ये टैरिफ ट्रंप की 'व्यापार कला' रणनीति का हिस्सा हैं। यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुए समझौते इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हालांकि, भारत की स्थिति संरचनात्मक रूप से थोड़ी अलग है। अमेरिका के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता अभी हुआ नहीं है। भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने के अमेरिकी दबाव का लगातार विरोध किया है।

अजय बग्गा
बाजार एवं आर्थिक मामलों के जानकार

यदि अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राजकोषीय घाटे को दोहरा झटका लगेगा। इससे निवेशकों की भावनाओं से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक प्रभावित होगी। टैरिफ घोषणा से भारतीय शेयर बाजारों में पहले ही गिरावट देखी जा चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आई है, और बढ़ते चालू खाता घाटे (सीएडी) की चिंताओं के कारण बॉन्ड यील्ड में भी दबाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर भारतीय निर्यातक अमेरिकी बाजार से निकलने को मजबूर होते हैं, तो नए विकल्पों की ओर रुख करने में काफी समय और निवेश लगेगा। निर्यात पर निर्भर उद्योगों में, खासकर कपड़ा, चमड़ा और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में नौकरियों पर संकट बढ़ रहा है। इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सरकार को टैरिफ के बाहरी झटके और कुछ बाजारों व क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरियों, दोनों का समाधान करना होगा। सरकार को विनिर्माण, कृषि-निर्यात, ई-कॉमर्स और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनियमन करना होगा। प्रमुख उपभोग और निर्यात श्रेणियों के लिए जीएसटी स्लैब कम करने से मांग बढ़ सकती है। रणनीतिक वित्तीय समर्थन, जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट, निर्यात प्रतिस्थापन पर केंद्रित पीएलआई और मुक्त भंडारण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रभावित निर्यात क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहन जरूरी है-चाहे वह ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी योजनाओं, या प्रभावित उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष वेतन सहायता के जरिये हो। वैकल्पिक बाजार पहुंच के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया व्यापार कूटनीति इकाई स्थापित की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक को पूंजी बहिर्वाह का प्रबंधन करने, मुद्रा संबंधी घबराहट से बचने और रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए।

एआई एक सुपरहीरो की तरह हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। -पैलो हमावद्दा

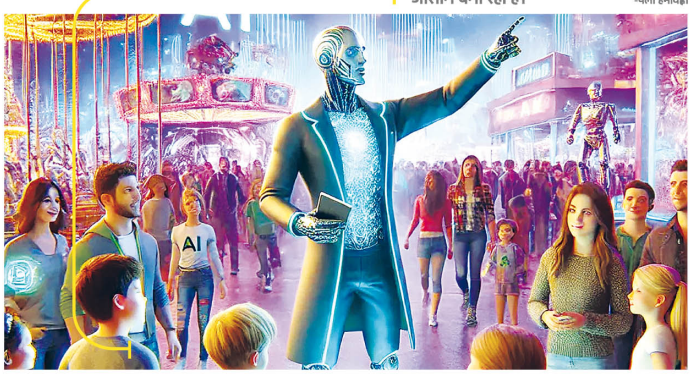

जोखिम लेना जरूरी है

जोखिम अक्सर फलदायी होते हैं। इन्हीं से आप सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। यही हमें बताएगा कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए।

जीवन गलती करने और उसे सुधारने की प्रक्रिया है। स्थिति बहुत खराब होती है, तब कुछ ऐसा होता है, जिससे सही रास्ता मिल जाता है। यदि हम गलती सुधारने के लिए निरंतर और थोड़ा बेहतर प्रयास करें, तो हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने 'पोलियो वैक्सीन' पर काम शुरू किया, तो हर प्रयोग इस तरह किया, जैसे मैं उस वायरस के भीतर हूं, उसकी प्रकृति को समझ रहा हूं।

जोनास साल्क

हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। यह हमें बताएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने अच्छे और बुरे, दोनों तरह के सपने देखे। मेरे सपनों ने मुझे डर पर विजय पाने की शक्ति दी। सपने वे हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, और तर्क हमें बताता है कि उस रास्ते पर कैसे चलना है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखें। आशा सपनों में, कल्पना में और उन लोगों के साहस में बसती है, जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करते हैं।

मैंने बच्चों को वैक्सीन दी और कई रात तक सोया नहीं, क्योंकि मैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित था। लेकिन यह जोखिम लेना जरूरी था। जोखिम अक्सर फलदायी होते हैं। आप सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे पूर्वज बनें। हमें यह सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। यदि हम प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो हम स्वयं को नष्ट कर लेंगे। मैंने हमेशा माना कि विकास बुद्धिमत्ता का पक्ष लेता है। हमें अपने ज्ञान के साथ बुद्धिमत्ता को संतुलित करना होगा। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या हमारे पास उसे संभालने की समझ है? बुद्धि और सही समझ के साथ मनुष्य एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।

जीवन धारा

जरूरी है कि हम बदलती परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने की आवश्यकता को स्वीकार करें। जीवन जादुई है। प्रकृति का काम करने का तरीका जादू की तरह है। हम सभी एक बड़े विकास का हिस्सा हैं, और हमारी चेतना, हमारी कल्पना, हमें भविष्य को आकार देने की शक्ति देती है। हम एक-दूसरे के साथ मिलकर जीना सीखें। हम अपने सपनों, अंतर्ज्ञान और मानवता के प्रति जिम्मेदारी को अपनाएं। जानिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है जिसे पूरा करने के लिए आप इच्छुक हैं। जीवन में साहस, सहयोग व ज्ञान के साथ हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है।

ज्योतिषी से पूछा, क्या एआई मेरी नौकरी खा लेगा

द गार्जियन की स्तंभकार एमी हॉकिंस ने जब एक ज्योतिषी से पूछा कि क्या एआई उनकी नौकरी छीन लेगा, तो उसका जवाब था कि फिलहाल तो नहीं। लेकिन, तीन साल बाद क्या होगा, कहना मुश्किल है।

स्व-सहायता, स्व-विकास और आत्म-मुग्धता के दौर में मार्गदर्शन करने वाले इतने केंद्र पहले कभी नहीं थे। जहां कभी चिंतित और अनिश्चित लोग जवाबों के लिए सर्च इंजन का सहारा लेते थे, वहीं अब हम अपनी समस्याओं को लेकर चैटजीपीटी से सार्थक चर्चा कर सकते हैं। यदि आप चीन में हैं, तो डीपसीक है। इसके बावजूद चीन के लोग एक अलग ही प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। दरअसल, बड़ी संख्या में चीनी युवाओं ने अपना भविष्य जानने के लिए पारंपरिक ज्योतिषियों की शरण में जाना शुरू किया है।

पिछले कुछ वर्षों में चीन के शहरों में भविष्य बताने वाले बार खुल गए हैं, जहां जुआनक्सुए (चीन की ज्योतिष कला) और अध्यात्म ज्ञान के साथ खाने-पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। दरअसल, चीनी युवाओं में दिख रहे इस बदलाव की वजह है। चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है और चूंकि बाहर जाकर खाना-पीना और किसी काउंसलर के पास जाकर परामर्श करना महंगा पड़ता है, इसलिए चीनी युवा भविष्य बताने वाले बारों का रुख कर रहे हैं। रहस्यवाद की गहरी जड़ों वाली संस्कृति, जिसमें ताओवाद, बौद्ध और लोक प्रथाओं का मिश्रण समाहित है, ऐसा होना स्वाभाविक ही है। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी इन परामर्श केंद्रों में जाकर देखूं। उसी दिन शाम को मैं पीले ताओवादी ताबीजों और पारदर्शी पर्दों से सजे एक बार में शामिल हुई। वहां के नियम सख्त थे। एक ड्रिंक लेने पर एक सवाल ही पूछा जा सकता था। तो मैं पहुंची छत्तीस साल की वान मो के पास, जो क्यूकियान या स्टिक के सहारे भविष्य बताने में माहिर हैं।

इस विधा में अपने मन में उठने वाले सवाल पर ध्यान केंद्रित कर लकड़ी की छड़ियों (स्टिक) से भरे लकड़ी के ही गोलाकार कंटेनर को हिलाना होता है। आखिरकार टेक्स्ट और अंकों से युक्त एक स्टिक गिर जाती है, उसके आधार पर भविष्यवक्ता उसकी व्याख्या कर उत्तर देता है। मुझे उम्मीद है कि क्यूकियान से मेरे पहले सवाल का बेहतर जवाब मिलेगा : क्या एआई मेरी नौकरी छीन लेगा? वान मो ने जोर देकर कहा, 'दोनों हाथों का इस्तेमाल करो और अपने सवाल पर ध्यान लगाओ।' वह मुझसे कहती हैं, 'एक विदेशी होने के नाते स्टिक में आपका लगाव शायद चीनी व्यक्ति जितना गहरा न हो। इसलिए आपको ज्यादा ध्यान से सोचने की जरूरत है।' कुछ सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने और जोर से हिलाने के बाद एक नहीं, बल्कि दो स्टिक हमारे बीच की मेज पर गिरीं।

वान मो ने पहली स्टिक को देखकर कहा, 'आगे चलकर एआई का आपके काम पर असर तो पड़ेगा, भले ही आप कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, लेकिन आप इसका मुकाबला नहीं कर सकतीं। मान लीजिए, यदि आप एक लेख लिखती हैं, तो एआई उतने ही समय में सौ लिख सकता है। आप इसके मुकाबले में हैं ही नहीं।' यह उस तरह का आध्यात्मिक समाधान नहीं है, जिसकी मैंने उम्मीद की थी। दूसरी स्टिक देखकर वान मो मुझे बताती हैं, 'फिलहाल, तीन वर्ष तक आप पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एआई बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा।'

वान मो की भविष्यवाणी के बाद मैं इस स्थिति में नहीं थी कि दूसरा सवाल पूछूं, फिर भी मैंने तय किया कि एक सवाल और पूछूंगी। मैं सोच रही थी कि क्या वान मो को पता है कि एआई उसकी भी नौकरी ले लेगा-या उसने बस इससे समझौता कर लिया है। आखिरकार मैंने अपना दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत जुटा ली। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, 'क्या मेरा वेतन बढ़ेगा।' इसका जवाब तत्काल मिला। 'फिलहाल, ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि, स्टिक बदलाव को लेकर है। कुछ उम्मीद है, लेकिन तत्काल नहीं।

रैग एआई

रैग या आरएजी (रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जेनरेशन) एक ऐसी तकनीक है, जो एलएलएम को किसी सवाल का जवाब देने से पहले बाहरी ज्ञान भंडार से प्रासंगिक जानकारी खोजने व उसके उपयोग में सक्षम बनाती है। यह एलएलएम को उसके अपने प्रशिक्षण डाटा से परे, अप-टू-डेट और विशिष्ट जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है। रिट्रीवल के अंतर्गत उपयोगकर्ता के सवाल पर एआई सिस्टम बाहरी ज्ञान भंडार से जानकारी जुटाता है। ऑगमेंटेशन मतलब खोजी गई प्रासंगिक जानकारी को उपयोगकर्ता के मूल प्रश्न के साथ मिलाकर एक नया संवर्धित (ऑगमेंटेड) प्रॉम्प्ट बनाया जाता है। जेनरेशन यानी नए प्रॉम्प्ट को एलएलएम में भेजा जाता है। एलएलएम इस संवर्धित संदर्भ का उपयोग करके सटीक और विश्वसनीय प्रतिक्रिया देता है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 69 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

खेलों में मेंटल हेल्थ पर नीतियां समय की जरूरत

खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा है। हाल में ब्रिटेन की 20 वर्षीय तैराक और पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आंद्रिया ने मेंटल हेल्थ के कारण खेल से ब्रेक लिया। यह निर्णय न केवल साहसिक है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मेंटल हेल्थ के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी दर्शाता है। मगर, भारत और दक्षिण एशिया में मेंटल हेल्थ अब भी एक उपेक्षित मुद्दा है।

मेंटल हेल्थ के कारण खेल से संन्यास लेने के उदाहरण विश्वभर में देखे जा सकते हैं। अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में मानसिक दबाव के चलते कुछ स्पर्धाओं से हटने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई तैराक इयान थोर्प ने 2006 में डिप्रेशन के कारण संन्यास लिया, हालांकि बाद में वापसी की। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने 2021 में फ्रेंच ओपन के दौरान मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक लिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि विकसित देशों में मेंटल हेल्थ को गंभीरता से लिया जाता है। वैश्विक स्तर पर मेंटल हेल्थ पर खर्च में भारी अंतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अमरीका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट का लगभग 10-12% (लगभग 1,200-1,500 डॉलर प्रतिवर्ष) मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च होता है। यूरोप में यह आंकड़ा 8-10% (लगभग 800-1,000 यूरो) और ब्रिटेन में 9% (लगभग 700 पाउंड) है। जापान में 6-7% (लगभग 70,000 येन) और चीन में केवल 2-3% (लगभग 200-300 युआन) खर्च होता है, जो उनकी आय का अपेक्षाकृत कम हिस्सा है। दक्षिण एशिया में स्थिति चिंताजनक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, श्रीलंका इस क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करता है (स्वास्थ्य बजट का 4%, लगभग 10 डॉलर प्रति व्यक्ति), जबकि पाकिस्तान सबसे कम (0.5%, लगभग 1 डॉलर)। भारत का खर्च 1% से कम (लगभग 2 डॉलर प्रति व्यक्ति) है, जो वैश्विक औसत से काफी नीचे है। खिलाड़ियों के लिए भारत में मेंटल हेल्थ जांच या रिटायरमेंट की आयु सीमा का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। सेना और अन्य क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए उम्र-आधारित रिटायरमेंट नीतियां हैं लेकिन, खेलों में ऐसी नीति का अभाव है। विकसित देशों जैसे अमरीका और ब्रिटेन में खिलाड़ियों के लिए नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श और मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में खेलों के लिए समग्र दृष्टिकोण की बात है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर विशेष जोर नहीं है।

भारत को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए नीतियां बनाने की जरूरत है। स्कूलों से लेकर पेशेवर खेल तक, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श को अनिवार्य करना होगा। दक्षिण एशिया में श्रीलंका का मॉडल, जहां कम संसाधनों में भी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, भारत के लिए प्रेरणा हो सकता है। खिलाड़ियों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता देकर ही भारत वैश्विक खेल मंच पर सही मायनों में चमक सकता है।

पुरुष हृदय में पत्नी का ब्रह्मांश भी रहता है और स्वयं का भी। दोनों का प्रारब्ध साथ हो जाता है, कन्यादान के बाद। देह दोनों की प्रकृति रूप पृथक्-पृथक् है। प्रारब्ध कर्मों की कामना हृदयस्थ मन में उठती है।

दाम्पत्य भाव का कर्म विधान

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

स्त्री नई सन्तान पैदा नहीं कर सकती। पुरुष ही बीजी है। स्त्री का बीजात्मा पुरुष बीज में ही आहुत रहता है। स्त्री-पुरुष दोनों की कर्म समष्टि ही दाम्पत्य पुरुषार्थ का स्वरूप बनता है। स्त्री के स्वयं के पुरुषार्थ कर्म अलग नहीं होते, न मोक्ष ही अलग होता।

जीवन में सब कुछ अस्थायी होते हुए भी स्थायी प्रतीत होता है। एक फिल्मी गीत है–न कोई था, न कोई है... जीवन का सबसे बड़ा सच यही है। हम मिट्टी के मकान हैं, जैसे बरसात में बच्चे बनाते हैं- ढहा देते हैं। माया हमें बनाती रहती है, ढहाती रहती है। जो मायी है वह नए मकान में आकर रहता है, मकान ढहते ही विदा हो जाता है। मकान बदल लेता है। पुराना मकान भी पुनः मिट्टी हो जाता है। हम नए मकान को समझे बिना ही इसमें रहकर चले जाते हैं। क्या-क्या विशेषताएं हैं इस मकान की, क्या-क्या संभावित कर्म किए जा सकते हैं, कैसे इसे व्यवस्थित रख सकते हैं, मौसम के थपेड़ों से बचा सकते हैं। न इसके बनने का पता होता है, न ही गिरने की चेतना।

शास्त्र कहते हैं–**'ब्रह्म सत्यं, जगन्नमिथ्या'**- जो आज है, कल नहीं रहेगा। जगत के सभी प्राणी इस श्रेणी में ही आते हैं। कैसे? ब्रह्म शब्द का अर्थ ही बृंहण है–निरन्तर बढ़ने वाला, फैलने वाला। उसका स्वयं का संकल्प भी है–**एकोऽहं बहुस्याम्**। यदि सब बढ़ते ही गए तो इस त्रिलोकी में रहने को स्थान ही नहीं बचेगा। अतः प्राणी की उपयोगिता के अनुरूप उसकी आयु भी तय है। संतुलन बना रहता है। रक्षा करने वाले देवता 33 हैं और उजाड़ने वाले असुर 99 हैं, जिन्हें हम चारों ओर देख सकते हैं। यही स्थूल जगत का देवासुर संग्राम है।

निर्माण और ध्वंस दोनों एक ही बिन्दु पर स्थित हैं। बच्चे दोनों में समान रूप से आनन्द लेते हैं। यह समत्व ही योग है, ब्राह्मी स्थिति है। शाश्वत और नश्वर दोनों तत्त्व साथ हैं। अपरिवर्तनीय अमृत तत्त्व एवं परिवर्तनीय मृत्यु तत्त्व दोनों आत्मा (अहं) के दो विवर्त हैं। दोनों में अन्तरान्तरी भाव है। अतः अद्वैत भाव है–**एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।** ब्रह्म और माया को ही रस और बल (मायाबल) कहते हैं। माया का यह शब्द-तन्मात्रा रूप ससीम गुण भूतों का सृजन करता हुआ असीम को अपने मापदण्ड से सीमित कर देता हैं। यही मायाबल है। परात्पर में अपने सहज धर्म से सीमा को बनाने वाले मायाबल का उदय होता है। असीम परात्पर में भी बल तो था ही क्योंकि रस और बल अविनाभूत तत्त्व हैं। सदैव साथ रहते हैं। यहां एक केन्द्र बल का अभाव था। बलों का ग्रन्थिबन्धन संभव नहीं था। अतः सृष्टि कर्म संभव नहीं था। केन्द्र बन जाने पर बलों की ग्रन्थिबन्धन प्रवृत्ति के कारण सृष्टि भाव बन जाता है। माया बल भी उदित होने से पूर्व अव्यक्त था। व्यक्त होते ही उसने असीम परात्पर को सीमित कर दिया। सीमाभाव में आया हुआ परात्पर ही अव्यय कहलाता है। अर्थात् माया बल ही ब्रह्म की साक्षी में स्वग्रन्थि बन्धनों के द्वारा विश्व रूप बन जाता है। इस साक्षी मात्रानुबन्ध से भले ही कह दें कि माया ने सीमित कर दिया किन्तु सहज रूप से अद्वैत भाव अक्षुण्ण है इस सूक्ष्म विवेक से।

ब्रह्म सीमित नहीं हो सकता। सृष्टि का प्रथम सत्य पुरुष अव्यय है। अव्यय की दो प्रकृतियां परा और अपरा ही सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होती हैं। सृष्टि में उसका साक्षी भाव रहता है। गीता में अव्यय कृष्ण अपनी परा और अपरा प्रकृतियों को बताते हुए कहते हैं कि –

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ (गीता 7/4)
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ (गीता 7/5)

-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब मेरी अपरा प्रकृति हैं किन्तु हे महाबाहु अर्जुन! इनसे अतिरिक्त मेरी परा शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं (जीवन रूप) सम्मिलित हैं जो इस संसार के जीवन का आधार हैं।

रस-बल ही स्थूल सृष्टि में वृषा-योषा हैं। 84 लाख योनियों में क्योंकि यहीं एकमात्र कर्मयोनि है तथा प्रजापति की प्रतिकृति है–**पुरुषो वै प्रजापतिर्नेदिष्ठम्** (शत. 2/5/1/1)। मानव रूप पुरुष और स्त्री को समझने की आवश्यकता है। पुरुष ब्रह्म का प्रतिनिधि तत्त्व है, स्त्री माया का प्रतिनिधितत्त्व है। ब्रह्म की सृष्टि अमृत भाव की है, पुरुष सृष्टि है-अव्यय पुरुष की है। दूसरी सृष्टि ब्रह्म सत्य रूप की है। माया के कारण परात्पर ब्रह्म के अमृत-ब्रह्म-शुक्र तीन स्वरूप बन जाते हैं। ये क्रमशः हमारे कारण-सूक्ष्म-स्थूल शरीर रूप में कार्य करते हैं।

कारण शरीर अव्यय पुरुष की संस्था है, आलम्बन है। यहां किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। यह गीता कृष्ण की प्रतिष्ठा है। इसमें संचित कर्म होते हैं। प्रारब्ध सूक्ष्म शरीर में निमित्त कारण है। सूक्ष्म देह में जीवात्मा का हृदय है, श्वोवसीयस मन है। पुरुष हृदय में पत्नी का ब्रह्मांश भी रहता है और स्वयं का भी। दोनों का प्रारब्ध साथ हो जाता है, कन्यादान के बाद। देह दोनों की प्रकृति रूप पृथक्-पृथक् है। प्रारब्ध कर्मों की कामना हृदयस्थ मन में उठती है। प्राणमय कोष के माध्यम से सर्वेन्द्रिय मन में पहुंच जाती है। शरीर को क्रियामय कर्म करने की प्रेरणा होती है। यह कामना अपरिवर्तनीय है एवं इस कामना का फल भी पूर्व निर्धारित ही होता है। कामना यदि पुरुष मन में है, तो कर्म भी पुरुष शरीर ही करेगा। कामना यदि स्त्री मन की है तो कर्म भी स्त्री देह के माध्यम से ही होगा।

इसी प्रकार पुरुष के निजी कर्म पुरुष देह से होते हैं, स्त्री के निजी कर्म स्त्री देह से। इनकी कामना भी सर्वेन्द्रिय मन में ही, इन्द्रियों के माध्यम से होती हैं। ये जीव की नई कामनाएं होती हैं। इनके अपने नए फल संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। कुछ और भी कर्म होते हैं जो नित्य, नियोजित, स्वाभाव-जनित अथवा वातावरण के प्रभाव से अचानक किए जाते हैं। इनमें स्थूल कर्म निजी ही रहते हैं, किन्तु सूक्ष्म प्राणात्मक-भावनात्मक कर्म तो हृदयस्थ जीवभाव को प्रभावित करते हैं।

कर्म तत्कालीन भी होते हैं और पुरुषार्थ कर्म के रूप में, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप तथा शुद्ध भक्तियोग से प्रेरित भी होते हैं। स्त्री के सूक्ष्म-भावनात्मक कर्म पुरुष हृदय में पुरुष जीवात्मा में आहुत हो जाते हैं। कन्यादान के दौरान लड़की का पिता लड़की के ब्रह्म अंश को भी लड़के (दूल्हे) के अंश के साथ प्रतिष्ठित कर देता है। स्त्री नई सन्तान पैदा नहीं कर सकती। पुरुष ही बीजी है। स्त्री का बीजात्मा पुरुष बीज में ही आहुत रहता है। स्त्री-पुरुष दोनों की कर्म समष्टि ही दाम्पत्य पुरुषार्थ का स्वरूप बनता है। स्त्री के स्वयं के पुरुषार्थ कर्म अलग नहीं होते, न मोक्ष ही अलग होता।

प्रकृत में स्त्री सौम्या है, पुरुष में आहुत रहती है। व्यवहार में स्त्री संकल्पवान-आग्नेय तत्त्व है। पुरुष का भोग करती है। सूक्ष्म शरीर में दोनों युग्म रूप हैं। पुरुष हृदय में अव्यय पुरुष केन्द्रित है, जो कि सूक्ष्म रूप में परा प्रकृति अथवा अक्षर प्रकृति से एकाकार रहता है। दोनों के सूक्ष्म कर्म संयुक्त ही नजर आते हैं। स्त्री के सभी पूजा-अनुष्ठान-प्रार्थनाएं पुरुष की लम्बी आयु के लिए होते हैं। सांसारिक दृष्टि से सुहागन स्त्री का अपना महत्व है। पति की मृत्यु का अर्थ वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ और होता है।

मृत्यु काल में स्त्री का ब्रह्मांश भी पति के जीवात्मा के साथ विदा हो जाता है। विधवा स्त्री का आग्नेय आधार खो जाता है। वह एक प्राणी शरीर मात्र रह जाती है। शरीर ही उसके जीने का आधार रह जाता है। उसका रक्षक भी नहीं रहता। पराधीन अवस्था किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं होती। तपस्वी स्त्रियां देहातीत होकर जी सकती हैं। जीते जी शरीर छोड़ देती हैं। **क्रमशः**

gulabkothari@epatrika.com

बुक इनसाइट

द रोज ऑफ तिब्बत

लायनल डेविडसन की किताब 'द रोज ऑफ तिब्बत' एक अद्भुत रोमांचक उपन्यास है, जो पाठकों को हिमालय की बर्फीली चोटियों और तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों में ले जाता है। यह कहानी एक ब्रिटिश स्कूल टीचर चार्ल्स ह्यूस्टन की है, जो अपने लापता भाई की तलाश में तिब्बत की यात्रा करता है। यह यात्रा केवल एक भाई की खोज नहीं, बल्कि साहस, आत्म-बलिदान व आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी चुनौतीपूर्ण दास्तान बन जाती है। कहानी में रोमांच, युद्ध, प्रेम, रहस्य और ऐतिहासिक संदर्भों का अद्भुत मिश्रण है। लेखक ने तिब्बत की संस्कृति, परंपरा और राजनीतिक हालातों को इतनी गहराई और सजीवता से उकेरा है कि पाठक खुद को वहीं महसूस करता है। चार्ल्स की इस खोजी यात्रा में उसे कई बार मौत से सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका जज्बा और भाई के प्रति प्रेम उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। लेखक की भाषा सरल होते हुए भी बेहद प्रभावशाली है।

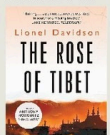

आर्ट एंड कल्चर

लोक नाट्य: समृद्ध भारत की पहचान

भारत में व्याप्त आंचलिकता ही उसकी विशिष्टता है। प्रत्येक अंचल की अपनी विशिष्ट संस्कृति है और विविध कला रूप हैं। आश्चर्यजनक यह है कि एक ही कथानक विभिन्न अंचलों के कलारूपों, विशेषकर लोक नाट्य में अलग-अलग तरह से हमारे सामने आता है। इसी के समानांतर लोक में कथागायन की अनूठी परंपरा भी विद्यमान रही है। लोक नाट्य में गायन, नृत्य और संगीत का भरपूर उपयोग होता है और इसे संवाद और अभिनय के माध्यम से पूर्णता प्रदान की जाती है। यह महज मनोरंजनभर नहीं है, बल्कि इससे संपूर्ण भावनात्मक अनुभव सामने आता है।

लोक नाट्य एक तरह से आंचलिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है और यह लोगों के मानस को पुष्ट करते हुए मानवीय मूल्यों के प्रति रुचि पैदा करता है। भारत के प्रत्येक राज्य के अपने विशिष्ट लोक कथागायन और लोक नाट्य हैं। यदि कथागायन को लें तो मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का आल्हा-ऊदल, राजस्थान की पाबूजी की फड़, महाराष्ट्र और गुजरात की हरिकथा, उत्तरप्रदेश व पंजाब में राम एवं कृष्णकथा, ओडिशा में दसकथा, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में बर्राकथा प्रमुख हैं। वहीं, जब हम लोक नाट्य की बात करें तो हमारे सामने एक बेहद विविधता भरी तस्वीर उभरती है। लोक नाट्यों की सूची पर निगाह डालें तो राजस्थान का ख्याल, ढारा ढारु के खेल, मध्यप्रदेश में माच, तेजाजी की कथा, कलगी तुर्रा और ख्याल, चतुर्भाणी, केरल का कुड़ीअट्टम, कर्नाटक का यक्षगान, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में प्रचलित भागवत कथा (इसका शास्त्रीय स्वरूप कुचिपुड़ी हो गया है।) बंगाल और ओडिशा में प्रचलित मयूरभंज और पुरुलिया छाऊ, असम के अंकीय नाट और भाओना का और वहीं रामायण, रासलीला, रामलीला और कृष्णलीला पर आधारित नाट्य भारत के अधिकांश प्रदेशों के अलावा समीपवर्ती, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा पूर्वी एशिया के थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस और कंबोडिया में भी प्रचलन में हैं। वहीं ओडिशा और बंगाल में जत्रा अब भी पूरे जोर शोर से विद्यमान है। गुजरात का भवई, महाराष्ट्र का तमाशा, छतीसगढ़ का नाचा, जम्मू कश्मीर का भांड पथैर, हिमाचल के करियाला भगत और हिरण और उत्तरप्रदेश के स्वांग, ख्याल और नौंटकी जैसे सुंदर लोक नाट्य अब भी अस्तित्व में हैं। इनमें से अधिकांश पौराणिक गाथाओं पर आधारित हैं, लेकिन कई लोक नाट्यों जैसे माच, तमाशा, ख्याल, नौटंकी, स्वांग और नाचा में समसामयिक विषयों के साथ ही साथ मनोरंजन के नए स्वरूपों और नए विषयों का समावेश हो रहा है। एक तरह से ये समकालीन विषयों को भी अपनी विषयवस्तु बना रहे हैं।

भारतीय इतिहास में वर्ष 1100 से 1900 तक का काल काफी उथल-पुथल भरा रहा है। इस दौरान बहुत से सभ्यतामूलक परिवर्तन भी सामने आए। इसी कालखंड में वर्तमान में प्रचलित अधिकांश लोक नाट्य भी प्रचलन में आए। इन लोक नाट्यों ने भारतीय संस्कृति में प्रविष्ट हो रहे बाहरी या विदेशी तत्त्वों/विचारों का बेहद चतुराई से सफलतापूर्वक विरोध किया और न केवल अपना अस्तित्व बनाए रखा, बल्कि भारतीय संस्कृति की लोकधारा का प्रवाह भी सतत बनाए रखा। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य दो असाधारण ग्रन्थ भारत में प्रकाश में आए। ये हैं, पहला भागवत और दूसरा गीतगोविंद। इन्हें मूलतः शास्त्रीय ग्रंथ कहा जा सकता है, लेकिन लोक कलारूपों ने इन्हें सबसे बेहतर ढंग से आत्मसात किया।

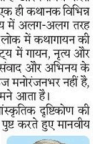

चिन्मय मिश्र
वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी
@patrika.com

टैक्सेशन रिटर्न प्रणाली व इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी हो बदलाव

जीएसटी व्यवस्था को आसान बनाने की जरूरत

भारत में नब्बे के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, उसके बाद आर्थिक सुधारों की जो बातें हुईं, उनमें से एक था वन नेशन-वन टैक्स का फैसला। इसके तहत ही जीएसटी की तैयारी की गई और कमेटियां भी बनीं। कारोबारियों को बताया गया कि यह आसान व्यवस्था होगी और उनके लिए टैक्स भरना पहले से भी आसान होगा। लेकिन, कारोबारी-व्यापारी अब तक जीएसटी भुगतान में सहज नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, मसलन दो तरह के सामान जो मिलकर एक उत्पाद होते हैं, उन पर अलग-अलग टैक्स दरें हैं। अगर हम भारत के एक पॉपुलर स्नैक 'बन मस्का' को देखेंगे तो पाएंगे कि बन पर टैक्स की दर अलग है और मस्का यानी मक्खन पर अलग। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जो जीएसटी की विसंगतियां बताती हैं।

इसके अलावा कई सेवाओं पर 18 फीसदी का भारी भरकम टैक्स भी है। व्यापारियों का कहना है कि दरों में विसंगति न हो और उन्हें तार्किक बनाया जाए। उनकी यह भी शिकायत है कि वे पूरे माह जीएसटी रिटर्न भरने में लगे रहते हैं, नहीं तो लाखों की देनदारी का नोटिस आ जाता है।

इस समय टैक्स के चार स्लैब हैं- 5, 12, 18 और 28 फीसदी। स्लैब को कम करके तथा दरों को तर्कसंगत बनाने से वैधानिक मामले कम हो जाएंगे। साथ ही, जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। जीएसटी से जुड़े मामलों के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। जीएसटी को शुरू करने तथा सुचारू रूप से लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी और वह अब भी इसका काम देखती है। वित्त मंत्री की बहुत इच्छा रही है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए ताकि इसके दाम भी पूरे देश में लगभग एक समान हों, लेकिन कई सदस्य इसे होने नहीं दे रहे हैं। वे अपने-अपने राज्यों के संकीर्ण हित के चलते ऐसा नहीं होने देते। जब भी किसी राज्य को अपना राजस्व बढ़ाना होता है वह तुरंत ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक, जहां इनकी कीमतें सबसे ज्यादा हैं। अगर इस पर जीएसटी लगा होता तो ऐसा संभव नहीं था।

उधर सरकार की शिकायत है कि अब भी जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। साल 2022-23 में देश में दो लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय जीएसटी अधिकारियों ने टैक्स चोरी के 86,717 मामलों का पता लगाया।

जीएसटी को लेकर अब कई कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल इसमें आमूलचूल बदलाव करेगा। टैक्स स्लैब घटाए जाएंगे व सरलीकरण पर जोर दिया जाएगा।

मधुरेन्द्र सिन्हा
वरिष्ठ पत्रकार
एवं स्तंभकार
@patrika.com

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

प्रकृति की जादुई रचनात्मकता की प्रतीक नॉर्वे में 'ड्रैगन की आंख'

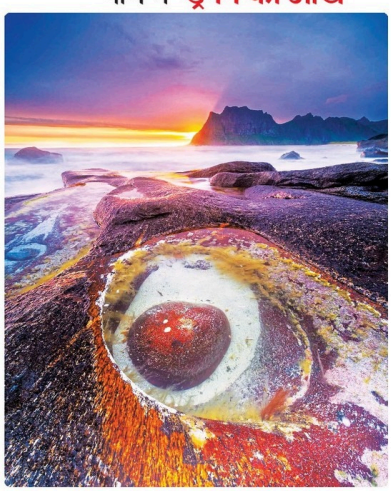

नॉर्वे के लोफोटेन द्वीपसमूह में स्थित उत्ताक्लेव बीच पर पाया जाने वाला 'ड्रैगन की आंख' एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक प्राकृतिक शिलारूप है, जो प्रकृति की जादुई रचनात्मकता का प्रतीक है। यह नेत्राकार आकृति वास्तव में ग्लेशियर पॉट होल है, जो आखिरी हिम युग के दौरान फेनोस्कैंडियन आइस शीट के नीचे बनी थी। पिघलते हुए हिमजल और उसमें घुले रेत-कणों ने ग्नीस नामक कायांतरित शिला को धीरे-धीरे घिसकर यह गड्ढा बना।

उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से क्रियान्वित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक बन गया है पीएम-किसान

पीएम-किसान: भारत के गांव-गांव में 'समृद्धि का बीज'

ग्रामीण समृद्धि और समावेशी विकास के सफर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना एक अग्रणी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई इस पहल ने लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और पूरी तरह से डिजिटल, कुशल एवं पारदर्शी प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के एक वैश्विक मॉडल के रूप में खुद को स्थापित किया है।

मूल रूप से, पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए 2,000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस तकनीक-संचालित कदम से बिचौलियों की भूमिका, लाभ मिलने में होने वाली देरी और त्रुटि की गुंजाइश खत्म होती है। इस योजना में अब-तक, कुल 3.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार, पीएम-किसान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से क्रियान्वित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक बन गया है।

दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसानों के लिए ये लाभ बुवाई या कटाई के मौसम में एक अहम आर्थिक सेतु का काम करते हैं। ये लाभ अल्पकालिक नकदी प्रवाह के तनाव को कम करते हैं, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी लाते हैं और संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। पीएम-किसान की सफलता का श्रेय भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को जाता है। जेएएम की तिकड़ी- जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी- ने बड़े पैमाने पर लाभ के निर्बाध वितरण को संभव बनाया है। स्व-पंजीकरण से लेकर भूमि स्वामित्व के सत्यापन और डीबीटी द्वारा समर्थ भुगतान तक, इस पूरी योजना का जीवनचक्र डिजिटल है। राज्य सरकारों के सहयोग से, पीएम-किसान डिजिटल रूप से समन्वित तथा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने वाले शासन के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में कार्य करता है।

आईएफपीआरआई, एफएओ, आईसीएआर और आईसीआरआईएसएटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने छोटे किसानों की आय बढ़ाने, ऋण की सुलभता में सुधार, असमानता को कम करने और आधुनिक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पीएम किसान की भूमिका पर प्रकाश डाला है।

पीएम-किसान का सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह ने ग्रामीण बाजारों को पुनर्जीवित किया है, कृषि-उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित किया है और घरेलू उपभोग के पैटर्न को मजबूत किया है।

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में पीएम-किसान जैसी पहल समावेशी प्रगति की नींव रखती है। पीएम-किसान विश्वास, तकनीक और परिवर्तन की कहानी है। यह दुनिया के लिए भारत का योगदान है। यह योजना एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक दूरदर्शी नीति, डिजिटल नवाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर, लाखों लोगों को सशक्त बना सकती है और 21वीं सदी के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।

डॉ. प्रमोद मेहरदा
अतिरिक्त सचिव
अरिंदम मोदक
सलाहकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
@patrika.com

दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसानों के लिए ये लाभ बुवाई या कटाई के मौसम में एक अहम आर्थिक सेतु का काम करते हैं।

आपकी बात

पात्र मतदाता न हो मतदान से वंचित

देश में घुसपैठियों के खतरे की वजह से चुनाव आयोग भी विशेष सघन पुनरीक्षण करना चाहता है ताकि अवैध घुसपैठियों के मतदाता पहचान पत्र निरस्त हों। पुनरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों के अधिकारों का हनन न हो। कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न हो। इस अभियान को लेकर कोई भी किसी तरह का भ्रम न रखे। **- डॉ. राजेन्द्र कुमावत, जयपुर**

समझौता दोनों देशों के हित में

ऐसे समय जब विश्व के देश अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से विचलित हैं, भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। इसे व्यापार, निवेश, विकास और रोजगार सृजन का अच्छा माध्यम बताया जा रहा है। **- संजय डागा, इंदौर**

आज का सवाल

मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

प्रेरणा

यदि तुम सूर्य को खो बैठने पर आंसू बहाओगे तो तारों को भी खो बैठोगे। -रवीन्द्रनाथ ठाकुर

संपादकीय

क्या चीन अमेरिका को पाक में पैठ बनाने देगा?

ट्रम्प का यह कहना हास्यास्पद है कि हो सकता है आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान से पेट्रोल खरीदे। पाकिस्तान में अगर अमेरिका ने 5 अरब डॉलर (4500 करोड़ रु.) लगाकर तेल खोजा भी तो कम से कम पांच साल लगेंगे इसे निकालने में। और कितने भंडार की उम्मीद है? मात्र उतनी जो अगर भारत समूचा भी खरीदे तो उसकी 50 दिन की जरूरत के बराबर ही होगा। फिर यह भंडार बलूचिस्तान के इलाके में संभव है, जहां पाकिस्तानी सेना भी इन दिनों जाने से डरती है। क्या ट्रम्प ने ये तथ्य जांचे? विशेषज्ञों के हिसाब से पाकिस्तान में अपुष्ट रूप से 200-300 मिलियन बैरल का कुल भंडार संभव है, जो अगर मिला भी तो वह स्वयं उस देश में आतंरिक खपत से ही सवा साल में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की अपनी तेल की खपत पांच लाख बैरल रोज है (भारत की इससे दस गुना है)। ट्रम्प यह भी भूल रहे हैं कि चीन ने भी पाकिस्तान में हजारों करोड़ डॉलर लगाए हैं और वो अमेरिका को वहां पैठ बनाने नहीं देगा। यह सच है कि भारत के कुल तेल आयात का 40% रूस से आता है। पर भारत की नीति है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा, खरीदेगा। रूस या खाड़ी के मुकाबले अमेरिका से दूरी बड़ी बाधा है। ट्रम्प ने एक समय यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन को व्यावहारिक और असाधारण प्रतिभा वाला कहा था, आज उन्हीं के देश की इकॉनोमी को बर्बाद क्यों बताने लगे हैं?

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

कम से कम कथा या प्रवचन को मोबाइल पर ना सुनिए

चांदनी घर जलाने आई है। इसका सीधा मतलब है, मोबाइल की रोशनी अब हमारे जीवन में नुकसान के दूसरे चरण में चल रही है। स्ट्रीमिंग के दौर में सबकुछ लोग हथेली पर कर रहे हैं। हमारा विषय है कम से कम कथा, प्रवचन मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यम पर ना सुनिए। इसके लिए लाइव ही अच्छा है। अब तो न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि आंखें दृश्यों को मस्तिष्क में ले जाती हैं और अमिग्डाला- यानी मस्तिष्क का वो भाग, जहां से भावना, संवेदना जागती है- उसको प्रभावित करती है। ये काम आंख करती है। लाइव कथा सुनने से भावना, संवेदना, धैर्य, समझ और चरित्र सब आपकी पकड़ में आ जाते हैं। यदि आप यही सबकुछ मोबाइल या टीवी के परदे से सुन रहे हैं, तो उसका असर लाइव के मुकाबले कमजोर होगा। आंखें ठोकर पहले खाती हैं, उसके बाद पैर लड़खड़ाते हैं। तो आंख बड़ी महत्वपूर्ण है। कोशिश करिए कि महीने में एक बार कुछ ना कुछ लाइव जाकर सुनिए। रूबरू होकर ज्ञान मिलना अलग प्रभाव देगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नज़रिया • बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का सवाल

गरीबों के पास वोट की ताकत के अलावा कुछ और नहीं है

मतदान

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

यह एक तथ्य है कि भारत में कुलीन वर्ग गरीबों की तुलना में कम वोट देता है। कारण यह है कि अपेक्षाकृत विशेषाधिकार-प्राप्त भारतीयों के लिए लोकतंत्र का कोलाहल अकसर थकाऊ होता है। लेकिन वंचित तबके की बड़ी आबादी के लिए यही लोकतंत्र सशक्तीकरण और एक सामाजिक हैसियत हासिल करने का उपकरण होता है। भले ही इस तबके में बहुत से लोग अशिक्षित हों, लेकिन सामूहिक रूप से अमूमन उन्हें इस बात की गहरी समझ होती है कि उनका प्रतिनिधित्व सबसे अच्छे तरीके से कौन कर सकेगा। वे जानते हैं कि सत्ता में भले कोई भी हो, लेकिन हर पांच साल में एक बार उन्हें भी अवसर मिलेगा कि वे सत्ताधीश को सत्ता से बाहर कर सकें या कम से कम उसके प्रति अपनी असहमति तो जता सकें। इसके लिए उनके पास वोट ही एकमात्र साधन है। यही कारण है कि उनके लिए चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

ऐसे में गरीबों और कमजोरों को उनके मताधिकार से भी वंचित कर देना उनसे वो एकमात्र जरिया छीन लेने जैसा है, जिससे वो उन्हें हाशिए पर कर देने वाले तंत्र में अपनी कोई सार्थक हिस्सेदारी निभाते हैं। यह उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता की गर्भनाल को काटने जैसा है। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए सिर्फ मताधिकार ही है, जिसके जरिए वे अपनी उम्मीदें कायम रखते हैं। भारत जैसे देश में- जहां अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है- वहां मताधिकार से वंचित कर देना उनकी निराशा को अराजकता और विद्रोह में भी तब्दील कर सकता है।

यही वह महत्वपूर्ण बात है, जिसे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू करते वक्त चुनाव आयोग को समझना चाहिए। आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संविधान-प्रदत्त अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ना ही मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के उसके अधिकार पर कोई ऐतराज कर सकता है। लेकिन अगर पुनरीक्षण का काम गलत समय पर और गलत तरीके से किया गया तो बहुत सम्भावना है कि भले ही कुछ अनधिकृत मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएं, लेकिन कई वैध मतदाता भी इससे अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे।

10 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को कम किए बिना तीन बेहद प्रासंगिक सवाल उठाए। पहला, हमेशा की तरह आयोग पहचान के सबूत के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? 28 जुलाई की सुनवाई में भी कोर्ट ने जोर देकर कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को 'व्यापक पैमाने पर निकालने के बजाय व्यापक पैमाने पर जोड़ना चाहिए।' और यदि ऐसा नहीं होता है तो सर्वोच्च अदालत इसमें दखल देगी। आयोग को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरा, आयोग चुनाव से कुछ ही माह पहले जून में एसआईआर क्यों कर रहा है? इससे पहले पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था। अब अचानक से बिहार में इसे कराने का फैसला क्यों किया गया, और वह भी इतनी देर से? निश्चित रूप से 8 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में इस प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय ढंग से करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। और तीसरा सवाल यह कि आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार कैसे मिल गया, यह तो गृह मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में है?

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मोटे तौर पर 50 प्रतिशत महिलाएं और 40 प्रतिशत पुरुष अशिक्षित थे। 2023 की जाति-जनगणना के अनुसार राज्य के दलितों में महज 3 प्रतिशत, अति पिछड़ों में 5 प्रतिशत और मुसलमानों में सिर्फ 7 प्रतिशत लोगों ने ही 12वीं कक्षा पास की है। इतने कम समय में वांछित नए दस्तावेज लेने के लिए ये लोग स्थानीय नौकरशाही से कैसे पार पा सकेंगे? बिहार के लाखों लोग अन्य राज्यों में प्रवासी हैं। दयनीय स्थितियों में जी रहे ये लोग कैसे अपने दस्तावेजों की व्यवस्था करेंगे? सच्चाई यह है कि आज वहां धरातल पर पूरी तरह से घबराहट और भ्रम की स्थिति है, क्योंकि बेसहारा गरीब लोग अपना मताधिकार मांग रहे हैं। आयोग द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किए गए आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर हैं।

अवैध प्रवासियों को निशाना बनाने के चक्कर में चुनाव आयोग ने बिना किसी पारदर्शिता के लाखों वैध मतदाताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। यह एक त्रासदी है, जिसे हमें उसके सही परिप्रेक्ष्यों में ठीक तरह से समझना होगा।

ऐसे में मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं : 'हम उनकी याद में अकसर उन्हीं को भूल गए।' अवैध प्रवासियों को निशाना बनाने के चक्कर में आयोग ने बिना किसी पारदर्शिता के लाखों वैध मतदाताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। यह एक त्रासदी है, क्योंकि गरीबों के पास अपने वोट की ताकत के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

मुद्दा • दहेज उत्पीड़न में दो महीने तक गिरफ्तारी पर रोक

फर्जी मामलों में पीड़ित को मुआवजा देना अब जरूरी है

कानूनन

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
viraggupta@hotmail.com

दहेज उत्पीड़न और विवाहिताओं के खिलाफ क्रूरता के मामलों में दो महीने तक गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला भी कहीं पुराने फैसलों की तरह कानून की किताबों में गुम न होकर रह जाए? इसके लिए 5 बिंदुओं पर समझ जरूरी है।

1. गिरफ्तारी : जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य (1994) के फैसले के अनुसार हिरासत और गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अनेक अधिकार मिले हैं। चीफ जस्टिस वेंकटचलैया के अनुसार विवेक का इस्तेमाल किए बगैर मनमाने तरीके से गिरफ्तारी असंवैधानिक और गैर-कानूनी है। 1996 में डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के फैसले में हिरासत में लिए लोगों के कानूनी अधिकार तय किए गए थे। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के फैसले में हिरासत और जेल को अपवाद कहा गया था। इन फैसलों के अनुसार जारी शासनादेशों का अनुपालन नहीं होने से थानों और अदालतों के चक्कर में करोड़ों परिवार तबाह हो रहे हैं।

2. सुप्रीम कोर्ट : नए फैसले के अनुसार धारा 498-ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जून 2022 के आदेश के अनुसार जिलों में परिवार कल्याण समितियों का गठन होना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा मामले में जून 2017 में एक बड़ा फैसला दिया था। उसके अनुसार धारा 498-ए से जुड़े अधिकांश मामलों में फर्जी तरीके से पति और उसके परिजनों को पुलिस केस में फंसाया जाता है। फैसले में नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी को मार्च 2018 तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश था, जिसका 8 साल बाद कोई विवरण नहीं आ रहा। धारा 498-ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ऐसे अनेक पुराने फैसलों पर जब अमल नहीं हो रहा तो अब नए फैसले के बाद जमीनी स्तर पर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा?

3. संसद से कानून : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 की विशिष्ट शक्तियों के दुरुपयोग और सुप्रीम कोर्ट के सुपर-संसद बनने पर रोष व्यक्त किया था। अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश अधीनस्थ अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। पर उन फैसलों के अनुसार सरकार और संसद ने आईपीसी या बीएनएस और सीआरपीसी या बीएनएसएस की कानून की किताबों में बदलाव नहीं किए। इस संसदीय विफलता की वजह से पुलिस की मनमर्जी के साथ अदालतों में अराजकता बढ़ रही है।

4. जिला अदालतें : अदालतों में चल रहे 5.07 करोड़ मुकदमों में से लगभग 70 फीसदी यानी 3.52 करोड़ आपराधिक हैं। गरीबों को सही मामलों में भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। दूसरी तरफ नेताओं और रसूखदार लोगों के इशारों पर सिविल मामलों में भी फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नए-पुराने फैसलों से साफ है कि पारिवारिक मामलों में फर्जी तरीके से पति और उसके परिजनों को फंसाने का दुश्चक्र चल रहा है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जिला अदालतों में रूटीन तरीके से आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। जमीन के मामलों में पटवारी की रिपोर्ट और आपराधिक मामलों में पुलिस दरोगा की एफआईआर को अदालतों में अकाट्य मानने के साम्राज्यवादी रिवाज की वजह से आजाद भारत के करोड़ों लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी थाने और अदालतों के धक्के खाने के लिए अभिशप्त हैं।

फर्जी तरीके से दर्ज एफआईआर और गैर-कानूनी हिरासत के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिले। ऐसा होगा तो ही दहेज उत्पीड़न और एससी/एसटी समेत सभी मामलों में कठोर कानूनों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

5. गुजारा भत्ता : सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे और गुजारा भत्ता की रकम रद्द होने के साथ हाल ही के शिवांगी बंसल वाले मामले में आईपीएस पत्नी को माफीनामा भी देना पड़ा। लेकिन पति और पिता को 100 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे होगी? कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में पत्नी ने गुजारा भत्ता के नाम पर 12 करोड़ रुपए, लग्जरी फ्लैट और कार की मांग की थी। लिव-इन रिश्तों को कानूनी मान्यता और स्त्री-पुरुष समानता के दौर में तलाक के कानून को सरल बनाने के साथ गुजारा भत्ता के नियमों को व्यावहारिक बनाने के लिए सात दशक पुराने कानूनों में बदलाव लाने की जरूरत है।

डिजिटल इंडिया का समय है। ऐसे में आम जनता के हितों और अधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्विवाद फैसलों के विवरण का ऐप जारी हो। फैसलों का पालन नहीं करने वाले पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलने के साथ प्रशासनिक निलम्बन की कार्रवाई हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

2 अगस्त के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने टेक कंपनियों के कर्ज लेकर एआई में निवेश करने और चीनी मॉडलों की स्थिति आदि पर खास खबरें की हैं।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

एआई बदल रहा है दुनिया : एआई हर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाता जा रहा है। पढ़ें तकनीक, व्यापार, खुफिया सूचनाएं, राजनीतिक प्रचार आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स...

ओपिनियन माइक्रोसॉफ्ट पर 4 लाख करोड़ कर्ज, मेटा की भी 2.62 लाख करोड़ कर्ज लेने की योजना

गूगल, अमेजन, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां एआई में निवेश के लिए ले रहीं कर्ज, इस साल 35 लाख करोड़ खर्च होंगे

अमेरिका स्थित दिग्गज कंपनियों अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट आदि के खर्चों में एक नया ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है। ये कंपनियां अपनी पुरानी कार्यशैली के विपरीत अब प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेकर एआई में निवेश कर रही है। इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लाइल के जेसन थॉमस का अनुमान है, टेक कंपनियों का खर्च ताजा तिमाही के दौरान अमेरिका के आर्थिक विकास का एक तिहाई हो गया है। सवाल उठता है, इस खर्च का बोझ कौन उठाएगा। विश्लेषकों का अनुमान है, यह बोझ बड़ी टेक कंपनियों के निवेशकों और शेयरधारकों को उठाना होगा।

इस साल कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी। मोर्गन स्टेनले के एनालिस्ट मानते हैं, 2028 तक डेटा सेंटर्स पर 253 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंसल्टेंसी फर्म मेकिंजी का अनुमान है, 2030 तक यह खर्च 586 लाख करोड़ रु. होगा। 2023 के बाद अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 70 लाख करोड़ रु. के कैशफ्लो को पूंजीगत खर्च और शेयरहोल्डरों के बीच बांटा है। अमेजन के शेयरधारक बिल्डिंग निर्माण, इक्विपमेंट की खरीद जैसे भारी पूंजीगत खर्च में हिस्सेदारी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें रिटर्न कम मिल रहा है।

एपल के निवेशकों को फायदा हुआ है। फिर भी, उन्हें चिंता है कि निवेश पर खर्च न करने के कारण कंपनी एआई में पीछे चल रही है। यदि कंपनियां कंज्यूमर की तुलना में एआई देर से अपनाती हैं तो बड़ी टेक कंपनियों को अपने निवेश पर तेजी से रिटर्न मिलने में मुश्किल जाएगी। शेयरहोल्डर धीमे विकास की भरपाई अपनी आय के ज्यादा हिस्से की मांग से करेंगे।

एआई पर खर्च शेयर बाजार के बजाय कर्ज लेकर किया जा रहा है। यह बड़ी टेक कंपनियों के पुराने तरीकों से अलग है। इस साल की पहली छमाही में टेक कंपनियों के इन्वेस्टमेंट का कर्ज 2024 के पहले छह महीनों से 70% अधिक है। अप्रैल में अल्फाबेट ने 2020 के बाद पहली बार बॉण्ड जारी किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कैश के बजाय उधारी में बढ़ोतरी की है। यह 2023 के बाद लगभग तीन गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मेटा प्राइवेट कंपनियों से 2.62 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए चर्चा कर रही है। सिलिकॉन वैली के डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर कर्ज में बढ़ोतरी कर रहे हैं। प्राइवेट मार्केट्स के समान बड़ी टेक कंपनियां का केंद्रीकरण हो रहा है। टेक कंपनियां पूंजी जुटा रही हैं क्योंकि वे सोचती हैं कि एआई का फायदा कुछ लोगों के हाथ में रहेगा। निवेशक उन्हें इसलिए कर्ज दे रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह स्थिति शेयर और पूंजी बाजार वॉल स्ट्रीट की भी है।

कैश फ्लो के मुकाबले कंपनियों का पूंजीगत खर्च बढ़ रहा

कैश फ्लो के मुकाबले टेक कंपनियों का पूंजीगत खर्च बढ़ रहा है। मोर्गन स्टेनले का अनुमान है, तीन वर्षों में दोनों में 131 लाख करोड़ रुपए का अंतर आ जाएगा। इस तरह आमदनी कम हो जाएगी। कर्जदाताओं के लिए जोखिम की स्थिति रहेगी। पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी से जरूरत से ज्यादा निर्माण होता है। रिटर्न में गिरावट से दिवालियापन के हालात बनते हैं। इक्विटी निवेशक ऐसे हालात से निपट सकते हैं। लेकिन बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे निवेशक यह सहन नहीं कर पाएंगे।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

इंटेलिजेंस पेंटागन ने दिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट

अमेरिका, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों में एआई की पैठ

डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसी दिन चीन की एक कंपनी डीपसीक ने एक विश्वस्तरीय लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च कर दिया। ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए एक चेतावनी बताया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस घटनाक्रम से हैरान रह गईं।

पिछले साल बाइडन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया कि वे गूगल डीपमाइंड और ओपेन आई जैसी फ्रंटियर लैब्स के साथ सहयोग करें। 14 जुलाई को पेंटागन ने ओपेनएआई, एक्स एआई जैसी कंपनियों को एजेंटिक मॉडल्स पर प्रयोग के लिए 200 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए।

फ्रंटियर लैब्स सैन्य कामकाज तक ही सीमित नहीं रहीं, अमेरिकी जासूसी तंत्र में इनका इस्तेमाल शुरू हो गया है। चैटबॉट्स को टॉप-सीक्रेट डेटा के विश्लेषण में लगाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी में कहा था कि उसकी क्लाउड सेवाओं के 26 उत्पादों को खुफिया एजेंसियों में इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। अब लगभग हर अमेरिकी खुफिया एजेंसी क्लाउड, जीपीटी के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही है।

ब्रिटेन के एक अधिकारी के अनुसार, यूके इंटेलिजेंस कम्युनिटी में हर किसी को टॉप-सीक्रेट एलएलएम एक्सेस मिला हुआ है। यूरोप की एकमात्र एआई चैम्पियन फ्रांस की मिस्त्रल की साझेदारी फ्रांस की सैन्य एआई एजेंसी के साथ है। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद इजराइली सेना द्वारा जीपीटी-4 का उपयोग 20 गुना बढ़ गया। ओपेनएआई की कटरीना मुलिगन कहती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में एआई का अपनाना अभी उस स्तर पर नहीं है, जहां होना चाहिए।

एआई मॉडल्स गलत जवाब कम दें तभी कारगर

एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रिचर्ड कार्टर का मानना है कि खुफिया एजेंसियों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मॉडल्स में गलत जवाब देने की दर कम हो। वे कहते हैं खुफिया तंत्र को स्थिरता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता की जरूरत है। जबकि लैब्स ज्यादा एडवांस एजेंटिक मॉडल्स पर ध्यान दे रही हैं।

चीन एआई से ताकतवर इनसाइट्स निकाल रहा

इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी के फिलिप रीनर कहते हैं कि चीन ने डीपसीक जैसे मॉडल्स को सैन्य व जासूसी कामों में अपनाया है। उनके यहां हमारे जैसे नैतिक प्रतिबंध नहीं हैं, और इसीलिए वे अधिक ताकतवर इनसाइट्स तेजी से निकाल पा रहे हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

इन्वेस्टमेंट

दक्षिण-पूर्व एशिया बन रहा है एआई निवेश का हब

दक्षिण-पूर्व एशिया एआई में निवेश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में लगभग 2 गीगावॉट डेटा सेंटर क्षमता है, जो यूरोप के सबसे बड़े डेटा-सेंटर हब के बराबर है। एआई की दौड़ में दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर और मलेशिया सर्वाधिक लाभ उठा रहे हैं। हुआवे और अलीबाबा ने क्षेत्र में डेटा सेंटर बना लिए हैं। अलीबाबा ने टेनसेंट और इंडोनेशियाई टेक फर्म गोटो से साझेदारी की है। टेनसेंट अकेले 2030 तक इंडोनेशिया में 500 मिलियन डॉलर निवेश की योजना बना रहा है। अल्फाबेट, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट भी निवेश कर रहे हैं। अमेजन 2028 तक सिंगापुर में विस्तार के लिए 9 अरब डॉलर खर्च करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने मलेशिया और इंडोनेशिया में 4 अरब डॉलर निवेश का वादा किया है। अल्फाबेट मलेशिया में 2 अरब डॉलर का डेटा सेंटर बना रहा है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टेक्नोलॉजी चिप्स की किल्लत से सामने आ रही हैं संचालन की दिक्कतें

चीन ने एआई मॉडल्स बना लिए, पर चला नहीं पा रहा

बमुश्किल छह महीने पुरानी बात है। चीन की एआई फर्म डीपसीक ने अपने वी3 मॉडल्स से दुनिया को हैरान कर दिया था। ये पहली बार था, जब अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश ने ऐसे ओपन-सोर्स मॉडल तैयार कर दिखाए थे, जो सिलिकॉन वैली में डिजाइन किए गए मॉडलों को टक्कर दे रहे थे। और वह भी तब, जब अमेरिका ने चीन को उच्च-स्तरीय सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति से वंचित कर दिया था।

लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद चीनी फर्मों ने विश्व-स्तरीय एआई मॉडलों की ट्रेनिंग जारी रखी। जुलाई में गूगल और मेटा के एक पूर्व छात्र द्वारा स्थापित बीजिंग स्थित प्रयोगशाला मूनशॉट एआई में किमी के2 को लान्च किया गया। यह सीधे वैश्विक लीडरबोर्ड में शीर्ष पर पहुंच गया। किमी के2 ने कोडिंग क्षमता के परीक्षणों में चैटजीपीटी 4.1 और वैज्ञानिक जानकारियों के परीक्षणों में क्लाउड 4 ओपस से बेहतर प्रदर्शन किया।

लेकिन कोई मॉडल्स केवल तभी प्रभावित कर सकते हैं, जब उनका इस्तेमाल किया जाए। और यहीं पर चिप-सम्बंधी प्रतिबंधों से चीन को मार पड़ी। इनकी किल्लत से डेटा सेंटरों की एआई लैब्स के संचालन में दिक्कतें आने लगी हैं। स्लोडाउन, उपयोग की सीमाएं और कनेक्शनों का ड्रॉप होना आम बात हो गई है। मूनशॉट ने एक्स पर यह तक पोस्ट कर दिया कि 'किमी के2, सुना है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं!' इधर डीपसीक ने भी अपने नए एआई मॉडल के लॉन्च को टाल दिया, ताकि कहीं उसे भी इसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

पिछले कुछ महीनों में चीनी कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के कई तरीके भी खोज निकाले हैं। अप्रैल से अब तक, एक अरब डॉलर मूल्य के प्रतिबंधित चिप्स चीन में आ चुके हैं और हुआवे जैसी घरेलू कंपनियों ने कुछ मामलों में एनवीडिया के उच्च-स्तरीय उत्पादों से मेल खाने वाले चिप्स भी विकसित किए हैं।

एआई के लिए कमर कसे हुए है चीन का शीर्ष नेतृत्व

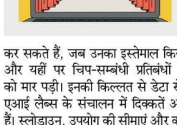

चीन एआई-बूम के लिए उपजाऊ भूमि की तरह है। वहां करोड़ों की संख्या में साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। उसके पास ग्रिड्स का बुनियादी ढांचा है और उसका राजनीतिक नेतृत्व भी तेजी से डेटा सेंटर बनाने के लिए कमर कसे हुए है। वह पश्चिम के तमाम सार्वजनिक डेटा स्रोतों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

रिसर्च फर्जी खबरें व सूचनाएं फैलाईं

चुनावों में एआई का दुरुपयोग हो रहा, कई देशों में इसकी मदद से झूठा प्रचार हुआ

विश्व में एआई के दौर के सबसे पहले चुनाव 2024 में हुए हैं। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या एआई से बड़े पैमाने पर गलत प्रचार हुआ था। क्या डीपफेक और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से फर्जी खबरें और जानकारियां फैलाई गईं या इससे राजनेताओं को दूसरी भाषा के वोटरों से संपर्क करने में सहूलियत हुई। एक पैनल के विश्लेषण से कई देशों के चुनाव अभियान में एआई का दुरुपयोग सामने आया है। इनमें भारत भी है। इंटरनेशनल इनफॉरमेशन एनवायरनमेंट पैनल के विशेषज्ञों द्वारा जुटाए गए डेटा से पता लगता है कि पिछले साल पांच में से चार चुनाव में एआई का इस्तेमाल हुआ है। ग्रुप ने पाया कि अमेरिका से भारत और ब्रिटेन से इंडोनेशिया तक के चुनावों में एआई का उपयोग हुआ है। बोत्सवाना, मंगोलिया और टोगो केवल ऐसे देश रहे, जहां एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया। पैनल को 46 प्रतिशत मामलों में कंटेंट के मूल स्रोत का पता नहीं लगा। 20 प्रतिशत ज्ञात स्रोत विदेशी थे। भारत में मृत राजनेताओं को प्रचार अभियान में फिर से जीवित दिखाया गया।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 143

गाजा पर बदलता माहौल

गाजा में नागरिकों पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों पर महीनों आंखें मूंदे रहने के बाद आखिरकार प्रमुख पश्चिमी देशों ने अपना रुख बदलते हुए सख्ती दिखाई है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने फिलिस्तीन को दी सशर्त मान्यता सितंबर में बढ़ा दी है तथा संयुक्त राष्ट्र महा सभा के 80वें सत्र के पहले दो राष्ट्रों वाले हल को समर्थन देने की बात कही है। व्यावहारिक तौर पर तो यह कद सांकेतिक ही है क्योंकि फिलिस्तीन राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन व्यापक भूराजनीतिक संदर्भों में यह बदलाव इजरायल के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रुख में बहुत अहमियत रखता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच में से चार सदस्यों (चीन और रूस भी) से पहली बार द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता मिलने की संभावना है। ऐसे में अमेरिका अलग-थलग पड़ जाएगा। वे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से उन 147 देशों में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। भारत ने बहुत आरंभ में ही उसे मान्यता दे दी थी। रुख में इस बदलाव से पहले तीन देशों ने संयुक्त घोषणा की थी कि वे गाजा में इजरायल के आक्रामक रुख से 'भयाक्रांत' हैं और पश्चिमी तट पर अवैध बस्तियों के विस्तार की निंदा करते हैं।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के इन तीन साझेदार देशों की सरकारें गाजा और पश्चिमी किनारे पर इजरायली अत्याचारों के खिलाफ बढ़ते जनमत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। गत सप्ताह स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला सदस्य देश बना जिसने गाजा में आक्रामक भूमिका निभाने वाले दो इजरायली मंत्रियों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। 30 जुलाई को यूरोपीय संघ के 58 पूर्व दूतों ने आग्रह किया कि संघ हथियारों का निर्यात बंद करे, इजरायल पर प्रतिबंध लगाए और वहां अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए।

इस सप्ताह के आरंभ में फ्रांस और इटली में बंदरगाहों पर काम करने वालों ने इजरायल भेजे जा रहे हथियारों की खेप रोक दीं और अपनी सरकारों से इजरायल को राजनयिक समर्थन रोकने के लिए कहा। जर्मनी में जनसंहार (होलोकॉस्ट) का इतिहास होने के कारण इजरायल को तगड़ा समर्थन हासिल है। उसने भी गाजा में विमानों से राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही मगर इजरायल को समर्थन भी वह देता रहेगा। सऊदी अरब ने भी हवाई मार्ग से वहां खाद्य सहायता पहुंचाई और इस संकट पर अब तक दिखाई जा रही उदासीनता त्याग दी। इन घोषणाओं के साथ ही महत्त्वपूर्ण राजनयिक गतिविधियों से भरा हफ्ता भी पूरा हो गया। एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 29 और 30 जुलाई को न्यूयॉर्क घोषणा पत्र जारी किया गया तथा आठ दशकों से चले आ रहे विवाद को हल करने की चरणबद्ध योजना पेश की। इसका अंत स्वतंत्र और असैन्य फिलिस्तीन के रूप में होगा, जो इजरायल के साथ शांति से रहेगा।

लगभग उसी समय दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में आठ देशों के हेग समूह ने चीन, स्पेन और कतर सहित करीब 30 देशों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें गाजा में इजरायल की हरकतों के खिलाफ कई कदमों पर सहमति बनी। इनमें हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध, हथियार ले जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध और इजरायली कंपनियों से जुड़े ठेकों पर पुनर्विचार शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ फ्रांसेस्का अल्बानीज भी इस बैठक में रहीं और उन्होंने इसे 'पिछले 20 महीनों का सबसे अहम राजनीतिक घटनाक्रम' करार दिया।

अब सवाल यह है कि जनमत में इस बदलाव से जमीनी दशा भी कितनी बदल पाएगी। चूंकि अमेरिका से इजरायल को लगातार समर्थन और 70 फीसदी हथियार मिल रहे हैं, इसलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में रक्षा बलों पर और पश्चिमी तट में बसने वालों पर शायद ही लगाम कसें। असली इम्तहान तो इस बात का होगा कि यूरोप क्या इजरायल पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की शुल्क की धमकियों का जोखिम उठाएगा। अधिक दबाव बनाए बगैर आठ दशक से चले आ रहे इस संघर्ष का दो राज्यों वाला समाधान हकीकत नहीं बन पाएगा।

अजय मोहंती

अमेरिकी धौंस के आगे बिल्कुल न झुके भारत

भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के आगे झुकने के बजाय उसका मुकाबला करना चाहिए। एक बार झुक गए तो अमेरिका की मांगें बढ़ती ही जाएंगी। बता रहे हैं श्याम सरन

पिछला एक हफ्ता भारत की आंखें खोलने वाला रहा है। राष्ट्रपति के तौर पर डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीदें उस समय चकनाचूर हो गईं, जब ट्रंप ने अपने 'मित्र' भारत पर 25 फीसदी शुल्क लगाने का ऐलान कर डाला। यही नहीं उन्होंने रूस से हथियार और तेल खरीदने, ईरान से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने तथा ब्रिक्स प्लस का सदस्य होने के कारण भारत पर जुर्माना लगाने की बात भी कही।

हालांकि जुर्माना कितना होगा, यह अभी नहीं पता है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत प्राय बताते हुए कहा कि यह भी उसी तरह गर्त में चली जाएगी, जैसे उनके पुराने दोस्त रूस की अर्थव्यवस्था जा रही है। अब यह मामला व्यापार या शुल्क की जंग भर का नहीं रह गया है बल्कि भूराजनीतिक चुनौती बन गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी दोस्तों और दुश्मनों को झुकाने की अपनी सनक में वाणिज्यिक उपायों को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देशों ने उनकी अतिरंजित और भेदभाव भरी मांगों के सामने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका में भारी निवेश का वादा किया है, जो पता नहीं ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने तक पूरा हो पाएगा या नहीं।

चीन जैसे अन्य देशों ने अपनी वाणिज्यिक बढ़त का इस्तेमाल कर अमेरिका का प्रतिरोध किया है। मगर भारत के पास तो इस तरह की बढ़त भी नहीं है तो क्या उसे चुपचाप अमेरिकी मनमानी सहन कर लेनी चाहिए?

धौंस जमाने वालों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी धौंस नहीं सही जाए। अगर पहली बार में ही झुक गए तो भविष्य में और भी दबाव पड़ सकता है तथा बार-बार घुटने टेकने पड़ सकते हैं। अभी जान छुड़ाने के लिए छोटी कीमत चुका दी गई तो भविष्य में बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। भारत अगर अभी ट्रंप की मांगों के खिलाफ खड़ा नहीं होता है तो आगे चलकर अमेरिका की फरमाइशें बढ़ती ही जाएंगी और वह बड़ी रियायतें मांगेंगे। अगर हमने अभी सीमा रेखा नहीं खींची तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में इसकी विश्वसनीयता तथा प्रभाव के लिए दुष्परिणाम होंगे।

क्या भारत को अपने प्रतिरोध की कीमत चुकानी होगी? बिल्कुल चुकानी होगी और हमें इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्तों की सीमा क्या है?

2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल 186 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो भारत के कुल व्यापार का 10.73 फीसदी है। भारत का 8 फीसदी निर्यात अमेरिका जाता है और अमेरिका से हम 6 फीसदी आयात करते हैं। 10 फीसदी व्यापार की निर्भरता ज्यादा तो है मगर ऐसा भी नहीं है कि उसका खत्म होना बरदाश्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो उसी साल अमेरिका चौथे नंबर पर रहा और भारत में 81.04 अरब डॉलर की कुल आवक में उसका योगदान केवल 11 फीसदी रहा। हिस्सेदारी का यह आंकड़ा ज्यादा तो है मगर इतना ज्यादा नहीं है कि उसे किसी अन्य देश से हासिल न किया जा सके। अनुमान है कि उच्च टैरिफ लागू होने के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दो फीसदी तक कमी आ सकती है। परंतु यह बहुत बड़ी कीमत नहीं है। अतीत में जब हम कमजोर देश थे तब भी अहम मसलों पर अपना रुख साफ करने की कीमत हमने चुकाई है।

ट्रंप के कदमों के भूराजनीतिक परिणाम और भी चिंतित करने वाले हो सकते हैं। वह अन्य देशों के साथ भारत के रिश्तों पर वीटो चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि अमेरिका तय करे कि भारत किसके साथ कैसे रिश्ते रखे। इसे पुरजोर तरीके से नकारा जाना चाहिए। भारत के पास ब्रिक्स प्लस और क्वाड में बने रहने की पर्याप्त वजह है। रूस के साथ हमारा रिश्ता कई तरह से हमारे हित में है। हालांकि इसमें अब कुछ विविधिता आ रही है लेकिन उसकी अपनी वजह हैं। अमेरिकी विदेश नीति में जिस तरह किसी एक की सनक के कारण पल भर में दुश्मन और दोस्त बदल जाते हैं, उसे देखते हुए जरूरी है कि भारत साझेदारियों का अपना नेटवर्क बनाए रखे तथा मजबूत करे। अन्य देशों के साथ भारत के रिश्तों में सबसे अहम रही है उसकी विश्वसनीयता। विभिन्न देश भारत पर भरोसा कर सकते हैं कि उसके साथ रिश्तों में निरंतरता बनी रहेगी। हमें एक अस्थिर चित्त वाले नेता के फेर में अपनी यह साख गंवानी नहीं चाहिए। भले ही वह दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया क्यों न हो? हमने दशकों में जो विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा अर्जित की है उसे इस हाथ दे उस हाथ ले वाले रिश्ते की भेंट नहीं चढ़ा देना चाहिए।

भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और भी बहिर्मुखी बनाना चाहिए मगर ऐसा अपने हित के लिए करना चाहिए, ट्रंप की मांगें पूरी करने के लिए नहीं। अच्छी बात यह है कि भारत ने कुछ व्यापार समझौते कर लिए हैं और उसे दोगुनी तेजी के साथ ऐसे अन्य समझौतों की दिशा में बढ़ना चाहिए जैसे यूरोपीय संघ के साथ समझौता। भारत ने बिना किसी ठोस वजह के स्वयं को दक्षिण-पूर्व एशिया के जीवंत आर्थिक क्षेत्र से अलग कर लिया है। उसे डर है कि चीन उस मार्ग का इस्तेमाल अपने माल को भारत में खपाने के लिए कर सकता है। परंतु इससे भारत को चीन से होने वाले निर्यात में कोई कमी नहीं आई है और इस समय वह अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। हमें पूर्व के अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक जुड़ाव का रास्ता दोबारा तैयार करना होगा क्योंकि वह अहम भूराजनीतिक पहलू है।

इस क्षेत्र के अधिकांश देश चाहते हैं कि भारत चीन को टक्कर देने वाला भरोसेमंद देश बने मगर यह तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास मजबूत आर्थिक आधार न हों। भारत को व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी (सीपीटीपी) का हिस्सा बनने के लिए आवेदन करना चाहिए, जहां फिलहाल न तो चीन है और न ही अमेरिका। आज के हालात में खुद को ट्रंप की नीतियों से बचाने के लिए शायद सबसे अच्छा रास्ता यह साहसी कदम ही होगा।

अंत में एक बात उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमें झुक जाना चाहिए और ट्रंप के कार्यकाल को किसी तरह गुजार लेना चाहिए क्योंकि जल्द ही अच्छे दिन लौट आएंगे। जमीनी हालात अगर किसी भी वजह से एक बार बदल जाते हैं तो उन्हें वापस पहले जैसा करना बहुत मुश्किल होता है।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

चंद्रशेखर की विरासत लेकर चले हैं हरिवंश

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

राज्य सभा का उप सभापति (लोक सभा में उपाध्यक्ष होते हैं और राज्य सभा में उप सभापति होते हैं, जिनका पद 2019 से ही खाली पड़ा है) होना कोई आसान काम नहीं है। सभापति प्रश्नकाल में सदन की अध्यक्षता करते हैं और इसके पूरे होते ही आसन छोड़ देते हैं।

शून्य काल (जब सदस्यों को तत्काल सूचना देकर और कई बार सूचना दिए बगैर ही मुद्दे उठाने की इजाजत होती है) को आम तौर पर उप सभापति ही संभालते हैं। यही वह समय होता है, जब तख्तियां दिखने लगती हैं, कागज फाड़े जाते हैं और कई बार नियम भी तोड़ दिए जाते हैं। महत्त्वपूर्ण और कई बार विवादास्पद चर्चाओं की अध्यक्षता भी उप सभापति ही करते हैं। ऐसे में उनकी नजर हर जगह होनी चाहिए।

हरिवंश नारायण सिंह या हरिवंश (जो नाम खुद उन्हें भी पसंद है) पहली बार 2014 में राज्य सभा के सदस्य बने थे और 2018 में उन्हें उप सभापति चुन लिया गया। उनके नाम की सिफारिश उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने की थी। बिहार में उनकी पार्टी ने पाले बदले मगर वह इस पद पर बने रहे। राज्य सभा में उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ और इसके साथ ही उप सभापति के पद से भी वह हट गए। लेकिन जब जदयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में लौटी तब उन्हें फिर से राज्य सभा के लिए निर्वाचित किया गया और वह उप सभापति भी बन गए। उनके दोबारा चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'वह शानदार अंपायर हैं और सदन की हर पंक्ति में खड़े हैं।'

उन्हें राजनीति के लिए जदयू के नीतीश कुमार ने चुना था। लेकिन हरिवंश का कर्मक्षेत्र पत्रकारिता था और उनके वास्तविक आदर्श थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। दोनों एक ही इलाके - पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार - से आते थे। चंद्रशेखर बलिया से थे। हरिवंश का परिवार जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में रहता था। दोनों परिवारों के कई ताल्लुकात थे।

चंद्रशेखर समाजवादी थे। हरिवंश लोहिया के रास्ते पर चलते थे। दोनों की पहली मुलाकात जसलोक अस्पताल में हुई थी, जहां गुर्दे खराब होने के कारण जेपी भर्ती थे। हरिवंश हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग में काम कर रहे थे और उन्होंने चंद्रशेखर का साक्षात्कार किया। बाद में उन्होंने कई बार उनका साक्षात्कार किया और उनके दृढ़ विचारों से प्रभावित हो गए। बाद में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री (1990-91) बने तो वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मीडिया सलाहकार बना दिए गए।

चंद्रशेखर के प्रभाव और पत्रकार के तौर पर प्रशिक्षण के कारण उनके मन में यह विचार दृढ़ता से घर कर गया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और अंत में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। 1989 में जब उन्होंने रांची से प्रकाशित होने वाले प्रभात खबर में काम शुरू किया तो उसकी केवल 500 प्रतियां बिकती थीं। अगले आठ साल में और खास तौर पर बिहार से कटकर झारखंड बनने के बाद इसकी 2 लाख प्रतियां बिकने लगीं। हरिवंश ने खबरों को स्थानीय रंग देकर यह कारनामा किया। इस दौरान भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने जैसे मसले प्रमुख मुद्दे बन गए और अखबार खुद को 'केवल अखबार नहीं आंदोलन' लिखता था। प्रभात खबर उन चुनिंदा अखबारों में था, जिसने लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते समय हुए चारा घोटाले की खबर सबसे पहले दी और सुशील मोदी जैसे नेताओं की मदद से अंत तक इस पर लिखता रहा।

राजनीति में आने के बाद हरिवंश की विनम्रता उनके बहुत काम आई। 2020 में विपक्ष दो कृषि विधेयकों को समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजे जाने की मांग कर रहा था किंतु हरिवंश ने इस पर ध्वनि मत की इजाजत दे दी। इस पर विपक्ष उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आया। उम्मीद के मुताबिक सभापति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। लेकिन ऐसा केवल एक बार हुआ। भारतीय संसद के इतिहास के जिस दौर में सांसदों का निष्कासन आम बात हो गई थी (2024 के शीतकालीन सत्र में 46 राज्य सभा सांसद निलंबित किए गए) उसमें विशेषाधिकार हनन के मसले पर जिस तरह उन्होंने चर्चा कराई, उससे निष्पक्षता और न्याय भरा उनका रुख सामने आया।

उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य राघव चड्ढा पर यह झूठा दावा करने का आरोप लगा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को प्रवर समिति के पास भेजे जाने के प्रस्ताव पर सांसद उनके साथ हैं, जबकि सांसदों के हस्ताक्षर उनके पास नहीं थे। गृहमंत्री अमित शाह ने झूठे हस्ताक्षरों का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। हरिवंश ने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही चतुराई के साथ संभाली और निलंबन खत्म हो गया। विपक्ष के एक सदस्य ने कहा, 'जब हरिवंश आसन पर होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आवाज सुनी जाएगी। दूसरे सभापतियों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।'

निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर को नए उप राष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है। लोक सभा और राज्य सभा में निर्वाचित सदस्यों तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या देखते हुए चुनाव में सरकार के उम्मीदवार की विजय लगभग तय है। तीन नामों की चर्चा चल रही है - एक केंद्रीय मंत्री, दक्षिण के एक राज्य के राज्यपाल और उप सभापति। यदि हरिवंश चुने जाते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन को नई दिशा मिलेगी।

आपका पक्ष

अंतरिक्ष में निसार से धरती पर पैनी नजर

भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर 30 जुलाई को निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब यह मिशन अपने 90 दिन के निर्णायक कमिशनिंग चरण में है। यह न केवल तकनीकी जांच है, बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में एक सक्रिय मॉनिटरिंग सिस्टम की तैनाती है। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दोहरे रेडार सिस्टम एल-बैंड और एस-बैंड का उपयोग किया गया है। यह तकनीक उपग्रह को इतनी संवेदनशीलता प्रदान करती है कि वह पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मिलीमीटर स्तर तक डिटेक्ट कर सकता है। इससे ग्लेशियर मूवमेंट, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और लैंड स्लाइड डिटेक्शन जैसी गतिविधियों की सटीक मॉनिटरिंग संभव होगी। इस 90 दिन की अवधि में एंटीना डिप्लॉयमेंट, ऑर्बिट स्टेबिलिटी और सिग्नल क्लैरिटी की गहन जांच होगी। यह चरण तय करेगा कि निसार कितनी प्रभावी और प्रिसाइज डेटा भविष्य में प्रदान कर पाएगा। आने वाले समय में निसार मिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट पॉलिसी और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। यह मिशन न केवल विज्ञान का उपकरण है, बल्कि मानवता की स्थिरता और सुरक्षा का एक दूरदर्शी प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा जो पृथ्वी के हर बदलाव को मौन रूप से पढ़ता है और समय रहते चेतावनी देता है।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

इसरो ने अमेरिका के साथ साझेदारी में 30 जुलाई को निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया

भारतीय धन व ब्रेन के बहिर्गमन पर नियंत्रण

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजा खोलने के बाद दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों का देश में दस्तक देने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन के साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भी दिल्ली में अपना केंद्र खोलने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के दुनिया के दूसरे देशों में होने वाले पलायन को थामने के लिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने चार और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने परिसर खोलने की मंजूरी दी है। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को नोएडा में, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय को ग्रेटर नोएडा में, ला-ट्रोब को बेंगलूरु में और ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई में परिसर की अनुमति दी गई है। आने वाले दिनों में चार अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों को भी जल्द ही अनुमति देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश रुख करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या वर्ष 2016 में 4.4 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 7.7 लाख हो गई, वर्ष 2024 तक यह लगभग 18 लाख तक पहुंच गई, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा पर विदेशी व्यय में काफी वृद्धि हुई। इससे बचने के लिए यह उपाय उत्तम है कि भारत में ही उन उच्च शिक्षण संस्थानों के केंद्र हों।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस दिल्ली शुक्रवार को फिलिपींस स्थित मनीला बंदरगाह पहुंचा।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 2 अगस्त 2025

भारत का रुख़ सही

ट्रंप की दादागिरी के आगे न झुके सरकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अचानक भारत को लेकर बेहद आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और यह भी चेताया है कि रूस से व्यापार की एवज में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया जाएगा। ट्रंप के इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है इस बारे में सरकार आकलन कर रही है।

देशहित में हो डील

ट्रेड डील । ट्रंप का हालिया बयान केवल टैरिफ या व्यापार घाटे से नहीं जुड़ा। इसके पीछे लंबी हताशा और अपनी इमेज बचाने की चिंता है। कई चरण की बातचीत के बावजूद दोनों देशों की ट्रेड डील किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। रोड़ा अटका हुआ है कृषि और डेयरी सेक्टर पर। हर डील अपनी शर्तों पर करने वाले ट्रंप इन दोनों सेक्टर में अमेरिका के लिए खुली छूट चाहते हैं। ऐसा करना भारतीय किसानों के हित में नहीं होगा और सरकार को इस मामले में बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। व्यापार एकतरफा फायदे को देखकर नहीं किया जा सकता।

रूस से व्यापार । अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के साथ असहमति की जो वजहें गिनाई हैं, उसमें रूस से तेल खरीदना प्रमुख है। हमारे सहयोगी अखबार TOI का मानना है कि 2022 तक भारत की तेल आपूर्ति में रूस का हिस्सा सिर्फ 1% था। आज यह आंकड़ा 35-40% है, और जरूरत पड़ने पर इससे पीछे हटना संभव है, क्योंकि अब रूसी तेल पर पहले जितना फायदा नहीं हो रहा। लेकिन, यहां बात केवल फायदे नहीं, दो देशों के रिश्तों और हक की भी है। भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं। आखिर अमेरिका ने भी तो उस पाकिस्तान के साथ डील की, जो वैश्विक मंचों पर कई बार आतंकवाद की शरणस्थली साबित हो चुका है।

अस्थिर पॉलिसी । ट्रंप न अपने बयानों पर स्थिर रहते हैं और न पॉलिसी पर। जिन देशों ने उनके साथ डील की है, उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटेन, वियतनाम से डील के बावजूद टैरिफ बढ़ रहा है। इसी तरह, EU के कई देश नाराज हैं क्योंकि आयात शुल्क औसत 4.8% से बढ़कर अब 15% हो चुका है। यानी किसी भी सूरत में टैरिफ की स्थिति पहले वाली नहीं रहेगी।

दोस्त जैसा व्यवहार । रुबियो ने भारत को अमेरिका का सहयोगी और रणनीतिक भागीदार बताया है। लेकिन, उनका बर्ताव एक दोस्त जैसा नहीं है। भारत को अगर कुछ मामलों में अमेरिका की जरूरत है, तो अमेरिका को भी कई जगह भारत का साथ चाहिए।

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में कई अहम पहलू साफ़ हुए

फिर भी बचे रह गए कुछ सवाल

पूनम पाण्डे

पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कुल 35 घंटे की चर्चा हुई। इस चर्चा का सबको इंतजार था ताकि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं पर स्थिति साफ हो सके, जिन्हें लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लोकसभा में करीब 19 घंटे की चर्चा हुई और राज्यसभा में 16 घंटे से ज्यादा। भारतीय सेनाओं के शौर्य और क्षमता को हर किसी ने सराहा। कुछ सवाल जो उठाए जा रहे थे उनके जवाब भी मिले। लेकिन अब भी कुछ अहम पहलू ऐसे हैं, जिन पर सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।

खुद रोका ऑपरेशन। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से जो बातें रखी गईं, उनमें साफ किया गया कि दुनिया के किसी भी देश या नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। यह दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में किया। यह भी कहा गया कि भारत के हमले से पाकिस्तान घबरा गया था और वह डर कर खुद शरण में आया। सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। चूंकि भारत का मकसद आतंकवादी आकाओं के ठिकानों को निशाना बना कर उन्हें स्पष्ट संदेश देना ही था, इसलिए इस मकसद के पूरा होने के बाद संघर्ष जारी रखने का कोई कारण नहीं था। लिहाजा, भारत ने पाकिस्तान की अपील स्वीकार कर ली। केंद्र की तरफ से इस सवाल का जवाब भी मिल गया जो विदेश मंत्री के एक बयान के बाद उठ रहा था कि हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि 9 आतंकवादी ठिकानों पर सफल हमले के बाद भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) की तरफ से पाकिस्तान के DGMO को इसकी जानकारी दी गई।

कितने फाइटर जेट का नुकसान । ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अब तक लगातार कहा जा रहा है कि कितने जेट का नुकसान हुआ, यह पूछना ही गलत है। लेकिन सवाल यह भी है कि इसका जवाब देने में नुकसान क्या है। 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स के एयर मार्शल ए के भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। साथ ही कहा गया कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं। अगर सिर्फ मशीन का ही कोई नुकसान हुआ है तो इसे बताने से फौज का मनोबल कैसे कम होगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद यानी 10 मई के बाद इसका जवाब मिलता तो इसका असर किस पर पड़ता। बहरहाल, तथ्य यह है कि संसद में 35 घंटे की चर्चा के बाद भी यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है।

चीन की भूमिका । ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का क्या रोल रहा, इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से यह पहले ही कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भारत की सैन्य तैनाती पर नजर रखने के लिए अपने सैटलाइट का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को इसकी रियल टाइम जानकारी दी। साथ ही, भारत-पाकिस्तान संघर्ष को चीन ने अपने लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया।, उसने अपने अलग-अलग वेपन सिस्टम का टेस्ट किया।

पाक से मिला संकेत । फिक्की एक कार्यक्रम में 4 जुलाई को सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने कहा था कि 'जब भारत-पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की बातचीत चल रही थी तब पाकिस्तान यह तक कह रहा था कि हमें पता है आपकी ये-ये यूनिटें कार्रवाई के लिए तैनात हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उसे पीछे हटाया जाए। इसका मतलब है कि उसे चीन से रियल टाइम जानकारी मिल रही थी'।

रियल टाइम टारगेटिंग । इससे पहले 31 मई को सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग में CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि 'ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की कमर्शल सैटलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया हो। लेकिन अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि उसे रियल-टाइम टारगेटिंग में मदद मिली'। संसद में चर्चा के बाद भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका कि चीन का इसमें क्या, कैसी और कितनी भूमिका रही।

ट्रंप का ऐलान । संसद में चर्चा के दौरान भी और इससे पहले भी कई बार सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने में किसी और देश ने कोई भूमिका नहीं निभाई। हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप करीब 30 बार अपनी भूमिका की बात दोहरा चुके हैं। ऐसे में संसद की चर्चा के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया कि जब अमेरिका का कोई रोल था ही नहीं, तो भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम के लिए राजी हो गए हैं, ये ऐलान भारत या पाकिस्तान से पहले ट्रंप ने कैसे कर दिया?

गाज़ा में भुखमरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन का आरोप है कि इस्राइली सेना गाजा में उसके सेंटर्स को भी निशाना बना रही है। आम लोगों तक मदद नहीं पहुंचने दी जा रही। यूरोप ने भी चिंता जताई है। गाजा में क्या है भूख की स्थिति, क्या करना चाह रहा इस्राइल?

5 पॉइंट

1 नया सिस्टम
इस्राइल का आरोप है कि गाजा में पहुंचने वाली मदद को हमास के लड़ाके लूट लेते हैं। हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए वह अपना सिस्टम लागू करना चाहता है, जिसके जरिये राहत और मदद पहुंचाई जाए।

2 कम सप्लाई
इस्राइली सेना के कब्जे वाले इलाके में Gaza Humanitarian Foundation के माध्यम से चार केंद्र चल रहे हैं, लेकिन ये कम हैं। इन केंद्रों पर खाने-पीने का सामान लेने के लिए कई बार भगदड़ मच चुकी है।

3 धीमी रफ्तार
100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि इस्राइल का मदद पहुंचाने का सिस्टम बहुत ही धीमा है। इससे भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। ब्रिटेन समेत EU के कई सदस्य देशों ने इस्राइल की आलोचना की है।

4 भूख से मौत
संयुक्त राष्ट्र ने मई में कहा था कि गाजा सबसे भूखी जगह है और पूरी आबादी पर अकाल का खतरा है। आंकड़ों के मुताबिक, केवल जुलाई में ही भूख से 46 मौतें हुई हैं। 24 घंटे के भीतर 10 लोगों की जान गई।

5 शांति ही उपाय
हमास और इस्राइल के बीच कतर में चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। समझौते के तहत 60 दिनों के संघर्षविराम, बंधकों की रिहाई और अंतिम युद्धविराम पर बातचीत होनी है।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

अंतर्दृष्टि

हर वक्त उपलब्ध रहना खोखला बना देता है हमें

सुंदर चंद ठाकुर

हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां 'उपलब्ध' होना सबसे बड़ा गुण बन गया है। हर समय फोन उठाना, तुरंत जवाब देना, मीटिंग्स में दिखना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना - अब इसे ही जिम्मेदारी, प्रोफेशनलिज्म और आधुनिक जीवन की निशानी माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि ये 24x7 उपलब्धता हमें भीतर से कितना थका रही है? कभी-कभी दिन के अंत में ऐसा क्यों लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं कर पा रहे? असल में यह जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होना, धीरे-धीरे एक मानसिक थकान, एक अव्यक्त बोझ बन गया है। हम हर वक्त जवाब देने की चिंता में रहते हैं - चाहे वो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो या कॉल। पहले समय में लोग अनुपलब्ध होते थे और उस अनुपलब्धता में ही उनकी रचनात्मकता, उनकी गहराई, उनका चिंतन पलता था।

महान कलाकार, कवि, लेखक, संत - सब एकांत से निकले। पर आज हम उस मौन से भागते हैं। क्योंकि मौन अब बोरियत लगता है। हमारा मन उस शांति को सहन ही नहीं कर पाता, जिसमें आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। हर समय उपलब्ध होने की इस आदत ने एक और नुकसान किया है। हमने अपने रिश्तों में भी एक सतही हड़बड़ी ला दी है। सोचिए - अगर आपका मन हर पांच मिनट में किसी संदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह कभी एकाग्र कैसे हो पाएगा? हमने अपने अंदर एक ऐसा अलर्ट सिस्टम बसा लिया है, जो लगातार सोचता है -

'कहीं किसी ने कुछ भेजा तो नहीं?'
'कहीं मैं लेट तो नहीं रिप्लाई कर रहा?'
'कहीं मुझे नज़रअंदाज तो नहीं किया गया?'

यह बेचैनी अब उत्पादकता के रूप में छुपी हुई है। हमें यह समझना होगा कि हर समय उपलब्ध रहना कोई सद्गुण नहीं है। बल्कि कभी-कभी अनुपलब्ध होना भी आत्म-संरक्षण है। जब आप सब कुछ और सबको एक्सेस देते हैं, तो धीरे-धीरे आप खुद अपने आप से एक्सेस खो देते हैं। कुछ पल ऐसे होने चाहिए दिन में जब फोन साइलेंट हो। जब आपकी आवाज सिर्फ आपके मन को सुनाई दे। समय आ गया है कि यह तय करें कि हम कब, किसके लिए, कितनी देर के लिए उपलब्ध होंगे। क्योंकि अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे, तो एक दिन आपके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए...

कभी-कभी फोन को नीचे रखिए,
खिड़की के पास बैठिए,
कोई जवाब मत दीजिए
बल्कि अपने भीतर के प्रश्नों को सुनिए।

यकीन मानिए - जो लोग सबसे गहराई से जुड़े होते हैं, वे हर समय उपलब्ध नहीं होते। वे केवल सही समय पर सच्चे रूप में उपस्थित होते हैं। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की भागती दुनिया में।

ऑफ़ दि ट्रैक

टमाटर से निकला आलू

दिलीप लाल

जिस आलू को आज हम दुनिया की सबसे लोकप्रिय खाद्य फसलों में गिनते हैं, उसका जन्म एक अद्भुत प्राकृतिक संयोग से हुआ था। हालिया शोध से पता चला है कि करीब 90 लाख वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका में उभरते हुए एंडीज पर्वतों के क्षेत्र में एक प्राचीन टमाटर प्रजाति और Solanum etuberosum नामक एक बिना कंद वाली आलू जैसी जंगली वनस्पति के बीच प्राकृतिक संकरण हुआ। इसी जैविक मेल से कंद यानी आलू बनने लगे। इस सफलता में दो प्रमुख जीन की भूमिका है - एक जीन SP6A, जो टमाटर से आया जिससे कंद बना और दूसरा जीन IT1, जो S. etuberosum जिससे भूमिगत तनों की वृद्धि हुई। इस प्रकार जो पौधा जन्मा, वह इंसानों की भूख मिटाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। हालांकि आधुनिक खेती और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने आलू की पुरानी किस्मों को बहुत कम कर दिया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया है कि आलू की शुरुआत कैसे हुई और उसके जीन कैसे बने। उनके पास मौका है कि वे पुराने फायदेमंद गुणों को फिर से ढूंढें और आलू को मौसम में बदलाव और बीमारियों से लड़ने के लिए और मजबूत बना सकें।

ये जो रतन थियाम है, सबसे पहले इंसान है

किसी युग का युगपुरुष वह होता है जो अपने समय की मूक आकांक्षाओं को शब्द दे सके, अभिव्यक्ति दे सके। रतन थियाम अपने युग के वही युगपुरुष थे, जिन्होंने खासकर रंग-कर्म के जरिए अपने युग की, हमारे युग की आकांक्षाओं को मुखर स्वर दिया। कुछ ही दिनों पहले उनका देहावसान हुआ है। पेश है रतन थियाम का आखिरी इंटरव्यू, जो कुछ समय पहले ***मंजरी श्रीवास्तव*** *ने लिया था :*

NBT आख़िरी इंटरव्यू

रतन थियाम

■ आप नाटकों में अपने सौंदर्यबोध के लिए जाने जाते हैं। आपके हिसाब से सौंदर्यबोध क्या है? आप सौंदर्यबोध को कैसे परिभाषित करेंगे?

जिस तरह की चीज़ों को देखकर खुशियां मिलती हैं, ज़िंदगी खिल उठती है, संवेदनाएं लहरों की तरह प्रवाहित होने लगती हैं, जिसकी खुशबू से आपका चेतन एवं अवचेतन दोनों सराबोर हो उठता है, ऐसी चीज़ों को मेरे हिसाब से सौंदर्यबोध कहा जा सकता है। इसे व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। सौन्दर्यबोध के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा –

'बाम से उतरती है हसीन दोशीज़ा/ जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती है।'

■ आज के इस मशीनी और AI के युग में भी आपके नाटकों में मानवीय संवेदना और संस्पर्श बेहद प्रखर रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह कैसे?

मानवीय संवेदना और संस्पर्श जैसी चीज़ों को आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित तभी कर सकते हैं जब आप चाहत पर फोकस करें। और उस चाहत की जब आप अवधारणात्मक रूप में व्याख्या करेंगे, दूसरे शब्दों में, जब आप उसे कॉनसेप्चुअलाइज़ करेंगे तो एक आकार बनता है और वह आकार होता है सौन्दर्यबोध से परिपूर्ण मानवीय संवेदना और संस्पर्श का। शायद, मैं जाने-अनजाने चाहत को कॉनसेप्चुअलाइज़ करना जानता हूं और मेरी रचनाओं में आपको मेरी चाहत ही दिखती है। मैं एक अति भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हूं और नदी, पहाड़, झरने बल्कि कहें, प्रकृति की हर शै से प्यार करता हूं। मेरा यही प्यार आपको मेरी रचनाओं में दिखता है। सौंदर्यबोध तो वह है जो आप महसूस करते हैं। जिस गहराई से महसूस करेंगे, आपको उसके अनुरूप डिवाइस भी मिल जाएंगे। सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति के लिए भाषा तलाशना आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। लेकिन इसके बाद डिलीवर करना होता है। और हम खुद को एक साथ दो जह डिलीवर (प्रस्तुत) करते हैं, पहला मंच पर और दूसरा अपने और दर्शकों के मन में।

■ अपने सांस्कृतिक परिवेश से आप ऐसे किन तत्वों को लेते हैं जो आपको कलात्मक रूप से समृद्ध करते रहे हैंऔर आपमें सौन्दर्यबोध को ना ■ सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं बल्कि उसमें इज़ाफ़ा भी कर रहे हैं?

मेरे लिए परंपराएं एक जलप्रपात की तरह हैं जिसमें हज़ारों सालों से पानी आ रहा है। वह ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहमान है यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता चला आ रहा है। उसका एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास। उसके गौरव को नष्ट करने बीच-बीच में बड़े-बड़े पत्थर भी आ जाते हैं जिनसे हमारी ये परंपराएं टकराती रहती हैं। उन पत्थरों का नाम है – सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक तत्व। इस टकराहट के बावजूद वह जलप्रपात बहता रहता है। आज भी निरंतर टकरा रहा है पर चलता जा रहा है, निरंतर प्रवाहमान है और आदमी से यह सवाल पूछ रहा है कि आपकी पहचान क्या है, आपका परिचय क्या है। आदमी को इसका उत्तर मिलता नहीं पर वह जो पहचान है न, वही हमारी परंपराएं हैं, वही हमारी संस्कृति है। जब हम किसी से मिलते हैं तो अपने वजूद में अपनी पूरी परंपरा और पूरी आधुनिकता को साथ समेट कर मिलते हैं, अपनी पूरी संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर सामनेवाले से मुख़ातिब होते हैं। अगर इंसान को अपना परिचय और अस्तित्व बचाकर रखना है तो उसे परंपराओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए परंपराओं को मैंने अपना प्रेरणास्रोत बनाकर रखा है और उसे कई कोणों और आयामों से देखने की कोशिश की है। परंपराओं में समकालीन मूल्यों को खोजने की कोशिश की है।

> **“ जब हम किसी से मिलते हैं तो अपने वजूद में अपनी पूरी परंपरा और पूरी आधुनिकता को साथ समेट कर मिलते हैं, अपनी पूरी संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर सामनेवाले से मुख़ातिब होते हैं। अगर इंसान को अपना परिचय और अस्तित्व बचाकर रखना है तो उसे परंपराओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा**

■ निर्देशक रतन, चित्रकार रतन, कवि रतन और एक आम मणिपुरी रतन में आप किन स्तरों पर, किस तरह का फर्क पाते हैं?

ये रतन थियाम भी सोचता रहता है कि एक आम या सामान्य आदमी बनना सबसे बड़ी बात होती है। फिर अगर वह एक पेंटर बनना चाहता है तो वह दुनिया की हर चीज़ को अपने कैनवस पर उतारना चाहता है और वही कैनवस स्पेस और स्टेज (मंच) बनकर उसके सामने आ जाता है, जब वह निर्देशक बनता है। इन दोनों के बीच से जब पोएट या कवि रतन निकलता है तो उसकी सारी कल्पनाशीलता, रंग, शब्द और लयात्मकता या यूं कहें कि उसकी सारी चीज़ों में एक संगीत उत्पन्न हो जाता है तब कहीं जाकर वह एक मुकम्मल रतन थियाम बनता है। मैं कहूंगा, अगर कलाकार होना है तो इंसान होना बहुत ज़रूरी है। कलाकार वह नागरिक होता है जो अपने आसपास के लोगों के बारे में विचार करता है। इसीलिए यह जो रतन थियाम है न, यह सबसे पहले इंसान है, एक आम नागरिक है। एक आम नागरिक जो करता है वह सबकुछ करता है यह रतन थियाम, और अपने सारे कलात्मक प्रयासों को स्वयं में स्थानांतरित करता रहता है और खुद को समृद्ध करता रहता है।

www.nbt.in

प्यारे मौसम में उदास बच्चे

खुद अपनी आंख से

नमिता जोशी

एक ज़माना था... हमारा स्कूल था संजय बाल विद्यालय, वो आलीशान इमारत नहीं था... एक टेंट था। सच्ची में! पूरा स्कूल एक बड़े से तंबू जैसा लगता था, जिसमें छत के साथ-साथ हमारे सपने भी थोड़े-थोड़े टपकते थे। बरसात के दिन हमारे लिए त्योहार जैसे होते थे। घर से निकलते ही बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़तीं और मन में एक ही सवाल गूंजता - आज पढ़ाई होगी या टेंट से पानी क्लास के अंदर आ जाएगा? और जैसे ही टप-टप पानी गिरता, हम बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। प्रेयर से पहले ही प्रिंसिपल की तरफ से ऐलान होता- बच्चो, आज स्कूल बंद! उस पल जो खुशी मिलती थी, वैसी तो गर्म समोसे में पड़ी हरी मिर्च खा कर भी नहीं मिलती! और अगर गलती से लंच तक स्कूल चल गया और उसके बाद बारिश शुरू हुई तो बस समझो क्लासरूम में पढ़ाई की जगह पानी की नावें चलती थीं और टीचर भी हार मान जाती थीं: जाओ, जाओ! खेल लो, आज का दिन गया। कभी कभी ये भी होता था कि क्लास का नया टेंट लगा हो या हाल ही में रिपेयर हुआ हो तो समझो बच्चों की शरारतें भी नए मोड़ पर आ जाती थीं। ये भी कोई बात हुई कि टेंट नया हो और बारिश में पानी अंदर न आए? ये तो हमारी 'बचपन की प्लानिंग' के खिलाफ था! तो कुछ बच्चे मिलकर, टीचर की नज़र बचाकर उस टेंट में छोटा सा छेद कर देते थे। फिर दुआ करते थे कि तेज़ बारिश हो ताकि टपकन शुरू हो जाए और पढ़ाई बंद। और जैसे ही पानी अंदर घुसता, प्लान बी एक्टिवेट हो जाता। दो-तीन क्लास के बच्चों को एक साथ किसी एक कोने वाले टेंट में ठूंस दिया जाता। अब पढ़ाई कहां होती? वहां तो मस्ती का अखाड़ा लग जाता! कोई कोनों में बैठकर चुपचाप कहानियां सुनाता, कोई दोस्तों के कान में जोक्स फुसफुसाता और कोई बस्ते को तकिया बनाकर झपकी लेने की कोशिश करता।

फिर जैसे ही बारिश थमती, छुट्टी की घंटी बजती। मतलब पढ़ाई का आधा दिन गया पानी में! भीगे जूते, गीले कपड़े और हाथ में मिट्टी लगे लंचबॉक्स के साथ हम घर लौटते। लेकिन असली चालाकी तो अगले दिन की छुट्टी पक्की करने में होती थी। सुबह उठते ही ऐलान - मम्मी, मेरे जूते नहीं सूखे! और मम्मी भी समझ जाती थीं कि आज कोई स्कूल जाने वाला मूड नहीं है। लेकिन आज सुबह बेटे अबीर को स्कूल बस तक छोड़ने गई, तो देखा... इतने प्यारे मौसम में एक भी बच्चा मुस्कुराता नहीं दिखा। सब चुपचाप बस में बैठ गए- AC वाली, स्लाइडिंग दरवाज़ों वाली बिल्डिंग स्कूल की बस में। इन बच्चों के हिस्से में कोई Rainy Day नहीं आता...और तब जाकरउस पुराने टपकते टेंट की कीमत समझ आई है... वो जो छुट्टियां बिना reason के मिलती थीं, दरअसल वही सबसे बड़ी reason थीं हमारी खुशी की। सबसे बड़ी छुट्टी वही होती है, जो बिना मांगे मिल जाए। और सबसे बड़ा स्कूल वो, जो बच्चों को भीगने की आज़ादी दे।

चलते-चलते...

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन में ऐसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस A एजेंट तैयार किए जो गलती करने पर खुद को दंडित करते थे। हालांकि ये भावनाएं इंसानों जैसी नहीं हैं, पर यह दिखाता है कि सामाजिक भावना जैसी विशेषताएं AI में व्यवहारिक रूप से संभव हैं। रॉयल सोसायटी इंटरफेस में यह रिसर्च हाल ही में प्रकाशित हुई है।

रीडर्स मेल

▶ जवाबदेही तय हो

1 अगस्त का संपादकीय 'अपराध किया किसने' मालेगांव बम विस्फोट केस में आए हालिया अदालती फैसले में जांच एजेंसियों की गंभीर विफलताओं को उजागर करता है। 17 साल बाद जब अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, तो इससे स्वाभाविक ही न्याय प्रक्रिया और अभियोजन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। कोर्ट की टिप्पणियों से साफ है कि जांच के हर स्तर पर लापरवाही हुई। यह न केवल पीड़ितों के साथ अन्याय है, बल्कि न्याय प्रणाली में आमजन के भरोसे को भी कमजोर करता है। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह विचार होना चाहिए कि पीड़ितों को कैसे न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही जांच एजेंसियों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

मृदुल रावत, ईमेल से

▶ सही आंकड़े सामने आएंगे

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। प्रक्रिया से निर्वाचक की पात्रता का भौतिक सत्यापन भी हो जाएगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध या दोहरी नागरिकता प्राप्त लोगों का सही आंकड़ा पता चल सकेगा। असली चुनौती तो उन इलाकों में है, जहां मतदाता पलायन कर गए हैं। चुनाव-सुधार और धनबल-बाहुबल के खिलाफ वोटरों को सजग करने के लिए यह एक निष्पक्षीय कदम है। इस प्रक्रिया से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। साथ ही अन्य राज्यों में भी यह कार्य करने के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शनिवार • 2 अगस्त • 2025

www.rashtriyasahara.com

सत्रह साल बाद राहत

करीब सत्रह साल पहले हुए मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सातों अभियुक्तों को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने बरी कर दिया है। इस घटना में सात जान गई थीं और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में 323 गवाहों से पूछताछ की गई जिनमें से 37 बयान से मुकर गए। अदालत ने कहा कि कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता। अदालत सिर्फ धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने की बात कहते हुए अदालत ने जांच की खामियों को उजागर किया और आरोपियों को संदेह का लाभ पाने की हकदार बताया। सितम्बर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिलों में रखे विस्फोटकों में हुए धमाकों की जांच शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक

दस्ता कर रहा था जिसे 2011 में एनआईए को सौंप दिया गया था। अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई लोकल ट्रेन में हुए विस्फोट के मामले में बरी सभी अभियुक्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अदालत द्वारा संदेह का लाभ देना और ठोस सबूत देने में सफल न होने को इंगित करना बेशक, न्याय के दायरे में आता है। मगर असल सवाल तो ज्यों का त्यों है कि बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर, कौन है। साक्ष्यों, विश्वसनीय प्रमाणों व प्रत्यक्षदर्शियों के अतिरिक्त अन्य एंगल से जांच करने में कोताही क्यों और किसके कहने पर की गई। अगर यह जानबूझकर हुआ तो इसके पीछे किसकी साजिश थी, और मंशा क्या थी। ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इन दोनों विस्फोटों की घटनाओं की बुनियाद में दबे हैं, जिन्हें अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता। हिन्दुत्ववादी संगठनों और धार्मिक चोला ओढ़ने वालों पर लगाए गए आरोपों के पीछे की साजिश का परत-दर-परत खुलासा किया जाना देश और समाज के हित में होगा। बरी किए गए अभियुक्तों पर लगाई गई मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धाराएं 2017 में ही हटाए जाने के पीछे का मकसद समझना भी पेचीदा है। इतने लंबे वक्त में विस्फोटों में इस्तेमाल आरडीएक्स का स्रोत जांच एजेंसियां क्यों नहीं ढूंढ पाईं। साजिश रचने के आरोपों में हुईं बैठकों से संदिग्ध मसौदा या साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद मामले को तूल किसके कहने पर दिया गया। विस्फोट हुआ इसमें संदेह नहीं है तो असल अपराधियों की धरपकड़ के प्रति न्याय प्रक्रिया को कड़ाई से पक्षपात के बगैर कदम उठाना होगा।

शरणार्थी या घुसपैठिए

उच्चतम न्यायालय ने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा है। सवाल तो केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से पूछा गया है लेकिन शायद इस सवाल पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित हम सभी को विचार करना है क्योंकि मनुष्य को मनुष्य समझना ही सब भूलते जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि पहले यह तय होना चाहिए कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं, या घुसपैठिए। बाकी मुद्दे बाद में तय कर लिए जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिह की पीठ ने देश में रोहिंग्याओं से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि पहला महत्त्वपूर्ण मुद्दा सरल है, क्या वे शरणार्थी हैं, या अवैध रूप से प्रवेश करने वाले घुसपैठिए। पीठ ने पूछा, क्या रोहिंग्या शरणार्थी घोषित किए जाने के हकदार हैं? अगर हां, तो उन्हें कौन-सी सुरक्षा, विशेषाधिकार या अधिकार हासिल हैं? पीठ ने आगे पूछा

कि दूसरा मुद्दा यह है कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं, और घुसपैठिए हैं, तो क्या उन्हें निर्वासित करने की केंद्र और राज्य सरकारों की कार्रवाई उचित थी।अगर रोहिंग्याओं को अवैध घुसपैठिया माना भी गया है, तो क्या उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकता है या फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है बशर्ते अदालत उन पर ऐसी शर्तें लगाए जिन्हें वह उचित समझे? पीठ का यह सवाल भी काबिलेगौर है कि क्या उन रोहिंग्याओं, जिन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है और जो शरणार्थी शिविरों में हैं, को पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मामले की गंभीरता देखते हुए पीठ ने याचिकाओं को तीन समूहों में विभाजित किया। पहला, जो रोहिंग्याओं से संबंधित हैं, दूसरा, जो रोहिंग्याओं से जुड़े मुद्दों से संबंधित नहीं है, और तीसरा, जो पूरी तरह से अलग मामले से संबंधित है। तीनों समूहों की याचिकाओं का निर्धारण अलग-अलग किया जाएगा। सबसे गंभीर मामला यह है कि जिन रोहिंग्याओं को घुसपैठिया कह कर हिरासत में ले लिया जाता है, वे लंबे समय तक हिरासत में रहने को मजबूर होते हैं। हो क्या रहा है कि चुनावी राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर रोहिंग्याओं को आसान शिकार बनाया जा रहा है जबकि वे म्यांमार में जातीय हिंसा के पीड़ित और सहानुभूति के पात्र हैं।

कटाक्ष/ कबीरदास

ट्रंप है कि मानता नहीं

भई ये ट्रंप तो मान कर ही नहीं दे रहा है। मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है-मुझे पॉ पॉ कहलवाने दो! पॉ पॉ वही जो वार रुकवाए। और इस ट्रंप ने तो एक नहीं कई-कई वार रुकवाई हैं। अब तक कम से कम पांच-छह तो हो ही गई होंगी। इंडिया-पाकिस्तान की वॉर भी। अब तो विश्व पॉ पॉ कहलवाने दो। इस बार तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाने दो। दूर हटो, ऐ दुनिया वालो ये शांति का नोबेल ट्रंप का है! मोदी जी ने ट्रंप को बहुत समझाने की कोशिश की कि इंडिया-पाकिस्तान की वॉर रुकवाने की दावेदारी छोड़ दें। बाकी सब वारों को रुकवाने के दावे करता रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।

इंडिया-पाकिस्तान को छोड़ कर भी चार-पांच युद्ध रुकवाने का दावा तो वह करता रह ही सकता है। ज्यादा ही जिद करेगा तो शांति के नोबेल के लिए उसकी दावेदारी का पाकिस्तान और इस्राइल के बाद इंडिया भी समर्थन कर देगा। कम से कम मोदी जी की तरफ से इसमें उसे किसी कंपटीशन का सामना नहीं पड़ेगा। वह रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा कर पॉ पॉ कहलवाने का मामला तो यूं ही चलते-चलाते टाइप का था। उसमें ऐसी खास गंभीरता नहीं थी। हमारी तरफ से ट्रंप ही ले ले शांति का नोबेल। ट्रंप ही कहलवा ले विश्व पॉ पॉ। मोदी तो विश्व गुरु कहलाने में ही संतुष्ट है। अब वह भी न हो तो यूं ही सही। हम तो फकीर हैं जी, कभी भी झोला उठा कर विश्व गुरु के आश्रम की ओर निकल लेंगे। पर ट्रंप को कौन समझा सकता है। उसके सिर पर तो दीवानगी सवार है। चौबीस-पच्चीस बार तो बोल ही दिया होगा कि मैंने इंडिया-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया और वह भी व्यापार का लालच देकर। विपक्षियों ने बहुत हल्ला मचाया तो हार कर मोदी जी को भी संसद में कहना पड़ा कि किसी भी विदेशी नेता ने तो इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था! दूर से देखने पर ट्रंप के दावे का खंडन सा लगता था, पर था नहीं। पर ट्रंप ने दूर से ही देखा और अड़ गया, युद्ध तो मैंने ही रुकवाया। अगले दिन तक उन्तीसवीं-तीसवीं बार कह दिया कि इंडिया-पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया। 25 फीसद टैरिफ और लगा दिया और उसके ऊपर से रूस से व्यापार का जुर्माना भी। मोदी जी भी दोस्ती में सरेंडर नहीं करें तो या करें? ट्रंप है कि मानता ही नहीं।

अनमोल वचन

सभी लोगों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, गुणों की नहीं। सब गुणों की अपेक्षा स्वभाव ही सिर पर चढ़ा रहता है (क्योंकि वही सर्वोपरिहै)।

-हितोपदेश

तूफान से कैसे निकले किश्ती !

ट्रंप का टैरिफ

मे. जनरल (रि.) एसबी अस्थाना

30 जुलाई, 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर सीधे-सीधे 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा करके भारत को करारा झटका दिया। यह घोषणा एक अगस्त से लागू किए जाने की बात कहते हुए यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर इस बात के लिए भी जुर्माना लगाएगा कि वह रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीद रहा है।

ट्रंप अपनी घोषणा को यह कह कर तार्किक ठहरा रहे हैं कि भारत 'बेहद ज्यादा टैरिफ' लगाता है, इतना ही नहीं भारत तमाम तरह के 'मौद्रिक व्यापार अवरोधक' भी थोपे हुए है। बहरहाल, ट्रंप की घोषणा से भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका उठ खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात रूस से कारोबारी संबंध रखने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा जुर्माना लगाना है। भारत पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि वह रूस से अपने कच्चे तेल की 35 प्रतिशत आपूर्ति करता है। इस फैसले से भारत के समक्ष व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों में रक्षा संबंधी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

भारत, अमेरिका का नौवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2024 में दोनों देशों के बीच 136.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दुतरफा व्यापार (भारतीय सूत्रों के मुताबिक) हुआ था। इसमें भारत ने 91.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया जबकि अमेरिका से 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया था।

इस प्रकार भारत के लिए 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच 129.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ जिसमें भारत ने अमेरिका से 41.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पाद आयात किए जबकि अमेरिका ने भारत को 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पाद निर्यात किए। जाहिर है कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन अमेरिका को अखरता रहा है।

हालांकि, ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी आयात पर औसत टैरिफ 5 प्रतिशत से कम है, जो कि पूरी तरह से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा नियत सीमा के भीतर है। अलबत्ता, भारत व्हिस्की, शराब और ऑटोमोबाइल्स जैसे कुछ विशेष आइटमों पर उच्च शुल्क जरूर लगाता है। और इसमें बुराई भी क्या हो सकती है, जब इस प्रकार

संरक्षणवादी नीतियां अमेरिका समेत कई अन्य देश भी अपनाते हैं। भारत से अमेरिका को निर्यातित उत्पादों में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर), फार्मास्युटिकल्स (12.73 बिलियन डॉलर) और मेटल्स एंड स्टोन्स (11.88 बिलियन डॉलर) आदि शामिल हैं, जबकि अमेरिका भारत को जिन उत्पादों का निर्यात करता है, उनमें खनिज तेल (12.6 बिलियन डॉलर), कीमती स्टोन्स (5.31 बिलियन डॉलर) और मशीनरी (3.29 बिलियन डॉलर) के साथ ही सोयाबीन (2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।

ट्रंप की घोषणा से पहले भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ औसतन 2.5 प्रतिशत था, जबकि भारती शुल्क 10 से 80 प्रतिशत के बीच थे, जो क्षेत्रवार थे-सेब और चावल जैसे कृषि उत्पादों में ये लगाए जा रहे थे। कृषि और फार्मास्युटिकल्स आदि पर गैर-शुल्कीय अवरोध से काफी से अमेरिका खिन्न था। ट्रंप ने टैरिफ को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहा है जिसके जरिए वे अमेरिकी उद्योग-व्यापार को संरक्षित करना चाहते हैं।

भारत की जहां तक बात है, तो अमेरिका अपने यहां सेवा और शिक्षा क्षेत्र में भारत के योगदान को अनदेखा कर रहा है। भारत को अपने किसानों की आजीविका को बचाए रखने के लिए डेयरी उत्पादों, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही अमेरिकी आकांक्षाओं के सामने अपने हित सुरक्षित करने की चिंता है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाने से भारत के ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों पर खासा असर पड़ना निश्चित है। यहां तक भारत में असेंबल किए गए आईफोन भी महंगे हो जाएंगे। एक आकलन के मुताबिक, भारत से इन उत्पादों का निर्यात ट्रंप के टैरिफ से 50 प्रतिशत तक गिर जाएगा यानी भारत को सीधे-सीधे 3 बिलियन ऐमरिकी डॉलर का नुकसान होगा। भारत, जो 140 करोड़ की आबादी का देश है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार को दुगुना करके 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाना चाहता है। ट्रंप की घोषणा से यह लक्ष्य हासिल करना खतरे में पड़ सकता है।

अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी ट्रंप का टैरिफ भारी पड़ने वाला है। उन्हें महंगाई से दो-चार होना पड़ सकता है खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र उनके लिए महंगा हो सकता है। जेपी मार्गन के अलावा अनेक अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि इससे अमेरिकी जीडीपी 1.6 प्रतिशत मद्धिम पड़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो सकती है। चीन के बरक्स अमेरिकी प्रयासों में अमेरिका का एक इंडो-पैसिफिक साझेदार भारत उससे अलग-थलग पड़ सकता है। संभव है कि भारत, रूस-चीन-इंडिया (रिक) गठजोड़ के करीब बढ़ निकले। भारत वैश्विक पटल पर अपने बाजार को आसियान, ईयू के साथ ही अफ्रीका तक फैला सकता है।

इसके अलावा, भारत रक्षा और टेक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को यकीनन तेज करेगा। कोविड में जिस तरह भारत ने आपूर्ति श्रृंखला का जिस तरह से स्थानीयकरण किया था, उस अनुभव ने भी भारत को काफी मदद मिल सकती है। भारत के सामने एक विकल्प यह भी है कि वह अमेरिकी घोषणा का कड़ा जवाब दे। बेशक, यह उपाय प्रतिगामी होगा लेकिन संप्रभुता और भावी परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए जरूरी है। भारत तूफान के वेग को भांप कर मजबूत बन कर उभरने में सक्षम है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र, सुधार और राष्ट्रीय संकल्प के बल पर भारत अस्थिरता के इस तूफान से अपनी किश्ती निकाल ले जाएगा।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी ट्रंप का टैरिफ भारी पड़ने वाला है। उन्हें महंगाई से दो-चार होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र उनके लिए महंगा हो सकता है। जेपी मार्गन व अनेक अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि अमेरिकी जीडीपी 1.6 प्रतिशत मद्धिम पड़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। चीन के बरक्स अमेरिकी प्रयासों में अमेरिका का इंडो-पैसिफिक साझेदार भारत उससे अलग-थलग पड़ सकता है। संभव है कि भारत, रूस-चीन-इंडिया (रिक) गठजोड़ से जा जुड़े

संक्रमण रोकने और सेहत बनाए रखने में मददगार 'शिरीष'

- शिरीष के फल, फूल, पत्तियां न केवल इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि इनके औषधीय गुण भी शरीर और मस्तिष्क, दोनों के लिए लाभकारी हैं। शिरीष के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो शरीर में संक्रमण रोकने और सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं
- सुश्रुत संहिता में शिरीष के फूलों और पत्तियों का उल्लेख विभिन्न रोगों के उपचार के रूप में किया गया है। चरक संहिता में शिरीष के फूलों को शरीर के भीतर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए प्रभावी औषधि माना गया है

(मीडिया इनपुट्स)

मृत अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्ता विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो 6.5 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है। इसका राष्ट्रीय ऋण भी कम है जबकि अमेरिका पर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। छपते डॉलर के पीछे छिपे आप ब्रिक्स से डरे हुए हैं जो अमेरिकी डॉलर को तेजी से छीज रहा है, और आपको 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना ही होगा।

मिन्हाज मर्चेंट, लेखक
@MinhazMerchant

रूस में जापान जैसा कहर

सुनामी | **प्रमोद भार्गव**

तीन साल से भी अधिक समय से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस में 8.8 तीव्रता के भीषण भूकंप ने नई त्रासदी खड़ी कर दी है। रूस के पूरब में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में 30 जुलाई, 2025 को आए भूकंप के झटकों से कामचटका और पास के कुरील द्वीप समूह के भूखंड हिल गए। इसे विश्व में आए सबसे तीव्र भूकंपों में दर्ज किया गया है। इस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान और अनेक लोगों के घायल होने की सूचनाएं हैं। इसके असर से प्रायद्वीप के समुद्र तटों से 16 फीट ऊंची सुनामी जैसी लहरें टकराईं जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इसकी तुलना मार्च, 2011 में जापान में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप से की जा रही है। इसे समुद्री सुनामी कहा गया था। इस सुनामी से जापान के फुकुशिमा, दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कूलिंग सिस्टम निष्क्रिय करना पड़ा था।

अलास्का स्थित राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र के समन्वयक डेव स्नाइडर का कहना है कि सुनामी जैसी लहरों का प्रभाव कई घंटों या एक दिन से भी अधिक समय तक रह सकता है। सुनामी केवल एक लहर नहीं होती, बल्कि यह लंबे समय तक चलने वाली शक्तिशाली लहरों की एक श्रृंखला होती है। सुनामी एक विमान की गति से सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र पार करती है किंतु जब लहरें किनारे के निकट पहुंचती हैं, तब उनकी गति धीमी पड़ जाती है किंतु किनारे पर इनके एकत्रीकरण से जल प्रलावन की आशंका बढ़ जाती है। इस कारण पानी की ये लहरें धरती पर पहुंचती हैं, और आगे-पीछे होती रहती हैं।

दुनिया में अब तक 8.6 तीव्रता से 9.5 तीव्रता के भूकंप चिली, अलास्का, सुमत्रा, तोहोकू, कामचटका (1952), चिली (2010), इक्वाडोर, अलास्का (1965), अरुणाचल प्रदेश भारत और सुमात्रा (2012) आए हैं। इनमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।

दरअसल, दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों व पर्यावरणविद् की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में हमारा भी हाथ होता है। प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 सालों में एक बार भूकंप आने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब यह घट

कर 4 साल हो गई है। भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है, उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हुई है। 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में जो भूकंप आया था, उससे 20 थर्मान्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। यहां हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा-नागाशाकी में गिराए गए परमाणु बमों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। 2011 में जापान और फिर क्योटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चलता है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रहीं भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भी भूकंप के मुहाने पर हैं।

भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। जापान, इक्वाडोर और नेपाल समेत पूरी दुनिया इस अभिशाप को झेलने के लिए जब-तब विवश होती रही है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए।

प्राकृतिक आपदाएं अब व्यापक व विनाशकारी साबित हो रही हैं क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडल भी परिवर्तित हो रहा है। अमेरिका व ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में दो शताब्दियों के भीतर बेतहाशा अमीरी बढ़ी है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण इसी अमीरी की उपज हैं। यह कथित विकासवादी अवधारणा कुछ और नहीं, प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन कर पृथ्वी को खोखला करने का ऐसा उपाय है, जो ब्रह्मांण्ड में फैले अवयवों में असंतुलन बढ़ा रहा है। इस विकास के लिए पानी, गैस, खनिज, इस्पात, ईंधन और लकड़ी जरूरी हैं। नतीजतन, जो कॉर्बन गैसें बेहद न्यूनतम मात्रा में बनती थीं, वे अब अधिकतम मात्रा में बनने लगी हैं। न्यूनतम मात्रा में बनी गैसों का शोषण और समायोजन भी प्राकृतिक रूप से हो जाता था, किंतु अब वनों का विनाश कर दिए जाने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में इकतराफा दबाव बढ़ रहा है। इस कारण धरती पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी प्रत्यावर्तित होने की बजाय धरती में ही समाने लगी है। गोया, धरती का तापमान बढ़ने लगा जो जलवायु परिवर्तन का कारण तो बना ही, प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन रहा है।

नेतृत्व | **संत राजिन्दर**

आज के आधुनिक युग में अगर देखें तो युवाओं में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जिससे कि समाज में उनकी एक अलग से पहचान बने। वे चाहते हैं कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुना जाए और इसके साथ-साथ वे यह भी चाहते हैं कि उस बात पर अमल भी किया जाए लेकिन यहां वे अक्सर भूल जाते हैं कि जागरूक नेता बनने के लिए केवल उत्साह, प्रेरणा, कुशलता और चीजों को करने की किताबी जानकारी होना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर कोई कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, और अगर ठीक तरीके से हो रहा है, तो उसे और बेहतर किस प्रकार से किया जा सकता है? इन सबकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक कुशल नैतिक नेतृत्व के सभी पहलुओं का बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करके उसे अपने जीवन में ढालना होगा। नैतिक नेतृत्व के दो मुख्य पहलू हैं : खुद को सही रूप में जानना; और दूसरों की सेवा करना। एक सच्चे नेता को सबसे पहले खुद की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहां खुद की जानकारी से तात्पर्य अपने अंदर नैतिक गुणों का विकास करते हुए दूसरों की सेवा करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो लोग हमारा अनुसरण करेंगे, उन्हें भी हमारे व्यवहार से मार्गदर्शन प्राप्त होगा क्योंकि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, उन्हें वह हमारे आचरण में भी झलकता हुआ दिखाई देगा। यह बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि समाज में जो हम कहते हैं लोग उस पर नहीं, बल्कि जो हम करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारे अंदर एक सच्चे नेता के रूप में अच्छा व्यवहार करने के साथ-साथ हमारी आदतें, हमारे दिल और दिमाग का सही दिशा में होना बहुत ही जरूरी है। एक सच्चे नेता में अपने अस्तित्व का सही मकसद सामने रखने का साहस होना चाहिए। उसमें ऐसा जीवन व्यतीत करने का साहस होना चाहिए जो दूसरों के लिए मददगार हो। ऐसा नेतृत्व ही संगठित और नैतिक नेतृत्व कहलाता है। असल मायने में यह जीवन का नेतृत्व है। ऐसे नेता अपने अंतर में जाकर खुद का निरीक्षण करते हैं। वे अपने अंतर में पिता-परमेश्वर की ताकत से जुड़ कर दूसरों में उत्साह-हिम्मत की भावना फैलाते हैं।

रीडर्स मेल

एसआईआर पर भाजपा की नीति

भारत की सबसे बड़ी, सबसे अमीर एवं सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बीजेपी, एक ही देश के दो अलग अलग राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए अलग-अलग नीति को क्यों अपना रही है? बिहार में जब चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड को अमान्य दस्तावेज घोषित कर दिया तो बीजेपी चुप रही। मगर मणिपुर की बात जब हो रही है तो वो आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज बनाने में क्यों अड़ी है? सुप्रीम कोर्ट ने दो बार बिहार में एसआईआर के लिए आधार और वोटर कार्ड को शामिल करने की सलाह दी है लेकिन आयोग ने उस सुझाव को मानने से मना कर दिया। वहीं, चुनाव आयोग मणिपुर में वो बीजेपी के आग्रह को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जब आधार कार्ड को आप बिहार में नहीं मान रहे तो कहीं भी मत मानिए। अगर आप हर राज्य के लिए अलग-अलग दस्तावेज को मंजूरी देते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप मतदाता सूची में सुधार नहीं कर रहे, बल्कि उन मतदाताओं को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, जो फिरकापरस्ती एवं धार्मिक कट्टरवाद का विरोधी हैं। आप उस हर मतदाता का मताधिकार छीनना चाहते हैं, जो संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है।

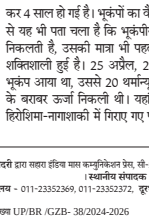

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

एलटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दोष

लोक सेवा आयोग (उत्तर प्रदेश) ने राजकीय विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक के शिक्षकों, जिन्हें एलटी ग्रेड शिक्षक कहा जाता है, के 7466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है जिसमें परीक्षा दो चरणों में (प्री वस्तुनिष्ठ व मेन्स विस्तृत लिखित) होगी। ऐसा आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है जबकि पिछली एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में केवल एक ही स्तर की परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) ली गई थी तथा परीक्षा का स्तर इतना कठिन था कि कुल पदों के सापेक्ष बहुत अधिक संख्या में सीट्स खाली रह गई थीं। इस बार परीक्षा वस्तुनिष्ठ के साथ-साथ विस्तृत भी है तो परीक्षा उत्तीर्ण करना स्वप्न जैसा होगा। आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि कुल पदों के सापेक्ष 15 गुना विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे जो संख्या में 111990 बैठते हैं। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की कॉपी जांचने में अनियमिता होने की आशंका है। छात्रों की मांग है कि या तो आयोग एक ही स्तर पर परीक्षा कराए या मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही हो ताकि परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता आए।

चंद्रकांत कुआंखेड़ा, सहारनपुर

भारत-ब्रिटेन समझौता लाभप्रद

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे देश के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। यह एक असाधारण डील है। दुनिया की चौथे और पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था के बीच मुक्त व्यापार के कारण एक सामंजस्य विकसित होगा। भारत के छोटे उद्योगों के उत्पादों की खपत में वृद्धि होगी। लोगों को रोजगार मिलेगा। इस समझौते से कृषि, दवा, फुटवियर, ज्वेलरी, खिलौने और टेक्सटाइल जैसे अनेक क्षेत्रों में भारतीय व्यापार को फायदा मिलेगा। इस समझौते में टैरिफ में कमी, व्यापार के लिए सरल नियम, सेवाओं के लिए मजबूत प्रावधान और व्यावसायिक गतिशीलता को आसान बनाने वाले उपाय भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अस्थिरता से कुछ राहत भी मिलेगी।

ललित महालकरी, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

वर्ष-34, अंक 345

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

दल-बदल और लोकतन्त्र !

भारत के लोकतन्त्र में दल-बदल ऐसी लाइलाज बीमारी बन चुका है जिसकी वजह से राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में लगातार गिरावट आयी है। इस बारे में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी बहुत सामयिक व महत्वपूर्ण है कि दल-बदल लोकतन्त्र के लिए खतरा है। दुनिया में कोई भी लोकतन्त्र वैचारिक स्वतन्त्रता के बिना नहीं चल सकता है। अपने वैचारिक सिद्धान्तों के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं और उन्हीं के आधार पर आम जनता के बीच जाकर उससे समर्थन मांगते हैं। जनता उन पर विश्वास करके ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावों में हराती-जिताती है। मगर जब विजयी होकर ये प्रतिनिधि सत्ता के मोह में दल-बदल करते हैं तो जनता हैरान रह जाती है। दरअसल यह मामला राजनीति में सीधे अवसरवाद से जुड़ा होता है जिसमें वैचारिक प्रतिबद्धता दूसरे पायदान पर पहुंच जाती है। सत्ता के लिए विचारों को तिलांजलि दे देना ही अवसरवाद कहलाता है। भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए स्व. राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान 80 के दशक में एक कानून संसद ने बनाया जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा गया।

इस कानून के तहत किसी भी दल के सदस्य तभी किसी दूसरे दल में प्रवेश कर सकते थे जबकि वे अपने दल के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई हों। मगर इस कानून के चलते भी छोटे-छोटे दलों से दूसरे दलों में पलायन नहीं रुका तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान यह संख्या एक-तिहाई से बढ़ाकर दो-तिहाई कर दी गई। इससे दल-बदल करना थोड़ा मुश्किल तो हो गया मगर इसका तोड़ भी निकाल लिया गया। यह तोड़ 2000 के करीब गोवा राज्य से निकला जब दल बदलने को आतुर कुछ विधायकों का इस्तीफा दिलवा कर विधानसभा की कुल सदस्य शक्ति में कमी इस प्रकार कराई गई कि सत्ताधारी दल का बहुमत कम हुई सदस्य शक्ति के आधार पर बना रहे। इसके साथ ही दल-बदल कानून में यह प्रावधान किया गया कि अपना दल बदलने वाले सदस्यों की सदस्यता के बारे में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को ही होगा। यह प्रावधान संविधान की दसवीं अनुसूची में डाल दिया गया जिससे अध्यक्ष के इस अधिकार को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। मगर इसका तोड़ भी निकाल लिया गया और यह तोड़ अध्यक्ष को मिले असीमित अधिकार के तहत ही निकाला गया। कानून में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि अध्यक्ष किस समय सीमा के भीतर दल-बदल करने वाले सदस्यों की सदस्यता का फैसला करेंगे। इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष पर ही छोड़ दी गई कि वह अपनी सुविधा के अनुसार इस बारे में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करें।

> **इस कानून के तहत किसी भी दल के सदस्य तभी किसी दूसरे दल में प्रवेश कर सकते थे जबकि वे अपने दल के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई हों। मगर इस कानून के चलते भी छोटे-छोटे दलों से दूसरे दलों में पलायन नहीं रुका तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान यह संख्या एक-तिहाई से बढ़ाकर दो-तिहाई कर दी गई। इससे दल-बदल करना थोड़ा मुश्किल तो हो गया मगर इसका तोड़ भी निकाल लिया गया। यह तोड़ 2000 के करीब गोवा राज्य से निकला जब दल बदलने को आतुर कुछ विधायकों का इस्तीफा दिलवा कर विधानसभा की कुल सदस्य शक्ति में कमी इस प्रकार कराई गई कि सत्ताधारी दल का बहुमत कम हुई सदस्य शक्ति के आधार पर बना रहे।**

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई व ए.जी. मसीह की दो सदस्यीय पीठ ने तेलंगाना राज्य के दस भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में दल-बदल करके प्रवेश करने सम्बन्धी याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यह काम भारत की संसद का है कि वह विचार करे कि इस मामले में चुने हुए सदनों के अध्यक्षों को जो अधिकार दिये गये हैं क्या वे दल-बदल को रोकने में सक्षम और उपयोगी हैं? यह स्थिति इसीलिए पैदा हुई है कि तेलंगाना के दस विधायकों ने अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति से 2023 में राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस में दल-बदल की घोषणा की थी। इसके खिलाफ भारतीय राष्ट्र समिति ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रार्थना की कि इन सभी की सदस्यता रद्द की जाये। मगर अध्यक्ष महोदय ने सात महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक सम्बन्धित विधायकों को नोटिस तक जारी नहीं किया। जबकि दल-बदल कानून में अध्यक्ष को अयोग्यता के बारे में निर्णय करने का अधिकार इसीलिए दिया गया था क्योंकि ऐसी याचिकाओं के न्यायालय में दायर होने की वजह से बहुत समय लगता था। अत: सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मामले में अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर मामले को निपटाने का प्रयास करें। विद्वान न्यायमूर्तियों ने संसद को भी आगाह किया है कि वह अध्यक्ष को मिले अधिकारों की समीक्षा करे और कारगर कदम उठाये। सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना पूरी तरह उचित है क्योंकि पिछले तीस सालों में जिस तरह दल-बदल कानून का विभिन्न राज्यों में तोड़ निकाला गया है वह विस्मित करने वाला है। जब दल-बदल कानून नहीं था तो सत्तर के दशक तक राज्यों में सरकारों का भविष्य दल बदल पर टिका हुआ माना जाता था। साठ के दशक में 1967 के चुनावों के बाद निर्दलीय व कुछ अन्य पार्टियों के सदस्य भी सुबह से शाम के बीच ही दल-बदल लिया करते थे। इसका पहला उदाहरण 1956 में ओडिशा में देखने को मिला था जब तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री नवकृष्ण चौधरी की कांग्रेसी सरकार दैनन्दिन के आधार पर बहुमत खो और पा रही थी। इससे तंग आकर तब तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पार्टी के कद्दावर नेता स्व. डॉ. हरेकृष्ण मेहताब से राज्य की राजनीति की बागडोर संभालने की विनती की थी। उस समय डॉ. मेहताब मुम्बई के राज्यपाल थे। डॉ. मेहताब ने मुख्यमन्त्री बनते ही दल-बदल का मुकाबला करने के लिए राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखकर अपनी सरकार बचाई थी। इसके बाद 1967 में जब देश के नौ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो दल-बदल का बाजार बहुत गर्म हुआ था और हरियाणा में 'आया राम-गया राम' का मुहावरा चल निकला था। मगर पिछले तीस सालों में दल-बदल कानून के विद्यमान रहने के बावजूद दल बदल के नये-नये तरीके ईजाद किये गये और इसके सहारे नई-नई सरकारें तक गठित की गईं।

ट्रंप करता टैरिफ वार है

गीता पाढा

"अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में तनाव और खींचतान बरकरार है,
तो कोई युद्धों से जूझते देशों के बीच मध्यस्थता
करवाने का श्रेय लेने को तैयार है,
बंदूकें, बम और मिसाइलें तब लगती बेकार हैं
जब दुश्मन सीमा पर नहीं,
बल्कि सोच समझकर करता किसी भी
देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार है,
यह 25% भारी टैरिफ का वार है,
जो ले आया भारतीय बाजार में हाहाकार है...।"

पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिन्दूर पर संसद के दोनों सदनों में हुई गर्मागर्म बहस के दौरान जिस प्रकार पाक अधिकृत (गुलाम) कश्मीर का मुद्दा उठा उससे एक बार फिर साबित हो गया कि भारत कश्मीर के इस हिस्से को लिये बिना चैन से नहीं बैठेगा। वैसे तकनीकी तौर पर देखा जाये तो यह हिस्सा भारतीय संघ का आज भी हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने 1948 में हड़प लिया था। कश्मीर में पाकिस्तान की स्थिति एक आक्रमणकारी देश की है, यह भी 1949 में भारत ने राष्ट्रसंघ में सिद्ध कर दिया था। जम्मू-कश्मीर रियासत के 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समय जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपने सशस्त्र कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने भेजा था उसकी पोल भी राष्ट्रसंघ में 1949 में खुल गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था कि उसकी सेनाओं ने भी कश्मीर के मोर्चे पर भारत की सेनाओं का मुकाबला किया था। मगर दिसम्बर 1947 में ही भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू इस मसले को लेकर राष्ट्रसंघ में चले गये थे जिसकी वजह से कश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय करण हो गया था।

इसके बाद राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद ने 1948 में हस्तक्षेप किया और 30 दिसम्बर 1948 को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई मगर तब तक कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसके बाद जनवरी 1949 में राष्ट्रसंघ ने पूरे जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह इसके द्वारा नियुक्त आयोग की निगरानी में कराने का प्रस्ताव पारित किया। पं. नेहरू ने ही शुरू में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव किया था। 7 जनवरी 1949 को आयोग ने जनमत संग्रह कराने की शर्तों को प्रकाशित भी कर दिया। उस समय नेशनल कान्फ्रेंस के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमन्त्री थे। पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि जनमत संग्रह से पूर्व शेख अब्दुल्ला की सरकार को पदमुक्त किया जाये और रियासत में तैनात भारतीय सेना को भी हटाया जाये। मगर भारत ने इन दोनों शर्तों को मानने से इंकार कर दिया था। मूल प्रस्ताव में यह शर्त थी कि पाकिस्तान गुलाम कश्मीर से अपनी सेनाएं हटायेगा और भारत को यह हक होगा कि वह चुनाव या जनमत संग्रह कराने के लिए आवश्यक सरकारी अमला व फौज को रखे। उस समय के अखबारों में 8 जनवरी 1949 को छपा था कि ''संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ने जनमत संग्रह की शर्तों को प्रकाशित कर दिया है जिसके आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि जम्मू-कश्मीर रियासत भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ शामिल होगी। आयोग की शर्तों से स्पष्ट हो जाता है कि जनमत संग्रह पूरी तरह निष्पक्ष व स्वतन्त्र होगा। जब पं. जवाहर लाल नेहरू ने जब शुरू में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था तो उहोंने किसी मानसिक संकोच या दुराव-छिपाव से काम नहीं लिया था'। कमीशन के प्रस्ताव में यह शर्त भी थी कि जनमत संग्रह व्यवस्थापक को राष्ट्रसंघ ही मनोनीत करेगा मगर उसकी नियुक्ति की घोषणा जम्मू-कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार ही करेगी और मतसंग्रह के लिए उसे जरूरी अधिकार भी राज्य सरकार ही देगी। मत संग्रह व्यवस्थापक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऊंची ख्याति होगी और जिस पर सभी को विश्वास होगा। भारतीय फौज भी रियासत में बनी रहेगी। उसे कहां– कहां और कितनी संख्या में रखा जायेगा इसका फैसला सूबे की सुरक्षा और जनमत संग्रह की स्वतन्त्रता को ध्यान में रख कर किया जायेगा।'

पाकिस्तान चाहता था कि उसकी फौजें भी जम्मू-कश्मीर में रहे और शान्ति–व्यवस्था बनाने में उनकी भी मदद ली जाये। इसे एक सिरे से नकार दिया गया। इस घटना क्रम का यदि आज विश्लेषण किया जाये तो हम पायेंगे कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का जो इलाका हड़प रखा है वह शत-प्रतिशत रूप से भारत का ही हिस्सा है और 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में हुए इसके विलय का चीखता हुआ प्रमाण है। आज का दीगर सवाल यह है कि भारत इस इलाके को किस प्रकार भारतीय संघ में समाहित करे। इस सिलसिले में 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया जाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संविधान में यह अनुच्छेद सिर्फ जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में ही जोड़ा गया था और यह काम संविधान सभा में ही हुआ था। इसे मूल रूप में ही अस्थाई रखा गया था। इसे समाप्त करने से पिछली सरकारों के कदम डगमगाते थे क्योंकि इस सूबे के क्षेत्रीय दल इस मुद्दे पर केन्द्र से सीधे भिड़ जाते थे और धमकियां देने पर उतारू हो जाते थे। साथ ही अलगाववादी ताकतें अलग से सक्रिय हो जाती थीं। मगर वर्तमान मोदी सरकर के गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने सभी प्रकार की आशंकाओं को बरतरफ करते हुए यह ऐतिहासिक कार्य कर डाला और कश्मीर के विलय को अन्य राज्यों के समकक्ष ही रखा। इसके बाद राज्य की परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन आना शुरू हुआ। जिसकी वजह से राज्य में पर्यटकों की संख्या में साल दर साल इजाफा होता रहा। ऑपरेशन सिन्दूर पर संसद में हुई बहस के दौरान भी गुलाम कश्मीर का मामला सामने आया और गृहमन्त्री ने पुरजोर तरीक से एलान किया कि एक न एक दिन यह भारत में मिल कर रहेगा। गृहमन्त्री तो यहां तक कह गये कि कांग्रेस की सरकारों ने इसे पाकिस्तान को दिया मगर भाजपा सरकार इसे वापस लायेगी। दर असल यह संकल्प का मामला है क्योंकि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही यह प्रतिबिम्ब होता है। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को जिन्दा रखने के लिए ही अपनी सेनाओं को अभी तक पाला–पोसा है। तभी तो कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ऐसा एकमात्र देश है जिसकी सेना नहीं है बल्कि ऐसी फौज है जिसका अपना मुल्क है। इस बात का मतलब बहुत गहरा होता है जो पाकिस्तान को एक नाजायज मुल्क घोषित करता है।

पाकिस्तान ने पिछले 76 सालों के दौरान गुलाम कश्मीर के जन भूगोल को ही बदल कर रख दिया है। गुलाम कश्मीर से कश्मीरी बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। यहां के कश्मीरी लोगों के मानवीय अधिकारों को कदम-कदम पर कुचला जाता है। इसलिए रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह का यह कथन फिजूल नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आयेगा जब गुलाम कशमीर के लोग खुद भारत में मिलने की अलख जगायेंगे। दर असल पिछले 77 सालों के दौरान ऐसे भी कई मौके आये हैं जब कश्मीर समस्या का हल होते-होते रह गया। एक अवसर स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आया था। इससे पहले 1964 में भी नेहरू सरकार के दौरान ऐसा मौका आया था। पं. नेहरू ने 1964 में शेख अब्दुल्ला को नजरबन्दी से मुक्त कर पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान में उस समय जनरल अयूब का फौजी शासन था। जनरल अयूब ने शेख अब्दुल्ला का स्वागत बहुत गर्म जोशी के साथ किया था। मगर जब शेख अब्दुल्ला भारत वापस लौट गये तो उन्हें 'नेहरू का गुर्गा' भी बता डाला।

इसके बावजूद शेख अब्दुल्ला जनरल अयूब को भारत की यात्रा करने की सलाह देकर आये थे और जनरल अयूब इसके लिए राजी भी हो गये थे। 27 मई 1964 को पं. जवाहर नेहरू स्वर्ग सिधार गये। इस दिन शेख अब्दुल्ला गुलाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कह रहे थे कि कश्मीर समस्या का हल जल्दी ही निकलेगा मगर तभी उन्हें सभा के बीच में सूचना दी गई की पं. नेहरू का स्वर्गवास हो गया है। अत: वह योजना क्या थी कोई नहीं जान सका। लेकिन अब मोदी सरकार से भारत की जनता को अपेक्षा है कि गुलाम कशमीर को भारत का अंग जल्दी ही बना लिया जायेगा।

ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे 'दमदार' दिखी प्रियंका गांधी

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

ऑपरेशन सिंदूर पर गरमागरम बहस और भारत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त और शुभचिंतक माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित प्रहार के बीच संसद में यह हफ्ता काफी हंगामेदार रहा। उन्होंने न केवल भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया, बल्कि रूस से तेल और हथियार खरीदने पर जुर्माना भी लगाया, जबकि बार-बार दोहराते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया था। संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर एक दमदार भाषण देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जो उन्होंने बिना एक बार भी लड़खड़ाए शुद्ध हिंदी में दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से प्रशंसा बटोरी, यहां तक कि भाजपा सांसदों ने भी उनकी परिपक्वता और संयमशीलता के लिए निजी तौर पर उनकी सराहना की। प्रियंका गांधी ने इस अवसर के लिए लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे कई लोग सिंदूर के रंग का प्रतीक मानते थे। उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने पहलगाम में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीड़ितों और उनके परिवारों पर पड़े दर्द और दु:ख पर बात की, जब आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। यह एक ऐसा भाषण था जिसने दिल को छू लिया। जब उन्होंने पीड़ितों के नामों की सूची पढ़ी, तो भाजपा सांसदों ने तुरंत इशारा किया कि वे हिंदू थे। प्रियंका ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने बस उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वे सभी भारतीय हैं। उनके गंभीर लहजे और सहानुभूति के भाव ने हमले के लिए जिम्मेदार खुफिया विफलता के लिए सरकार की उनकी कड़ी आलोचना के प्रभाव को किसी भी तरह से कम नहीं किया। उन्होंने सत्ता पक्ष को याद दिलाया कि हालांकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चूक की ज़िम्मेदारी ली थी, लेकिन सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया है। न तो किसी को सज़ा मिली है, न ही किसी को दंडित किया गया है, और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के बाद सोनिया गांधी के भावुक होने पर तंज कसने की कोशिश का भी जवाब दिया। प्रियंका ने इसका कड़ा जवाब दिया और कहा कि उनके पिता (राजीव गांधी) की आतंकवादियों ने हत्या की थी, तब उनकी माँ ने आंसू बहाए थे।

जया बच्चन को गुस्सा क्यों आया ?

बॉलीवुड अदाकारा और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान गुस्से में थीं। उन्होंने कई बार अपना आपा खोया और न केवल उन भाजपा सांसदों पर, जो उनका विरोध कर रहे थे, बल्कि शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पर भी भड़क गईं, जो गुस्से में अभिनेत्री को शांत करने की कोशिश कर रही थीं। जब बच्चन ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों पर भारत के जवाबी हमले के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम के चुनाव की आलोचना की, तो बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि नाम ही गलत है क्योंकि आतंकवादियों ने उन महिलाओं के सिंदूर मिटा दिए थे जिनके पति 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर हमले में मारे गए थे। भाजपा सांसद खड़े होकर लगातार उन्हें टोक रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे। बच्चन का गुस्सा साफ़ दिखाई दे रहा था क्योंकि वे उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। जब चतुर्वेदी ने उन्हें शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया, तो बच्चन ने उन पर भी हमला बोला और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वे उन्हें "नियंत्रित" न करें। चतुर्वेदी शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ चुप हो गईं। बच्चन किसी तरह अपनी बात कहने में कामयाब रहीं और उन्होंने सरकार पर खुफिया विफलता और लोगों को सुरक्षित न रख पाने का आरोप लगाया।

ट्रंप ने दिया थरूर-मनीष तिवारी को बोलने का मौका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत को "मृत अर्थव्यवस्था" कहने के हालिया हमले ने विद्रोही कांग्रेस सांसदों शशि थरूर और मनीष तिवारी को ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान बोलने की अनुमति न दिए जाने पर अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया। दोनों ने इस विवाद पर अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाया, जिससे उन्हें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिली, जबकि शर्मिंदा कांग्रेस नेताओं ने उनकी टिप्पणियों को कमतर आंकने की कोशिश की। थरूर ने मोदी सरकार का बचाव किया और ट्रंप पर निशाना साधा, जबकि तिवारी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि ट्रंप की टिप्पणी भारतीय स्वायत्तता के लिए एक श्रद्धांजलि थी। उनका रुख कांग्रेस और राहुल गांधी के रुख से अलग था, जिन्होंने वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में "सच" बोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की पीठ थपथपाई थी। थरूर और तिवारी दोनों को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से रोका गया, दोनों कांग्रेस सांसद मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के लिए समर्थन मांगने के लिए विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

मुझे भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था : पूर्व एटीएस अधिकारी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी, जो 2008 के मालेगांव बम धमाके की जांच करने वाली टीम का हिस्सा थे, ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने इस निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा, मुझे फरार आरोपियों संदीप डांगे और रामजी कलसांगरा को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इसके साथ ही, मुझे मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश सीधे परमबीर सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों से आया था। मुजावर ने कहा कि उन्हें इस काम के लिए आधिकारिक तौर पर तैयार किया गया था। उनके पास 10 लोगों की टीम, पर्याप्त फंडिंग और एटीएस द्वारा एक सर्विस रिवॉल्वर भी

उपलब्ध कराया गया था। लेकिन, मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने कहा, यही वह समय था जब 'भगवा आतंकवाद' शब्द ने जोर पकड़ना शुरू किया। मुझे मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मैं ऐसा झूठ नहीं गढ़ सकता था। मैं निर्देशानुसार नागपुर में रहा, लेकिन मैंने गिरफ्तारी नहीं की क्योंकि यह नैतिक और कानूनी रूप से गलत होता। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने भागवत को गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। मुझे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में मैंने कोर्ट में सभी दस्तावेज पेश किए, जो साबित करते थे कि आरएसएस प्रमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आखिरकार, मुझे बरी कर दिया गया। अब दस साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये दस्तावेज एनआईए को भी दिए गए और अंतिम फैसले के दौरान पेश किए गए। मुजावर का यह बयान विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत द्वारा 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित भी शामिल हैं। कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सभी आरोप खारिज कर दिए। मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर, 2008 को नासिक जिले के मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास हुआ था, जब रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल पर फिक्स किए गए बम का धमाका हुआ था।

संस्कृत को संचार का माध्यम बनाने की आवश्यकता : भागवत

नागपुर, (पंजाब केसरी): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और इसे संचार का माध्यम बनाने की आवश्यकता है।

कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय में एक भवन के उद्घाटन समारोह में भागवत ने कहा कि संस्कृत को समझने और उसमें संवाद करने की क्षमता रखने में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को सरकारी संरक्षण मिलेगा, लेकिन जनता का संरक्षण मिलना भी जरूरी है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ''मैंने यह भाषा सीखी है, लेकिन मैं इसे धाराप्रवाह नहीं बोल पाता हूं। संस्कृत को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है और इस भाषा में संवाद जरूरी है।'' भागवत ने कहा कि 'आत्मनिर्भर' बनने की आवश्यकता पर सभी एकमत हैं, जिसके लिए हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का विकास करना होगा।

उन्होंने कहा, ''भाषा एक भाव है। स्वत्व कोई भौतिक चीज़ नहीं, बल्कि व्यक्तिगत है और यह भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति का स्रोत है।''आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संस्कृत को जानना, देश को समझने के समान है। भागवत ने विश्वविद्यालय में अभिनव भारती अंतरराष्ट्रीय अकादमिक भवन का उद्घाटन किया।

रेप केस मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

बेंगलुरु, (पंजाब केसरी): बेंगलुरु में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया।

जज संतोष गजानन भट ने रवन्ना को दोषी करार दिया। अदालत शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना और उसके वकील को दोषसिद्धि पर अपनी अंतिम दलीलें देने का मौका देने के बाद सजा की अवधि की घोषणा करेगी। प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और जैसे ही फैसला सुनाया गया, अदालत कक्ष में बैठे-बैठे उसकी आंखों में आंसू देखे गए और वह उन्हें पोंछते नजर आए। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गए और रो पड़े।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

75 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

जो आगे बढ़ने का जोखिम उठाते हैं, वही जान सकते हैं कि कोई कितनी दूर जा सकता है। -टीएस इलियट

बांग्लादेश की नीयत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में एक सवाल के जवाब में बेहद गंभीर व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का खुलासा किया, जो ढाका में सक्रिय एक कट्टरपंथी समूह 'सल्तनत-ए-बांग्ला' द्वारा तुर्किये के एक गैर-सरकारी संगठन के समर्थन से 'ग्रेटर बांग्लादेश' का नक्शा जारी किए जाने से संबंधित है, जिसमें भारत के भी कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथ हावी हो रहा है और अंतरिम सरकार के मुखिया के चिकन नेक और इसी तरह के दूसरे बयान सामने आते रहे हैं, उनसे बांग्लादेश की नीयत का पता चलता है। इस पृष्ठभूमि में देखें, तो ग्रेटर बांग्लादेश के विचार के पीछे एक दूरगामी भू-राजनीतिक मंशा और सांप्रदायिक उन्माद से भरी खतरनाक परियोजना के लक्षण देखे जा सकते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश का विचार दशकों पुराना है, जो कट्टरपंथी इस्लामी गुटों और बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों के बीच पनपता रहा है, लेकिन विदेशी समर्थन के साथ उसका इस रूप में सामने आना भारत की अखंडता को सीधी चुनौती है। इसे भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की समस्या से अलग करके नहीं देखा जा सकता, जिनकी आए दिन धरपकड़ हो रही है। उल्लेखनीय है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिये पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु तक पहुंच गए हैं। कुछ ही समय पहले गुजरात और दिल्ली में हुई कार्रवाई में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अभाव में यह अनुमान लगाना कठिन है कि कितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, लेकिन विभिन्न रपटें बताती हैं कि इनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। स्थानीय स्तर पर देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन घुसपैठियों की मौजूदगी ने सामाजिक-आर्थिक संतुलन पर किस तरह असर डाला है। पश्चिम बंगाल में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव इसका एक प्रत्यक्ष नतीजा है। यही नहीं, राज्यों में अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करने की शिकायतों ने स्थानीय राजनीति को और जटिल बना दिया है। अच्छी बात है कि सरकार घुसपैठियों से छुटकारे का हरसंभव प्रयास कर रही है। ग्रेटर बांग्लादेश का विचार मौजूदा जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियों की झलक देता है। इनसे निपटने के लिए कूटनीतिक सतर्कता और सामाजिक एकजुटता, दोनों स्तरों पर आगे बढ़ना होगा। यह केवल एक सीमाई मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और पहचान के खिलाफ वैचारिक चुनौती भी है, जिसे हम एकजुट होकर ही जीत सकते हैं।

अतीत की परछाइयों से बाहर निकलता भारत

दुनिया बदल रही है। ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार से दुनिया सकते में है। वैश्विक संबंधों की सुनामी में भारत ने अपने आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखते और हितों की रक्षा करते हुए अपनी भूमिका को पुन: परिभाषित किया है। यह अतीत की गलतियों और बंधनों से मुक्ति का नव दृष्टिकोण है।

बलबीर पुंज
पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

क्या भारत की आंतरिक-बाह्य नीतियां विदेश से प्रभावित हैं? लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में 'ऑपरेशन सिंदूर' को स्थगित किया। इस संदर्भ में राहुल का व्यवहार कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि वह अपने विदेश दौरों में अक्सर अमेरिका-यूरोप से भारत में 'लोकतंत्र बचाने' की गुहार लगाते हैं? राहुल की ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पाकिस्तान जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की भी मांग कर चुके हैं। जब राहुल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहें, तो मुझे आश्चर्य होता है। वैश्विक राजनीति कोई किशोरावस्था की तकरार नहीं, जिसमें व्यक्ति क्षणिक आवेश में अपमानजनक या कटु शब्दों का प्रयोग करता हो। इस तरह के गैर-जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा केवल राहुल गांधी से ही की जा सकती है, जिन्होंने वर्ष 2013 में सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के एक अध्यादेश को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी।

वास्तव में, ट्रंप के टैरिफ प्रहार और लंबित व्यापार समझौते पर भारत ने जो निर्भीक रुख अपनाया है, वह राहुल के दावे को पूरी तरह झुठलाता है। जैसे अमेरिका अपने हितों के अनुसार मित्र और शत्रु चुनने हेतु स्वतंत्र है, उसी प्रकार भारत को भी अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। शीतयुद्ध काल से रूस (तब सोवियत संघ) भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। इस ऐतिहासिक संबंध को किस दिशा में और कितनी गहराई तक ले जाना है, यह केवल भारत तय करेगा, कोई अन्य देश नहीं। भारत के इस आत्मविश्वासपूर्ण और स्वायत्त दृष्टिकोण से शेष विश्व, विशेषकर अमेरिका और यूरोप स्तब्ध हैं। दशकों तक भारत की विदेश नीति बाह्य-वैचारिक प्रभाव से संचालित होती रही, जिसके कारण भारत को बार-बार उन देशों के सामने झुकना पड़ा, जो हमारे दूरगामी हितों के विपरीत खड़े थे। वर्षों तक भारत ने फलस्तीन और इस्लामी देशों का समर्थन किया, जबकि वे कश्मीर के मुद्दे पर मजहबी कारणों से पाकिस्तान का साथ देते रहे। जब पाकिस्तान या चीन से भारत का टकराव हुआ, तब भारतीय नेतृत्व अमेरिका-यूरोप से मध्यस्थता की याचना करता दिखा, जिसमें कई बार स्थिति गिड़गिड़ाने तक पहुंच गई थी। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखकर पाकिस्तानी आक्रमण रोकने हेतु संपर्क साधा था। 5 दिसंबर, 1971 को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, 'इस संकट की घड़ी में भारत सरकार और भारत की जनता आपकी सहानुभूति की आकांक्षी है...आपसे आग्रह है कि आप पाकिस्तान को अकारण आक्रामकता एवं सैन्य दुस्साहस की नीति से तत्काल विरत होने के लिए प्रेरित करें...मैं महामहिम से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने निर्विवाद प्रभाव का उपयोग करें...।'

इंदिराजी का यह रुख उनके पिता पं. नेहरू की परंपरा से ही प्रेरित था। 1962 में भारत को न केवल चीन से अपमानजनक पराजय झेलनी पड़ी, बल्कि हम हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि से भी हाथ धो बैठे। यह सब नेहरूजी की मार्क्स-मैकॉले चिंतन से निकटता और चीन की साम्राज्यवादी मंशा की उपेक्षा का परिणाम था। पंचशील, सुरक्षा परिषद की सदस्यता चीन को सौंपना और 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' जैसे नारे भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। उस पर अमेरिका के समक्ष पं. नेहरू की बारंबार मिन्नतों ने भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान को और भी आहत किया।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी ब्रूस रीडेल ने अपनी पुस्तक *जेएफके फॉरगॉटन क्राइसिसः तिब्बत, द सीआईए एंड द सीनो-इंडियन वार* में भारत-चीन युद्ध के समय पं. नेहरू द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी को लिखे गुप्त पत्रों के अंश सार्वजनिक किए हैं। 11–19 नवंबर के बीच हुए पत्राचार में पं. नेहरू ने कहा था, 'यह संकट केवल भारत का नहीं, समूचे उपमहाद्वीप और एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अस्तित्व का प्रश्न है।' उन्होंने तत्काल हवाई मदद मांगते हुए लिखा– 'हमें कम से कम 12 स्क्वाड्रन सुपरसोनिक सर्व-मौसमी लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता है। देश में आधुनिक राडार व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है। जब तक हमारे सैनिकों को इस हेतु प्रशिक्षण नहीं मिल जाता, तब तक इन विमानों एवं राडार प्रतिष्ठानों का संचालन अमेरिका की वायुसेना के कर्मियों को करना होगा।' तब पं. नेहरू यह आश्वासन भी देते दिखे कि अमेरिकी बमवर्षक विमानों का उपयोग पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं, केवल 'चीन के विरुद्ध प्रतिरोध हेतु' किया जाएगा। इन पत्रों की भाषा से स्पष्ट होता है कि पं. नेहरू ने अमेरिका के समक्ष भारत का स्वाभिमान गिरवी रख दिया था।

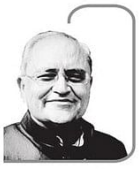

वर्ष 1965 के युद्ध में जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, तब भारतीय नेतृत्व ने जो कुछ जीता था, उसे अगले वर्ष ताशकंद जाकर सोवियत संघ (रूस) की मध्यस्थता से लौटा दिया। इसका रणनीतिक औचित्य आज तक स्पष्ट नहीं है। क्या इससे पाकिस्तान सुधरा? क्या उसने भारत के प्रति शत्रुभाव छोड़ दिया? ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीजी की रहस्यमयी मौत ने इस समझौते को और भी विवादास्पद बना दिया। ऐसे ही 1960 में पं. नेहरू ने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर पाकिस्तान के साथ अव्याहारिक 'सिंधु जल समझौता' किया था।

इसी तरह अमेरिकी दबाव में वर्ष 1995 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने पोखरण परमाणु परीक्षण टाल दिया था। परंतु 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयीजी ने अमेरिकी-यूरोपीय प्रतिबंधों की धमकियों को दरकिनार करते हुए सफलतापूर्वक पोखरण परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत से लड़ाई रोकने को कहा था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि तब अटलजी ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना के कारगिल से निकलते ही युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा। अर्थात-जब तक पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर है, युद्ध जारी रहेगा।

विश्व बदल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार से दुनिया सकते में है। वैश्विक संबंधों की सुनामी में भारत ने अपने आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखते और हितों की रक्षा करते हुए अपनी भूमिका को पुनःपरिभाषित किया है। यह अतीत की गलतियों और बंधनों से मुक्ति का एक सुखद और प्रशंसनीय नव दृष्टिकोण है। edit@amarujala.com

आर्थिकी

कहीं यह ट्रंप की चाल तो नहीं

ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ ने भारतीय व्यापार गलियारों में हलचल मचा दी है। संभव है कि अमेरिका ने बेहतर शर्तें सुनिश्चित करने के लिए यह दबाव बनाया हो।

अजय बग्गा
बाजार एवं आर्थिक मामलों के जानकार

ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा और रूस से तेल आयात पर द्वितीयक प्रतिबंध के खतरे से भारतीय वित्तीय बाजारों और व्यापार गलियारों में हलचल है। हो सकता है कि अमेरिका ने व्यापार समझौते में बेहतर शर्तें सुनिश्चित करने के लिए यह दबाव बनाया हो, लेकिन भारत पर इसका तत्काल प्रभाव तो पड़ेगा ही। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को 87 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, और लगभग 45 अरब डॉलर का आयात किया, जिससे भारत के पक्ष में 42 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष हुआ, जिस पर अब सीधा खतरा है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन, वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, चमड़े के सामान और जूते, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन और समुद्री खाद्य अमेरिका को निर्यात करता है। सामूहिक रूप से ये क्षेत्र अमेरिका को भारत के सालाना 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात करते हैं। 25 फीसदी टैरिफ न केवल उन्हें गैर-प्रतिस्पर्धी बना देगा, बल्कि निर्माताओं को घाटा सहने, बाजार से बाहर निकलने, या अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि ये टैरिफ ट्रंप की 'व्यापार कला' रणनीति का हिस्सा हैं। यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुए समझौते इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हालांकि, भारत की स्थिति संरचनात्मक रूप से थोड़ी अलग है। अमेरिका के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता अभी हुआ नहीं है। भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने के अमेरिकी दबाव का लगातार विरोध किया है।

यदि अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राजकोषीय घाटे को दोहरा झटका लगेगा। इससे निवेशकों की भावनाओं से लेकर आपूर्ति शृंखला तक प्रभावित होगी। टैरिफ घोषणा से भारतीय शेयर बाजारों में पहले ही गिरावट देखी जा चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आई है, और बढ़ते चालू खाता घाटे (सीएडी) की चिंताओं के कारण बॉन्ड यील्ड में भी दबाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर भारतीय निर्यातक अमेरिकी बाजार से निकलने को मजबूर होते हैं, तो नए विकल्पों की ओर रुख करने में काफी समय और निवेश लगेगा। निर्यात पर निर्भर उद्योगों में, खासकर कपड़ा, चमड़ा और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में नौकरियों पर संकट बढ़ रहा है। इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सरकार को टैरिफ के बाहरी झटके और कुछ बाजारों व क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरियों, दोनों का समाधान करना होगा। सरकार को विनिर्माण, कृषि-निर्यात, ई-कॉमर्स और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनियमन करना होगा। प्रमुख उपभोग और निर्यात श्रेणियों के लिए जीएसटी स्लैब कम करने से मांग बढ़ सकती है। रणनीतिक वित्तीय समर्थन, जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट, निर्यात प्रतिस्थापन पर केंद्रित पीएलआई और मुक्त भंडारण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रभावित निर्यात क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहन जरूरी है-चाहे वह ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी योजनाओं, या प्रभावित उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष वेतन सहायता के जरिये हो। वैकल्पिक बाजार पहुंच के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया व्यापार कूटनीति इकाई स्थापित की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक को पूंजी बहिर्वाह का प्रबंधन करने, मुद्रा संबंधी घबराहट से बचने और रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए।

एआई एक सुपरहीरो की तरह हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। -पैलो हमावद्वा

जोखिम लेना जरूरी है

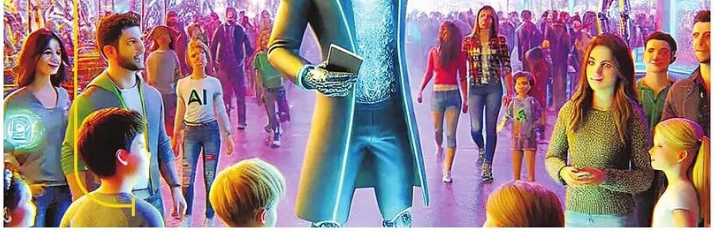

जोखिम अक्सर फलदायी होते हैं। इन्हीं से आप सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। यही हमें बताएगा कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए।

जोनास साल्क

जीवन धारा

जीवन गलती करने और उसे सुधारने की प्रक्रिया है। स्थिति बहुत खराब होती है, तब कुछ ऐसा होता है, जिससे सही रास्ता मिल जाता है। यदि हम गलती सुधारने के लिए निरंतर और थोड़ा बेहतर प्रयास करें, तो हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने 'पोलियो वैक्सीन' पर काम शुरू किया, तो हर प्रयोग इस तरह किया, जैसे मैं उस वायरस के भीतर हूं, उसकी प्रकृति को समझ रहा हूं।

हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। यह हमें बताएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने अच्छे और बुरे, दोनों तरह के सपने देखे। मेरे सपनों ने मुझे डर पर विजय पाने की शक्ति दी। सपने वे हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, और तर्क हमें बताता है कि उस रास्ते पर कैसे चलना है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखें। आशा सपनों में, कल्पना में और उन लोगों के साहस में बसती है, जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करते हैं।

मैंने बच्चों को वैक्सीन दी और कई रात तक सोया नहीं, क्योंकि मैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित था। लेकिन यह जोखिम लेना जरूरी था। जोखिम अक्सर फलदायी होते हैं। आप सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे पूर्वज बनें। हमें यह सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। यदि हम प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो हम स्वयं को नष्ट कर लेंगे। मैंने हमेशा माना कि विकास बुद्धिमत्ता का पक्ष लेता है। हमें अपने ज्ञान के साथ बुद्धिमत्ता को संतुलित करना होगा। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या हमारे पास उसे संभालने की समझ है? बुद्धि और सही समझ के साथ मनुष्य एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।

जरूरी है कि हम बदलती परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने की आवश्यकता को स्वीकार करें। जीवन जादुई है। प्रकृति का काम करने का तरीका जादू की तरह है। हम सभी एक बड़े विकास का हिस्सा हैं, और हमारी चेतना, हमारी कल्पना, हमें भविष्य को आकार देने की शक्ति देती है। हम एक-दूसरे के साथ मिलकर जीना सीखें। हम अपने सपनों, अंतर्ज्ञान और मानवता के प्रति जिम्मेदारी को अपनाएं। जानिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है जिसे पूरा करने के लिए आप इच्छुक हैं। जीवन में साहस, सहयोग व ज्ञान के साथ हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है।

ज्योतिषी से पूछा, क्या एआई मेरी नौकरी खा लेगा

द गार्जियन की स्तंभकार एमी हॉकिंस ने जब एक ज्योतिषी से पूछा कि क्या एआई उनकी नौकरी छीन लेगा, तो उसका जवाब था कि फिलहाल तो नहीं। लेकिन, तीन साल बाद क्या होगा, कहना मुश्किल है।

AI समय

स्व-सहायता, स्व-विकास और आत्म-मुग्धता के दौर में मार्गदर्शन करने वाले इतने केंद्र पहले कभी नहीं थे। जहां कभी चिंतित और अनिश्चित लोग जवाबों के लिए सर्च इंजन का सहारा लेते थे, वहीं अब हम अपनी समस्याओं को लेकर चैटजीपीटी से सार्थक चर्चा कर सकते हैं। यदि आप चीन में हैं, तो डीपसीक है। इसके बावजूद चीन के लोग एक अलग ही प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। दरअसल, बड़ी संख्या में चीनी युवाओं ने अपना भविष्य जानने के लिए पारंपरिक ज्योतिषियों की शरण में जाना शुरू किया है।

पिछले कुछ वर्षों में चीन के शहरों में भविष्य बताने वाले बार खुल गए हैं, जहां जुआनक्सुए (चीन की ज्योतिष कला) और अध्यात्म ज्ञान के साथ खाने-पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। दरअसल, चीनी युवाओं में दिख रहे इस बदलाव की वजह है। चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है और चूंकि बाहर जाकर खाना-पीना और किसी काउंसलर के पास जाकर परामर्श करना महंगा पड़ता है, इसलिए चीनी युवा भविष्य बताने वाले बारों का रुख कर रहे हैं। रहस्यवाद की गहरी जड़ों वाली संस्कृति, जिसमें ताओवाद, बौद्ध और लोक प्रथाओं का मिश्रण समाहित है, ऐसा होना स्वाभाविक ही है। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी इन परामर्श केंद्रों में जाकर देखूं। उसी दिन शाम को मैं पीले ताओवादी ताबीजों और पारदर्शी पर्दों से सजे एक बार में शामिल हुई। वहां के नियम सख्त थे। एक ड्रिंक लेने पर एक सवाल ही पूछा जा सकता था। तो मैं पहुंची छत्तीस साल की वान मो के पास, जो क्यूकियान या स्टिक के सहारे भविष्य बताने में माहिर हैं।

इस विधा में अपने मन में उठने वाले सवाल पर ध्यान केंद्रित कर लकड़ी की छड़ियों (स्टिक) से भरे लकड़ी के ही गोलाकार कंटेनर को हिलाना होता है। आखिरकार टेक्स्ट और अंकों से युक्त एक स्टिक गिर जाती है, उसके आधार पर भविष्यवक्ता उसकी व्याख्या कर उत्तर देता है।

मुझे उम्मीद है कि क्यूकियान से मेरे पहले सवाल का बेहतर जवाब मिलेगा : क्या एआई मेरी नौकरी छीन लेगा? वान मो ने जोर देकर कहा, 'दोनों हाथों का इस्तेमाल करो और अपने सवाल पर ध्यान लगाओ।' वह मुझसे कहती हैं, 'एक विदेशी होने के नाते स्टिक में आपका लगाव शायद चीनी व्यक्ति जितना गहरा न हो। इसलिए आपको ज्यादा ध्यान से सोचने की जरूरत है।' कुछ सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने और जोर से हिलाने के बाद एक नहीं, बल्कि दो स्टिक हमारे बीच की मेज पर गिरीं।

वान मो ने पहली स्टिक को देखकर कहा, 'आगे चलकर एआई का आपके काम पर असर तो पड़ेगा, भले ही आप कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, लेकिन आप इसका मुकाबला नहीं कर सकतीं। मान लीजिए, यदि आप एक लेख लिखती हैं, तो एआई उतने ही समय में सौ लिख सकता है। आप इसके मुकाबले में हैं ही नहीं।' यह उस तरह का आध्यात्मिक समाधान नहीं है, जिसकी मैंने उम्मीद की थी। दूसरी स्टिक देखकर वान मो मुझे बताती हैं, 'फिलहाल, तीन वर्ष तक आप पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एआई बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा।'

वान मो की भविष्यवाणी के बाद मैं इस स्थिति में नहीं थी कि दूसरा सवाल पूछूं, फिर भी मैंने तय किया कि एक सवाल और पूछूंगी। मैं सोच रही थी कि क्या वान मो को पता है कि एआई उसकी भी नौकरी ले लेगा-या उसने बस इससे समझौता कर लिया है। आखिरकार मैंने अपना दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत जुटा ली। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, 'क्या मेरा वेतन बढ़ेगा।' इसका जवाब तत्काल मिला। 'फिलहाल, ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि, स्टिक बदलाव को लेकर है। कुछ उम्मीद है, लेकिन तत्काल नहीं। इसके लिए आपको कुछ व्यक्तिगत समझौता करना होगा।' मैंने उनसे पूछा, मैं किस तरह का व्यक्तिगत समझौता कर सकती हूं।' वह हिचकते हुए कहती हैं, 'यदि आप वेतनवृद्धि चाहती हैं, तो जुआनक्सुए केवल सहायता प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने जो ब्रेसलेट पहना है, वह धन आकर्षित करने के लिए है। हम आपको ऐसा कुछ पहनने की सलाह देंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात अब भी अपने वरिष्ठों (सुपीरियर) के साथ संवाद बनाए रखना है।' मेरा समय खत्म हो चुका था। अगले दिन सुबह जल्दी उठने से पहले मैं घर जाकर थोड़ी नींद ले लेती हूं। मुझे यकीन है कि एआई को थकान की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

रैग एआई

रैग या आरएजी (रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जेनरेशन) एक ऐसी तकनीक है, जो एलएलएम को किसी सवाल का जवाब देने से पहले बाहरी ज्ञान भंडार से प्रासंगिक जानकारी खोजने व उसके उपयोग में सक्षम बनाती है। यह एलएलएम को उसके अपने प्रशिक्षण डाटा से परे, अप-टू-डेट और विशिष्ट जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है। रिट्रीवल के अंतर्गत उपयोगकर्ता के सवाल पर एआई सिस्टम बाहरी ज्ञान भंडार से जानकारी जुटाता है। ऑगमेंटेशन मतलब खोजी गई प्रासंगिक जानकारी को उपयोगकर्ता के मूल प्रश्न के साथ मिलाकर एक नया संवर्धित (ऑगमेंटेड) प्रॉम्प्ट बनाया जाता है। जेनरेशन यानी नए प्रॉम्प्ट को एलएलएम में भेजा जाता है। एलएलएम इस संवर्धित संदर्भ का उपयोग करके सटीक और विश्वसनीय प्रतिक्रिया देता है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य · सार्थक · सदैव

मसौदे पर मतभेद

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक नई मतदाता सूची जारी हो गई और उसकी व्यापक विवेचना का दौर स्वाभाविक ही तेज हो गया है। आने वाले दिनों में मतदाता सूची से तरह-तरह के आंकड़ों के उजागर होने की संभावना है, पर अभी से ही इस पर जो राजनीति हो रही है, वह सबका ध्यान खींच रही है। मुख्य विपक्षी दलों की सजगता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची में अगर कोई भी कमी पाई गई, तो चुनाव आयोग पर नए सवालों की बौछार होगी। मतदाता सूची को लेकर यह राजनीतिक सजगता प्रशंसनीय है। मतदाता सूची में गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग को सुधार का काम अवश्य करना चाहिए, पर उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। हो सकता है, यह मतदाता सूची पुनरीक्षण का पहला चरण हो और शिकायतों पर गौर करते हुए इसके दूसरे चरण की जरूरत पड़े। सुधार का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग यह देखे कि कोई दल या उसके कार्यकर्ता कहीं मतदाता सूची न बनाने लगें। आज जो दल सूची को लेकर सजग हैं, अगर वे पहले सजग हो जाते, तो यह नौबत नहीं आती। यह लोकतंत्र के हित में है कि हर पार्टी सिर्फ अपने फायदे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता से निकले।

मतदाताओं को भी ज्यादा सजग होना चाहिए। अपने नाम के आसपास अगर कोई फर्जी नाम दिखे, तो स्वयं मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। बिहार में मतदाता सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है और जहां मतदाता अपना नाम देखने के साथ ही, सुधार के प्रयास कर सकते हैं। गौर करने की बात है, पुनरीक्षण से पहले बिहार में 7.93 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। पुनरीक्षण के पहले चरण के दौरान 7.24 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कराए हैं। आयोग के अनुसार, सात लाख मतदाताओं ने कई जगहों पर नामांकन करा रखा है, जबकि 35 लाख मतदाता स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका कोई पता नहीं चल पाया है; अन्य 22 लाख मतदाता मृत बताए गए हैं।

बिहार की ताजा मतदाता सूची को ठीक से परखने की जरूरत है और यह काम राजनीतिक कुशलता से नहीं, लोकतांत्रिक ईमानदारी से पूरा किया जाना चाहिए।

विपक्ष ने यह आरोप पहले ही लगाया था कि इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से 60 लाख से अधिक लोग मताधिकार खो देंगे। वास्तव में, नई सूची को परखने की जरूरत है और यह काम राजनीतिक कुशलता से नहीं, लोकतांत्रिक ईमानदारी से होना चाहिए।

गंभीर बात है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है, कांग्रेस ने गड़बड़ी के ऐसे सुबूत जुटा लिए हैं, जिनकी तुलना एटम बम से की जा सकती है। मतदाता सूची के प्रति सजगता का यह नया दौर फलदायी होना चाहिए। अचरज नहीं, कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बिना देरी विशेष चर्चा कराने का आग्रह किया है। अगर यह चर्चा होती है, तो पूरी व्यापकता में विचार करना होगा कि अपने देश में मतदाता सूचियों को कैसे तैयार किया जाता है? अगर कोई सूची में गड़बड़ी कर रहा है, तो वह लोकतंत्र का शत्रु है। ऐसे शत्रुओं तक पहुंचना चाहिए और हमारी व्यवस्था में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक सुधार को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, पर यह हकीकत है कि राजनीतिक दल ही इसमें बाधक बनते रहे हैं। हारने वाले को सुधार की चिंता होती है, जबकि जीतने वाला सुधार विरोधी हो जाता है। ऐसे में, आज सबसे जरूरी है, लोकतांत्रिक ईमानदारी सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति!

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

02 अगस्त, 1950

गलत नेतृत्व

सिख भारत की एक बहादुर जाति है। बहादुरी का लक्षण पीड़कों और आक्रमणकारियों का प्रतिरोध तथा कमजोरों की सहायता है। बहादुर को देख पीड़कों और आक्रमणकारियों को जहां भय हो। आज यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तो मानना चाहिए कि कहीं-न-कहीं कोई गलती है, जिसके सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कायदे-आजम जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों का जो क्रम रहा, उसकी कटु स्मृति देश-विभाजन और उससे उत्पन्न समस्याओं के रूप में हमारे सामने है। और 'दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है' यह उक्ति सुज्ञात है। अतः सिखों को भी उसी ढंग पर चलते देखें, तो न खुशी हो सकती है, न आश्वस्त ही रहा जा सकता है। किन्तु लगता कुछ ऐसा ही है कि मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में सिख वही सब कर रहे हैं, जो कायदे-आजम के नेतृत्व में मुसलमानों ने किया। सिखों की अपनी भाषा अथवा सिख जाति के अपने प्रांत के नाम पर सिखिस्तान की मांग नई चीज नहीं है। कांग्रेस को बुरा-भला कहने और बदनाम करने की चाल भी वही मुस्लिम लीग का अनुसरण मालूम पड़ता है, जिस पर चलते हुए अब मास्टरजी ने फरमाया है कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन नं. 1 है। यही नहीं, आपने घोषित किया है कि जिस प्रकार प्रांतों को खुदमुख्तार बनाने की जिन्ना की मांग न मानने पर बाद में कांग्रेस को पाकिस्तान मंजूर करना पड़ा, उसी प्रकार पंजाबीभाषी प्रांत बनाने की मांग को अस्वीकार करने के बाद स्वतंत्र सिख राज की बात भी उसे माननी ही पड़ेगी।

जहां तक मास्टरजी की उपर्युक्त मांगों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि न तो वे देशहित में हैं और न सिखों के ही हित में। देशहित में इसलिए नहीं कि पार्थक्य भावनाओं से एकता का बहुत छिन्न-भिन्न होना निश्चित है। और सिखों के हित में इसलिए नहीं कि पंजाबीभाषी या सिखिस्तान के रूप में पृथक प्रांत बनाया जाये, तो जब हिन्दुओं के बहुमत में सिख नहीं रहना चाहते, तो हिन्दू भी सिखों के बहुमत में क्यों रहना पसन्द करेंगे? और जब सिखों का अपना अलग प्रांत हो तो अन्य प्रांतों में सिखों को बराबरी की सुविधा से क्यों रहने दिया जाना चाहिए तथा सेना व अन्य नौकरियों में जो उनका संख्या से अधिक अनुपात है, वह क्यों रहने देना चाहिए?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टैरिफ या सीमा शुल्क को लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नीतियों की वजह से यह अनावश्यक तनाव की स्थिति बनी है। वैसे, दोनों देशों का एक-दूसरे के लिए महत्व है, अतः दोनों अभी भी व्यापार वार्ता को किसी नतीजे तक पहुंचाने के इच्छुक हैं। अंतिम नतीजों का इंतजार है, पर तब तक पक्ष-विपक्ष में बहस भी तेज रहेगी।

आमने-सामने

नीयत और नीतियों की नाकामी का नतीजा

यहां स्कैन करें

सुप्रिया श्रीनेत | अध्यक्ष, कांग्रेस सोशल मीडिया

- अमेरिका जैसा बर्ताव कर रहा, उससे भारत की साख धूमिल हो रही है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर 25 फीसदी टैरिफ का नकारात्मक असर होगा।
- विदेश नीति का उद्देश्य हमारे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होना चाहिए।

अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा भारत पर 25 फीसदी टैरिफ और रूस से तेल एवं हथियार खरीदने पर जुर्माना थोपने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार की गंभीर विफलता का ताजा उदाहरण है। अमेरिका बीते कुछ महीनों से आए दिन भारत को लक्ष्य बनाकर जिस तरह का शर्मनाक बर्ताव कर रहा है, उससे भारत की साख धूमिल हो रही है।

इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बात यह कि अमेरिका की इन मनमानियों पर भारत का नेतृत्व रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए है। ट्रंप द्वारा 25 फीसदी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर और नकारात्मक असर होगा, खासतौर से तब, जब हमारी आर्थिक स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसका सीधा प्रहार हमारे उद्योगों, उत्पादन, निर्यात और नौकरियों पर होगा।

मिसाल के तौर पर, भारत में बनी दवाइयां अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, जिससे वहां उनकी खपत और मांग, दोनों गिरेंगी। नतीजतन हमारे यहां की कंपनियां उत्पादन में कटौती करेंगी, जिससे लाखों लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे। अक्तूबर की ट्रेड डील की डेडलाइन के पहले अमेरिका का प्रयास भारत को एक ऐसे समझौते के लिए मजबूर करना है, जिससे भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार पूरी तरह से अमेरिका के लिए खुल जाए।

अमेरिका की मंशा है कि भारत पर दबाव बनाकर अमेरिकी चीजों पर आयात शुल्क घटाया जाए। पर ऐसा करना भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी अपनी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। क्योंकि इससे भारत के लाखों घरेलू उद्योग तबाह हो जाएंगे। इन उद्योगों पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले कई करोड़ लोगों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग जाएंगे। अमेरिका का कुल व्यापार घाटा लगभग 1,200 अरब डॉलर है और भारत के साथ उसका घाटा सिर्फ 40 अरब डॉलर है, जो उसके कुल व्यापार घाटे का मात्र 3.3 फीसदी है। ऐसे में, यह साफ है कि यह निर्णय ट्रंप ने आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिए लिया है। एक तरफ ट्रंप रूसी हथियार और तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान से उसके तेल भंडार को बढ़ाने का समझौता करते हुए चुटकी लेते हैं कि भारत भविष्य में पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। यही नहीं, ट्रंप ने हमारी छह तेल रिफाइनिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, अमेरिकी कंपनियों को भारत में उत्पादन के खिलाफ धमकाया।

हमारी सरकार लगातार मूकदर्शक बनी रही। ट्रंप को भारत का अपमान करने पर करारा जवाब देने के बजाय देश के विपक्षियों का मुंह बंद कराना उसकी प्राथमिकता है। कुछ खबरों के मुताबिक, अमेरिका द्वारा जुर्माना लगाते ही, हमारी कंपनियों ने सस्ता रूसी तेल आयात करना तुरंत बंद कर दिया। आज राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी देखकर हर देशवासी के मन में सीधा सवाल है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने अमेरिका और व्यक्तिगत रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो किया, उससे क्या हासिल हुआ?

हमारा देश 2047 में विकसित बनने से अभी दूर है, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार ने विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक अपनी विफलताओं का जो गड्ढा खोदा है, उससे भारत का भारी नुकसान हो रहा है। जिस विदेश नीति का उद्देश्य दुनिया भर में हमारे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होना चाहिए, उसका इस्तेमाल भोंडे प्रचार और छवि चमकाने के लिए हो रहा है। उद्योग जगत से लेकर आम जनता तक के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि सरकार अमेरिका के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने के बजाय नतमस्तक क्यों है?

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

नए हालात में नई राह निकाल लेगा भारत

यहां स्कैन करें

गौरव वल्लभ | प्रोफेसर, वित्त व भाजपा नेता

- दोनों देश मजबूत साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते रहते हैं।
- अमेरिकी टैरिफ कार्रवाई का सामना करने वाला भारत अकेला देश नहीं है।
- भारत बदलती वैश्विक व्यवस्था में भी एक निर्णायक शक्ति हो सकता है।

अमेरिका-भारत व्यापार संबंध एक और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा से व्यापार वार्ताओं पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, दोनों देश एक मजबूत साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते रहते हैं, पर दुनिया में हर पल बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और देशों का आर्थिक राष्ट्रवाद उनकी नीतियों को संचालित करने लगा है।

भारत-अमेरिका के बीच विवाद का मूल केवल टैरिफ या बाजार तक पहुंच नहीं है, बल्कि भारत द्वारा अपने कृषि और डेयरी बाजार को खोलने से विवेकपूर्ण इनकार वाशिंगटन की गले की फांस बना हुआ है, लेकिन रूस के साथ भारत के ऊर्जा व रक्षा संबंधों से भी वाशिंगटन में गहरी बेचैनी है। जैसे-जैसे भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है, पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2022 में भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग दो प्रतिशत रूस से लेता था, पर वित्त वर्ष 2025 में यह लगभग 36 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ऐसा युद्धकालीन रियायत की वजह से हुआ है। अब इन रियायतों में कमी आ गई है। रूस अब तेल की लगभग पूरी कीमत वसूलने लगा है। अतः भारत के पास तेल के स्रोतों में विविधता लाने की नई गुंजाइश है, जिसमें अमेरिका से एलएनजी और कच्चा तेल लेना शामिल है। टकराव की स्थिति में यह संभावना संतुलन का काम कर सकती है।

वैसे, अमेरिका को भारतीय निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है। वैश्विक मानकों पर देखें, तो यह एक मामूली हिस्सा है, पर यह मायने रखता है। अगर टैरिफ लगा, तो कपड़ा, रसायन, दवा और ऑटो उपकरण जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। टैरिफ के झटके से भारत की निर्यात-आय में लगभग 30 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जिससे अल्पावधि में आपूर्ति श्रृंखला, रोजगार और सकल घरेलू उत्पादन प्रभावित होंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत का आर्थिक ढांचा घरेलू खपत पर आधारित है। भारत का घरेलू बाजार उसकी कंपनियों को ऐसा सहारा देता है, जो अनेक निर्यात प्रधान अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त नहीं है।

भारत की रक्षा खरीद पर वाशिंगटन का असंतोष समझ में आता है, पर यहां भारत का रुख व्यावहारिक है। वैसे, अमेरिकी टैरिफ-कार्रवाई का सामना करने वाला भारत अकेला नहीं है। हाल में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और वियतनाम जैसे अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगियों को भी इसी तरह की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है।

इस माहौल में भारत का दृष्टिकोण कुशल सौदेबाजी पर आधारित होना चाहिए। अपनी घरेलू प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता का लाभ उठाना चाहिए। उसे कृषि, ऊर्जा पहुंच और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। निकट-भविष्य में अस्थिरता के बावजूद, भारत के बाजार के मूल सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं। वित्तीय सेवाओं, उपभोक्ता वस्तुओं और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्र व्यापारिक तनावों से अपेक्षाकृत अछूते हैं। दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भी अमेरिकी टैरिफ से मुक्त हैं।

निर्यात पर भारत की कम निर्भरता उसे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने की गुंजाइश देती है। फिर भी जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार में बदलाव आ रहे हैं, वैसे-वैसे भारत को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करते रहना होगा। भारत न केवल एक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति के रूप में भी सशक्त हो सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जातिवाद की गांठ खोलते और बांधते बिहार के मतदाता

यहां स्कैन करें

बद्री नारायण | कुलपति, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान

बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। इस बार के चुनावी परिदृश्य में जातिगत जनगणना के विमर्श से बना माहौल और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पैदा विमर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिख रहे हैं। ये दोनों मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में इसलिए ज्यादा प्रभावी दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार के समाज में समाहित करने और बहिष्कार के प्रश्न प्रारंभ से ही प्रभावी रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां के समाज में जातीय चेतना बहुत प्रभावी रही है।

जाति-जनगणना हालांकि अब एक मुद्दे के रूप में उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े को भी शामिल करने की घोषणा कर दी है। हालांकि, इससे बनी जातीय चेतना का कैनवास अब भी सक्रिय है। मगर एसआईआर ने लोगों के मन में बहिष्करण का एक अनजाना भय पैदा किया है। जाहिर है, कुछ सियासी दल अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि, बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण वहां चुनावी जनतंत्र को अधिक परिपक्व और गहरा बनाने की ही एक कोशिश है। योग्य मतदाता जनतंत्र को ज्यादा बेहतर ढंग से जीते और उसके मूल्यों को संजोकर रखते हैं। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।

चंद दल एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक भय दिखाकर कुछ सामाजिक समूहों के मन में बहिष्करण का भय पैदा करना चाहते है। इसके लिए वे आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की अनुपलब्धता की आड़ ले रहे हैं। हालांकि, भारतीय समाज और बिहार का समाज आजादी के 77 वर्षों के बाद सिविल सोसाइटी में बदलता जा रहा है। अब वह अनौपचारिक से औपचारिक समाज में बदलता जा रहा है। एक औपचारिक समाज 'कागज-पत्तर' से लैस होता है। योजनाओं के लाभ, नौकरी संबंधी कागजात, कानूनी जरूरतों, पुलिस, कचहरी की बाध्यताओं ने उसे दस्तावेजों के प्रति सजग बना दिया है। राज्य के साथ संवाद की जरूरतों ने उपेक्षित, पिछड़े, सबाल्टर्न और दलित समूहों को जागरूक बनाया है। इसलिए एसआईआर के संदर्भ में पिछड़े, दलित और सबाल्टर्न समूहों के किसी भी भाग के बहिष्करण के भय का तर्क आधारयुक्त नहीं लगता।

कुछ सियासी पार्टियां अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए पुनरीक्षण के खिलाफ बने भ्रम का उपयोग करना चाहती हैं, जबकि यह कवायद राज्य में जनतंत्र को अधिक परिपक्व बनाने की ही कोशिश है।

निस्संदेह, जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक दलों ने जो अभियान चलाया, उसने बिहार के समाज में जातिगत गोलबंदी के प्रारूप को गहरे प्रभावित किया है। साल 2022 में बिहार की जातिगत गणना में 215 जातियां दर्ज की गई थीं। इनमें 27.12 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 36.01 फीसदी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 19.56 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 1.68 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और अगड़ों का प्रतिशत 15.5 प्रतिशत के आस-पास दर्ज किया गया। जातिवार देखें, तो बिहार में यादव सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी भी है।

19वीं शताब्दी के पहले दशक में ही यादव-गोप सामाजिक समूह का जातीय संगठन मजबूत हो चुका था। इस जाति समूह ने कुर्मी, कोइरी जैसी दो अन्य पिछड़ी जातियों के साथ त्रिवेणी बनाकर राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर इस जाति के लोगों ने उच्च क्रम में अपनी गतिशीलता सृजित की। बिहार की राजनीति में यादव जाति के दबदबे का प्रतिकार पिछड़ी जातियों की दो अन्य प्रभावी जातियों- कुर्मी व कोइरी के नेतृत्व में अति पिछड़ी व महादलित गोलबंदी से पैदा हुआ, जिसे नीतीश कुमार के नेतृत्व ने गति दी। भाजपा ने भी अपने नए स्वरूप में बिहार व उत्तर प्रदेश में पिछड़ों व दलितों की बड़ी जातियों के बरक्स छोटी-छोटी संख्या वाली जातियों को जोड़कर अपनी राजनीति विकसित की।

बिहार विधानसभा का यह चुनाव भी संख्या बल में मजबूत जातियों के बरक्स छोटी-छोटी संख्या वाली जातियों की गोलबंदी का चुनाव बनता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव प्रचार जितना आक्रामक होगा, उसके समानांतर नीतीश कुमार और भाजपा अति पिछड़ी, पचपनिया और महादलितों को गोलबंद करने की कोशिश करेगी। इस चुनाव में बिहारी जनता में विकास की आकांक्षा साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। बिहार के भविष्य का नारा लेकर प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखना यह है कि जाति चेतना की राजनीति और विकास व भविष्य की राजनीति यहां क्या आकार लेती है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

बड़े भाग मानुष तन पावा

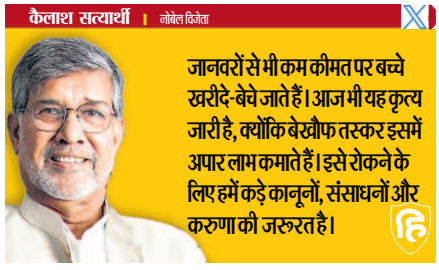

शरीर क्या है? कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की समष्टि मात्र है। नदी के दृष्टांत से यह तत्व सहज बोधगम्य हो सकता है। तुम अपने सामने नदी की जलराशि को देखो, पल भर में वह चली गई और उसकी जगह एक नई जलराशि आ गई। जो जलराशि आई, वह संपूर्ण नई है, परंतु देखने में पहली जलराशि की तरह है। शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है। मगर उसके परिवर्तनशील होने पर भी उसे स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। यही हमारे पास सर्वोत्तम साधन है।

सब प्रकार के शरीर में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है; मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है। यहूदियों और मुसलमानों के मतानुसार, ईश्वर ने देवदूत और अन्य समस्त सृष्टि के बाद मनुष्य की सृष्टि की। और मनुष्य के सृजन के बाद उसने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम करके आने के लिए कहा। इबलीस को छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया। अतएव ईश्वर ने इबलीस को अभिशाप दे दिया। इससे वह शैतान बन गया।

इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य-जन्म ही अन्य सभी जन्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पशु आदि योनियां मंद बुद्धि की हैं। ये प्रधानतः तम से निर्मित हुई हैं। देवदूत या देवता भी मनुष्य-जन्म लिए बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। इसी तरह मनुष्य समाज में भी अत्यधिक धन अथवा अत्यधिक दरिद्रता आत्मा के उच्चतर विकास में महान बाधक है। संसार में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, सभी मध्यम वर्ग से हुए थे। मध्यम वर्गवालों में सब शक्तियां समायोजित और संतुलित रहती हैं।

विवेकानंद

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

जानवरों से भी कम कीमत पर बच्चे खरीदे-बेचे जाते हैं। आज भी यह कृत्य जारी है, क्योंकि बेखौफ तस्कर इसमें अपार लाभ कमाते हैं। इसे रोकने के लिए हमें कड़े कानूनों, संसाधनों और करुणा की जरूरत है।

इजरायल को हद में रखने की जरूरत

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर इजरायल गाजा में युद्धविराम के लिए सहमत नहीं होता व स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तो ब्रिटेन सितंबर में फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे देगा। इसके बाद पुर्तगाल व कनाडा ने भी उसे मान्यता देने का एलान कर दिया है। इनसे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस दिशा में फैसला लिया है। मुद्दे को सुलझाने के लिए हाल ही में फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से ज्यादातर के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

ब्रिटेन की शर्तों में गाजा में जारी सैन्य अभियानों को समाप्त करना, पश्चिमी तट पर कब्जा करने की योजना पर रोक लगाना व दो-राष्ट्र के सिद्धांत के तहत शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होना शामिल है। इन देशों के एलान से फलस्तीन के निवासियों और उसके समर्थकों को बल मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीद की जानी चाहिए कि पश्चिम एशिया का यह सर्वाधिक जटिल विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा और अंततः इसका समाधान हो जाएगा।

फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना आज की जरूरत भी है। संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों द्वारा इस मान्यता के बाद ही पश्चिम एशिया का यह मामला शांत हो सकता है। इसके साथ ही गाजा में भूख से बिलबिलाते बच्चों समेत वहां के लोगों को मौजूदा नारकीय स्थिति से निजात मिल पाएगी। इस विवाद का सबसे जटिल पहलू हमास है। इस आतंकी संगठन की गतिविधियां समस्या समाधान में रोड़ा अटकाती हैं। मगर बात आगे बढ़े, तो हमास को भी रास्ते पर लाया जा सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुछ ऑफर दिया भी है। यहां यह तथ्य ध्यान में रखना होगा कि उस इलाके का मूल राष्ट्र फलस्तीन ही था, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने दुनिया भर के शरणार्थी यहूदियों को बसाने की पहल की थी। तब पूरा पश्चिम एशिया ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उस समय फलस्तीन के लोगों ने दुनिया भर में सताए जा रहे यहूदियों को वहां बसने दिया, लेकिन धीरे-धीरे इजरायल नाम से देश बसाकर इकट्ठा हुए यहूदी शेर बन गए और अमेरिकी समर्थन से फलस्तीनियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। इस दौरान इजरायल ने अपनी उस हद को तोड़कर फलस्तीनी जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया, जो संयुक्त राष्ट्र ने समझौते के तहत उसके लिए तय की थी। अब न्याय की मांग है कि इजरायल पुनः अपनी हद में लौटे। ब्रिटेन, फ्रांस समेत विश्व समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह इजरायल को राजी करे।

अद्वैत कृष्ण, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

फलस्तीन का दर्जा

फलस्तीन को अभी मान्यता नहीं मिले

इजरायल की सुरक्षा के नजरिये से देखा जाए, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का यह एलान कि उनका देश फलस्तीन को मान्यता दे सकता है, हमास के लिए इनाम ही होगा। फलस्तीन को मान्यता देने की ब्रिटेन की योजना गाजा में युद्धविराम सुनिश्चित करने के प्रयासों को कमजोर करेगी और संभवतः आतंकवाद को पुरस्कृत करेगी। फ्रांस और ब्रिटेन ने यदि फलस्तीन को मान्यता दी, तो इसका गलत संदेश जाएगा और इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

संयुक्त राष्ट्र में इजरायल-फलस्तीन संकट का स्थायी समाधान निकालने के लिए जो उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसमें दुनिया के कई देशों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत के हक में आवाज उठाई थी। सम्मेलन में न्यूयॉर्क घोषणापत्र नाम से एक योजना पेश की गई, जिसमें गाजा में जारी युद्ध को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने व भविष्य में एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की स्थापना की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह सम्मेलन सिर्फ अच्छी नीयत वाला एक और भाषण मंच बनकर नहीं रह जाना चाहिए। हालांकि, प्रस्ताव इस बात पर भी जोर देता है कि इजरायल की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। इस सम्मेलन की विफलता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका और संकट के एक पक्ष इजरायल ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।

जिस तरह से हमास व पीएलओ जैसे संगठन गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं और इजरायल पर आतंकी हमले करते रहते हैं, उनको देखते हुए फलस्तीन को मान्यता देना एक आतंकी देश पैदा करने जैसा ही होगा। आतंकी संगठनों के वर्चस्व में रहने वाले गाजा व फलस्तीन को स्वतंत्र मानने से वहां के आतंकी समूहों का मनोबल बढ़ेगा और इसका दुष्प्रभाव दुनिया के अन्य हिस्सों में चलने वाली ऐसी गतिविधियों पर भी पड़ेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में भी फलस्तीनी आंतकियों की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। वैश्विक स्तर पर इसी तरह की आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिका फलस्तीनी क्षेत्र में कोई आधिकारिक राजनयिक कार्यालय नहीं रखता है और न ही फलस्तीनियों को राजनयिक सेवाएं प्रदान करता है। अक्तूबर 2018 में वाशिंगटन डीसी में पीएलओ मिशन के बंद होने के बाद से फलस्तीनियों का अमेरिका में कोई प्रतिनिधि नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फलस्तीन को देश का दर्जा देने के बजाय वहां के आतंकी गिरोहों को नेस्तानाबूद करने का अभियान चलाया जाना चाहिए। फलस्तीन पर कोई भी सकारात्मक बात तब हो, जब हमास का खात्मा हो जाए।

मित्तुल कुमार ठाकुर, टिप्पणीकार

संपादकीय जागरण

(12) शनिवार, 2 अगस्त, 2025 : श्रावण शुक्ल - 8 वि. 2082

कर्म पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति

कार्रवाई करे चुनाव आयोग

राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर जैसे शरारत भरे और इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने एवं देश को गुमराह करने वाले आरोप लगाए, वे उनकी हताशा को ही दर्शाते हैं। वे अपनी नाकामी का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं और वह भी भद्दे तरीके से। चूंकि उनके ऐसे पुराने आरोप ठहर नहीं रहे इसलिए वे कुंठित हो रहे हैं। वे हताशा में हद पार कर रहे हैं। उन्हें यह भी भान नहीं कि वे नेता सदन हैं और उस कांग्रेस के नेता हैं, जिसने देश पर लंबे समय तक शासन भी किया और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के कुछ कदम भी उठाए। क्या कांग्रेस के लिए यह शर्म की बात नहीं कि जिस ईवीएम का उपयोग उसके शासनकाल में शुरू हुआ, उसके पीछे उसके ही बड़े नेता पड़े हैं। हाल के वर्षों में ईवीएम के कथित दुरुपयोग के जो भी आरोप लगे, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी पाया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगाए गए आरोप भी फर्जी ही पाए गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव आयोग के खिलाफ उलटा-सीधा नहीं, उलटा ही उलटा इसलिए बोला ताकि सांसद को मिले अधिकारों के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के नितांत झूठे और भारतीय लोकतंत्र की छीछालेदर करने वाले आरोपों का कड़ा प्रतिवाद करने के साथ यह कहकर उन्हें बेनकाब भी किया कि वे किस तरह अपने आरोपों का जवाब सुनने उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। चुनाव आयोग ने बार-बार उन्हें बुलाया, लेकिन लगता है कि वे खुद को इस संवैधानिक संस्था से भी ऊपर समझ रहे हैं। वे गांधी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह मुगालता पाल लें कि आम जनता उनके शरारत भरे आरोपों को सच मान लेगी। जनता का उनके आरोपों पर भरोसा होता तो चुनावों में कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं हो रही होती। वोट चोरी के आरोप लगा रहे राहुल और उनके साथी यह भूलना भी पसंद कर रहे हैं कि झारखंड और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कौन जीता था? अब यह आवश्यक है कि यदि राहुल गांधी या उनके सहयोगी अथवा कथित लोकतंत्र हितैषी चुनाव आयोग पर सिरे से झूठे आरोप लगाएं तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। यदि ऐसा काम राहुल संसद के बाहर करें तो उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग को पुलिस में शिकायत करने के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग लोकतंत्र बचाने के नाम पर उससे ही खेल रहे हैं। अब यह भी साफ है कि ऐसे लोग मतदाता सूचियों का सत्यापन नहीं होने देना चाहते, भले ही घुसपैठिये वोटर बने रहें। देशद्रोह तो यह है। इस मामले में जनहित याचिकाएं सुनने को आतुर सुप्रीम कोर्ट को भी सक्रिय होना चाहिए।

आचरण पर अविश्वास

यह माननीय स्तर के जन प्रतिनिधियों के लिए विचार का विषय है कि लोग उनके आचरण पर क्यों अविश्वास कर रहे हैं। माननीय कह रहे हैं कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उनका मान मर्दन किया है। दूसरी तरफ जनता के बीच विचार किया जा रहा है कि आज की तिथि में किसी माननीय के साथ ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि विधानमंडल की कार्यवाहियों का जबसे सीधा प्रसारण शुरू हुआ है, आम लोगों को यह सुविधा मिल गई है कि वे अपने प्रतिनिधियों के कामकाज को देख सकें। पहले यह सुविधा नहीं थी। ऐसे लोग जिन्हें संसदीय परंपरा में विश्वास है, अधिसंख्य माननीयों का आचरण देखकर क्षुब्ध हो रहे हैं। दो घटनाओं को देखिए। एक विधायक ने बहुत उचित काम के लिए पंचायत सचिव को फोन किया। पंचायत सचिव ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। लेकिन, जनता के एक हिस्से की राय है कि विधायक के बोलने का तरीका भी ठीक नहीं था। इस व्यर्थ के विवाद में सिस्टम की नाकामी दब गई, जिसके कारण किसी विधवा को पति की मृत्यु के तीन महीने बाद भी प्रमाणपत्र नहीं मिला। एक अन्य विधायक का आरोप है कि पटना एम्स में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। जनता में मतभेद है। क्योंकि डाक्टरों और सुरक्षा गार्डों ने विधायक पर ही दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। माननीय विचार करें, जनता उनके कथन पर क्यों पूरा विश्वास नहीं कर पा रही है।

संसदीय परंपरा में विश्वास करने वाले अधिसंख्य माननीयों का आचरण देखकर क्षुब्ध हो रहे

कह के रहेंगे माधव जोशी

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या ट्रंप भारत-अमेरिकी रिश्तों को बिगाड़ने पर तुले हैं?

आज का सवाल

क्या मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत के फैसले के बाद भगवा आतंक का जुमला उछालने वालों को माफी मांगनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सभी शिक्षा संस्थानों में लागू हो नई शिक्षा नीति

बद्री नारायण

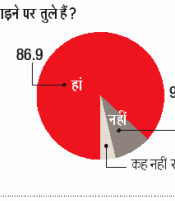

पांच वर्ष पुरानी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के शिक्षा जगत में एक ऐसा प्राणतत्व फूंकना है, जिससे सच्चे भारतीय मन की पीढ़ी विकसित हो सके

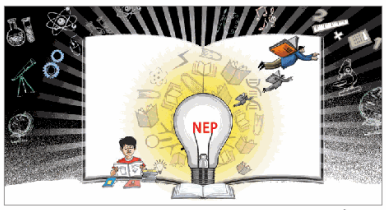

भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई परिवर्तनकारी योजनाएं तैयार की गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही योजनाएं मिलकर विकास को गति दे रही हैं। इसी दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति-2020 का निर्माण, विकास और कार्यान्वयन किया गया है। अब इस नीति को लागू हुए पांच वर्ष हो चुके हैं। यह सही समय है कि हम इसकी समीक्षा करें कि इसने भारतीय शिक्षा जगत में क्या परिवर्तन लाए हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए? नई शिक्षा नीति मूलतः एक दीर्घकालिक शैक्षिक परिवर्तन की रूपरेखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा में मौलिकता, उद्योग-अकादमिक संवाद और छात्रों में रोजगारपरकता विकसित करना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संकल्पित पंच प्रण में से एक युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास और भारतीय शिक्षा के विऔपनिवेशीकरण का लक्ष्य भी शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा जगत में एक ऐसा प्राणतत्व फूंकना है, जिससे देश में सच्चे भारतीय मन की पीढ़ी विकसित हो सके।

नई शिक्षा नीति विश्व में सर्वाधिक जनसंवाद से विकसित हुई शिक्षा नीति है। इसके लिए 1,10,623 ग्राम स्तरीय बैठक और 3,250 ब्लाक, 725 शहरी एवं 340 जिला स्तर पर संवाद आयोजित किए गए थे। इस दीर्घकालिक निर्माण प्रक्रिया के बाद इसके कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ हुआ। इन पांच वर्षों में अपने प्रारंभ से ही भारतीय शिक्षा जगत में बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित करने और अन्य लक्ष्यों को पाने के लिए पहले ढांचागत परिवर्तन किया गया। इस ढांचागत परिवर्तन के लिए स्कूल शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक कई सुधार किए गए। इनमें अनुशासनिकता पर आधारित चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गईं। मूल्यगत शिक्षा, स्किल आधारित कोर्स, रचनात्मक मौलिक पाठ्यचर्या आदि कई नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए। ये ढांचागत परिवर्तन देश के अधिकांश स्कूलों और उच्च शिक्षा में लागू हो रहे हैं। स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित की जा रही हैं, जो मौलिकता, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्किल, विकास, उद्योग और ज्ञान जगत संवाद पर आधारित हैं। स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा से जुड़े कई विद्वान और शिक्षक इस कार्य में लगे हैं। इनके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी की

अवधेश राजपूत

नई पाठ्यपुस्तकें इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं और कई पाठ्यपुस्तकें अब भी विकसित की जा रही हैं। यह काम और तेजी से किया जाना चाहिए। वास्तव में नई शिक्षा नीति एक दीर्घकालिक चरणबद्ध कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से मुख्य लक्ष्य भारतीय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति के तहत प्रशासनिक परिवर्तन के लिए ई-समर्थ कार्यक्रम विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम से अब तक 12,800 उच्च शिक्षा संस्थान जुड़ चुके हैं, जिनमें 1.75 करोड़ छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था के दैनिक प्रबंधन का संचालन हो रहा है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के क्रम में 'स्वयं प्लस' लागू किया गया है, जिससे पांच लाख इंटर्न प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसमें 1.74 लाख प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों से जुड़कर आजीविका प्रेरित शिक्षा ले रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की दिशा में भी कई कार्य किए गए हैं। भारतीय ज्ञान व्यवस्था से जुड़े गणित, एस्ट्रोनामी, सौंदर्यशास्त्र, जन स्वास्थ्य केंद्रित जैसे विषयों में उच्च शिक्षा के लिए लगभग 38 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। इनके शिक्षण के लिए शिक्षक और अनुदेशक प्रशिक्षित भी किए जा रहे हैं। भारतीय शिक्षा जगत विशेषतः उच्च शिक्षा में हो रहे इन ढांचागत, प्रशासनिक, व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, डिजाइन और पाठ्यपुस्तक निर्माण का एक बड़ा असर यह हुआ है कि भारतीय शिक्षा संस्थानों ने हाल के वर्षों में विश्व रैंकिंग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। विश्व स्तर पर कराए जा रहे क्यूएस-500 रैंकिंग में भारत के 11 विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष 46 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने क्यूएस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। क्यूएस एशिया रैंकिंग-2025 में भी देश के 163 विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। क्यूएस रैंकिंग में जगह बनाना गुणात्मक मूल्यांकन और सर्वांगीण प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन के बाद ही संभव हो पाता है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का एक लाभ यह भी हुआ है कि भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के कई देशों में अपने कैंपस खोल रहे हैं। दुनिया के कई विश्वविद्यालय भी भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं। हाल में मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में आइआइटी और आइआइएम जैसी संस्थाओं के कैंपस खोले गए हैं।

अब देश के सभी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए। शिक्षा के मामले में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब शैक्षिक संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों और प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा सतत कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा संचालित मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर्स, ओरिएंटेशन और रिफ्रेसर कोर्स तथा कई ज्ञान प्रशिक्षण केंद्र इसमें मददगार हो सकते हैं। हमें ऐसे पाठ्यपुस्तक भी विकसित करने चाहिए, जो सहज और सरल ढंग से ज्ञान विमर्श करते हुए नई शिक्षा नीति के आत्मा को अपने में प्रवाहित करें। स्कूल शिक्षा के लिए प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूला के लिए राज्य सरकारों और आमजन में स्वीकृति का भाव विकसित करना चाहिए। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति लगातार कई चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि इसका अगला चरण विकसित भारत-2047 के लिए आवश्यक देश के ज्ञान जगत और ज्ञान शक्ति को विकसित करेगा।

(लेखक टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, मुंबई के कुलपति हैं)
response@jagran.com

धैर्य और संकल्प की अद्भुत कहानी

विशाल सरीन

महिला विश्व शतरंज चैंपियन की कमी पूरी होना इसलिए खास है, क्योंकि शतरंज दुनिया का बहुत ही लोकप्रिय खेल है

जब आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के सामने हों और आप पर कमजोर होने का ठप्पा लगा हो तो उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। नागपुर की 19 वर्षीय किशोरी दिव्या देशमुख ने जार्जिया के बटुमी में विश्व महिला शतरंज कप जीतकर इसी की पुष्टि की। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर और चौथी महिला खिलाड़ी बनीं। बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित पिछले शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद करने वाली प्रमुख खिलाड़ियों में से एक दिव्या के लिए यह एक परीकथा जैसी कहानी रही है। वह देश की अगली ग्रैंडमास्टर बनने को तत्पर थीं, लेकिन सवाल यही था कि कब बनेंगी? ग्रैंडमास्टर बनने के लिए तीन ग्रैंडमास्टर मानदंड और 2500 की रेटिंग की आवश्यकता होती है। दिव्या के पास तब इनमें से किसी का भी बखान करने के लिए कुछ नहीं था, जब वह दूसरे राउंड से शुरू होने वाले अपने पहले मुकाबले में उतरीं। जार्जिया की केसरिया मगेलाद्जे के खिलाफ दो गेम के मैच में आसान और अपेक्षित 1.5-0.5 से जीत हासिल करने के साथ ही शतरंज के इतिहास में दर्ज होने वाली एक कहानी की शुरुआत हो गई। सर्बिया की इंजाक टेओडोरा तीसरे राउंड में दिव्या के हाथों 0.5-1.5 से हारने वाली अगली खिलाड़ी थीं और चौथे राउंड में उनका मुकाबला चीन की जिनर झू से हुआ। यह शायद उनके जीवन का सबसे कठिन मैच था।

पहला गेम जीतने और दूसरा हारने के बाद दिव्या ने 15 मिनट के टाईब्रेकर में चीनी खिलाड़ी को फिर से 1.5-0.5 से हरा दिया और अब उनका मुकाबला हमवतन ग्रैंडमास्टर डी. हरिका से था। दिव्या ने फिर टाईब्रेकर में 2-0 से जीत हासिल की और हरिका को दौड़ से बाहर कर दिया। पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की टैन झोंगयी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें 0.5-1.5 से हार का सामना करना पड़ा। दिव्या इस महामुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। यह कहानी एक और भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हंपी के बिना

संघर्ष और सफलता का नया नाम दिव्या देशमुख ● प्रेट्र

पूरी नहीं होगी, जो दिव्या से दोगुनी उम्र की हैं और धीरे-धीरे तेजी से आगे बढ़ रही थीं। जब उन्होंने दूसरी चीनी खिलाड़ी टिंगजी लेई को हराया, तो एक अखिल भारतीय फाइनल के लिए मंच तैयार हो गया। दिव्या ने पहले दो गेम फिर से ड्रा करके टाईब्रेकर में जगह बनाई। दूसरे मैच में हंपी का धैर्य जवाब दे गया। एक स्पष्ट ड्रा में उन्होंने जरूरत से ज्यादा जोर लगाया और हार गईं। अंततः शतंरज का विश्व कप 23 साल बाद भारत आया। पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 2000 (तब इसे नाकआउट विश्व चैंपियनशिप कहा जाता था) और 2002 में यह कप जीता था। हालांकि आनंद दोनों ही बार पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे। 15वीं वरीयता प्राप्त दिव्या ने शीर्ष दस में चार खिलाड़ियों को हराकर अपनी बादशाहत कायम की।

परीकथाएं अक्सर लंबी कहानी होती हैं, जो अक्सर छोटी हो जाती हैं। दर्द, कड़ी मेहनत, फार्म में उतार-चढ़ाव और जीवन की कठोर सच्चाइयों के बीच अनगिनत सपने होते हैं। विडंबना यह कि केवल सफलता याद रहती है। दिव्या लंबे समय से माता-पिता के साथ टूर्नामेंट और प्रशिक्षण शिविरों में जाती रही हैं। हर दूसरे शतरंज खिलाड़ी की तरह उन्हें भी उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ा, पर उनकी प्रतिभा पर कभी संदेह नहीं हुआ। भारत में शतरंज के सर्वोत्तम प्रशिक्षण केंद्र के मक्का कहे जाने वाले चेन्नई में दिव्या ने ग्रैंडमास्टर आरबी रमेश के मार्गदर्शन में कई शिविरों में भाग लिया। रमेश में प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने की गहरी समझ है। दिव्या की प्रतिभा तब पहचानी गई, जब वह पिछले शतरंज ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक बनीं। दिव्या की सफलता कोई क्षणिक सफलता नहीं है। वे केवल पिछली पीढ़ी की सफलता दोहराने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ऐसा स्थायी प्रभाव छोड़ना चाहती हैं, जो भविष्य के इतिहास में उनका नाम दर्ज कराए।

जब दिव्या अपने गृहनगर नागपुर पहुंचीं तो वह क्षण बहुत भावुक कर गया, जब उन्होंने गर्व से अपने पहले कोच राहुल जोशी की तस्वीर पकड़ी और अपना ग्रैंडमास्टर खिताब उन्हें समर्पित किया। जोशी का निधन 40 वर्ष की आयु में हो गया था। दिव्या की आंखों में झलक रहा था कि और वह यहीं नहीं रुकने वाली हैं। भारत में एक ट्राफी की कमी खल रही थी और वह थी महिला विश्व शतरंज चैंपियन की। यह कमी पूरी होना इसलिए खास है, क्योंकि शतरंज फुटबाल के बाद दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है।

कहते हैं, 'मुकुट भारी होता है।' विश्व कप जीतने के बाद दिव्या के पहले शब्द थे: 'मुझे अपने खेल में सुधार की जरूरत है।'' इससे हमें यकीन हो जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। बीते कुछ समय में दिव्या जैसी शानदार सफलता अन्य महिला खिलाड़ियों ने भी हासिल की है। इस पर ध्यान दें कि हमारी लड़कियां क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की तरह अन्य खेलों में भी कमाल कर रही हैं, जैसे मनु भाकर, ज्योति याराजी, सिफ्त कौर...। इनकी प्रेरणा हैं पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी काम, सायना नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि।

(लेखक शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर और फिडे के सीनियर ट्रेनर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

परनिंदा

परनिंदा की कुप्रवृत्ति से शायद ही कोई अछूता हो। जिस प्रकार परहित के समान कोई धर्म नहीं, परपीड़ा समान कोई निकृष्टता नहीं, उसी प्रकार परनिंदा भी सर्वथा त्याज्य है। रामचरितमानस में भगवान श्रीराम शबरी को नवधा भक्ति की समझ देते हुए कहते हैं, जो मिले वही पर्याप्त है, उसी में संतोष होना चाहिए और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। यह वर्जना इस बात को स्पष्ट करती है कि जाग्रत अवस्था में परनिंदा से बचना आवश्यक है। अच्छे लोग हमें खुशी देते हैं, श्रेष्ठ लोग स्मरणीय यादें देते हैं, जबकि परनिंदक नकारात्मक बातें सिखाते हैं। किसी संत ने कहा है, ''परनिंदा से किसी को कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे लोग महा मूर्ख होते हैं और पाप का पर्वत ढोने का काम करते हैं।'

परनिंदा को एक प्रकार का रस कहा गया है, जिससे परनिंदा प्रेमी विरत नहीं रह पाते, लेकिन यह एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जिसमें लोग कुंठा, प्रतिशोध या ईर्ष्या के कारण संलग्न होते हैं और अपनी कमियों को छिपाते एवं स्वयं को श्रेष्ठ दिखाते हैं। इससे न केवल दूसरों की भावनाओं का निरादर होता है, बल्कि यह आपसी संबंधों को भी क्षति पहुंचा सकता है। ऋग्वेद के अनुसार, यह स्वयं के अहित का कारण भी बन सकता है, क्योंकि निंदारस में रति पापकर्म के भागी बनने के साथ अपने मूल कार्य को विस्मृत कर देते हैं।

जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, निंदारसभोगी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके ईर्ष्यालु भाव की तरह कोई अन्य भी उसके प्रति ऐसे अनुदार विचार रख सकता है। इसे रस नहीं, घातक रोग समझकर इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सदैव प्रसन्न रहकर, छोटी-छोटी बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर, दूसरों के सहयोगी बनकर, शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहकर, सकारात्मक, धैर्यवान और क्षमाशील बने रहना आवश्यक है। अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधार की ओर अग्रसर होना चाहिए।

एसएन दुबे 'स्नेही'

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

लोकतंत्र के प्रहरी नि :शब्द क्यों?

'महाभियोग' भारतीय लोकतंत्र की वह संवैधानिक ढाल है, जिससे न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी थी, परंतु सुरेंद्र किशोर द्वारा लिखित आलेख 'महाभियोग पर अपनी नाकामी देखे संसद' यह उजागर करता है कि संसद इस ढाल का प्रभावी उपयोग करने में अब तक विफल रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत गंभीर कदाचार या अयोग्यता के आधार पर संसद विशेष बहुमत से न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। इस आलेख में यह तथ्य सटीक रूप से सामने आया है कि भारत में अब तक किसी भी उच्च न्यायाधीश को महाभियोग के जरिये हटाया नहीं जा सका, परंतु इसमें यह पहलू छूट गया है कि इसकी जड़ें सिर्फ संसदीय असफलता तक सीमित नहीं हैं। वास्तविक संकट दोहरे स्तर पर है- पहला, सांसदों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और दूसरा, न्यायिक प्रणाली की आंतरिक पारदर्शिता का अभाव। इसके अलावा 'जज बनाम संसद' की बहस को तूल देना भी इस संवैधानिक प्रक्रिया को निष्प्रभावी करता है। समाधान के तौर पर एक 'न्यायिक नैतिकता आयोग' का गठन आवश्यक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के साथ-साथ लोकपाल, नागरिक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ पत्रकार शामिल हों। यह आयोग न्यायपालिका की आंतरिक शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे। साथ ही नागरिकों को भी चुप्पी तोड़नी होगी। 'न्यायपालिका की गरिमा' के नाम पर अंध समर्थन लोकतंत्र के लिए खतरा है। यदि समय रहते हमने जजों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की, तो आने वाले वर्षों में न्याय व्यवस्था पर से जनविश्वास उठ जाएगा। और तब लोकतंत्र केवल कागजों में रह जाएगा।

awanishg30@gmail.com

कम होगा कोर्ट का बोझ

'लाभकारी पहल' शीर्षक से दैनिक जागरण ने संक्षिप्त आलेख प्रकाशित किया है। राजस्व विभाग ने निश्चित रूप से बेहतरीन प्रयास किया है। कानूनी मामलों के जानकार जब समाज में लोगों से बात करते हैं तो अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि यदि जमीन विवाद खत्म हो जाए तो जिलों में स्थित व्यवहार न्यायालय में फाइलों की ढेर स्वतः कम हो जाएगी। जमीन विवाद के मामले इतने लंबे चलते हैं कि कई बार दशकों बीत जाते हैं, लेकिन मामले का निष्पादन नहीं हो पाता। जमीन विवाद के मामले में आपसी झगड़े भी होते हैं, जिससे मामले बढ़ जाते हैं। इस लिहाज से राजस्व विभाग ने आगामी 16 अगस्त से 18 सितंबर तक घर घर जाकर जमीन के दस्तावेजों को दुरुस्त करने का जो निर्णय किया है, वह वास्तव में लाभकारी होगा। अपने उद्देश्यों का यदि 50 प्रतिशत भी विभाग हासिल कर लेता है तो पूरे भारत में यह एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा और दूसरे राज्य भी इस व्यवस्था को अपने यहां लागू करने पर विचार करेंगे।

विनीत झा, बिलंदपुर, राजापाकर, वैशाली

निसार की क्रांतिकारी भूमिका

गत 30 जुलाई को भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। निसार उपग्रह के सफल लांच के बाद यह मिशन अपने 90 दिनों के निर्णायक कमिशनिंग फेज में है। यह न केवल तकनीकी टेस्टिंग है, बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में एक सक्रिय मानिटरिंग सिस्टम की तैनाती है। इस मिशन की सबसे बड़ी फीचर यह है कि इसमें दोहरा रेडार सिस्टम, एल-बैंड और एस-बैंड का उपयोग किया गया है। यह तकनीक उपग्रह को इतनी संवेदनशीलता प्रदान करती है कि वह पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मिलीमीटर स्तर तक डिटेक्ट कर सकता है। इससे ग्लेशियर मूवमेंट, डिफारेस्टेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम और लैंड स्लाइड डिटेक्शन जैसी गतिविधियों की सटीक मानिटरिंग संभव होगी। इस 90 दिन की अवधि में एंटीना डिप्लायमेंट, आर्बिट स्टेबिलिटी और सिग्नल क्लैरिटी की गहन जांच होगी। यह फेज तय करेगा कि निसार कितना प्रभावी और प्रिसाइज डेटा भविष्य में प्रदान कर पाएगा। आने वाले समय में निसार मिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट पालिसी और बार्डर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। यह मिशन न केवल विज्ञान का उपकरण है, बल्कि मानवता की स्थिरता और सुरक्षा का दूरदर्शी प्लेटफार्म बनकर उभरेगा

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

X पोस्ट

राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को 'डेड' घोषित कर रहे हैं, उसी में उन्होंने 2014 में शेयर बाजार में 1.12 करोड़ रुपये लगाकर 10 करोड़ रुपये बनाए हैं। अगर ऐसी अर्थव्यवस्था डेड है तो भी अच्छी है।

नवनीत मिश्र@navneetmishra99

अमेरिकी धौंस का डटकर सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूरे अंक मिलने चाहिए। आज पश्चिमी जगत पतन का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मेलजोल अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित होगा। इसके जरिये वह एक और 9/11 को न्योता दे रहा है। प्रकाश सिंह@singh_prakash

ट्रंप द्वारा 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाना हमारे लिए एक चेतावनी है। बाहरी मांग अनिश्चित होती है। भारत को अब घरेलू खपत को अपने विकास का मुख्य इंजन बनाना होगा। 1.4 अरब उपभोक्ताओं वाली 4.2 लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है।

अजय बग्गा@Ajay_Bagga

भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वालों की सारी मशक्कत बेकार हो गई। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जनपथ

आधी रोटी खाय के रह लेंगे हम यार,
मत करिए अब ट्रंप से कौड़ी का व्यापार।
कौड़ी का व्यापार सोच जिसकी हो उथली,
उसे न भाते आम गिना करता वह गुठली।
लड़े ब्रिटिश के साथ हमारे बाबा गाँधी,
आधी धोती ओढ़ पहन कर उसमें आधी!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 112

****

कल्पमेधा

धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है।

– डेल कार्नेगी

जांच पर आंच

यह एक विचित्र विडंबना है कि आतंकवाद जैसे जटिल मसलों पर भी किसी खास घटना की जांच, उसकी समूची प्रक्रिया और उसके निष्कर्ष अदालत के कठघरे में ढह जाते हैं और वर्षों से जेल में बंद या फिर आतंकवाद के आरोपों में मुकदमा झेल रहे लोग बरी हो जाते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी मामले में कार्रवाई के क्रम में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर अदालत में मुकदमा चलाया जाए। मगर समूचे मामले की सुनवाई के बाद अगर सभी आरोपी बरी कर दिए जाएं, आरोप साबित करने के लिए पेश सबूतों पर सवाल उठें, तो यह किस तरह की कार्यप्रणाली का सबूत है? गौरतलब है कि पिछले सत्रह वर्षों से सुर्खियों में रहे मालेगांव बम विस्फोट के मामले में गुरुवार को मुंबई की विशेष एनआइए अदालत ने फैसला सुनाया और भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात लोगों को आरोपों से बरी कर दिया। सन 2008 में हुई उस घटना के संदर्भ में अदालत ने कहा कि केवल शक के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते।

अदालत के इस फैसले से एक बार फिर कई सवाल उठे हैं। आतंकवादी वारदात जैसे किसी सबसे संवेदनशील मामले की पड़ताल करते हुए कोई एजंसी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि आरोप और आरोपियों को लेकर उसकी मुख्य स्थापनाएं खारिज कर दी जाएं। मालेगांव बम विस्फोट से जुड़े मुकदमे में विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को निर्दोष करार देते हुए कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है, जिसमें आम नागरिक मारे गए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाया। हैरानी की बात है कि एक ओर जिन सबूतों के आधार पर यह मुकदमा सत्रह वर्षों तक चलता रहा, वे इतने निराधार थे कि सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया, दूसरी ओर उन सबूतों के गलत साबित होने में इतने वर्ष लग गए! इसी तरह, मुंबई में सन 2006 में सिलसिलेवार विस्फोटों के उन्नीस वर्ष के बाद हाई कोर्ट ने सभी बारह आरोपियों को बरी कर दिया। उस मामले में भी अदालत ने यही कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। मुंबई में ट्रेनों में सिलसिलेवार हुए बम विस्फोटों की घटना में तब एक सौ नवासी यात्रियों की जान चली गई थी और आठ सौ चौबीस लोग घायल हो गए थे।

सवाल है कि देश की शीर्ष जांच एजंसियों की कार्यप्रणाली और छानबीन का स्तर अगर यह है कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत बरी कर देती है, तो आखिर उतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले कौन थे और उन्हें नहीं पकड़ पाने के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि जो जांच एजंसियां आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों में पूरी पड़ताल के बाद आरोपियों को कठघरे में खड़ा करती हैं, उनकी जांच अदालत में खामियों से भरी पाई जाती है, गवाहों के बयानों में विरोधाभास होते हैं, कई अपने बयान से मुकर जाते हैं और आखिर आरोपी बरी हो जाते हैं। इसके अलावा, एक ही मामले की जांच करते हुए अगर राष्ट्रीय जांच एजंसी और आतंक निरोधक दस्ते के आरोपपत्र में विरोधाभास होते हैं, तो यह किस तरह की कार्यप्रणाली और तालमेल को दर्शाता है? यह अफसोसनाक है कि किसी आतंकवादी वारदात के मामले में वर्षों तक जांच और मुकदमा चलने के बावजूद आरोपी छूट जाते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हकीकत यह भी है कि फिर उस घटना के वास्तविक दोषी कौन थे और उन्हें कानून के कठघरे में कौन लाएगा!

सुरक्षा की सड़क

देश में बेहतरीन सड़कें बनाने के दावे के बावजूद आज भी कई सड़कें इतनी असुरक्षित क्यों हैं कि उन पर हादसों की आशंका बनी रहती है। कई राज्यों में ऐसी सड़कें हैं, जिनका वर्षों से रखरखाव नहीं हुआ और उन पर सफर करना एक जोखिम से गुजरना है। यह दुखद है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के बावजूद भारत में सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। आज सड़कों पर पैदल चलने वालों तक के लिए जगह नहीं बची है। दोपहिया चालक अक्सर जोखिम में रहते हैं। सड़क निर्माण में भारतीय कौशल से इनकार नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके हमारी सड़कें दुनिया में सबसे खतरनाक हैं, तो इसकी वजह क्या है? सड़कों पर अगर जीवन संकट में पड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि जीवन जीने का अधिकार सचमुच खतरे में है। इसी चिंता को चिह्नित करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि वाहन चलाने योग्य सुरक्षित और अच्छे रखरखाव वाली सड़क संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। दरअसल, अधिकतर राज्यों में लोक निर्माण विभाग खुद सड़कें नहीं बनाता। प्रायः निविदाएं जारी कर ठेकेदारों को जिम्मा सौंप दिया जाता है। नतीजा यह कि सड़कें सुरक्षा मानदंडों पर खरी नहीं उतरतीं।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और निजी कंपनी के बीच विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि सड़क का जिम्मा निजी ठेकेदार पर छोड़ने के बजाय सरकार को यह काम सीधे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। सड़कें जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं, तो इसका गुणवत्तापूर्ण निर्माण और इसकी समुचित देखरेख निस्संदेह सरकार का दायित्व है। आज जिस तरह सड़कों पर वाहनों का बोझ बढ़ा है, इसे देखते हुए सड़कों की देखभाल की जरूरत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। मानवीय भूल अपनी जगह हैं, लेकिन कई स्थानों पर यातायात संकेतक न होने और सड़कों पर दरारें पड़ने और धंसाव ने भी समस्या बढ़ाई है। सड़कों के निर्माण में अधिकतर त्रुटियां खराब अभियांत्रिकी के कारण ही सामने आई हैं। जरूरत इस बात की है कि नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार को बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर स्तर पर जिम्मेदारी तय करे।

संघर्ष के मोर्चे और शांति का तकाजा

गुटों में बंटी दुनिया अपने हितों पर केंद्रित होती जा रही है। अब तक अमेरिका और चीन को ताकतवर माना जाता रहा है। मगर अब वास्तव में ऐसा नहीं है। उभरते नए समीकरण कुछ और ही इशारा कर रहे हैं।

ऋतुपर्ण दवे

आज की नई दुनिया के सामने आसन्न विश्वयुद्ध का ऐसा खतरा पहले कभी नहीं था। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, वह नई तरह की और बहुत बड़ी चुनौतियों संग जोखिम से भरी हुई है। दो-दो विश्वयुद्ध यह दुनिया देख चुकी है। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-1918) और द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-1945) के 80 वर्षों बाद, जो वास्तविकता दिख रही है, वैसी पहले कभी नहीं दिखी। वर्तमान में कई देशों के आपसी युद्ध में विध्वंस की तस्वीरें दहला देती हैं। पहले ऐसा नहीं था। न इतनी उन्नत तकनीक थी और न ही टेलीविजन और सोशल मीडिया का वर्चस्व। युद्ध में उपयोग होने वाले उपकरण भी इतने घातक नहीं थे। ज्यादातर आमने-सामने युद्ध होते थे, तोप, बंदूक, गोला-बारूद और हवाई जहाजों से बमबारी और इससे हुई तबाही की तस्वीरें एक-दो दिनों बाद ही सामने आती थी और दुनिया युद्ध के बारे में जान पाती थी। मगर अब परिदृश्य बदल गया है। मैदान के बजाय आसमान में ही सारी लड़ाई केंद्रित हो गई है। मिसाइल और ड्रोन तकनीक ने हजारों मील दूर से अचूक निशानों के जरिए जहां युद्ध कौशल विकसित किया, वहीं इसकी विभीषिका नए रूप में सामने है। निश्चित रूप से विध्वंस का ऐसा नजारा दिखने लगा है कि युद्ध के नाम से ही लोग सहम जाते हैं।

रूस-यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है। दूसरी ओर कुछ समय पहले मध्य-पूर्व में ईरान-इजराइल के बीच महज बारह दिनों की लड़ाई ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था। तुर्किये-ईरान समेत कई और देशों के बीच तनाव चल रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच भी तनाव कम नहीं है। चीन-अमेरिकी संबंधों में तल्खी छिपी नहीं है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संग्राम ने दुनिया भर के देशों को झकझोर कर रख दिया है। महज दो शक्तिशाली देश आमने-सामने नहीं है, उनके समर्थक भी टकराव करते नजर आ रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच शुल्क और कारोबार को लेकर खींचतान से हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत के मुकाबले कई गुना छोटा देश ताइवान भी आसमान की ओर मिसाइलें ताने खड़ा है। ये संकेत अच्छे नहीं हैं।

अमेरिका का सहयोगियों से पूछना कि अगर चीन से जंग हुई, तो कौन-कौन उसका साथ देगा, यह अलग इशारा है। चिंताजनक यह भी कि महज 35,980 वर्ग किलोमीटर में फैला ताइवान खतरनाक मिसाइलों से लैस है। उसे अमेरिका की शह है। चीन ने ताइवान को उकसाया है। ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। वहां लोकतांत्रिक पद्धति है और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन है। दरअसल, 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान वहां गृहयुद्ध में हार चुकी राष्ट्रवादी सरकार ताइवान चली गई और वहां अपनी सरकार स्थापित की थी। मगर चीन, अब भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसी 12 जुलाई को चीन ने कहा कि वह ताइवान को वापस लेगा। लिहाजा ताइवान भी अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदे। जब ताइवान जैसा छोटा सा देश युद्ध के लिए तत्पर हो, तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं।

ताइवान को लेकर चीन-अमेरिका के बीच वर्षों से जारी टकराव कब किस नए मोड़ पर आ जाए, कोई नहीं जानता। अमेरिका दुनिया के नक्शे में ताइवान को एक देश बताता है। उसे सुरक्षा और उपकरण भी मुहैया कराता है। वहीं चीन कंबोडिया की मदद करने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। कंबोडिया एक ऐसा देश है, जहां पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल बीते युद्धों से बची हुई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए किया जाता रहा है। ऐसी सुरंगों के कारण वहां नागरिक घायल हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। इसे चीन की रणनीतिक चतुराई कहें या ट्रंप की चाल, जैसे ही अमेरिकी प्रशासन ने कंबोडिया को सहायता बंद की, कंबोडियन माइन एक्शन सेंटर यानी सीएमएसी का बयान सामने आया कि चीन ने 44 लाख डालर देने का वादा किया है ताकि बारूदी सुरंगों को साफ करने का काम अगले एक साल तक जारी रह सके। जाहिर है कि चीन, अमेरिका के पीछे हटते ही ऐसे मौके का फायदा उठाने से नहीं चूका और वहां अपना प्रभाव भी बढ़ाने लगा। ऐसा कर चीन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और दूसरे अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे उसकी व्यापारिक और सामरिक नीतियों को बल मिलेगा।

> **रूस-यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है। दूसरी ओर कुछ समय पहले मध्य-पूर्व में ईरान-इजराइल के बीच महज बारह दिनों की लड़ाई ने दुनिया को चिंता में डाल दिया था। तुर्किये-ईरान समेत कई और देशों के बीच तनाव चल रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच भी तनाव कम नहीं है। चीन-अमेरिकी संबंधों में तल्खी छिपी नहीं है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संग्राम ने दुनिया भर के देशों को झकझोर कर रख दिया है। महज दो शक्तिशाली देश आमने-सामने नहीं है, उनके समर्थक भी टकराव में उलझते नजर आ रहे हैं।**

हालांकि चीन की मंशा पश्चिम के पतन की रही है। यह राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में आगे बढ़ती दिख रही है। अपने शुल्क का डर दिखा कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भले ही कैसे भी मंसूबे पाल रखे हों, लेकिन कहीं न कहीं उनका शुल्क संग्राम प्रतिस्पर्धी चीन के लिए एक तरह से मददगार ही है, क्योंकि दुनिया अपने-अपने व्यापार के मामले में चीन की ओर देख रही है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। मगर नीयत के मामले में चीन पर दुनिया को भरोसा नहीं है। बावजूद इसके चीन की गतिविधियां और उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि चीन धीरे-धीरे अपने मंसूबों की ओर दबे पांव बढ़ता जा रहा है।

दुनिया फिलहाल दो देशों के बीच वर्चस्व की टकराहट को देख रही है। मगर भारत की धमक से चीन-अमेरिका दोनों ही उलझन में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को घटाता दिखता है, बल्कि अमेरिका की साख पर भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि उनकी महत्त्वाकांक्षा ने पहले दुनिया के सबसे बड़े अमीर कारोबारी एलन मस्क को गले लगाया और फिर उन्हें दुश्मन मान बैठे। मस्क भी अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाने की चुनौती दे रहे हैं। कमोबेश यही भारत के साथ ट्रंप ने किया। वे अपने चुनाव से पहले तक दोस्ती का दंभ भरते नहीं अघाते थे। मगर अब पूरी तरह से व्यावसायिक हितों की बात करने लगे हैं। वर्चस्व के इस युद्ध में भारत को अब अपनी भूमिका बढ़ानी होगी।

कुल मिला कर स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि गुटों में बंटी दुनिया अपने हितों पर केंद्रित होती जा रही है। अब तक अमेरिका और चीन को ताकतवर माना जाता रहा है। मगर अब वास्तव में ऐसा नहीं है। उभरते नए समीकरण कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। यूरोप के तीन छोटे से देश हैं- एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये बाल्टिक देश कहे जाते हैं। इनका क्षेत्रफल बिहार-झारखंड के कुल क्षेत्रफल के बराबर ही है। मगर ये चर्चा में रहते हैं। चूंकि भौगोलिक रूप से ये न केवल रूस के पास हैं, बल्कि यूक्रेन के भी करीब हैं। मगर अमेरिका की अगुआई वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से भी जुड़े हैं। ऐसी चर्चा है कि चीन अपना पहला हमला ताइवान पर करेगा। यहीं से महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। नाटो देश अमेरिका के साथ आ सकते हैं, तो चीन के साथ रूस, ईरान और उत्तर कोरिया आ सकते हैं। सीरिया, वेनेजुएला और क्यूबा भी रूस के समर्थन में हैं। मगर भारत जैसे कुछ देश हैं, जिनकी स्थिति गुटनिरपेक्ष वाली होगी जो समय-समय पर दिखी भी है।

आंखों से खोती नींद

दुनिया मेरे आगे

अशोक कुमार

सृष्टि के सृजनकाल से ही समस्त जीवों में अनेक शारीरिक क्रियाएं संचालित हो रही हैं। आहार, वायु और जल के अभाव में किसी भी जीव का जीवित रहना संभव नहीं है। इन तीन तत्त्वों के साथ-साथ मानव और अन्य जीवों के शरीर के लिए निद्रा भी एक अति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे शरीर और मन को विश्राम मिलता है। निद्रा की भरपूर खुराक लेकर व्यक्ति फिर दूसरे दिन भरपूर ऊर्जा से अपने काम में लग जाता है। यह हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंश है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हर जीव में निद्रा की अलग-अलग अवस्था है। एक ओर वन्य प्राणी के निद्रा की विविध अवस्था है, जिसमें कुछ जीव रात में नींद लेते हैं, जबकि कुछ दिन में। एक स्वस्थ शरीर को औसतन सात से आठ घंटे तक नींद की जरूरत होती है। युवा और प्रौढ़ स्तर के व्यक्ति अपनी शारीरिक मांग के अनुरूप निद्रा उतने घंटे ही ग्रहण करते हैं, जिससे वे अगले दिन अपने को तरोताजा महसूस करते हुए अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हैं। बुजुर्ग अपने उम्र के पड़ाव और अकेलेपन के कारण कई शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं, जिससे उनकी निद्रा में खलल पड़ती है।

हालांकि इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति के अवयव भी एक अति विशिष्ट कारक हैं, जो निद्रा के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। जिंदगी की भागदौड़ के कुप्रभाव से निद्रा भी अछूती नहीं रह पाई है। नींद में कमी की भारी कीमत समाज के एक बड़े समूह को चुकाने की स्थिति आ गई है। आज एक औसत भारतीय वयस्क प्रत्येक सप्ताह करीब तीन रात की अधूरी नींद ले रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य और दायित्व पालन पर पड़ रहा है। तेरह देशों में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अड़तालीस फीसद भारतीयों को सप्ताह में न्यूनतम तीन दिन नींद लेने में कठिनाई हो रही है, जिस कारण इसमें अधिकांश लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। भारतीय पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की नींद कम हो रही है। कोविड के दुष्परिणाम स्वास्थ्य के कई हिस्सों में उजागर हुए हैं, जिसमें अवसाद के कारण निद्रा भी प्रभावित हुई है। 'घर से काम के निपटान' यानी 'वर्क फ्राम होम' के सिलसिले ने भी नौकरी वाले लोगों की दिनचर्या सीमित कर दी थी और वे व्यायाम और सामाजिक गतिविधियों से मुक्त हो घरेलू तनाव की स्थिति से जुड़ गए थे। इसका कुप्रभाव यह हुआ कि वे मानसिक अवसाद के कारण अनिद्रा के आगोश में चले गए। ऐसी हालात में व्यक्ति का चिड़चिड़ापन, मोटापा, थकान, मधुमेह, रक्तचाप आदि ने उसे असामान्य जीवन जीने को विवश कर दिया।

अब भले लोग पहले से अधिक समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन कम सो रहे हैं। निद्रा में कमी वैसे बच्चों में भी देखी जा रही है, जो सुबह स्कूल आंख मलते हुए जाते हैं, क्योंकि विद्यालय से वापसी के बाद भारी बस्ते में 'होम वर्क' का भय उन्हें ठीक से सोने नहीं दे रहा है। फिर मोबाइल की लत भी नींद उड़ा रही है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के परीक्षार्थी को उच्च अंक पाने की होड़ में देर रात तक तैयारी करने से उनकी निद्रा कम हो रही है। नतीजतन, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का आंशिक लोप भी हो रहा है। उनके भीतर पाचन तंत्र कमजोर, आलस्य भाव और थकान के लक्षण दिख रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, करीब सत्तर फीसद भारतीय अच्छी नींद नहीं सो पा रहे हैं। जापान के नागरिक अपने कामकाज में अधिक संजीदा और परिश्रमी हैं। वे प्रकृति के अधिक नजदीक रहकर अपने खान-पान को भी अनुशासित रखते हैं। वे रात में जल्दी सोते हैं और भरपूर नींद लेकर प्रातः जल्द जागते हैं। अपनी दिनचर्या के प्रति बेहद सख्ती उन्हें हमेशा ऊर्जान्वित किए रहती है।

हमें याद रखना चाहिए कि भारत गांवों का देश है जहां कुल आबादी का सत्तर फीसद लोग वहीं रहते हैं। उनकी जीवन शैली में आधुनिकता के कुछ रंग अवश्य प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका स्वास्थ्य नगरीय जीवन जीने वाले नागरिकों की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल है। शुद्ध आबो-हवा से आच्छादित ग्रामीण परिवेश में कुछ क्षरण के बावजूद आपसी भाईचारे का ताना-बाना बना हुआ है। मानसिक तनाव के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखे जाते हैं, जबकि शहरों में अधिक।

> **जिंदगी की भागदौड़ के कुप्रभाव से निद्रा भी अछूती नहीं रह पाई है। नींद में कमी की भारी कीमत समाज के एक बड़े समूह को चुकाने की स्थिति आ गई है। आज एक औसत भारतीय वयस्क प्रत्येक सप्ताह करीब तीन रात की अधूरी नींद ले रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य और दायित्व पालन पर पड़ रहा है।**

निद्रा हमारे संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में मदद करती है, जैसे कि स्मृति, ध्यान और समस्या-समाधान की प्रवृत्ति को सदा सक्रियता प्रदान करना। ऐसी धारणा पर बल दिया गया है कि शयन कक्ष में आरामदायक वातावरण बनाने से निद्रा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जबकि व्यायाम और पोषणयुक्त आहार से निद्रा में अनुकूलता लाई जा सकती है। महत्त्वपूर्ण यह है कि निद्रा के समय हमारी मनःस्थिति कैसी है। अगर दिन भर के भागमभाग दिनचर्या की परेशानी से हम मुक्त हो शयन कक्ष के मद्धिम प्रकाश में विश्राम के लिए तैयार हैं तो निश्चित हमारी निद्रा शीतल होगी।

कई शोध प्रबंधों ने बताया है कि सोने के पूर्व हल्के संगीत का श्रवण हो या पुस्तक के कुछ पन्नों को पलटा जाए तो नींद ठीक से आ सकती है। डिजिटल युग में मोबाइल संस्कृति के जुड़ाव तरंग से कम से कम शयन के एक घंटे पूर्व निवृत्ति भी अच्छी नींद में सहायक मानी गई है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खेत-खलिहान में हर मौसम में काम करने वाले हमारे किसान भरी दुपहरी में किसी वृक्ष के नीचे चटाई या गमछे बिछाकर थोड़ी देर ही सही गहरी नींद का स्वाद चखकर फिर से अपने शरीर को ऊर्जान्वित कर लेते हैं। उचित तो यही है कि जब नींद के उचाटपन के तानेबाने को हमने बुना है तो शरीर की इस संजीवनी को अपनी दिनचर्या में सम्मान देने के लिए हर चेष्टा करनी होगी।

चौपाल

भ्रष्टाचार का दायरा

भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर बन चुका है जिससे पार पाना बहुत बड़ी चुनौती है। हैरानी की बात यह है कि इस पर नकेल कसने के लिए जो भी भ्रष्टाचार विरोधी इकाई बनाई गई है, उसी के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और रंगे हाथ पकड़े गए। सरकारों द्वारा जितने भी सतर्कता विभाग बनाए गए हैं, वे सब कमजोर साबित हुए हैं। विभागों में तैनात सतर्कता अधिकारी भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। कई लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। व्यवस्था और तंत्र मौन है। देश का सबसे शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जिसके पास भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। शक्तियों के अभाव में संस्था कोई भी सख्त कदम उठाने या कार्रवाई करने में असमर्थ है। देश जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता जा रहा है, इसे देखते हुए अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किया जाए। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अधिक से अधिक वैधानिक शक्तियां देकर उसे शक्तिशाली बनाया जाए और उसकी जवाबदेही भी तय की जाए।

– आरके शर्मा, दिल्ली

आतंक के विरुद्ध

'आतंक का चेहरा' (संपादकीय, 31 जुलाई) पढ़ा। तथ्य यही है कि पहलगाम हमला लश्कर-ए-तैयबा के बिना संभव नहीं था। भारत ने इस आतंकी हमले के जवाब में आपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। आतंकी हमले के बाद हमने वैश्विक मंच पर बार-बार दुनिया के सामने यह सच उजागर किया कि इसके पीछे पाक प्रायोजित 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' का हाथ है जो लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा ईकाई है। पहले अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना और अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की ताजा रपट में भी उसकी संलिप्तता उजागर होने से भारत के इस सत्य की पुष्टि ही हुई है कि पहलगाम हमले में इस आतंकी संगठन का ही हाथ था। सुरक्षा परिषद की रपट को भारत की कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। अब यह वैश्विक संस्थाओं पर निर्भर करता है कि वे आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दावों को किस नजरिए से देखती हैं।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम, हरियाणा

खेल और दुश्मनी

यह सच है कि खेल से आपसी प्रेम बढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी समझदारी की बातों को नहीं समझता है और भारत के प्रति दुश्मनी पाले रहता है। जबकि भारत ने उसे कई बार समझने के मौके भी दिए, लेकिन वह हमारी अहिंसा की भावना को कमजोरी समझने की भूल करता आया है। जिसके दिल में खोट हो, उससे दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके साथ खेलने से पीछे हटना ही बेहतर। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने 'चैंपियनशिप आफ लीजेंड्स 2025' सेमीफाइनल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेलने से मना कर दिया। हालांकि इस फैसले से पाकिस्तान बिना मेहनत किए ही फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इससे हम भारतीयों को जरा भी अफसोस नहीं है कि शत्रु देश की टीम फाइनल में पहुंच गई। हाल ही में पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों ने हमें दर्द दिया। पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे लोगों के साथ उन्होंने जो सलूक किया, उसके जख्म अभी तक हरे हैं।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

शुल्क का दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति के एकतरफा शुल्क एलान से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने की बात होगी। अभी तक अमेरिका इलेक्ट्रानिक मशीनरी, परिवहन उपकरणों और खनिज धातु पर शून्य फीसद शुल्क लगाता था। इसके अलावा पशु उत्पादन में दो फीसद, डेयरी उत्पादों पर 17 फीसद, तेल और तिलहन पर आठ फीसद और सबसे अधिक शराब और तंबाकू पर 18 फीसद शुल्क लगाता था, लेकिन अब यह सब 25 फीसद हो गया। इससे भारतीय निर्यातकों पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से एलान किया है, उससे तो यही लगता है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका देना चाहते हैं। क्या सच में भारत का व्यापार अमेरिका के बिना नहीं चल सकता हैं? फिलहाल शुल्क की नई मार से भारत में क्या परिस्थिति पैदा होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा।

– साक्षी कुमारी, गयाजी, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

अभिमत

प्रेमचंद की लेखनी में किसान, गांव और समाज पर ढेरों कहानियां हैं। जिनमें समाज की कुरीतियां, अभाव, गरीबी झलकती है। इनसे लड़ने की प्रेरणा भी है। जीने की जिजीविषा भी, संघर्ष भी है। कुल मिलाकर, प्रेमचंद ने जो देखा, जो महसूस किया, वह लिखा, वह आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज की समस्याएं, कुरीतियों, देश की गुलामी, राष्ट्रीय आंदोलन सब लिखा।

किसानी पर प्रेमचंद की कहानियां

नवाचार

■ **बाबा मायाराम**

दो दिन पहले 31 जुलाई को प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्मदिन था। उनकी कहानियां बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। उनका जन्म गांव में हुआ था, वहां पढ़े-बढ़े, मास्टरी की, गांव और समाज को देखा, उनके दुख-दर्द से जुड़े, उसे महसूस किया और उन पर कहानी व उपन्यासों की रचना की। आज प्रेमचंद का जीवन और उनकी कुछ कहानियों की चर्चा इस कॉलम में करना चाहूंगा, जिससे प्रेमचंद के जीवन व लेखन की झलक मिले।

यह तो सभी जानते हैं कि उनका जन्म 31 जुलाई, 1880 को बनारस के पास लमही गांव में हुआ था। बचपन में ही माता-पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई की, और शिक्षक की नौकरी की। नौकरी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। बाद में शिक्षा विभाग में स्कूलों का मुआयना करने वाले अधिकारी(इंस्पेक्टर) पर नियुक्त हुए। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हुए। गांधी और टालस्टाय का प्रभाव रहा। इसलिए नौकरी छोड़कर पूरी तरह लेखन करने लगे। कहानियां, उपन्यास, स्तंभ, लेख लिखे। उनकी कई कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

उनका जीवन सीधा सादा था। उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है कि मेरा जीवन सपाट, समतल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं।

उनके साहित्य और जीवन के बीच खाई या दीवार नहीं है। उनके बेटे व साहित्यकार अमृतराय उनकी जीवनी कलम के सिपाही में लिखते हैं कि पौ फटने से पहले ही हल-बैल लेकर अपने खेत पर चले जाने वाले किसान का अनुशासित, पर अनुशासन के आडम्बर से मुक्त, जीवन ही उनका जीवन है।

प्रेमचंद ने हमारे गांव, समाज, किसान को नजदीक से देखा। गांव में उनका जन्म ही हुआ, वे पले—बढ़े भी वहीं, पर बाद में नौकरी के दौरान कई गांवों में जाने का मौका मिला। वहां के दुख-दर्द को महसूस किया, उस पर लिखा, बल्कि खूब लिखा। बल्कि वे एक किसान की ही तरह थे, किसान कुदाल चलाता है, और वे कलम चलाते थे।

उनके बेटे और साहित्यकार अमृतराय ने उनकी जीवनी कलम के सिपाही में बताया है कि प्रेमचंद के लिए लिखने का क्या मायने हैं। लिखना महज दिमाग की खुजली मिटाना नहीं है, बल्कि जिंदगी है तो उसे भी जिंदगी के तमाम और रसझल्लों के बीच जिन्दा रहना होगा। इसकी तदबीर करनी होगी। इसके लिए अपने आपसे लड़ना होगा। दिमाग को दिल को इस बात की ट्रेनिंग देनी होगी।

मैं यहां गांव और किसान से जुड़ी प्रेमचंद की कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा, जिससे पता चल सके कि किसानों की समस्याएं अब भी वही है, जो उनके जमाने में थी। पूस की रात नामक कहानी बताती है कि किसानों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फसल बोने से लेकर फसल कटाई तक कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ठंड में भी खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। इस कहानी में एक किसान दंपति हल्कू और मुन्नी है। उनका खेत है, खेत में फसल है। फसल की रखवाली के लिए किसान जाता है। लेकिन पूस की रात, जब कंपकंपाती ठंड होती है, उस समय रखवाली करना मुश्किल होता है।

जब हल्कू को गर्म कपड़ों के अभाव में, कम्बल के बिना खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। क्योंकि कम्बल के पैसे कर्ज चुकाने के लिए देने पड़े। एक दिन वह उसके कुत्ते के साथ रखवाली करने गया। उस दिन बहुत ठंड थी। अलाव जलाया, कुछ समय उसके सहारे रहा, थोड़ी गर्मी शरीर में आ गई तो नींद आ गई। कुत्ता भोंकता रहा, एक बार हल्कू लगा भी कि खेत मे नीलगायों का झुंड आ गया, उसके कानों में आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। लेकिन यह उसका भ्रम है। वह उठा भी और फिर अलाव के पास बैठ गया और सो गया। और किसान हल्कू की आंख लग गई। और खेत की फसल नीलगायों के झुंड ने चर लिया। जब सुबह हुई तो किसान की पत्नी आई, और देखा कि खेत को जानवरों ने चर लिया है और उसका पति सो रहा है। उसने पति को जगाया और पूछा- क्या आज सोते ही रहोगे ?

आज भी जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा करना बहुत कठिन काम है। बहुत ठंड में भी किसानों को फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। वे मचान (मंडप) बनाकर वहां से खेतों की रखवाली करते हैं पर कई बार इसके बावजूद भी जंगली जानवर फसल चर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं। यह देश के अलग अलग कोनों में देखने में आया है कि फसलों को जानवरों से बचाना बहुत मुश्किल काम है। एक बार उत्तराखंड में गया तो वहां के किसानों ने बताया कि दिन में बंदर, रात में सुअर फसलों को बरबाद कर रहे हैं। यह वैसा ही है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी।

प्रेमचंद की एक और कहानी है दो बैलों की कथा। इस कहानी झुरी नामक किसान के पास दो बैल थे। हीरा और मोती। दोनों में अच्छी दोस्ती है। किसान भी उन दोनों को बहुत प्रेम करता है। वह कुछ समय के लिए उन्हें ससुराल भेज दिए। वहां से लौट आए। पर वहां एक छोटी लड़की बैलों को प्यार करती थीं। रोटी खिलाती थी। लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और वे रस्सी तुड़ाकर भाग गए।

किसी के मटर के खेत में घुस गए। कांजी हाऊस में बंद कर दिए गए। एक हफ्ते दोनों बैल वहीं बंधे रहे। वहां ढंग से न चारा मिला न पानी। दोनों कमजोर हो गए। हड्डियां निकल आईं। कुछ दिन बाद दोनों की नीलामी हो गई। नीलामी से खरीदने वाला व्यक्ति बैलों को लेकर चला, रास्ते में जिस किसान के बैल थे, वह उसके घर के पास जाकर रूक गए। किसान झूरी बोला- ये बैल मेरे हैं। नीलाम में लेने वाला बोला- मैंने तो नीलाम में लिए हैं। दोनों बैलों ने नीलाम लेने वाले व्यक्ति को दौड़ाया और इस तरह दोनों बैल उनके मालिक के पास ही रह गए।

यह कहानी बार-बार पढ़कर ग्रामीण व खेती-किसानी में बैलों का, पशुओं का महत्व समझ आता है। लेकिन अब बैलों की जगह ट्रेक्टर ने ले ली है। बैल हमारी खेती से बाहर हो गए हैं। पशु सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी दुर्दशा जीवन में पशुओं की नहीं देखी। पहले गांव में बड़ी संख्या में पशु होते थे। खेती भी बैलों पर निर्भर होती थी। उसके गोबर खाद से मिट्टी उर्वर होती थी। फसल अच्छी होती थी। फसलों के अवशेष व ठंडल पशुओं को खिलाने के काम आते थे। इस तरह खेती में लागत भी बहुत कम लगती थी।

इसी तरह प्रेमचंद की लेखनी में किसान, गांव और समाज पर ढेरों कहानियां हैं। जिनमें समाज की कुरीतियां, अभाव, गरीबी झलकती है। इनसे लड़ने की प्रेरणा भी है। जीने की जिजीविषा भी, संघर्ष भी है। कुल मिलाकर, प्रेमचंद ने जो देखा, जो महसूस किया, वह लिखा, वह आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज की समस्याएं, कुरीतियों, देश की गुलामी, राष्ट्रीय आंदोलन सब लिखा, कहानियों व उपन्यासों के माध्यम से रचनात्मक ढंग से कलम चलाई। वे जीवन में ऐसे ही संघर्ष करते रहे, अभाव, घरेलू परेशानियों से जूझते रहे। लेकिन फिर भी लिखते रहे, एक निष्काम कर्मयोगी की तरह, निरंतर अपने काम में लगे रहे। उनका जीवन व लेखन एक जैसा है, यही उनके साहित्य में है। इसलिए उनका जीवन और लेखन दोनों ही प्रेरणास्पद है। उनसे सदैव ही पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी।

ग्रामीण व खेती-किसानी में बैलों का, पशुओं का महत्व समझ आता है। लेकिन अब बैलों की जगह ट्रेक्टर ने ले ली है। बैल हमारी खेती से बाहर हो गए हैं। पशु सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी दुर्दशा जीवन में पशुओं की नहीं देखी। पहले गांव में बड़ी संख्या में पशु होते थे। खेती भी बैलों पर निर्भर होती थी। उसके गोबर खाद से मिट्टी उर्वर होती थी। फसल अच्छी होती थी। फसलों के अवशेष व ठंडल पशुओं को खिलाने के काम आते थे।

बीता सप्ताह

26 जुलाई

- राजस्थान में झालावाड़ में एक स्कूल की दत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई।
- लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली।
- अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ केन्द्र सरकार ने एएलटीटी, उतलू समेत 25 ओटीटी प्लेटफार्म प्रतिबंधित कर दिया।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मानव रहित यान से मिसाइल दागने का परीक्षण सफल कर लिया।

27 जुलाई

- पीएम नरेन्द्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
- लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सुप्रिया सुले सहित 17 सांसदों को मिला संसद रत्न।
- कंबोडिया बौद्ध विश्वविद्यालय के आईटी सेंटर से 150 छात्रों ने की डिग्री पूरी।
- फिलीपींस में चक्रवाती तूफान से 30 लोगों की मौत हो गई।

28 जुलाई

- हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई।
- थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष में 80 हजार कंबोडियाई ग्रामीणों ने छोड़ा घर। सकूल कॉलेज बंद हुए।
- चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का प्रस्ताव रखा।
- सिंगापुर में विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशीप 2025 में कनाडाई सुपरस्टर समर मैकिन्रोश ने महिलाओं के 400 मीटर तैराकी फाइनल में स्वर्णपदक जीता।

29 जुलाई

- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी दबाव में नहीं रोका गया।
- सेना का ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर में तीन आतंकी ढेर। पहलगाम हमले का मास्टर माइंड सुलेमान शाह उफ हाशिम मूस्म भी मारा गया।
- भारत की शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्वकप का खिताब जीता।
- सुप्रीम कोद्ट ने बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

30 जुलाई

- पीएम मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की बहस पर स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रूकवाई।
- पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीन आतंकी ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिए गए। अमित शाह ने यह जानकारी संसद में दी।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रलय मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए।
- स्वच्छता सर्वे में छत्तीसगढ़ ने सुधारी अपनी रैकिंग, टॉप 100 में छत्तीसगढ़ी के 25 शहर आए। 169 में 115 शहरों ने सुधारी रैकिंग।

31 जुलाई

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर 25 फीसदी टेरिफ लगाएगा।
- अंतरिक्ष में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उपग्रह निसार सफलता पूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ।
- चीनी पासपोर्ट धारक दुनियाभर के 90 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में यात्रा कर सकते हैं।
- भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन शिवशक्ति के तहत दो आतंकी ढेर किए।

1 अगस्त

- छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए प्रदेश को मिली 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात।
- उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा मोदी व डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है देश।
- महाराष्ट्र में प्रसिद्ध शनि शिगंणापुर मंदिर में हुआ बड़ा घोटाला।
- पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत बुनियादी ढांचे का हो रहा विकास।

मोदी सरकार व्यापार पैटर्न को संतुलित करे और घरेलू खपत को बढ़ावा दे

■ **डॉ. नीलांजन बनिक**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय निर्यात पर 25प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है जो आज एक अगस्त से लागू हो गया है। उन्होंने भारतीय निर्यात पर एक अतिरिक्त जुर्माने की भी बात की, जो रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने वाले देशों पर अधिभार के रूप में 100 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प को 'मित्र' भारत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारत के साथ व्यापार का हिस्सा चीन के साथ अमेरिका के व्यापार की तुलना में बहुत कम है। अमेरिकी हितों के कारण, चीन को भारत की तुलना में बेहतर व्यापार समझौता मिलने की संभावना है -चीन को अमेरिकी चिप-डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध हटाना इसका एक उदाहरण है।

यह पहली बार नहीं है जब ट्रम्प ने भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने न केवल भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया था, बल्कि उन्होंने भारत को सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) से भी हटा दिया था। 1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा स्थापित जीएसपी के तहत, अमेरिकी नीति निर्माताओं ने नामित लाभार्थी देशों – मुख्य रूप से निम्न-आय वाले देशों- से लगभग 3,500 उत्पादों के आयात को तरजीही शुल्क-मुक्त (शून्य-टैरिफ) दर पर अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य इन देशों को अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने में मदद करना था। विश्व बैंक के अनुसार, 'निम्न-आय' वाला देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2024 में प्रति वर्ष .1,045 से कम था।

चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है, इसलिए बढ़ते प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों के कारण दबाव महसूस होना स्वाभाविक है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत अमेरिका को जाता है, जिसका मूल्य 2023 में 77 अरब डॉलर और 2024 में 78 अरब डॉलर होगा।

हालांकि, यदि जीएसपी की वापसी सहित पिछले प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों को कोई संकेत माना जाए, तो इसका प्रभाव अपेक्षाकृत मामूली रहा है। जीएसपी के अंतर्गत योग्य वस्तुओं की एक त्वरित समीक्षा से पता चलता है कि वे मुख्य रूप से वस्त्र और परिधान, घड़ियां, जूते, काम के दस्ताने, ऑटोमोटिव घटक और चमड़े के परिधान जैसी श्रेणियों में आते हैं।

इन प्रमुख निर्यात श्रेणियों में, वस्त्र और परिधान तथा ऑटोमोटिव घटकों की कुछ वस्तुओं को जीएसपी सूची में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्बनिक रसायन, इस्पात और कुछ इंजीनियरिंग वस्तुओं—जैसे परमाणु बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों—का निर्यात भी जीएसपी लाभों की वापसी से प्रभावित हुआ। हालांकि, अमेरिका को कुल भारतीय निर्यात के अनुपात के रूप में इन वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाकृत कम है। भारत द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में मुख्यत: हीरे 19 प्रतिशत, पैकेज्ड दवाइयां 14प्रतिशत, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद 8.9प्रतिशत, ऑटोमोटिव कंपोनेंट 2.1प्रतिशत, और वस्त्र एवं परिधान 3.7प्रतिशत शामिल हैं। उपरोक्त में दिए गए प्रतिशत भारत के कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में अमेरिका को भारत के निर्यात की हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हाल ही में हुए हस्ताक्षर से दीर्घावधि में अत्यधिक टैरिफ के कुछ नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारतीय नीति निर्माताओं ने लगभग 20प्रतिशत टैरिफ की उम्मीद की थी, लेकिन ट्रम्प ने अंतत: 25प्रतिशत की दर लागू कर दी। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की बदौलत, भारत को अपने 99प्रतिशत निर्यात पर शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा, विशेष रूप से वस्त्र, आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में – ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में टिप्पणीकारों को डर है कि उच्च अमेरिकी टैरिफ से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका को भारतीय निर्यात पर भी सापेक्षिक रूप से कम असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रम्प ने उन देशों पर एकतरफ़ा टैरिफ़ लगा दिए हैं जिनके निर्यात अमेरिकी बाज़ार में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

बाहरी झटकों- चाहे संरक्षणवादी टैरिफ़ हों या युद्ध – का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए, भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र/निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मज़बूत घरेलू क्षेत्र से लाभान्वित होती है, जहां घरेलू खपत, सरकारी खर्च और निजी निवेश मिलकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण मूल्यवर्धन का योगदान 1 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है, जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में कोई सुधार नहीं दर्शाता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख चालक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) घट रहा है। 2023-24 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में सकल एफडीआई प्रवाह घटकर केवल 1 प्रतिशत और शुद्ध एफडीआई घटकर 0.6प्रतिशत रह गया है – जो 2005-06 के बाद से नहीं देखा गया स्तर है। व्यावसायिक वातावरण में कठोरता, उल्टा शुल्क ढांचा (आईडीएस) और भारत द्वारा द्विपक्षीय संधियों को समाप्त करने के निर्णय को एफडीआई के प्रवाह को हतोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

कट्स इंटरनेशनल द्वारा कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और धातु क्षेत्र में 1,464 टैरिफ लाइनों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि आईडीएस किस प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धात्मकता, जिसमें वस्त्र उद्योग से 136, इलेक्ट्रॉनिक्स से 179, रसायन से 64 और धातुओं से 191 वस्तुएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए, 14 डॉलर (1,000 रुपये) से कम कीमत वाले परिधानों पर 5प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि 14 डॉलर से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 12प्रतिशत कर लगता है। कपड़ा निर्माताओं के लिए, विपणन, गोदाम किराया, रसद, कूरियर सेवाओं और अन्य पूर्ति लागतों जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं में भी महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।

हालांकि, इन अतिरिक्त सेवाओं पर 18प्रतिशत की उच्च जीएसटी दर लागू होती है, जिससे ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। भारत के बजट 2025 में आईडीएस के मुद्दे को संबोधित किया गया है; उदाहरण के लिए, सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर टैरिफ 10प्रतिशत से बढ़ाकर 20प्रतिशत कर दिया है, जबकि ओपन सेल और संबंधित घटकों पर टैरिफ घटाकर 5प्रतिशत कर दिया है। इस प्रवृत्ति को जारी रखने की आवश्यकता है, और नीति निर्माताओं को विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए और सुधारों को लागू करना चाहिए।

टैरिफ वार्ता एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन भारत अमेरिकी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाकर अपनी स्थिति मज़बूत करने पर विचार कर सकता है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने खुद को एक प्रमुख हथियार विक्रेता के रूप में स्थापित किया और ज़्यादा हथियार और तेल बेचने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने 2008 से अब तक लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य की अमेरिकी रक्षा सामग्री के लिए अनुबंध किए हैं। संभावित ट्रंप 2.0 में भी यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। भारत को भी टैरिफ पर कम और घरेलू विकृतियों को दूर करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।

बाहरी झटकों- चाहे संरक्षणवादी टैरिफ़ हों या युद्ध – का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए, भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र/निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मज़बूत घरेलू क्षेत्र से लाभान्वित होती है, जहां घरेलू खपत, सरकारी खर्च और निजी निवेश मिलकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

मुंबई ट्रेन धमाके : हाईकोर्ट ने खोली जांच की पोल

11 जुलाई, 2006 को शाम 6.23 से 6.29 के बीच मुंबई की उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क में हुए सात सिलसिलेवार बम धमाकों में 187 की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हुए थे। रेल यात्री एक आसान लक्ष्य थे जिनके खिलाफ यह भयानक अपराध किया गया था। भारत के व्यवसायिक केंद्र मुंबई में लोकल ट्रेनें शहर के उत्तर-दक्षिण गलियारे में एक दिन में 60 लाख से अधिक आम लोगों को ले जाती हैं। इन विस्फोटों ने शहर और देश को हिलाकर रख दिया था लेकिन एक अलग तरह का झटका 19 साल बाद लगा जब 21 जुलाई, 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि मामला प्रभावी ढंग से हल नहीं हुआ है और 'असली खतरा बड़े पैमाने पर बना हुआ है'। उच्च न्यायालय ने मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से पांच को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में मामले की गलत जांच के लिए पुलिस के खिलाफ कठोर टिप्पणियां की हैं।

जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने 667 पन्नों के फैसले की शुरुआत इन शब्दों से की- 'अपराध के वास्तविक अपराधी को दंडित करना आपराधिक गतिविधियों को रोकने, कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस और आवश्यक कदम है। लेकिन आरोपियों को कटघरे में पेश कर किसी मामले को सुलझाने का झूठा आभास पैदा करना समाधान की भ्रामक भावना पैदा करता है। यह जनता के विश्वास को कम करता है और समाज को झूठा आश्वस्त करता है जबकि वास्तव में असली खतरा बड़े पैमाने पर बना हुआ है।'

वास्तव में न्यायाधीशों ने दर्ज किया कि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हम नहीं जानते कि अपराध किसने किया। कुछ निर्दोषों को यातनाएं दी गईं और हत्यारों के रूप में पेश किया गया लेकिन विस्तार से बनायी गयी कहानी जांच में खरी नहीं उतरी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी न केवल जांच एजेंसियों के लिए शर्म और बदनामी की बात है बल्कि उसने ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए जो इस तरह के एक सुनियोजित, समन्वित एवं जघन्य अपराध की तह तक जाने के लिए जांच की गुणवत्ता या एजेंसियों और उनके नेतृत्व की क्षमता से परे है। उन्होंने पूरे जांच नेटवर्क की अखंडता पर सवाल उठाए जिसने कानून के लंबे हाथ का इस्तेमाल किया और उन आरोपों को दबाया जो ठोस रूप से खारिज कर दिए जाते हैं। हालांकि यह ज्ञात है कि पुलिस प्रणाली परिपूर्ण नहीं है और विशेष रूप से संवेदनशील जांच के मामलों में कानून की उचित प्रक्रिया और बारीकियां खिंच जाती हैं। इस बात को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों में कानून के इस प्रकार के थोक उल्लंघन ने इस मामले में राज्य और उसकी एजेंसियों को एक नए धरातल पर खड़ा कर दिया है।

इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बारे में राज्य की काफी स्वाभाविक और स्पष्ट प्रतिक्रिया रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो इस हद तक इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की कि यह फैसला वर्तमान में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत अभियोजित अन्य मामलों की सुनवाई कर रही निचली अदालतों के समक्ष मिसाल के रूप में काम नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह ने अपने आदेश में कहा कि बरी होने के बाद पहले ही रिहा किए जा चुके लोगों को जेल में डालने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि 'कानून के सवाल पर विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए हम यह मानने के इच्छुक हैं कि विवादित निर्णय को किसी अन्य लंबित कार्रवाई में एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा इसलिए उस सीमा तक विवादित निर्णय के संचालन पर रोक रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान इस बात के लिए पर्याप्त समय है कि उच्च न्यायालय के फैसले से कुछ सबक लिए जाएं जिसमें आंखें खोलने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यदि जनता को यह विश्वास दिलाना है कि आतंकवादियों को सजा मिलेगी तो इसके लिए प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष अधिकारियों के बीच आंतरिक आत्म-मंथन शुरू होना चाहिए और अभियानों की कुछ समीक्षा होनी चाहिए। इस मामले से पता चलता है कि किसी भी अपराध को हल करने में यातना के उपयोग सहित जांच के पुराने तरीके मदद नहीं करते हैं लेकिन वास्तव में उनका उपयोग जांच की पसंदीदा रेखा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि असली अपराधी पहुंच से बाहर हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के शब्दों की गूंज जबरदस्त है। एक जगह जस्टिस ने कहा- आरोपी से कबूलनामे के लिए अपनाई गई पुलिस की बर्बरता और यातना के इस विस्तृत विवरण (फैसले के पिछले पैरा में वर्णित) को पढ़ना और कल्पना करना मुश्किल है; और अगर इसे सच और सही माना जाता है तो यह निश्चित रूप से अमानवीय, बर्बर और कठोर तरीकों को दर्शाता है। शिकायत में जिस तरह की यातना का जिक्र किया गया है, वह किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर देगी। वर्णन से पता चलता है कि बताई गई घटनाएं अस्पष्ट व सामान्य नहीं बल्कि विवरण अर्थात तारीख, स्थान, अधिकारियों के नाम और यातना की प्रकृति के साथ हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि, 'बर्बर और अमानवीय यातना' के इस विवरण की पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सकीय साक्ष्यों से भी होती है। अन्य स्थानों पर अदालत ने पाया कि इकबालिया बयानों से अपराध के महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा नहीं होता है, जैसे- 1. बमों को किन कंटेनरों में पैक किया गया था 2. बमों में कैसे विस्फोट किया गया था 3. बमों को ट्रिगर करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया था 4. डिवाइस कैसे सटीक रूप से सक्रिय हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात; 5. माहिम और बांद्रा स्टेशनों पर विस्फोट करने वाले बम किसने लगाए ?

एक बड़ी तस्वीर जो उभरती है वह असफल प्रशासन की है जो मजबूत आंतरिक और बाहरी जांच के अभाव में ढलान पर तेजी से फिसल रहा है, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अंधा समर्थन कर रहा है जबकि असली आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं और जो गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने से इनकार कर रहा है। इससे भी बदतर, यह एक धर्मनिरपेक्ष गिरावट है। हम किसी एक पार्टी या सरकार को दोष नहीं दे सकते- सभी एक ही नाव में सवार हैं और इस पतन में साझेदार हैं। धमाकों के बाद से महाराष्ट्र में विभिन्न दलों और सरकारों के तहत कुल 10 सरकारें रही हैं जिनमें दो बार केंद्रीय शासन भी शामिल है।

आखिरी बात, शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। वे न्याय के लिए काम नहीं करते हैं। वे देश के लिए अहितकारी हैं। यह संदेश पुलिस बल को नीचे से ऊपर तक भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह कुछ वर्गों ने बरी किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है, उसी तरह जांच में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। हमें वास्तविक दोषियों को खोजने के लिए कार्य करना चाहिए तथा उन सभी को दंडित करना चाहिए जिन्होंने मानदंडों का उल्लंघन किया है और हमें इस स्थिति तक पहुंचाया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट:द बिलियन प्रेस)

जगदीश रत्तनानी

एक बड़ी तस्वीर जो उभरती है वह असफल प्रशासन की है जो मजबूत आंतरिक और बाहरी जांच के अभाव में ढलान पर तेजी से फिसल रहा है, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अंधा समर्थन कर रहा है जबकि असली आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं और जो गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने से इनकार कर रहा है। इससे भी बदतर, यह एक धर्मनिरपेक्ष गिरावट है। हम किसी एक पार्टी या सरकार को दोष नहीं दे सकते।

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

अदालतों में बेनकाब हो रही जांच एजेंसियों की विफलताएं

क्या हमारी जांच एजेंसियां कॉम्पिटेंट नहीं रह गई हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में जिस तरह आरोपित बरी हो गए, उससे लगता है कि पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी एजेंसियों ने सुबूत जुटाने में कानूनी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। आखिर घटना तो घटी है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 178 से अधिक लोग मारे गए थे, उसी तरह मालेगांव ब्लास्ट में भी 7 लोग मारे गए थे व 93 लोग घायल हुए थे। जिन मामले में आतंकी कनेक्शन हैं, उसकी जांच में भी ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि एनआईए, सीबीआई, एसआईटी जैसी विशेषज्ञ जांचकर्ता वाली एजेंसियां अपने काम में कोताही बरतती होंगी, या उन्हें तकनीकी जांच का तरीका नहीं मालूम है। इसके बाद भी अगर आतंकी कनेक्शन वाले ब्लास्ट केसों में आरोपित बरी हो जा रहे हैं, हमारी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे ही। आखिर अदालतों में जांच एजेंसियों की विफलताएं क्यों बेनकाब हो रही है? करीब 17 वर्ष पहले 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें भगवा आतंकवाद का जुमला कांग्रेस की तरफ से उछला था। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में अभियुक्त रहीं बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व कर्नल पुरोहित समेत सात लोगों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश एके लाहोटी ने सभी अभियुक्तों को निर्दोष करार देते हुए कहा, 'यह एक अत्यंत गंभीर मामला है, जिसमें आम नागरिकों की जान गई, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाया।' न्यायाधीश लाहोटी ने कहा, 'केवल शक के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किए जा सकते।' अदालत की टिप्पणी जांच एजेंसियों के कामकाज की कलई खोलती है। अदालत ने ऐसी ही सख्त टिप्पणी मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में भी सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए की थी। मालेगांव ब्लास्ट किसने करवाया, 17 साल बाद भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। इसी तरह मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगारों का भी पता नहीं लगाया जा सका है। एक ही महीने में आए इन दो फ़ैसलों ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मालेगांव का मामला इसलिए भी अधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से बड़ा बन गया, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। इसके अलावा, लेफ़्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी धमाके की साज़िश के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था। वे उस समय भारतीय सेना में कार्यरत थे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अभी कुछ ही दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्यप्रणाली व कनविक्शन रेट को लेकर फटकार लगाई थी। ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसियां गंभीरता से तथ्यों के आधार पर काम नहीं कर रही हैं, परसेप्शन व शक को अधिक तरजीह दे रही हैं, शायद इसलिए केस अदालतों में नहीं ठहर रहे हैं। सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए आंकड़े के मुताबिक, ईडी की सफलता दर सिर्फ 0.13 फीसदी है 5892 मामले दर्ज किए, जिसमें 77% में साक्ष्य नही और केवल 8% दोषी करार दिए गए। पिछले दस सालों में ईडी ने राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से केवल दो में ही केस बने। जांच एजेंसियों को आत्मावलोकन करना चाहिए और मुंबई-मालेगांव ब्लास्ट के दोषियों का पता लगाना चाहिए।

रूस त्रासदी
प्रमोद भार्गव

रूस के पूरब में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में 30 जुलाई 2025 को आए भूकंप के झटकों से कामचटका और उसके आसपास कुरील द्वीप समूह के भूखंड हिल गए। इसे विश्व में आए सबसे तीव्र भूकंपों में दर्ज किया गया है। इस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान और अनेक लोगों के घायल होने की सूचनाएं हैं, इसके असर से प्रायद्वीप के समुद्र तटों से 16 फीट ऊंची सुनामी जैसी लहरें टकराईं, जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इसकी तुलना मार्च 2011 में जापान में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप से की जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं अब व्यापक व विनाशकारी साबित हो रही हैं, क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडल भी परिवर्तित हो रहा है।

भूकंप-सुनामी दे रहे खतरनाक संदेश

तीन साल से भी अधिक समय से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस में 8.8 तीव्रता के भीषण भूकंप ने नई त्रासदी खड़ी कर दी है। रूस के पूरब में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में 30 जुलाई 2025 को आए भूकंप के झटकों से कामचटका और उसके आसपास कुरील द्वीप समूह के भूखंड हिल गए। इसे विश्व में आए सबसे तीव्र भूकंपों में दर्ज किया गया है। इस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान और अनेक लोगों के घायल होने की सूचनाएं हैं, इसके असर से प्रायद्वीप के समुद्र तटों से 16 फीट ऊंची सुनामी जैसी लहरें टकराईं, जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इसकी तुलना मार्च 2011 में जापान में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप से की जा रही है। इसे समुद्री सुनामी कहा गया था। इस सुनामी से जापान के फुकुशिमा, दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कूलिंग सिस्टम निष्क्रिय करना पड़ा था। कामचटका में चार नवंबर 1992 को आए 9.0 तीव्रता के भूकंप के कारण भारी क्षति हुई थी। इस भूकंप से जनहानि इसलिए नहीं होने पाई, क्योंकि भूकंप क्षेत्र से रूस का बड़ा शहर पेत्रोपावलोव्स्क-कामचत्सकी लगभग 119 किमी की दूरी पर है। यहां की आबादी 18 लाख हैं।

भूकंप के बाद आने वाली सुनामी के खतरे से जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के तटवर्ती देशों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जापानी और अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया कि इस भूकंप की आरंभिक तीव्रता 8.0 थी, किंतु अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस तीव्रता का आकलन 8.8 किया और इसे 20.7 किमी भू-गर्भ से आना बताया है। अलास्का स्थित राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केन्द्र के समन्वयक डेव स्नाइडर का कहना है कि सुनामी जैसी लहरों का प्रभाव कई घंटों या एक दिन से भी अधिक समय तक रह सकता है। सुनामी एक विमान की गति से सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र पार करती है। किंतु जब लहरें किनारे के निकट पहुंचती हैं, तब उनकी गति धीमी पड़ जाती है। किंतु किनारे पर इनके एकत्रीकरण से जल प्रलावन की आशंका बढ़ जाती है। इस कारण पानी की ये लहरें धरती पर पहुंचती हैं और आगे- पीछे होती रहती हैं। दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में हमारा भी हाथ होता है। प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हुई है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जो भूकंप आया था, उनसे 20 थर्मान्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। यहां हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा-नागाशाकी में गिराए गए परमाणु बमों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। 2011 में जापान और फिर क्योटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चलता है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रही भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी

अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भी भूकंप के मुहाने पर हैं। जापान, इक्वाडोर और नेपाल समेत पूरी दुनिया इस अभिशाप को झेलने के लिए जब-तब विवश होती रही है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए जरूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब साढ़े पांच करोड़ साल पहले भारत और आस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक-दूसरे से अलग हो गईं और वे यूरेशिया परत से जा टकराईं। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूद दरारें बनीं। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है,जहां पृथ्वी की दो अलग-अलग परतें परस्पर टकराकर एक-दूसरे के भीतर घुस गई थीं। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया से हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसी प्रायद्वीप में ज्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किमी भीतर होती है। जापान के कुमामोतो में आया भूकंप जमीन से 20 किमी और क्योटो का 10 किमी नीचे था। जबकि नेपाल में जो भूकंप आया था, वह जमीन से महज 15 किमी नीचे था। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें जमीन से कम से कम 30 किमी नीचे से चलती हैं। ये तरंगें जितनी कम गहराई से उठेंगी, उतनी तबाही भी ज्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव भी कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है अब कम गहराई के भूकंपों का दौर चल पड़ा है। दरअसल, सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने व कम दबाव के कारण कमजोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है। कुछ भूकंप धरती की सतह से 100 से 650 किमी के नीचे भी आते हैं,लेकिन तीव्रता धरती की सतह पर आते-आते कम हो जाती है,इसलिए बड़े रूप में त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती है। दरअसल इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि एक तरह से वह द्रव रूप में बदल जाती है। इसलिए इसके झटकों का असर धरती पर कम ही दिखाई देता है। धरती की इतनी गहराई से प्रगट हुआ सबसे बड़ा भूकंप 1994 में बोलिविया में रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी की सतह से 600 किमी भीतर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। इसीलिए यह मान्यता बनी है कि इतनी गहराई से चले भूकंप धरती पर तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चट्टानें तरल द्रव्य के रूप में बदल जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं अब व्यापक व विनाशकारी साबित हो रही हैं, क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडल भी परिवर्तित हो रहा है।

यूरोपीय देशों में दो शताब्दियों के भीतर बेतहाशा अमीरी बढ़ी है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण इसी अमीरी की उपज है। यह कथित विकासवादी अवधारणा कुछ और नहीं, प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन कर, पृथ्वी को खोखला करने के ऐसे उपाय हैं, जो ब्रह्मांड में फैले अवयवों में असंतुलन बढ़ा रहे हैं। नतीजतन जो कॉर्बन गैसें बेहद न्यूनतम मात्रा में बनती थीं, वे अब अधिकतम मात्रा में बनने लगी हैं। धरती पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी प्रत्यावर्तित होने की बजाय, धरती में ही समाने लगी है। गोया, धरती का तापमान बढ़ने लगा, जो जलवायु परिवर्तन का कारण तो बना ही, प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन रहा है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

अर्थव्यवस्था
राजेश माहेश्वरी

डिजिटल भुगतान से आर्थिक विकास को मिली नई गति

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से हाल ही में जारी किए गए एक नोट, 'बढ़ता रिटेल डिजिटल भुगतानः इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व' के अनुसार, भारत तेज भुगतान में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। इस बदलाव का मूल आधार एकीकृत भुगतान इंटरफेस है, जिसे यूपीआई के नाम से जाना जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने देश में लोगों के पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को बदल दिया है। आज, भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने 18 बिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं। यूपीआई अब केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है। यह सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में नवाचार के लिए एक वैश्विक मानक है। आज यूपीआई का स्तर उल्लेखनीय है। अकेले जून 2025 में, इसने 24.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान किए। इसके जरिए 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन किए गए। बीते साल इसी महीने 13.88 बिलियन लेन-देन की तुलना में हुई यह प्रगति स्पष्ट है। केवल एक साल में इसमें लगभग 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई प्रणाली अब 491 मिलियन लोगों और 65 मिलियन कारोबारियों को सेवाएं देती है। यह 675 बैंकों को एक ही मंच पर जोड़ती है, जिससे लोग बिना किसी चिंता के आसानी से भुगतान कर सकते हैं कि वे किस बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के डिजिटल भुगतान का दायरा अभूतपूर्व वृद्धि के साथ पूरी दुनिया में अग्रणी बन चुका है। इस डिजिटल भुगतान की लहर ने विशेष रूप से वंचित एवं ग्रामीण समुदायों के वित्तीय लेनदेन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मोदी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-एनपीसीआई, फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर जैसी पिछड़े और संवेदनशील क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करने के लिए 2021 में आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड- पीआईडीएफ की स्थापना की। अब तक इस फंड के माध्यम से लगभग 4.77 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट देशभर में तैनात किए जा चुके हैं। ये टच पॉइंट डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को छोटे से छोटे गांव, कस्बा, सरकारी दफ्तर और व्यापारी केंद्रों तक पहुंचाने में सहायक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की प्रगति को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी आरबीआई—डीपीआई विकसित किया है, जो हर छह महीने में प्रकाशित होता है। यह सूचकांक मार्च 2025 तक 493.22 पर पहुंच गया, जो देशभर में डिजिटल भुगतान के अपनाने, बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन में निरंतर बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। यह संकेत है कि भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से सशक्त हो रहा है। यूपीआई की मदद से लाखों छोटे विक्रेता डिजिटल भुगतान स्वीकार कर पा रहे हैं, जिससे नकद लेनदेन की निर्भरता कम हो रही है। इसके अलावा, छोटे व्यापारियों के लिए कम-मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना, टीआरईडीएस के माध्यम से छूट देने की व्यवस्था और डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर को युक्तिसंगत बनाना जैसे कदम डिजिटल भुगतान को अधिक सुलभ और लाभकारी बना रहे हैं। यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम बना हुआ है। डिजिटल भुगतान की इस तेजी के साथ भारत ने खुद को एक अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी के रूप में स्थापित कर लिया है। डिजिटल रुपया और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान नेटवर्क के विकास से वित्तीय लेनदेन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और त्वरित होंगे। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को और देश-विदेश में विस्तार देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भारत एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हब बन सके। भारत यूपीआई को ब्रिक्स समूह में एक मानक बनाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो इससे रिमिटेंस में सुधार होगा, वित्तीय समावेशन में तेजी आएगी और डिजिटल भुगतान में वैश्विक तकनीकी अग्रणी के तौर पर भारत की छवि मजबूत होगी। भारत के डिजिटल भुगतान सशक्तिकरण ने न केवल आर्थिक लेनदेन को सरल बनाया है, बल्कि गरीब और पिछड़े वर्गों को भी वित्तीय दुनिया का हिस्सा बनाया है। यह डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी है, जो रोजाना करोड़ों नागरिकों की जिंदगी में सुधार लाकर भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हर युग में प्रासंगिक 'महादेव'

संकलित
दर्शन

कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का प्रशंसक हूं। प्रशंसक होने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं, क्योंकि उनका योगदान काल के परे है। इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशस्ति उस योगदान के लिए की जाती है, जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान किया है। जो उस समय की जरूरत के अनुसार था, वह उसे लेकर आया। गौतम बुद्ध के समय समाज कर्मकांडों में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह लोकप्रिय हो गए। अगर समाज में कर्मकांड नहीं होते, तो वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी, यदि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं होता, तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। आदियोगी या शिव का महत्व यही है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मानव चेतना को इस प्रकार से विकसित करने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहें। हमने उन्हें महादेव की उपाधि दी, क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान अद्भुत है।

मन को कभी भी निराश न होने दें

संकलित
प्रेरणा

सुबह होते ही, एक भिखारी सेठजी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया, सेठजी बाहर आए पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठजी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगीः अरे! क्या कर दिया आपने चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ो-दौड़ो और उसे वापिस लेकर आओ। सेठजी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोक कर कहाः भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वही पर खड़े सेठजी के एक मित्र ने उससे पूछाः मित्र! जब आपको पता चल गया था कि ये गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठजी ने मुस्कुराते हुए कहाः मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो! मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास। इसी लिए कहां गया है, मन प्रसन्न तो आप प्रसन्न। प्रसन्न मन हमारे शरीर पर काफी प्रभाव डालता है। प्रसन्न मन से किए गए कार्य में सफलता की संभावना अधिक होती है।

अंतर्मन

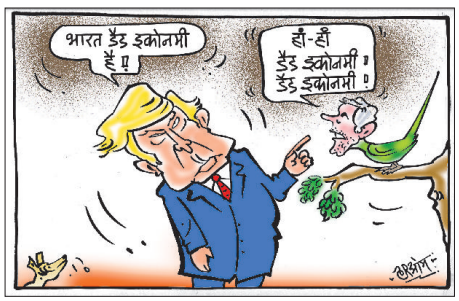

आज की पाती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती हो

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती होना चाहिए। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कानून के तहत लगभग 25 हजार जुर्माना और लगभग तीन साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार और प्रशासन इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। स्कूलों में इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया जाए और स्कूलों से विद्यार्थियों के माता-पिता को इसके लिए नोटिस भी भेजे जाए कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर एक्टिवा चलाते समय हैलमेट का प्रयोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, न कि चालान के डर से। - कुणाल सिंह ठाकुर

करंट अफेयर

रूस के हमले में 31 लोगों की मौत के बाद कीव में शोक दिवस

कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में पांच बच्चों समेत 31 लोगों की मौत के एक दिन बाद शुक्रवार को शहर में आधिकारिक शोक दिवस मनाया गया। इस हमले में 150 से अधिक घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बृहस्पतिवार के हमलों में सबसे कम उम्र का पीड़ित दो वर्ष का था, तथा घायलों में 16 बच्चे शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2022 में शहर पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से कीव पर एक ही हमले में मारे गए और घायल हुए बच्चों की यह सबसे अधिक संख्या है। अधिकारियों ने बताया कि रूसी बमबारी से शहर में नौ मंजिला आवासीय इमारत का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया जबकि 100 से अधिक अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें घर, स्कूल, किंडरगार्टन, चिकित्सा सुविधाएं और विश्वविद्यालय शामिल हैं। तीन साल से अधिक समय से जारी युद्ध के बाद नागरिक क्षेत्रों पर हमले बंद करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित पश्चिमी नेताओं के आह्वान को नजरअंदाज करते हुए रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेनी शहरों पर अपने हमलों को बढ़ा दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि जुलाई में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 5,100 से ज्यादा ग्लाइड बम, 3800 से ज्यादा ड्रोन और विभिन्न प्रकार की लगभग 260 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से 128 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं।

ऑफ बीट

नजरें मिलते ही भांप जाता, कुत्ता पढ़ सकता है आपका दिमाग

लंदन। कुत्ते एक शानदार साथी होते हैं क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जब आप रो रहे होते हैं तो वे अपने सिर को थोड़ा झुका कर आपको सांत्वना दे रहे होते हैं... जब आप तनाव में होते हैं तो वे दबे पांव आपके समीप आ जाते हैं और जब आप बहुत परेशानी में होते हैं तो वे आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य और कुत्ते के हजारों वर्षों के साथ का यह नतीजा है कि वे हमारी आवाज, चेहरे के भावों, यहां तक हमारे मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियों के साथ सामंजस्य कायम कर लेते हैं। लंदन साउट बैंक यूनिवर्सिटी ने अपने नए रिसर्च के बाद यह दावा किया है। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता प्रोफेसर लौरा एलिन पिगॉट ने बताया, जब आपके कुत्ते के साथ आपकी आंख मिलती है तो उसे यह भांपने में चंद सेकंड भी नहीं लगते है कि आपके भीतर कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि आप अपने कुत्ते को देखकर खुश होते हैं तो इस खुशी के कारण भी आपके मस्तिष्क में प्रेम करने वाले हार्मोन अर्थात ऑक्सीटोसिन का स्राव होने लगता है। इस असाधारण मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का आगाज मस्तिष्क से ही होता है। कुत्ते के दिमाग में चंद ऐसे क्षेत्र होते हैं जो मानव की तरह आवाजों को लेकर संवेदनशील होते हैं।

ट्रेंड

खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

देशभर के अन्नदाताओं के कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इससे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमारे किसान भाई-बहनों की आय भी बढ़ेगी।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

तिलक को श्रद्धांजलि

देश की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले 'लोकमान्य' बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके तेजस्वी विचार सभी देशवासियों को राष्ट्र सेवा एवं समाज उत्थान के कार्यों के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

-जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

शुरुआत अपने घर से

बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने घर से ही करनी होती है और हमने यही किया है। आज पहले महिला एवं बाल विकास विभाग को साफ़ किया, कर्मचारियों को जागरूक किया। क्योंकि जब हम खुद बदलाव को जीते हैं तभी समाज को प्रेरित कर सकते हैं।

-रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

नशा विरोधी पाठ्यक्रम

'युद्ध, नशे के विरुद्ध' अब सिर्फ़ नारा नहीं, एक जनआंदोलन बन चुका है। आज से पंजाब के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

कर्म पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति

कार्रवाई करे चुनाव आयोग

राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर जैसे शरारत भरे और इस संवैधानिक संस्था को बदनाम करने एवं देश को गुमराह करने वाले आरोप लगाए, वे उनकी हताशा को ही दर्शाते हैं। वे अपनी नाकामी का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं और वह भी भद्दे तरीके से। चूंकि उनके ऐसे पुराने आरोप ठहर नहीं रहे इसलिए वे कुंठित हो रहे हैं। वे हताशा में हद पार कर रहे हैं। उन्हें यह भी भान नहीं कि वे नेता सदन हैं और उस कांग्रेस के नेता हैं, जिसने देश पर लंबे समय तक शासन भी किया और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के कुछ कदम भी उठाए। क्या कांग्रेस के लिए यह शर्म की बात नहीं कि जिस ईवीएम का उपयोग उसके शासनकाल में शुरू हुआ, उसके पीछे उसके ही बड़े नेता पड़े हैं। हाल के वर्षों में ईवीएम के कथित दुरुपयोग के जो भी आरोप लगे, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी पाया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगाए गए आरोप भी फर्जी ही पाए गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव आयोग के खिलाफ उलटा-सीधा नहीं, उलटा ही उलटा इसलिए बोला ताकि सांसद को मिले अधिकारों के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके।

यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के नितांत झूठे और भारतीय लोकतंत्र की छीछालेदर करने वाले आरोपों का कड़ा प्रतिवाद करने के साथ यह कहकर उन्हें बेनकाब भी किया कि वे किस तरह अपने आरोपों का जवाब सुनने उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए। चुनाव आयोग ने बार-बार उन्हें बुलाया, लेकिन लगता है कि वे खुद को इस संवैधानिक संस्था से भी ऊपर समझ रहे हैं। वे गांधी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह मुगालता पाल लें कि आम जनता उनके शरारत भरे आरोपों को सच मान लेगी। जनता का उनके आरोपों पर भरोसा होता तो चुनावों में कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं हो रही होती। वोट चोरी के आरोप लगा रहे राहुल और उनके साथी यह भूलना भी पसंद कर रहे हैं कि झारखंड और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कौन जीता था? अब यह आवश्यक है कि यदि राहुल गांधी या उनके सहयोगी अथवा कथित लोकतंत्र हितैषी चुनाव आयोग पर सिरे से झूठे आरोप लगाएं तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। यदि ऐसा काम राहुल संसद के बाहर करें तो उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग को पुलिस में शिकायत करने के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग लोकतंत्र बचाने के नाम पर उससे ही खेल रहे हैं। अब यह भी साफ है कि ऐसे लोग मतदाता सूचियों का सत्यापन नहीं होने देना चाहते, भले ही घुसपैठिये वोटर बने रहें। देशद्रोह तो यह है। इस मामले में जनहित याचिकाएं सुनने को आतुर सुप्रीम कोर्ट को भी सक्रिय होना चाहिए।

प्रेरणास्रोत बनें शिक्षक

शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत होते हैं। बच्चे शिक्षक से ही सीखकर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पंजाब में लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल भूखड़ी कलां का मामला हैरान करने वाला है। यहां कार्यरत ईटीटी अध्यापिका को निलंबित किया गया, क्योंकि वह स्कूल में नशा करती थी। स्थानीय लोगों ने शिक्षिका के आचरण की शिकायत की थी। पंचायत ने शिक्षिका को नशा छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक थी। ऐसे शिक्षक से बच्चे क्या सीखेंगे? शिक्षकों को उदाहरण स्थापित करना चाहिए, जिससे बच्चे और बेहतर करने के लिए प्रेरित हो सकें। सरकार प्रदेश से नशे का कलंक मिटाने के लिए प्रयासरत है। नशे के विरुद्ध अभियान भी जारी है और अब तक बीस हजार से अधिक नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार अब नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए नशे से बचाव का एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी शुरू कर रही है। अभिभावकों का दायित्व है कि उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि स्कूल में अध्यापक कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है और वहां पढ़ाई का माहौल कैसा है। यदि अभिभावक जागरूक होंगे, तो बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल बनेगा। शिक्षकों को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए ताकि वे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें।

> ऐसी शिक्षिका का निलंबन आवश्यक था, क्योंकि वह स्कूल में नशा करती थी। ऐसे शिक्षकों से बच्चों को क्या सीख मिलेगी?

सभी शिक्षा संस्थानों में लागू हो नई शिक्षा नीति

बद्री नारायण

पांच वर्ष पुरानी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के शिक्षा जगत में एक ऐसा प्राणतत्व फूंकना है, जिससे सच्चे भारतीय मन की पीढ़ी विकसित हो सके

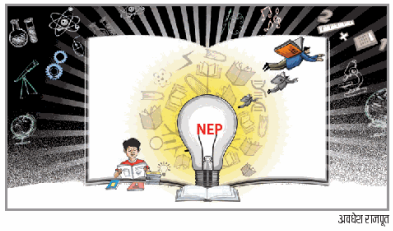

भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई परिवर्तनकारी योजनाएं तैयार की गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही योजनाएं मिलकर विकास को गति दे रही हैं। इसी दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति-2020 का निर्माण, विकास और कार्यान्वयन किया गया है। अब इस नीति को लागू हुए पांच वर्ष हो चुके हैं। यह सही समय है कि हम इसकी समीक्षा करें कि इसने भारतीय शिक्षा जगत में क्या परिवर्तन लाए हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए? नई शिक्षा नीति एक दीर्घकालिक शैक्षिक परिवर्तन की रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा में मौलिकता, उद्योग-अकादमिक संवाद और छात्रों में रोजगारपरकता विकसित करना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संकल्पित पंच प्रण में से एक युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास और भारतीय शिक्षा के विऔपनिवेशीकरण का लक्ष्य भी शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा जगत में ऐसा प्राणतत्व फूंकना है, जिससे देश में भारतीय मन की पीढ़ी विकसित हो सके।

नई शिक्षा नीति विश्व में सर्वाधिक जनसंवाद से विकसित हुई शिक्षा नीति है। इसके लिए 1,10,623 ग्राम स्तरीय बैठक और 3,250 ब्लाक, 725 शहरी एवं 340 जिला स्तर पर संवाद आयोजित किए गए थे। इस दीर्घकालिक निर्माण प्रक्रिया के बाद इसके कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ हुआ। इन पांच वर्षों में अपने प्रारंभ से ही भारतीय शिक्षा जगत में बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित करने और अन्य लक्ष्यों को पाने के लिए पहले ढांचागत परिवर्तन किया गया। इस ढांचागत परिवर्तन के लिए स्कूल शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक कई सुधार किए गए। इनमें अनुशासनिकता पर आधारित चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाएं विकसित की गईं। मूल्यगत शिक्षा, स्किल आधारित कोर्स, रचनात्मक मौलिक पाठ्यचर्या आदि कई नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए। ये ढांचागत परिवर्तन देश के अधिकांश स्कूलों और उच्च शिक्षा में लागू हो रहे हैं। स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित की जा रही हैं, जो मौलिकता, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्किल, विकास, उद्योग और ज्ञान जगत संवाद पर आधारित हैं। स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा से जुड़े कई विद्वान और शिक्षक इस कार्य में लगे हैं। इनके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकें इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं और कई पाठ्यपुस्तकें अब भी विकसित की जा रही हैं। यह काम और तेजी से किया जाना चाहिए। वास्तव में नई शिक्षा नीति एक दीर्घकालिक चरणबद्ध कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से मुख्य लक्ष्य भारतीय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना है।

अवधेश राजपूत

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति के तहत प्रशासनिक परिवर्तन के लिए ई-समर्थ कार्यक्रम विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम से अब तक 12,800 उच्च शिक्षा संस्थान जुड़ चुके हैं, जिनमें 1.75 करोड़ छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था के दैनिक प्रबंधन का संचालन हो रहा है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के क्रम में 'स्वयं प्लस' लागू किया गया है, जिससे पांच लाख इंटर्न प्रशिक्षित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की दिशा में भी कई कार्य किए गए हैं। भारतीय ज्ञान व्यवस्था से जुड़े गणित, एस्ट्रोनामी, सौंदर्यशास्त्र, जन स्वास्थ्य केंद्रित जैसे विषयों में उच्च शिक्षा के लिए लगभग 38 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। इनके शिक्षण के लिए शिक्षक और अनुदेशक प्रशिक्षित भी किए जा रहे हैं। भारतीय शिक्षा जगत विशेषतः उच्च शिक्षा में हो रहे इन ढांचागत, प्रशासनिक, व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, डिजाइन और पाठ्यपुस्तक निर्माण का एक बड़ा असर यह हुआ है कि भारतीय शिक्षा संस्थानों ने हाल के वर्षों में विश्व रैंकिंग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। विश्व स्तर पर कराए जा रहे क्यूएस-500 रैंकिंग में भारत के 11 विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष 46 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने क्यूएस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। क्यूएस एशिया रैंकिंग-2025 में भी देश के 163 विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। क्यूएस रैंकिंग में जगह बनाना गुणात्मक मूल्यांकन और सर्वांगीण प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन के बाद ही संभव हो पाता है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का एक लाभ यह भी हुआ है कि भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के कई देशों में अपने कैंपस खोल रहे हैं। दुनिया के कई विश्वविद्यालय भी भारत में अपने कैंपस खोल रहे हैं। हाल में मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में आइआइटी और आइआइएम जैसी संस्थाओं के कैंपस खोले गए हैं।

देश के सभी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए। शिक्षा के मामले में दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब शैक्षिक संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए अधिक से अधिक शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों और प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा संचालित मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर्स, ओरिएंटेशन और रिफ्रेसर कोर्स तथा कई ज्ञान प्रशिक्षण केंद्र इसमें मददगार हो सकते हैं। ऐसे पाठ्यपुस्तक भी विकसित करने चाहिए, जो सरल ढंग से ज्ञान विमर्श करते हुए नई शिक्षा नीति के आत्मा को अपने में प्रवाहित करें। स्कूल शिक्षा के लिए प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूला के लिए राज्य सरकारों और आमजन में स्वीकृति का भाव विकसित करना चाहिए। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति लगातार कई चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि इसका अगला चरण विकसित भारत-2047 के लिए आवश्यक देश के ज्ञान जगत और ज्ञान शक्ति को विकसित करेगा।

(लेखक टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, मुंबई के कुलपति हैं)
response@jagran.com

धैर्य और संकल्प की अद्भुत कहानी

विशाल सरीन

महिला विश्व शतरंज चैंपियन की कमी पूरी होना इसलिए खास है, क्योंकि शतरंज दुनिया का बहुत ही लोकप्रिय खेल है

जब आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के सामने हों और आप पर कमजोर होने का ठप्पा लगा हो तो उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। नागपुर की 19 वर्षीय किशोरी दिव्या देशमुख ने जार्जिया के बटुमी में विश्व महिला शतरंज कप जीतकर इसी की पुष्टि की। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर और चौथी महिला खिलाड़ी बनीं। बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित पिछले शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद करने वाली प्रमुख खिलाड़ियों में से एक दिव्या के लिए यह एक परीकथा जैसी कहानी रही है। वह देश की अगली ग्रैंडमास्टर बनने को तत्पर थीं, लेकिन सवाल यही था कि कब बनेंगी? ग्रैंडमास्टर बनने के लिए तीन ग्रैंडमास्टर मानदंड और 2500 की रेटिंग की आवश्यकता होती है। दिव्या के पास तब इनमें से किसी का भी बखान करने के लिए कुछ नहीं था, जब वह दूसरे राउंड से शुरू होने वाले अपने पहले मुकाबले में उतरीं। जार्जिया की केसरिया मगेलाद्जे के खिलाफ दो गेम के मैच में आसान और अपेक्षित 1.5-0.5 से जीत हासिल करने के साथ ही शतरंज के इतिहास में दर्ज होने वाली एक कहानी की शुरुआत हो गई। सर्बिया की इंजाक टेओडोरा तीसरे राउंड में दिव्या के हाथों 0.5-1.5 से हारने वाली अगली खिलाड़ी थीं और चौथे राउंड में उनका मुकाबला चीन की जिनर झू से हुआ। यह शायद उनके जीवन का सबसे कठिन मैच था।

पहला गेम जीतने और दूसरा हारने के बाद दिव्या ने 15 मिनट के टाईब्रेकर में चीनी खिलाड़ी को फिर से 1.5-0.5 से हरा दिया और अब उनका मुकाबला हमवतन ग्रैंडमास्टर डी. हरिका से था। दिव्या ने फिर टाईब्रेकर में 2-0 से जीत हासिल की और हरिका को दौड़ से बाहर कर दिया। पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की टैन झोंगयी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें 0.5-1.5 से हार का सामना करना पड़ा। दिव्या इस महामुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। यह कहानी एक और भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हंपी के बिना पूरी नहीं होगी, जो दिव्या से दोगुनी उम्र की हैं और धीरे-धीरे तेजी से आगे बढ़ रही थीं। जब उन्होंने दूसरी चीनी खिलाड़ी टिंगजी लेई को हराया, तो एक अखिल भारतीय फाइनल के लिए मंच तैयार हो गया। दिव्या ने पहले दो गेम फिर से ड्रा करके टाईब्रेकर में जगह बनाई। दूसरे मैच में हंपी का धैर्य जवाब दे गया। एक स्पष्ट ड्रा में उन्होंने जरूरत से ज्यादा जोर लगाया और हार गईं। अंततः शतरंज का विश्व कप 23 साल बाद भारत आया। पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 2000 (तब इसे नाकआउट विश्व चैंपियनशिप कहा जाता था) और 2002 में यह कप जीता था। हालांकि आनंद दोनों ही बार पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे। 15वीं वरीयता प्राप्त दिव्या ने शीर्ष दस में चार खिलाड़ियों को हराकर अपनी बादशाहत कायम की।

संघर्ष और सफलता का नया नाम दिव्या देशमुख। प्रेट्र

परीकथाएं अक्सर लंबी कहानी होती हैं, जो अक्सर छोटी हो जाती हैं। दर्द, कड़ी मेहनत, फार्म में उतार-चढ़ाव और जीवन की कठोर सच्चाइयों के बीच अनगिनत सपने होते हैं। विडंबना यह कि केवल सफलता याद रहती है। दिव्या लंबे समय से माता-पिता के साथ टूर्नामेंट और प्रशिक्षण शिविरों में जाती रही हैं। हर दूसरे शतरंज खिलाड़ी की तरह उन्हें भी उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ा, पर उनकी प्रतिभा पर कभी संदेह नहीं हुआ। भारत में शतरंज के सर्वोत्तम प्रशिक्षण केंद्र के मक्का कहे जाने वाले चेन्नई में दिव्या ने ग्रैंडमास्टर आरबी रमेश के मार्गदर्शन में कई शिविरों में भाग लिया। रमेश में प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने की गहरी समझ है। दिव्या की प्रतिभा तब पहचानी गई, जब वह पिछले शतरंज ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक बनीं। दिव्या की सफलता कोई क्षणिक सफलता नहीं है। वे केवल पिछली पीढ़ी की सफलता दोहराने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ऐसा स्थायी प्रभाव छोड़ना चाहती हैं, जो भविष्य के इतिहास में उनका नाम दर्ज कराए।

जब दिव्या अपने गृहनगर नागपुर पहुंचीं तो वह क्षण बहुत भावुक कर गया, जब उन्होंने गर्व से अपने पहले कोच राहुल जोशी की तस्वीर पकड़ी और अपना ग्रैंडमास्टर खिताब उन्हें समर्पित किया। जोशी का निधन 40 वर्ष की आयु में हो गया था। दिव्या की आंखों में झलक रहा था कि और वह यहीं नहीं रुकने वाली हैं। भारत में एक ट्राफी की कमी खल रही थी और वह थी महिला विश्व शतरंज चैंपियन की। यह कमी पूरी होना इसलिए खास है, क्योंकि शतरंज फुटबाल के बाद दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है।

कहते हैं, 'मुकुट भारी होता है।' विश्व कप जीतने के बाद दिव्या के पहले शब्द थेः "मुझे अपने खेल में सुधार की जरूरत है।" इससे हमें यकीन हो जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। बीते कुछ समय में दिव्या जैसी शानदार सफलता अन्य महिला खिलाड़ियों ने भी हासिल की है। इस पर ध्यान दें कि हमारी लड़कियां क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की तरह अन्य खेलों में भी कमाल कर रही हैं, जैसे मनु भाकर, ज्योति याराजी, सिफ्त कौर...। इनकी प्रेरणा हैं पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी काम, सायना नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि।

(लेखक शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर और फिडे के सीनियर ट्रेनर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

परनिंदा

परनिंदा की कुप्रवृत्ति से शायद ही कोई अछूता हो। जिस प्रकार परहित के समान कोई धर्म नहीं, परपीड़ा समान कोई निकृष्टता नहीं, उसी प्रकार परनिंदा भी सर्वथा त्याज्य है। रामचरितमानस में भगवान श्रीराम शबरी को नवधा भक्ति की समझ देते हुए कहते हैं, जो मिले वही पर्याप्त है, उसी में संतोष होना चाहिए और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। यह वर्जना इस बात को स्पष्ट करती है कि जाग्रत अवस्था में परनिंदा से बचना आवश्यक है। अच्छे लोग हमें खुशी देते हैं, श्रेष्ठ लोग स्मरणीय यादें देते हैं, जबकि परनिंदक नकारात्मक बातें सिखाते हैं। किसी संत ने कहा है, 'परनिंदा से किसी को कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे लोग महा मूर्ख होते हैं और पाप का पर्वत ढोने का काम करते हैं।'

परनिंदा को एक प्रकार का रस कहा गया है, जिससे परनिंदा प्रेमी विरत नहीं रह पाते, लेकिन यह एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जिसमें लोग कुंठा, प्रतिशोध या ईर्ष्या के कारण संलग्न होते हैं और अपनी कमियों को छिपाते एवं स्वयं को श्रेष्ठ दिखाते हैं। इससे न केवल दूसरों की भावनाओं का निरादर होता है, बल्कि यह आपसी संबंधों को भी क्षति पहुंचा सकता है। ऋग्वेद के अनुसार, यह स्वयं के अहित का कारण भी बन सकता है, क्योंकि निंदारस में रति पापकर्म के भागी बनने के साथ अपने मूल कार्य को विस्मृत कर देते हैं।

निंदारसभोगी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके ईर्ष्यालु भाव की तरह कोई अन्य भी उसके प्रति ऐसे अनुदार विचार रख सकता है। इसे रस नहीं, घातक रोग समझकर इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सदैव प्रसन्न रहकर, छोटी-छोटी बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर, दूसरों के सहयोगी बनकर, शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहकर, सकारात्मक, धैर्यवान और क्षमाशील बने रहना आवश्यक है। अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधार की ओर अग्रसर होना चाहिए।

एसएन दुबे 'स्नेही'

गंभीर समस्या बने आवारा कुत्ते

सुनीता मिश्रा

> शहर से लेकर गांव-देहात तक की गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर चिंता व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'क्या बड़े दिल वाले लोगों देशभर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में देशभर में कुत्तों के काटने के 37 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए, जबकि 54 लोगों की रेबीज के कारण संदिग्ध मौत हुई। इन घटनाओं ने न केवल बच्चों और बुजुर्गों में डर पैदा किया, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को भी उजागर किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक रेबीज से एक भी मौत न होने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन, पशुपालन विभाग और कई गैर सरकारी संगठन मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्कूलों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में रेबीज के बारे में जानकारी देना, पालतू और सड़कों पर रहने वाले कुत्तों का टीकाकरण कराना इस अभियान का अहम हिस्सा है।

रेबीज से होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं, इसके लिए समय पर जागरूकता और इलाज की जरूरत है, लेकिन लोगों की लापरवाही, अज्ञानता और सही जानकारी की कमी के चलते यह अभी भी जानलेवा बनी हुई है। मामूली खरोंच या थोड़ा सा काटने पर भी तुरंत डाक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल हजारों लोग रेबीज के कारण जान गंवाते हैं, जिनमें से अधिकतर मामले समय पर इंजेक्शन नहीं लगाने की वजह से होते हैं। कुत्ता चाहे पालतू हो या फिर आवारा उसके काटने पर तुरंत मेडिकल मदद लें और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाएं। यह इंजेक्शन कुत्ते काटने से बने जख्म के आधार पर लगाए जाते हैं। अगर इंजेक्शन कुछ घंटों के भीतर न दिया जाए, तो शरीर में वायरस फैलकर दिमाग, नर्वस सिस्टम और अंत में हृदय प्रणाली पर हमला करता है, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है।

बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए। अगर वे खेलने के लिए बाहर जाने की जिद करते हैं, तो उन्हें कुत्तों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सिखाएं। बच्चों को बताएं कि जब वे अकेले हों तो कुत्तों के नजदीक न जाएं, क्योंकि गली के कुत्ते कभी-कभी आक्रामक हो जाते हैं, खासकर जब वे गुस्से में या डरे हुए हों। अगर अभिभावकों को गली-मोहल्ले में कोई काटने वाला आवारा कुत्ता दिखाई दे, तो उन्हें जल्द से जल्द स्थानीय पशु नियंत्रण को सूचित करना चाहिए। इससे वे अन्य बच्चों को भी आवारा कुत्तों से बचा सकेंगे।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

लोकतंत्र के प्रहरी निःशब्द क्यों?

'महाभियोग' भारतीय लोकतंत्र की वह संवैधानिक ढाल है, जिससे न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी थी, परंतु सुरेंद्र किशोर द्वारा लिखित आलेख 'महाभियोग पर अपनी नाकामी देखे संसद' यह उजागर करता है कि संसद इस ढाल का प्रभावी उपयोग करने में अब तक विफल रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत गंभीर कदाचार या अयोग्यता के आधार पर संसद विशेष बहुमत से न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। इस आलेख में यह तथ्य सटीक रूप से सामने आया है कि भारत में अब तक किसी भी उच्च न्यायाधीश को महाभियोग के जरिये हटाया नहीं जा सका, परंतु इसमें यह पहलू छूट गया है कि इसकी जड़ें सिर्फ संसदीय असफलता तक सीमित नहीं हैं। वास्तविक संकट दोहरे स्तर पर है- पहला, सांसदों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और दूसरा, न्यायिक प्रणाली की आंतरिक पारदर्शिता का अभाव। इसके अलावा 'जज बनाम संसद' की बहस को तूल देना भी इस संवैधानिक प्रक्रिया को निष्प्रभावी करता है। समाधान के तौर पर एक 'न्यायिक नैतिकता आयोग' का गठन आवश्यक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के साथ-साथ लोकपाल, नागरिक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ पत्रकार शामिल हों। यह आयोग न्यायपालिका की आंतरिक शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे। साथ ही नागरिकों को भी चुप्पी तोड़नी होगी। 'न्यायपालिका की गरिमा' के नाम पर अंध समर्थन लोकतंत्र के लिए खतरा है। यदि समय रहते हमने जजों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की, तो आने वाले वर्षों में न्याय व्यवस्था पर से जनविश्वास उठ जाएगा। और तब लोकतंत्र केवल कागजों में रह जाएगा।

awanishg30@gmail.com

आनलाइन अश्लीलता पर लगे रोक

डिजिटल युग ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इनमें सबसे गंभीर समस्या है आनलाइन अश्लीलता की। ओटीटी प्लेटफार्म्स, सोशल मीडिया और शार्ट वीडियो एप्स पर बढ़ती अश्लील सामग्री युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों पर गहरा असर डाल रही है। अश्लील कंटेंट न केवल नैतिक गिरावट का कारण बन रहा है, बल्कि अपराध को भी बढ़ावा दे रहा है। नाबालिगों में यौन अपराधों के बढ़ते मामले इस बात का संकेत हैं कि यह समस्या केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। सरकार ने आइटी नियम और डिजिटल कंटेंट गाइडलाइंस के जरिए रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ कानून काफी नहीं हैं। एआइ आधारित फिल्टर, सख्त दंड और नियमित निगरानी की जरूरत है। साथ ही परिवार और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। बच्चों की आनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना और स्कूलों में साइबर नैतिकता सिखाना जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अनैतिक सामग्री फैलाने की आजादी नहीं है। इसलिए हमें तकनीक, कानून और जागरूकता तीनों स्तरों पर कदम उठाने होंगे।

karunakar.gonda@gmail.com

न्याय का तकाजा

मालेगांव में 2008 में हुए धमाके में छह लोगों की मौत और कई घायल हुए थे, लेकिन 17 साल चली जांच और सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने कहा है कि जिन सुबूतों के आधार पर आरोप लगाए गए, वे टिकाऊ और विश्वसनीय नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि जांच के हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई, घटनास्थल की बैरिकेडिंग ठीक से नहीं हुई, घायलों की संख्या को लेकर भ्रम रहा और मेडिकल सर्टिफिकेट तक में हेरफेर हुआ। इन खामियों के कारण न सिर्फ निर्दोषों ने 17 साल जेल में बिताए, बल्कि इससे देश की कानून व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी गहरा नुकसान पहुंचा है। आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को फंसाना न सिर्फ अपराध है, बल्कि यह देश की सुरक्षा प्रणाली पर जनता के विश्वास को भी डगमगाता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

> इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
> अपने पत्र इस पते पर भेजें :
> दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
> डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
> ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेंद्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

अंतरिक्ष में भारत

एनआईएसएआर का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का एक सपना था। वे भारत के विकास और प्रगति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहते थे, संचार, मौसम पूवार्नुमान और संसाधन प्रबंधन जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने लोगों के उत्थान और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कर सके। वर्षों से भारत विक्रम साराभाई के सपने को साकार करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका एक उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो विश्वस्तरीय है और इसका उपयोग मौसम पूवार्नुमान से लेकर भारत के प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण तक, अपने लोगों की बेहतरी के लिए किया गया है। भारत ने बुधवार को श्रीहरिकोटा से एनआईएसएआरः नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, के सफल प्रक्षेपण के साथ एक बार फिर ऐसा ही किया।

1.3 बिलियन डॉलर की लागत वाला यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे महंगा है, न केवल एक तकनीकी मील का पत्थर था, बल्कि इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक भी था कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कितनी दूर तक पहुंच गया है। इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, एनआईएसएआर दोनों एजेंसियों के बीच अपनी तरह का पहला बड़ा सहयोग है।

यह सिर्फ.उपग्रह प्रक्षेपण के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि यह क्या दर्शाता है। जब भारत ने 1975 में सोवियत सहायता से अपना पहला उपग्रह, आर्यभट्ट, प्रक्षेपित किया था, तब वह विदेशी प्लेटफार्मों और विशेषज्ञता पर निर्भर था। आज, वह नासा के साथ मिलकर विकसित दुनिया के सबसे जटिल उपग्रहों में से एक, अपने स्वयं के रॉकेट, जीएसएलवी एफ-16, पर प्रक्षेपित कर रहा है। एनआईएसएआर -आवृत्ति रडार का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह है, जिसमें नासा एल-बैंड रडार और इसरो एस-बैंड रडार प्रदान कर रहा है।

यह हाइब्रिड प्रणाली पृथ्वी की सतह की छवियों में अभूतपूर्व स्तर का विवरण प्रदान करती है।एनआईएसएआर हर 97 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और हर 12 दिनों में ग्रह के उच्च-रिजॉल्यूशन स्नैपशॉट कैप्चर करेगा। ये चित्र वैज्ञानिकों को पृथ्वी के भूभाग में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने में मदद करेंगे—वनों की कटाई और ग्लेशियरों के विस्थापन से लेकर मिट्टी की गति, कृषि पैटर्न और यहां तक कि भूकंप और भूस्खलन के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों तक। एनआईएसएआर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है।

वास्तव में, इसरो को एक विश्वस्तरीय अंतरिक्ष एजेंसी बनाने का श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। कम लागत वाले उपग्रहों और अंतरग्रहीय अन्वेषणों के प्रक्षेपण से लेकर स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने तक, इसरो एक विश्वसनीय और सम्मानित अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है। हालांकि, एनआईएसएआर को जो बात अलग बनाती है, वह यह है कि यह भारत को न केवल प्रक्षेपण सेवाओं के प्रदाता के रूप में, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक अवसंरचना के सह-निर्माता के रूप में भी स्थापित करता है।

भारत और अमेरिका, दो महान देशों ने एक परिवर्तनकारी उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया है, और इसे भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया गया। यह विश्वास, क्षमता और पृथ्वी विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एनआईएसएआर भारत और वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक गहन सहयोग की शुरूआत हो सकता है। भारत अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान और भविष्य के ग्रहों और चंद्रमा संबंधी उपक्रमों की खोज की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इस तरह की साझेदारियाँ महत्वपूर्ण होंगी। साथ ही, जटिल मिशनों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने की भारत की बढ़ती क्षमता उसे अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में एक मजबूत आधार प्रदान करती है। एनआईएसएआर की सफलता, हर मायने में, एक परिपक्व क्षण है। और जब जीएसएलवी एफ16, एनआईएसएआर को लेकर आकाश में उड़ान भर रहा था, तो वह अपने साथ एक उपग्रह से भी अधिक कुछ लेकर गया था, वह एक ऐसे भविष्य का वादा लेकर आया था, जहां भारत अंतरिक्ष नवाचार में अग्रणी होगा।

नई शिक्षा नीति के पांच साल

एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम में 21वीं सदी के व्यावहारिक अनुभव और कौशल आवश्यकताओं को शामिल करने की भी परिकल्पना की गई है। शैक्षणिक और कौशल-आधारित शिक्षा की समानता और एकीकरण सुनिश्चित करने वाले नियामक ढाँचों को राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है।

गीता भट्ट
लेखिका, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हैं।

शिक्षा और उससे जुड़े ज्ञान के प्रतिमान प्रगतिशील समाजों की नींव रहे हैं। भारतीय विद्वत्ता के समृद्ध प्राचीन भंडार को दुनिया भर में मान्यता मिली है और इसने कई लोगों को अपने-अपने शैक्षणिक क्षेत्रों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है।

इतनी समृद्ध ज्ञान विरासत के बावजूद, इस राष्ट्र को वर्ष 2020 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने में 73 वर्ष लग गए, जो 'भारत की ज्ञान परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर आधारित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों' के अनुरूप थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई 2020 को पेश की गई थी और इसे पांच वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह हमें नीति के कार्यान्वयन का समग्र दृष्टिकोण अपनाने, अनुकूल परिवर्तनों, स्कूली और उच्च शिक्षा में समग्र प्रगति, साथ ही सुधार की आगे की संभावनाओं का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है।

शिक्षण माध्यम के रूप में भाषा विषयों की वैचारिक स्पष्टता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षाविदों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की वकालत की है। स्वतंत्रता के बाद, डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (दिसंबर 1948-अगस्त 1949) में शिक्षा पर की गई शुरूआती सिफारिशों में से एक में कहा गया था कि यथाशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

हालाँकि, यह सिफारिश तभी लागू हुई जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सिफारिश की गई कि 'कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उसके बाद तक' शिक्षण माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। पिछले पाँच वर्षों से भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता एक सतत प्रक्रिया रही है। दो वर्ष पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 12 भारतीय भाषाओं में 100 पुस्तकों का लोकार्पण किया था। दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) एक राष्ट्रीय वेब प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग शिक्षा के ई-अवसंरचना के रूप में किया जाता है, जहां 31 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं के लिए सक्रिय पुस्तकें (जो क्यूआर कोड के साथ आती हैं) तैयार की जा रही हैं।

भारतीय भाषाओं में स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना के लिए 2025-26 के बजट में 347.03 करोड़ का आवंटन संस्थानों को पाठ्यक्रम में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि 96.71 प्रतिशत छात्रों की मातृभाषा बाईस अनुसूचित भाषाओं में से एक है, जबकि केवल 10.6 प्रतिशत ने कहा कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं।

भारतीय भाषाओं में शिक्षा एक माध्यम के रूप में शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाएगी और आने वाले वर्षों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज में, बी.टेक छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग पूरी तरह से मराठी में पढ़ाई जाती थी। उन्होंने शीर्ष कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल किया, जिससे यह साबित हुआ कि तकनीकी शिक्षा में सफलता के लिए भाषा कोई बाधा नहीं है। हमारी पाठ्यपुस्तकों में औपनिवेशिक विरासत के बोझ को अंततः भारतीय योगदान ने बदल दिया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिक चिंताओं में से एक है, लेकिन यह एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाने पर भी जोर देती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा पाँचवीं और आठवीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में दस नई पाठ्यपुस्तकें लॉन्च की हैं, जिनमें भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कला शिक्षा शामिल हैं।

वैचारिक समझ, शैक्षणिक दृष्टिकोण और अनुभवात्मक अधिगम पर जोर देने वाली और भी पाठ्यपुस्तकें जल्द ही आने वाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, पाठ्यपुस्तकों को हमारी विरासत में निहित करना एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है जिसका उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है।

एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम में 21वीं सदी के व्यावहारिक अनुभव और कौशल आवश्यकताओं को शामिल करने की भी परिकल्पना की गई है। शैक्षणिक और कौशल-आधारित शिक्षा की समानता और एकीकरण सुनिश्चित करने वाले नियामक ढाँचों को राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचे (एनसीआरएफ) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है। शैक्षणिक कार्यक्रमों, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में, यह समानता और समतुल्यता एक एकीकृत क्रेडिट प्रणाली में निर्बाध स्थानांतरण में सहायता करेगी। उच्च शिक्षा के किसी कार्यक्रम में छात्र के लिए बहु-प्रवेश-निकास विकल्पों ने शैक्षणिक लचीलापन प्रदान किया है। देश भर के छात्रों की शैक्षणिक साख को सुव्यवस्थित करने के लिए, छात्रों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) नामक एक विशिष्ट 12-अंकीय आईडी तैयार की जा रही है, जो शैक्षणिक रिकॉर्ड का डिजिटल रूप से प्रबंधन करती है और उन्हें अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में संग्रहीत करती है। यह प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त रिकॉर्ड प्रबंधन 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' अभियान का समर्थन करता है, जिससे पूरे देश में पहुँच और निरंतरता सुनिश्चित होती है।

एनईपी 2020 के पाँच वर्षों ने देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाया है। अगले पांच वर्षों में इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने का एक महत्वपूर्ण पहलू संकाय का क्षमता निर्माण होगा। वर्तमान में, निष्ठा (राष्ट्रीय विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल) और एमएमटीटीसी (मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम) क्रमशः स्कूलों और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। शिक्षकों को अनुभवात्मक शिक्षण और योग्यता-आधारित मूल्यांकन जैसी नई शैक्षणिक विधियों से लैस करने की आवश्यकता है। भौतिक रूप से सशक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की गति को बढ़ा सकते हैं। 1965 में कोठारी आयोग से लेकर एनईपी 2020 तक, देश की विभिन्न शिक्षा नीतियों में शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत का बजटीय प्रावधान एक निरंतर विशेषता रही है।

शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर इसे जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। संविधान में शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण, इसे केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों में सुधार, प्रदर्शन का स्तर, सीखने के परिणामों का स्तर और स्कूल स्तर पर सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना है। हालांकि, राज्य सरकारें महत्वपूर्ण हितधारक हैं, और उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी लक्ष्यों तक पहुँचने में संभावित अंतराल पैदा कर सकती है।

एक मानकीकृत निगरानी तंत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी मूल्यांकन और कार्यान्वयन में मदद कर सकता है, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में। राज्यों द्वारा नीति के साथ जुड़ाव का अलग-अलग स्तर और देश का विशाल आकार, कभी-कभी एनईपी 2020 के एकसमान और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिंता का विषय बन जाता है।

एनईपी 2020 ने अपने कार्यान्वयन के पहले पाँच वर्षों के भीतर व्यवस्थित शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार पेश किए हैं। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहे एक राष्ट्र के रूप में, शिक्षा को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भारत की बौद्धिक और कौशल पूंजी, और आर्थिक ताकत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूरे देश में अक्षरशः क्रियान्वयन ऐसे नागरिकों को तैयार करेगा जो भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, समानता, सतत विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे तथा विश्व के साथ आत्मविश्वास से जुड़ने के लिए सक्षम होंगे।

सार्वजनिक सरोकार मामलों पर रहस्यमयी चुप्पी

जब सरकार की मुखर और लगातार आलोचना करने वाले नेता अचानक जनहित के मुद्दों पर चुप हो जाते हैं, तो यह जांच को आमंत्रित करता है।

अमित श्रीवास्तव
लेखक, दिल्ली विवि में पढ़ाते हैं।

भारतीय राजनीति में, जो नहीं कहा जाता, वह अक्सर उससे ज्यादा जोर से बोलता है जो कहा जाता है। जब सरकार की मुखर और लगातार आलोचना करने वाले नेता अचानक जनहित के मुद्दों पर चुप हो जाते हैं, तो यह जांच को आमंत्रित करता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक प्रमुख उद्योगपति से जुड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे के बाद हम ठीक यही देख रहे हैं, जिसका ज़िक्र कभी विपक्षी विमर्श में अक्सर होता था।

हाल ही में ईडी के छापों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति पर फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करने, धन की हेराफेरी करने और हजारों करोड़ रुपये का दुरुपयोग करने का आरोप है। दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और ऑडिट रिपोर्ट सहित सबूत इस मामले को बेहद गंभीर बनाते हैं। 77,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण चूक के साथ एक पूरा व्यापारिक साम्राज्य ध्वस्त हो गया है। जाँच एजेंसियों के नए निष्कर्ष भी बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों का संकेत देते हैं।

ये कोई छोटी-मोटी बातें नहीं हैं। अगर भ्रष्टाचार सचमुच वह समस्या है जिससे हम लड़ रहे हैं, तो इस पर मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। लेकिन अजीब बात है कि जो लोग आमतौर पर बोलते हैं, वे अब चुप हैं। सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी सामग्री ने राजनीतिक बयानों, प्रेस वाताओं और सोशल मीडिया अभियानों की झड़ी लगा दी होती।

हालांकि, यहां पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के उन वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, जो लंबे समय से खुद को आर्थिक कदाचार के खिलाफ योद्धा के रूप में पेश करते रहे हैं। जिन नामों का कभी कॉर्पोरेट-राजनीतिक गठजोड़ के प्रतीक के रूप में बार-बार उल्लेख किया जाता था, उन्हें चुनिंदा रूप से कहानी से हटा दिया गया है।

यह चुनिंदा चुप्पी चौंकाने वाली है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, अंबानी और

अडानी जैसे नाम भाषणों, नारों और अभियानों में प्रमुखता से शामिल रहे हैं, जो सरकार की बड़े व्यवसायों से कथित निकटता को चुनौती देते हैं। लेकिन वित्तीय धोखाधड़ी के इस हालिया मामले में, ऐसा लगता है कि इन राजनेताओं ने क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ आक्रोश की पटकथा को छोड़ दिया है।

विपक्ष द्वारा कॉर्पोरेट पक्षपात के बारे में ऐतिहासिक रूप से लगातार चिंताएँ उठाए जाने को देखते हुए यह चुप्पी विशेष रूप से हैरान करने वाली है। कोई सोच सकता है कि कहानी बनाने वाली मशीनरी पहले की घटनाओं और इस हालिया घटनाक्रम के बीच अंतर क्यों करती है। कहानी निर्माण के स्तर को देखते हुए, प्रतिक्रिया का अभाव आकस्मिक के बजाय रणनीतिक प्रतीत होता है। यह एक असहज प्रश्न को जन्म देता है: क्या विपक्ष का भाई-भतीजावाद-विरोधी बयान कभी व्यवस्थागत सुधारों के बारे में था, या सिर्फ. राजनीतिक रूप से उपयोगी विरोधियों को निशाना बनाने के बारे में?

उम्मीद की जाती है कि राजनीति मे सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग नैतिकता व भ्रष्टाचार के मामले में सभी विषया पर समभाव रखेंगे।

परंतु निहित स्वार्थों के चलते बहुत से मामले में प्रतिक्रिया चयनात्मक हो जाती है। तरह की चुनिंदा सक्रियता विश्वसनीयता को कमजोर करती है। जनता, जो तेजी से समझदार होती जा रही है। वास्तविक विश्वास और प्रदर्शनकारी आक्रोश के बीच अंतर कर सकती है। जब राजनीतिक दल यह तय करते हैं कि किन आरोपों को उजागर करना है और किनको नजरअंदाज करना है, तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सिद्धांत के बजाय सिर्फ.एक चुनावी हथियार बनाकर रह जाने का जोखिम उठाते हैं।

यह किसी कॉर्पोरेट समूह का समर्थन करने के बारे में नहीं है। अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक लोकतंत्र में, राजनीतिक नेता कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, या प्रतिक्रिया न देने का चुनाव कैसे करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उनकी चुप्पी न केवल उनकी नैतिक स्थिति को कमजोर करती है, बल्कि सार्वजनिक चर्चा की ईमानदारी पर भी सवाल उठाती है। इससे पता चलता है कि आलोचनाएं लाभ-हानि को देखकर की जाती हैं। राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है, खासकर जब शासन, पारदर्शिता और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर बात की जाए।

जब जांच-पड़ताल की जगह मौन ले लेता है, तो सिर्फ.विश्वसनीयता ही नहीं, बल्कि विश्वास भी खो जाता है। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, मौनं सम्मति लक्षणं, मौन अक्सर स्वीकृति का संकेत देता है। राजनीतिक विमर्श के मामले में, यह मिलीभगत का भी संकेत हो सकता है।

आप की बात

ट्रंप के विचित्र बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शायद अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठे हैं। आये दिन अपने बेतुके बयानों से अब उनकी छवि निरन्तर धुमिल होती जा रही है। जब से उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल का भार सम्भाला है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वे किसी देश को टैरिफ की धमकी न देते हों।उनके टैरिफ रेट प्रतिदिन घट बढ़ रहे हैं। वो नहीं जानते कि व्यापार जब दो व्यक्तियों या देशों के बीच होता है तो उससे दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। कोई देश इतना मूर्ख या कमजोर नहीं होता कि वो अमेरिका द्वारा थोपा गया टैक्स रेट तो अमेरिका को दे देगा और अपने निर्यात पर वो बिना कुछ लिए दिये अमेरिका में बेचेगा। ट्रम्प के बड़बोले पन की सीमा तब लंघ गई जब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ' मृत ' कह डाला।यह बयान उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण है क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था व्यवस्था विश्व में सर्वाधिक तेज गति से और निरन्तर बढ़ने वाली चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ,जो 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान लेने वाली है। अब दिल्ली को भी सारे संकोच छोड़ कर अमेरिका को भी उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। क्योंकि एक तरफा मित्रता दुर्बलता की सूचक होती है।

– **डॉ नरेन्द्र टोंक**, मेरठ

अंतरिक्ष से धरती की रक्षा

30 जुलाई 2025 को भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की झ्र निसार उपग्रह का सफल लॉन्च। अब यह मिशन अपने 90-दिन के निर्णायक कमिशनिंग फेज में है। यह न केवल तकनीकी टेस्टिंग है, बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में एक सक्रिय मॉनिटरिंग सिस्टम की तैनाती है। इस मिशन की सबसे बड़ी फीचर यह है कि इसमें दोहरी रेडार सिस्टम झ्र ल-बैंड और एस-बैंड झ्र का उपयोग किया गया है। यह तकनीक उपग्रह को इतनी संवेदनशीलता प्रदान करती है कि वह पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मिलीमीटर स्तर तक डिटेक्ट कर सकता है। इससे ग्लेशियर मूवमेंट, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, अरली वॉर्निंग सिस्टम, और लैंड स्लाइड डिटेक्शन जैसी गतिविधियों की सटीक मॉनिटरिंग संभव होगी। इस 90-दिन की अवधि में एंटीना डिप्लॉयमेंट, ऑर्बिट स्टेबिलिटी , और सिग्नल क्लैरिटी की गहन जांच होगी। यह फेज तय करेगा कि निसार कितनी प्रभावी और प्रिसाइज डेटा भविष्य में प्रदान कर पाएगा। आने वाले समय में निसार मिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट पॉलिसी, और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। यह मिशन न केवल विज्ञान का उपकरण है, बल्कि मानवता की स्थिरता और सुरक्षा का एक दूरदर्शी प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा जो पृथ्वी के हर बदलाव को मौन रूप से पढ़ता है और समय रहते चेतावनी देता है।

– **अवनीश कुमार गुप्ता**, आजमगढ़

लोकतंत्र की विडंबना

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब तक संसद एक भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिये पद से नहीं हटा सकी है, जबकि यह एकमात्र संवैधानिक उपाय है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी. रामास्वामी के खिलाफ लाया गया पहला महाभियोग प्रस्ताव इसका ज्वलंत उदाहरण है। जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए थे, फिर भी संसद में यह प्रस्ताव गिर गया क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उन्हें बचाने का फैसला पहले ही कर लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर जजों ने उनके साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, और अंततः रामास्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनका यह कहना कि ह्लमहाभियोग प्रस्ताव गिरने से मेरे दृष्टिकोण की पुष्टि हुई, न केवल विडंबनापूर्ण था बल्कि लोकतंत्र के उस स्तंभ पर भी चोट था जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। दुखद है कि आज भी कुछ राजनीतिक दल इस संवैधानिक प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते। न्यायिक पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय वे राजनीतिक समीकरण साधने में लगे रहते हैं। जस्टिस वर्मा के ताजा मामले में भी यही देखा गया, जब उन्होंने अपने खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई।

– **विभुक्ति बुपक्या**, खाचरोद, उज्जैन

आत्महत्याओं की मूल वजह

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन अश्लीलता एक खतरनाक सामाजिक चुनौती बन चुकी है। यह केवल एक नैतिक पतन का कारण नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रही है। ओटीटी प्लेटफार्म्स, सोशल मीडिया एप्स और स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से नग्नता और अति-कामुकता को आधुनिकता का प्रतीक बनाकर परोसा जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। यह प्रवृत्ति न केवल पारिवारिक मूल्यों को कमजोर कर रही है, बल्कि समाज की संस्कृति और मयार्दा को भी क्षति पहुँचा रही है। इसमें उलाने के बाद युवा वर्ग अपने जीवन के विकास की ओर से उदासीन होकर अपना हाथों ही अपनी प्रगति के रास्ते बंद कर लेता है .और अश्लीलता की गंदी कोठरी में खुद को बंद कर लेता है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 25 ऐसे एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया जो अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री फैला रहे थे। यह एक सराहनीय कदम है, परंतु सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। समाज और परिवार को भी समान रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। युवाओं में आत्म-अनुशासन और नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना जरूरी है ताकि वे इस डिजिटल जाल में न फंसे। एक शोध के अनुसार, औसत भारतीय युवा प्रतिदिन कई घंटे स्ट्रीमिंग मीडिया पर बिताता है।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम